राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 5 अंक 57

मूल्य ₹8.00, नई दिल्ली, शुक्रवार, 6 अगस्त, 2021

www.jagran.com

पृष्ठ 14

शांत तूफान के नाम से प्रसिद्ध हैं रवि दहिया

>> 12

रवि को रजत से करना पड़ा संतोष

टोक्यो, प्रेट्र: रवि दहिया ओलिंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान बनने से चूक गए। दहिया को पुरुषों के 57 किग्रा भार वर्ग के फाइनल में रूसी ओलिंपिक समिति (आरओसी) के जावुर युवुगेव से हारकर रजत पदक से संतोष करना पड़ा। कुश्ती में यह भारत का दूसरा रजत पदक है। इससे पहले सुशील कुमार ने भी 2012 लंदन ओलिंपिक में रजत पदक जीता था।

आज महिला टीम से पदक की उम्मीद

टोक्यो: रानी रामपाल की अगुआई वाली भारतीय महिला हाकी टीम शुक्रवार को ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ कांस्य पदक का मैच खेलेगी।

भारत उदय

- भारत को टोक्यो ओलिंपिक में एक दिन में मिले दो पदक
- 41 साल बाद पुरुष हाकी में जीता सोने जैसा कांसा
- फाइनल में हार के बाद पहलवान रवि को मिला रजत

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली: टोक्यो ओलिंपिक में पहली बार एक दिन में भारत को दो पदक मिले। गुरुवार की सुबह मनप्रीत सिंह की अगुआई में रणबांकुरों ने जर्मनी को 5-4 से हराकर कांस्य पदक हासिल कर भारतीय हाकी का पुनर्जन्म किया तो शाम को पहलवान रवि दहिया ने फाइनल में हारने के बावजूद रजत पदक जीता। अब भारत के पांच पदक हो गए हैं और यह किसी खेल महाकुंभ में देश का दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। लंदन ओलिंपिक में भारत ने दो रजत और चार कांस्य के साथ कुल छह पदक जीते थे।

भारत ने हाकी में 41 साल से चला आ रहा सूखा खत्म करने के साथ खेल का पुराना गौरव लौटाया। 1-3 से पिछड़ने के बाद भारतीय टीम ने ना सिर्फ वापसी की, बल्कि आठ मिनट में चार गोल दागकर ऐसी बढ़त बनाई जो अंत तक कायम रही। गोलकीपर पीआर श्रीजेश की अगुआई वाली रक्षापंक्ति इस कदर दीवार बनकर खड़ी हुई कि जर्मन आक्रमण वापसी नहीं कर पाया।

भारत के गोल

- सिमरनजीत सिंह 17वें व 34वें मिनट
- हार्दिक सिंह 27वें मिनट
- हरमनप्रीत सिंह 29वें मिनट
- रूपिंदर पाल सिंह 31वें मिनट

<< जीत के बाद गोलपोस्ट पर चढ़ गए गोलकीपर पीआर श्रीजेश • प्रेट्र

प्रधानमंत्री ने कप्तान मनप्रीत और कोच रीड को फोन कर दी बधाई

नई दिल्ली, प्रेट्र : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कप्तान मनप्रीत, कोच ग्राहम रीड और सहायक कोच पीयूष दुबे को फोन करके बधाई दी। प्रधानमंत्री ने मनप्रीत से कहा, 'बहुत, बहुत बधाई। आपने गजब का काम किया है, पूरा देश नाच रहा है। उस दिन (बेल्जियम के खिलाफ हार के बाद) आपकी आवाज ढीली-ढीली थी। आज पूरा जोश है। आप लोगों की मेहनत काम कर गई। मेरी तरफ से सभी खिलाड़ियों को बधाई देना। हम 15 अगस्त को मिल रहे हैं, मैंने सभी को बुलाया है, उस दिन मिलेंगे।' प्रधानमंत्री ने रीड को इतिहास रचने के लिए बधाई दी। रीड ने कहा कि सेमीफाइनल की हार के बाद आपकी बातों से टीम को प्रेरणा मिली।

संबंधित खबरें >> पेज 12

जागरण विशेष

भारतीय छात्रा के कोरोना मास्क को गूगल ने सराहा

दुर्गापुर: भारतीय छात्रा दिगंतिका बसु का इनोवेशन खास है। बंगाल की रहने वाली इस 17 वर्षीय छात्रा ने ऐसा मास्क बनाया है, जो कोरोना वायरस को शरीर में जाने से रोककर उसे बाहर ही नष्ट कर डालता है। (पेज-6)

न्यूज गैलरी

राजनीति ▶ पृष्ठ 4

न सरकार और न ही कैप्टन के काम आए प्रशांत किशोर

चंडीगढ़ : चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर (पीके) ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के प्रधान सलाहकार के पद से इस्तीफा दे दिया है। पांच माह के अपने कार्यकाल के दौरान वह न तो सरकार के काम आए और न ही मुख्यमंत्री के। प्रशांत किशोर ने 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत में अहम भूमिका अदा की थी।

राष्ट्रीय फलक ▶ पृष्ठ 5

बगैर स्थायी पते के भी मिलेंगे उज्ज्वला कनेक्शन

नई दिल्ली : सरकार जल्द ही उज्ज्वला योजना का दूसरा फेज लागू करने जा रही है। इसके तहत उन लोगों को भी एलपीजी कनेक्शन देने का इंतजाम होगा, जिनके पास स्थायी पता नहीं है। इसका फायदा शहरों में रहने वाले गरीबों और देश के विभिन्न हिस्सों में रोजगार की तलाश में जाने वाले श्रमिकों को खास तौर पर होगा। इसे जल्द लागू करने की तैयारी है।

अंतरराष्ट्रीय ▶ पृष्ठ 11

लश्करगाह में जंग तेज, तालिबान को खदेड़ने की कोशिश

काबुल : अफगानिस्तान में प्रांतीय राजधानियों पर कब्जे के लिए चल रही लड़ाई के दौरान लश्करगाह में खून-खराबा बढ़ गया है। मौजूदा स्थिति में 17 प्रांतों की राजधानी खतरे में हैं। इधर अफगान सरकार ने दावा किया है कि उसने 24 घंटे में 303 तालिबान आतंकियों को ढेर कर दिया है।

रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स होगा खत्म, कंपनियों को बड़ी राहत

बड़ा फैसला ▶ निवेश और देश की साख बढ़ाने में अहम होगा यह कदम

वोडाफोन और केयर्न एनर्जी के साथ कर संबंधी विवाद होंगे खत्म

- शिपिंग कारपोरेशन और एयर इंडिया के विनिवेश का भी साफ होगा रास्ता
- यूपीए सरकार के कार्यकाल में रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स किया गया था लागू

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

यूपीए सरकार में लागू किए गए रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स (पिछली तारीख से लगने वाले कर) को सरकार हमेशा के लिए दफन करने जा रही है। इस साहसिक कदम से विदेशी निवेशकों के बीच भारत की साख मजबूत होगी और विदेशी निवेश बढ़ेगा। इसी के साथ, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स से जुड़े वोडाफोन और केयर्न एनर्जी के सभी मामले खत्म होने की राह खुलेगा। एयर इंडिया और शिपिंग कारपोरेशन के विनिवेश में भी आसानी होगी। केयर्न एनर्जी रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के मामलों में भारत के एसेट्स पर दावा कर रही है, जिनमें एयर इंडिया और शिपिंग कारपोरेशन के एसेट्स भी शामिल हैं। कुछ वैश्विक अदालतों में रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के मामले में भारत की हार से देश की छवि को भी धक्का लगा है।

सरकार ने 2012 से पहले के सभी रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के मामलों को वापस लेने का फैसला किया है। इस मद में वसूले गए टैक्स को भी सरकार वापस करेगी। इस फैसले को कानूनी रूप देने के लिए गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कराधान विधि संशोधन विधेयक, 2021 लोकसभा में रखा। इसके तहत 28 मई, 2012 से पहले परोक्ष रूप से भारतीय एसेट्स के ट्रांसफर पर लगने वाले रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स खत्म हो जाएंगे।

रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को लेकर विधेयक में कहा गया है कि इससे आकर्षक निवेश स्थल के रूप में भारत की छवि को धक्का लगा है। पिछले कुछ वर्षों में वित्तीय और इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में निवेश के प्रोत्साहन के लिए कई पहल की गई हैं। इसके बावजूद निवेशकों के मन में रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स की शंका कायम रही, जिससे कहीं न कहीं निवेश प्रभावित हो रहा था।

टैक्स विशेषज्ञ भी मान रहे हैं कि कांग्रेस सरकार के जमाने से चल रहे रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को समाप्त करने से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह संदेश निश्चित रूप से जाएगा कि भारत में कानून का राज है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, सरकार ने अब तक रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के मामले में 8,100 करोड़ रुपये की वसूली की है, जिसमें 7,900 करोड़ रुपये केयर्न एनर्जी के हैं। वोडाफोन पर सरकार की कोई देनदारी नहीं है। विधेयक के प्रस्ताव के मुताबिक सरकार रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के मद में वसूली गई राशि वापस करेगी, लेकिन कंपनियों को भी भारत सरकार के खिलाफ अदालतों से सभी मुकदमों को वापस लेना होगा।

टैक्स एक्सपर्ट असीम चावला कहते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के सभी मामले खत्म होने से मुकदमेबाजी में बर्बाद होने वाले सरकार के समय और पैसे दोनों की बचत होगी। सरकार को यह काम 2014 में ही कर देना चाहिए था। इस विधेयक के तहत आयकर कानून 1961 में संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि भविष्य में 2012 से पहले परोक्ष रूप से भारतीय एसेट्स के ट्रांसफर पर रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स की मांग न हो।

संसद के मानसून सत्र के दौरान गुरुवार को लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। प्रेट्र

जेटली भी गलत मानते थे इस व्यवस्था को

पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली कई बार सार्वजनिक रूप से स्वीकार चुके थे कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स गलत है। इससे निवेश प्रभावित होता है। सूत्रों का कहना है कि एनडीए सरकार 2014 से ही इसे हटाना चाहती थी, लेकिन इसे हटाने में सात साल लग गए। कांग्रेस के नेताओं ने भी रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को कभी देश के आर्थिक विकास के लिए अच्छा नहीं माना, लेकिन इसे हटाने का फैसला नहीं हो सका।

राजनीतिक विरोध व कोरोना के बावजूद सुधारों पर नहीं ठिठकेंगे कदम पेज>>7

जासूसी के आरोप सही तो मामला गंभीर : सुप्रीम कोर्ट

पेगासस मामला ▶ पूछा, जब पता चला फोन टैप हुआ है तो शिकायत क्यों नहीं दर्ज कराई

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

पेगासस जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर अखबार में आई खबर सही है तो मामला गंभीर है। लेकिन साथ ही सवाल उठाया कि जब मामले का पता 2019 में लग गया था तो अब तक शिकायत क्यों नहीं की और अब इसे क्यों उठाया जा रहा है? कोर्ट ने यह भी कहा कि ज्यादातर याचिकाएं मीडिया रिपोर्टों पर आधारित हैं। कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए विचार करने का मन तो बनाया, लेकिन गुरुवार को याचिकाओं पर औपचारिक नोटिस जारी नहीं किया। कोर्ट ने मामले को 10 अगस्त को फिर सुनवाई पर लगाने का आदेश देते हुए याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे याचिका की प्रति एडवांस में केंद्र सरकार को दें, ताकि उस दिन नोटिस स्वीकार करने के लिए सरकार की ओर से कोई मौजूद हो।

प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने वरिष्ठ पत्रकार एन. राम, भाकपा सांसद जान ब्रिटास, एडीटर्स गिल्ड आफ इंडिया समेत कुछ अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि वह निजता के हनन को गंभीर मानती है, लेकिन कुछ सवाल हैं।

जस्टिस रमना ने कहा कि याचिकाकर्ता जानकार और साधन संपन्न लोग हैं। उन्हें अतिरिक्त सामग्री एकत्र करने के लिए कुछ और प्रयास करना चाहिए था। याचिकाकर्ता की ओर से पेश कपिल सिब्बल ने कहा कि उनके पास इस बारे में सीधे तौर पर कोई सामग्री या जानकारी नहीं थी। निगरानी की सीमा के बारे में भी उन्हें नहीं मालूम था। इसके बगैर याचिका कैसे दाखिल करते। उन्हें वाशिंगटन पोस्ट और अन्य मीडिया रिपोर्ट से इस निगरानी के बारे में पता चला। मीडिया रिपोर्ट में लोगों की लिस्ट आई है। गुरुवार सुबह भी मीडिया में जानकारी आई है कि इस कोर्ट की रजिस्ट्री के कुछ अधिकारियों के फोन टैप हुए हैं। न्यायपालिका के वरिष्ठ सदस्यों के भी। इस पर जस्टिस रमना ने कहा कि सच्चाई सामने आनी चाहिए।

केंद्र सरकार को याचिका की प्रति देने का दिया आदेश

टेलीग्राफ एक्ट और आइटी एक्ट में हैं शिकायत के प्रविधान

प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि कुछ याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उनका फोन हैक हुआ था या उसकी टैपिंग हुई। जब उन्हें पता चला तो क्या उन्होंने इस बारे में क्रिमिनल कंप्लेन (शिकायत) दर्ज कराई या इसका प्रयास किया? आपको पता होगा कि टेलीग्राफ एक्ट और आइटी एक्ट में क्रिमिनल कंप्लेन दर्ज कराने के लिए प्रविधान हैं। सिब्बल ने कहा कि पहले उनके पास कोई जानकारी नहीं थी। एक याचिका में पेश वरिष्ठ वकील सीयू सिंह ने कहा, 2019 से लेकर जुलाई 2021 तक लोगों के नाम पता नहीं थे। नाम जुलाई में पता चले। वरिष्ठ वकील मीनाक्षी अरोड़ा, श्याम दीवान, अरविंद दत्तार और राकेश द्विवेदी ने कहा कि यह किसी एक व्यक्ति से जुड़ा मामला नहीं है।

नाम से पक्षकार बनाने पर आपत्ति

सुप्रीम कोर्ट ने वकील एमएल शर्मा की याचिका पर सवाल उठाया। कोर्ट ने शर्मा से कहा कि आपने याचिका में भारत सरकार को पक्षकार नहीं बनाया, बल्कि एक व्यक्ति को नाम से पक्षकार बनाया है। आपकी याचिका में समस्या है। किसी व्यक्ति को नोटिस कैसे जारी किया जाए। शर्मा ने कोर्ट से पक्षकार की सूची से नाम हटा कर सरकार को पक्षकार बनाने का संशोधन करने की इजाजत मांगी। कोर्ट ने उन्हें इजाजत दे दी। कोर्ट ने शर्मा से कहा कि आपने अखबार की खबर के आधार पर याचिका दाखिल कर दी है। यह याचिका दाखिल करने का तरीका नहीं है।

जासूसी का सुबूत देने में विपक्ष पूरी तरह से विफल : भाजपा पेज>>3

पाक में फिर हिंदू मंदिर पर हमला, मूर्तियों को तोड़ा

लाहौर, प्रेट्र : पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक बार फिर हिंदू मंदिर पर कट्टरपंथियों की अगुवाई में हजारों लोगों ने हमला कर दिया। रहीम यार खान जिले के इस भव्य गणेश मंदिर में घुसकर उन्मादी कट्टरपंथियों ने सभी मूर्तियों को तोड़ डाला। मंदिर के बड़े हिस्से में आग लगा दी। हालात बेकाबू होने के बाद सेना तैनात की गई।

यहां रहने वाले हिंदुओं के 100 परिवारों का जीवन खतरे में है। हमलावरों ने इन हिंदुओं को भी निशाना बनाने की कोशिश की।

अल्पसंख्यक हिंदुओं के मंदिर पर यह हिंसक घटना लाहौर से 590 किमी दूर हुई। यहां के रहीमयार खान जिले के भोंग में हिंदुओं का बड़ा और भव्य मंदिर है। इस मंदिर को गणेश मंदिर के नाम से जाना जाता है। मंदिर पर अचानक कट्टरपंथियों ने हजारों लोगों की भीड़ के साथ हमला बोल दिया। यहां मूर्तियों को पूरी तरह तोड़ दिया गया। मंदिर की सजावट में लगे झूमर, कांच के सामान को नष्ट कर दिया गया। यही नहीं भीड़ ने मंदिर परिसर को आग के हवाले कर दिया।

भोंग में हिंदू मंदिर पर घंटों तक चली तोड़फोड़ और आगजनी के दौरान पूरी अराजकता रही। योजनाबद्ध तरीके से की गई हिंसा में पुलिस शामिल रही। वहां एक पुलिसकर्मी भी नहीं पहुंचा।

इमरान की पार्टी के सांसद ने कार्रवाई की मांग की : सत्तारूढ़ इमरान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ के सांसद डा रमेश कुमार वंकवानी ने मंदिर पर हमले के वीडियो ट्विटर पर साझा किए हैं। इन वीडियो में कट्टरपंथी मुस्लिम भगवान की मूर्तियों को निशाना बनाकर तोड़ रहे हैं। मंदिर परिसर में आग भी लगी दिखाई दे रही है। सांसद वंकवानी ने अपने ट्वीट में कहा है कि भोंग में हालात बेहद खराब हैं। पुलिस की लापरवाही शर्मनाक है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से कार्रवाई की मांग की है। पाकिस्तान में अराजकता का आलम यह है कि घंटों चली हिंसा में अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है।

अराजकता

- जबरदस्त तोड़फोड़ कर मंदिर को किया आग के हवाले
- हजारों मुस्लिमों की भीड़ की हिंसा में पुलिस रही गायब, सेना तैनात
- मंदिर के निकट रहने वाले 100 हिंदू परिवारों की जान को खतरा

पाकिस्तान के रहीम यार खान जिले में स्थित गणेश मंदिर में घुसकर उन्मादी कट्टरपंथियों ने मूर्तियों को तोड़ डाला। घटना के बाद इसे आगे से कपड़े से ढक दिया गया है। एपी

पाकिस्तान हिंदू मंदिरों की पवित्रता बनाए रखने में विफल पेज>>11

देश को रोकने में लगे कुछ लोग कर रहे सेल्फ गोल : मोदी

- पीएम ने किया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न महोत्सव का शुभारंभ
- संसद की कार्यवाही रोकने वाले कर रहे जनभावना का अपमान
- यूपी के जरिये दिल्ली का सपना देखने वाले खुद को करते रहे समृद्ध

नई दिल्ली में गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से संवाद किया। एएनआइ

जो अपने पद के लिए परेशान हैं, वे भारत को रोक नहीं सकते। नया भारत पद नहीं, पदक जीतकर दुनिया पर छा रहा है। -नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विपक्षी दल जनभावना का निरंतर अपमान कर रहे हैं। आज जब देश कोरोना की विभीषिका से पार पाते हुए विभिन्न क्षेत्रों में नई ऊंचाइयों को छू रहा है तो कुछ लोग संसद की कार्यवाही में बाधा डालकर देशहित के काम रोकने की स्पर्धा में लगे हैं। गुरुवार को पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न महोत्सव का आनलाइन शुभारंभ किया। अपने संबोधन में टोक्यो ओलिंपिक में भारतीय हाकी टीम के शानदार प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए पीएम ने कहा कि जब हमारे युवा गोल पर गोल दागकर भारत के लिए नई सिद्धियां प्राप्त कर रहे हैं, तो कुछ लोग राजनीतिक स्वार्थ में 'सेल्फ गोल' (आत्मघाती गोल) करने में लगे हैं। जनता ऐसी देशहित विरोधी राजनीति की बंधक नहीं बन सकती है। महंगाई को लेकर विपक्ष के हमले की धार कुंद करने के उद्देश्य से यह कहने से नहीं चूके कि सरकार इसे नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है और हम जल्द ही इस पर काबू पाएंगे।

पांच अगस्त का बताया महत्व : मोदी ने लोगों को बताया कि करोड़ों हिंदुस्तानियों के लिए पांच अगस्त की तारीख भावनात्मक रूप से क्यों यादगार है। उन्होंने याद दिलाया कि दो साल पहले इसी तारीख को संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाकर जम्मू-कश्मीर के हर नागरिक को हर अधिकार और सुविधाओं में भागीदार बनाया गया था। पिछले वर्ष इसी तारीख को अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण की ओर कदम बढ़े। आज ओलंपिक में हमारे युवाओं ने देश को बड़ा तोहफा दिया है और आज ही उप्र के 15 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज वितरण के लिए यह पुण्य आयोजन हो रहा है।

राजनीति के चश्मे से देखा गया उप्र : मोदी ने पिछली सरकारों को कठघरे में खड़ा करते हुए कहा कि बीते दशकों में उप्र को हमेशा राजनीति के चश्मे से देखा गया। दिल्ली के सिंहासन का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, यह सपना देखने वाले बहुत लोग आए और गए, लेकिन उन्होंने कभी सोचा भी नहीं कि उप्र देश के विकास में अग्रिम भूमिका निभा सकता है। किसी ने वंशवाद, किसी ने परिवार के लिए तो किसी ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए उप्र का इस्तेमाल किया। ऐसे लोगों ने खुद को समृद्ध किया, उप्र को नहीं। योगी सरकार के आने पर उप्र इस कुचक्र से बाहर निकल आया है।

भारत के ग्रोथ इंजन का पावर हाउस पेज>>5

खाओ और पढ़ो

शिक्षा मंत्रालय ने की तैयारी, सभी स्कूली बच्चों का बनेगा हेल्थ कार्ड, कुपोषण प्रभावित जिलों से इसे जल्द शुरू करने का हो सकता है एलान, मिड-डे स्कीम के तहत प्री-प्राइमरी के बच्चे को भी मिलेगा खाना

मिड डे मील से पहले स्कूलों में अब नाश्ता भी मिलेगा

अरविंद पांडेय, नई दिल्ली

अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ सरकार अब स्कूली बच्चों की सेहत का भी पूरा ख्याल रखेगी। इसकी तैयारी तेजी से शुरू हो गई है। इसके तहत स्कूलों में पढ़ने वाले सभी बच्चों का हेल्थ कार्ड तैयार होगा। साथ ही उन्हें मिड-डे मील के साथ सुबह का नाश्ता भी दिया जाएगा। अभी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को सिर्फ मिड-डे मील ही दिया जाता है। हालांकि सुबह का नाश्ता देने की शुरुआत अभी ऐसे जिलों से की जाएगी जो कुपोषण से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं।

सरकार ने यह पहल नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) की सिफारिश के बाद की है, जिसमें यह कहा गया है कि कई अध्ययनों से यह साफ हुआ है कि सुबह के पौष्टिक नाश्ते के बाद कुछ घंटों में कई सारे मुश्किल विषयों का अध्ययन अधिक प्रभावी होता है। इस दौरान पढ़े गए विषय जल्द याद होते हैं। नीति में इसके आधार पर ही स्कूली बच्चों को मिड-डे मील के साथ सुबह का नाश्ता देने की भी सिफारिश की गई है। नीति के अमल में तेजी से जुटे शिक्षा मंत्रालय ने इस बीच जो योजना बनाई है, उसमें नाश्ता स्कूल के किचन में नहीं बनेगा। नाश्ता क्षेत्रीय स्वयंसेवी या महिला संगठनों की मदद से तैयार कराया जाएगा। यह पैक्ड फूड पोषण से भरपूर होगा। इसे लेकर राज्यों से सुझाव मांगे गए हैं। शिक्षा मंत्रालय से जुड़े सूत्रों की मानें तो हेल्थ कार्ड व नाश्ते की योजना के साथ मिड-डे मील की स्कीम को विस्तार देने की भी तैयारी है। अब इसके दायरे में प्री-प्राइमरी या बाल वाटिका भी होगी। अभी इस स्कीम के दायरे में पहली से आठवीं तक के ही बच्चे शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक मंत्रालय ने इन सभी को तेजी से लागू करने की तैयारी पूरी कर ली है, जिसकी जल्द घोषणा हो सकती है। हेल्थ कार्ड में बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ी जरूरी जानकारी के साथ टीकाकरण का भी पूरा ब्योरा रहेगा।

सेहत का भी ख्याल। फाइल फोटो

करीब 12 लाख स्कूली बच्चों को मिलेगा लाभ

स्कूली बच्चों को मिड-डे मील के साथ यदि सुबह का नाश्ता देने की योजना शुरू होती है, तो इसका लाभ देश के करीब 12 लाख स्कूली बच्चों को मिलेगा। हालांकि इसकी शुरुआत अभी सिर्फ कुपोषण से प्रभावित जिलों से ही करने की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में मौजूदा समय में कुपोषण से प्रभावित करीब 113 जिले हैं। इनमें से ज्यादातर आदिवासी क्षेत्रों के हैं। वैसे भी केंद्र सरकार ने कुपोषण से प्रभावित इन सभी जिलों को वर्ष 2022 तक इससे मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। माना जा रहा है कि इस मुहिम से यह लक्ष्य को हासिल करना काफी आसान होगा।

फेमा के उल्लंघन पर फ्लिपकार्ट को ईडी का 10,600 करोड़ का नोटिस

नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विदेशी मुद्रा कानून के कथित उल्लंघन के लिए ई-कामर्स कंपनी फ्लिपकार्ट और उसके प्रमोटरों को करीब 10,600 करोड़ रुपये का कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार फेमा की विभिन्न धाराओं के तहत पिछले महीने 10 लोगों को नोटिस जारी किया गया था, जिनमें फ्लिपकार्ट, उसके संस्थापक सचिन बंसल और बिन्नी बंसल शामिल हैं। (पेज-7)

अमेरिका में छह माह बाद मिले एक लाख से ज्यादा नए मामले

वाशिंगटन : अमेरिका में कोरोना महामारी फिर बढ़ती जा रही है। इस बार कोरोना का डेल्टा वैरिएंट कारण बन रहा है। नतीजन पीड़ितों की दैनिक संख्या में उछाल आ गई है। बीते 24 घंटे में देशभर में एक लाख से ज्यादा नए मामले पाए गए। छह माह बाद एक दिन में इतनी बड़ी संख्या में नए संक्रमित मिले हैं। (पेज-11)

90 हजार 31 लोगों को राजधानी में गुरुवार को शाम सात बजे तक कोरोना रोधी टीका लगाया गया। एक दिन पहले कोविशील्ड की एक लाख 67 हजार 840 डोज दिल्ली पहुंची। इससे दिल्ली में कुल आठ लाख से अधिक डोज टीका उपलब्ध है।

आबोहवा को क्षति पहुंचाने वाले पेड़-पौधों की अब खैर नहीं

जागरण एक्सक्लूसिव

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली

- हानिकारक पेड़-पौधों से मुक्ति दिलाने को केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने गठित की छह सदस्यीय कमेटी
- दिल्ली से प्रो. सीआर बाबू को बनाया गया इसका सदस्य, कमेटी तैयार करेगी वनस्पति और जलवायु को इन पौधों से बचाने की रिपोर्ट

दिल्ली एनसीआर सहित देशभर में आबोहवा को नुकसान पहुंचा रहे विलायती कीकर सहित अन्य हानिकारक विदेशी पेड़-पौधों की अब खैर नहीं है। इनसे छुटकारा पाने की दिशा में केंद्र सरकार ने हाल ही में एक विशेष कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी अपनी रिपोर्ट में इन सभी हानिकारक पेड़-पौधों से वनस्पति और जलवायु बचाने के लिए रिपोर्ट और कार्ययोजना दोनों तैयार करेगी।

केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा गठित इस छह सदस्यीय कमेटी का अध्यक्ष वन महानिदेशक, भारत सरकार को बनाया गया है, जबकि उप महानिरीक्षक (वन एवं वन्य जीव) राकेश कुमार जगनिया कमेटी के सदस्य सचिव बनाए गए हैं। कमेटी के अन्य सदस्यों में एक सेवानिवृत्त वन अधिकारी और दो आला अधिकारियों के साथ-साथ राजधानी के मशहूर वनस्पति विज्ञानी प्रो. सीआर बाबू को भी सदस्य रखा गया है।

सदस्य सचिव की ओर से कमेटी की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इस अधिसूचना में कमेटी के गठन का उद्देश्य विदेशी एवं आक्रामक प्रजाति के पेड़-पौधों के प्रबंधन के निमित्त राष्ट्रीय नीति एवं कार्ययोजना तैयार करना बताया गया है। जल्द ही कमेटी के सदस्यों की पहली बैठक होने की संभावना है। बताया जाता है कि इस कमेटी की रिपोर्ट को आधार बनाकर ही केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर नीति को अंतिम रूप देगी।

कालकाजी स्थित हंसराज सेठी उद्यान में लगे विलायती कीकर के पेड़। जागरण

विलायती कीकर सबका दुश्मन

विलायती कीकर धरती और जल का ही नहीं बल्कि इंसान और बेजुबानों का भी बड़ा दुश्मन है। बहुतायात में मिलने के कारण यह आबोहवा में ही घुलकर दिल्लीवासियों को श्वास और एलर्जी सरीखी बीमारियों का शिकार बना रहा है। यह और इसी प्रजाति के अन्य पेड़- पौधे इलेलोपैथी नाम का रसायन छोड़ते हैं। यह रसायन आसपास किसी अन्य वनस्पति को पनपने ही नहीं देते। इस रसायन से जमीन की उर्वरक क्षमता भी प्रभावित होती है और भूजल का स्तर भी नीचे चला जाता है।

कीकर कई रोगों के लिए रामबाण

हिमाचल में बबूल को कीकर कहा जाता है। इसका वानस्पतिक नाम अकेशिया निलोटिका है। इसके पत्ते, बीज व छाल में औषधीय गुण होते हैं। इसमें पीले फूल लगते हैं। मटर के आकार की फली के दाने विभिन्न असाध्य रोगों के लिए रामबाण हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस पौधे में भगवान विष्णु का निवास माना जाता है। प्राचीन समय में इसकी पूजा होती थी। हिमालयन जड़ी-बूटी उत्पादन एवं संरक्षण परिषद के राज्य महासचिव सीता राम ने बताया कि जिन लोगों को कीकर के गुणों की जानकारी है, वे इसकी लकड़ी की दातुन भी करते हैं, जो दांतों के लिए बहुत लाभ देती है। किसी अंग में जलन होने पर इसकी छाल का काढ़ा मिश्री के साथ पीने से राहत मिलती है। पत्तों को पीसकर घाव पर लगाने से घाव ठीक हो जाता है। कीकर के पत्ते तथा छाल का चूर्ण शहद में मिलाकर सेवन करने से खांसी में लाभ होता है। इसके कोमल पत्तों को गाय के दूध में पीस कर रस की बूंदें आंखों में डालने से आंखों का दर्द ठीक होता है। इससे आंखों की सूजन में भी लाभ होता है।

एनसीआर में वायु गुणवत्ता प्रबंध आयोग विधेयक को संसद की मंजूरी

- राज्यसभा में हंगामे के बीच ध्वनिमत से विधेयक पारित

नई दिल्ली, प्रेट्र: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग विधेयक, 2021 को गुरुवार को संसद की मंजूरी मिल गई। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता सूचकांक से संबंधित समस्याओं को लेकर बेहतर समन्वय, अनुसंधान, पहचान और समाधान के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंध आयोग गठित करने के प्रविधान वाले इस विधेयक को राज्यसभा में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच ध्वनिमत से मंजूरी दी गई। लोकसभा इसे पहले ही मंजूरी दे चुकी है।

उच्च सदन में वन एवं पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने विधेयक को चर्चा के लिए रखते हुए कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में वायु प्रदूषण के निराकरण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए यह विधेयक लाया गया है।

विधेयक पर विपक्ष के हंगामे के बीच संक्षिप्त चर्चा हुई जिसमें राकांपा की वंदना चव्हाण ने कहा कि यह बहुत दुख की बात है कि सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद सरकार ने वायु गुणवत्ता के लिए यह कदम उठाया।

बीजद के प्रसन्न आचार्य ने आयोग में किसानों के प्रतिनिधित्व की मांग की। कांग्रेस के दीपेंद्र सिंह हुड्डा, द्रमुक के आरएस भारती, अन्नाद्रमुक के एम थंबीदुरई, वाईआरएस कांग्रेस पार्टी के अयोध्या रामी रेड्डी, माकपा की झरनादास वैद्य, टीआरएस सदस्य के आर सुरेश रेड्डी, राजद के मनोज झा, टीएमसी (एम) के जीके वासन, आम आदमी पार्टी के सुशील कुमार गुप्ता, शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी ने भी विधेयक पर हुई चर्चा में अपनी बात रखी। चर्चा के जवाब में भूपेंद्र यादव ने कहा कि दिल्ली में पिछले कुछ सालों में वायु प्रदूषण बढ़ने के कारणों में यातायात, औद्योगिक प्रदूषण और जैविक कचरे को जलाना आदि शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इस समस्या से निपटने के लिए एक समेकित संस्था जरूरी थी। इसी उद्देश्य से यह विधेयक लाया गया है। इसमें पर्यावरण क्षेत्र के विशेषज्ञ लोगों के साथ ही एनसीआर के समीपवर्ती क्षेत्रों के लोगों को शामिल किया गया है।

उन्होंने कहा कि सरकार देश के पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए हम ऐसी व्यवस्था चाहते थे जिसमें नवाचार, समाधान, समन्वय हो। यादव ने कहा कि आयोग में किसानों का प्रतिनिधित्व होगा। उन्होंने कहा विधेयक के माध्यम से हम पूरी तरह संसद के प्रति जवाबदेह होंगे और आयोग की रिपोर्ट हर साल संसद के पटल पर पेश की जाएगी। यह विधेयक इससे संबंधित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं संलग्न क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग अध्यादेश, 2021 का स्थान लेगा।

न्यूज गैलरी

सेंट स्टीफंस कालेज में दाखिला आवेदन शुरू

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय संबद्ध सेंट स्टीफंस कालेज में स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। गुरुवार को दाखिला पोर्टल खुला। छात्र स्नातक के विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं। कालेज 12वीं के अंक को 85 फीसद जबकि साक्षात्कार प्रक्रिया को 15 फीसद आधार बनाकर दाखिला देगा। 50 फीसद सीटें ईसाई छात्रों के लिए आरक्षित हैं। कोरोना संक्रमण के चलते स्पोर्ट्स में दाखिले के लिए ट्रायल नहीं होंगे। (जासं)

एयरपोर्ट पर तस्करी के आरोप में तीन सूडानी पकड़े गए

नई दिल्ली : इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की टीम ने सूडान के तीन नागरिकों को सोना तस्करी के आरोप में पकड़ा है। तीनों आरोपित दुबई से भारत आए हैं। तलाशी के दौरान इनके बैग में सोने के बिस्किट बरामद किए गए। बुधवार को यहां पहुंचने पर इमिग्रेशन क्लियरेंस के बाद ग्रीन चैनल पार कर टर्मिनल बिल्डिंग से फरार होने की जुगत में थे। इसी दौरान कस्टम की टीम ने तीनों को पकड़ लिया। (जासं)

परेशान करने को दायर हुआ वाद : जयलाल

नई दिल्ली : इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आइएमए) के अध्यक्ष जेए जयलाल ने अपने खिलाफ आयुर्वेद से संबंधित टिप्पणी को लेकर माफी मांगने वाली याचिका को एलोपैथिक डाक्टरों को परेशान करने वाला बताया है। उन्होंने वाद को खारिज करने की मांग की है। तीस हजारी की सिविल न्यायाधीश दीक्षा राव ने पक्षकारों को 29 सितंबर तक जवाब देने का निर्देश दिया है। जयलाल ने एक टीवी साक्षात्कार में कहा था कि भारत सरकार आधुनिक चिकित्सा को आयुर्वेद से बदलने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उनके सांस्कृतिक मूल्य और हिंदुत्व में पारंपरिक विश्वास है। (जासं)

फर्जी अंतरराष्ट्रीय काल सेंटर का भंडाफोड़, 32 गिरफ्तार

ग्रेटर नोएडा : ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित टेकजोन फोर में छापेमारी कर बिसरख कोतवाली पुलिस ने फर्जी अंतरराष्ट्रीय काल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। आरोपित अमेरिका, जर्मनी, न्यूजीलैंड सहित कई अन्य देशों में रहने वाले विदेशी नागरिकों से डालर में ठगी करते थे। मौके से 32 युवकों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि मालिक समेत 20 अभी फरार हैं। आरोपित तीन साल से ठगी का कारोबार कर रहे थे। अब तक कुल 50 करोड़ की ठगी कर चुके हैं। मामले में आगे की जांच की जा रही है। (जासं)

मुसीबत में मुफ्त आक्सीजन बांटने वालों पर कार्रवाई नहीं

सुनवाई ▶ ड्रग कंट्रोलर की रिपोर्ट को हाई कोर्ट ने रिकार्ड पर लिया

भाजपा सांसद गौतम गंभीर के खिलाफ आगे की कार्रवाई जारी रहेगी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

पिछली सुनवाई में अदालत द्वारा सवाल उठाने के बाद दिल्ली ड्रग कंट्रोलर ने गुरुवार को कहा कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान जरूरतमंदों को आक्सीजन बांटने वाले नेक इंसानों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने का फैसला लिया है। न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने ड्रग कंट्रोलर की रिपोर्ट को रिकार्ड पर लेते हुए कहा कि मामले पर सही कदम उठाया गया है। पीठ ने इसके साथ ही कहा कि मामले में आगे सुनवाई करने की जरूरत नहीं है और याचिका का निपटारा किया जाता है। इस मामले में सांसद गौतम गंभीर के खिलाफ आगे की कार्रवाई जारी रहेगी।

याचिका का किया निपटारा। फाइल फोटो

अदालत के आदेश पर ड्रग कंट्रोलर ने दवा की जमाखोरी करने के मामले में सांसद गौतम गंभीर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। पिछली सुनवाई पर ड्रग कंट्रोलर ने पीठ को बताया था कि आक्सीजन की जमाखोरी के लिए आम आदमी पार्टी के जंगपुरा से विधायक प्रवीण कुमार के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। पीठ ने ड्रग कंट्रोलर के इस कदम पर सवाल उठाते हुए पूछा था कि क्या विभाग मुफ्त आक्सीजन का वितरण करने वाले गुरुद्वारा, मंदिर व सामाजिक संगठन समेत प्रत्येक व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करेगा? इसके जवाब में दिल्ली सरकार की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने पीठ को बताया कि मुफ्त आक्सीजन बांटने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई न करने का फैसला लिया गया है।

उन्होंने कहा कि इस संबंध में नीति बना ली गई और संबंधित अधिकारी द्वारा स्वीकृत भी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि महामारी अभी खत्म नहीं हुई है और अगर इस तरह की कार्रवाई की गई तो कोई भी भला इंसान लोगों की मदद करने के लिए आगे नहीं आएगा।

उन्होंने कहा कि इस संबंध में शुरू की गई सभी कार्रवाई को विभाग द्वारा वापस लिया जाएगा। दवा व आक्सीजन की कालाबाजारी व जमाखोरी करने वाले राजनेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर अधिवक्ता विराग गुप्ता के माध्यम से शूटर दीपक सिंह द्वारा दायर याचिका पर अदालत सुनवाई कर रही थी।

पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों को मिलनी चाहिए मौलिक सुविधाएं

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : मजनूं का टीला स्थित शरणार्थी शिविर में रह रहे पाकिस्तान से आए हिंदुओं को मौलिक सुविधा मुहैया कराने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को उचित निर्णय लेने को कहा है।

मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल व न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने कहा कि याचिका को प्रतिवेदन के तौर पर लेकर तथ्यों, कानून और नीति के अनुसार निर्णय करें। शरणार्थी कैंप में पानी, स्वच्छता और बिजली जैसी बुनियादी जरूरतें उपलब्ध कराने की मांग को लेकर एनजीओ व कुछ शरणार्थियों की तरफ से याचिका दायर की गई थी।

उन्होंने कहा कि वे जातीय भेदभाव के कारण पाकिस्तान से भागकर भारत आए हैं और मजनूं का टीला व सिग्नेचर ब्रिज के पास बने शिविरों में रहते हैं। उन्होंने कहा कि इन शिविरों में सुविधाएं नहीं हैं और उनके साथ लैंगिक भेदभाव किया जा रहा है। अधिवक्ता गौतम झा के माध्यम से याचिका दायर कर उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार शिविरों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए बाध्य है और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देश के बावजूद अधिकारियों द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया है।

पिंक लाइन पर आज से मजलिस पार्क से शिव विहार तक चलेगी मेट्रो

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

मेट्रो की सीधी सेवा। फाइल फोटो

पिंक लाइन के त्रिलोकपुरी-मयूर विहार पाकेट एक के बीच नवनिर्मित कारिडोर पर शुक्रवार से मेट्रो का परिचालन शुरू होगा। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सुबह में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये हरी झंडी दिखाकर इस कारिडोर पर मेट्रो के परिचालन का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद दोपहर तीन बजे से इस कारिडोर पर यात्रियों के लिए मेट्रो सेवा उपलब्ध हो जाएगी। वैसे तो यह कारिडोर महज 290 मीटर लंबा है, लेकिन इस छोटे से कारिडोर पर मेट्रो का परिचालन शुरू होने से पिंक लाइन के पूरे 58.59 किलोमीटर हिस्से पर शिव विहार से मजलिस पार्क तक सीधी मेट्रो उपलब्ध हो जाएगी। इससे पूर्वी दिल्ली से दक्षिणी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली व बाहरी दिल्ली के बीच आवागमन की सुविधा बेहतर हो जाएगी।

पिंक लाइन को रिंग रोड के समानांतर बनाया गया है। इसका मकसद रिंग रोड पर वाहनों के दबाव को कम करना है। अभी तक पिंक लाइन के दो हिस्सों पर मेट्रो का परिचालन हो रहा है। इसके एक हिस्से पर मजलिस पार्क से मयूर विहार पाकेट एक के बीच और दूसरे हिस्से पर त्रिलोकपुरी से शिव विहार के बीच मेट्रो का परिचालन हो रहा है। इन दोनों कारिडोर के बीच त्रिलोकपुरी से मयूर विहार पाकेट एक स्टेशन तक 290 मीटर हिस्सा जमीन विवाद में फंस गया था। इससे इसके निर्माण में देरी हुई। जमीन विवाद खत्म होने के बाद दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने स्टील के गार्डर से इस कारिडोर का निर्माण पूरा किया। इसलिए पिंक लाइन का अब पूरा हिस्सा आपस में जुड़ गया है। लिहाजा, त्रिलोकपुरी से मयूर विहार पाकेट एक के बीच परिचालन शुरू होते ही पिंक लाइन का पूरा कारिडोर यात्रियों के लिए खुल जाएगा। इससे पिंक लाइन दिल्ली मेट्रो का सबसे बड़ा कारिडोर बन जाएगा। इसका 39.48 किलोमीटर हिस्सा एलिवेटेड व 19.11 किलोमीटर हिस्सा भूमिगत है। इस कारिडोर पर कुल 38 मेट्रो स्टेशन हैं। इनमें से 26 एलिवेटेड व 12 भूमिगत स्टेशन हैं। वहीं ब्ल्यू लाइन की कुल लंबाई 56.61 किलोमीटर है।

हमने लीक नहीं की दिशा रवि मामले में जांच की जानकारी : पुलिस

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : कृषि कानूनों के विरोध में एक टूलकिट साझा करने के मामले में दिशा रवि के खिलाफ जांच से जुड़ी जानकारी दिल्ली पुलिस ने मीडिया में लीक नहीं की है। अधिवक्ता अमित महाजन के माध्यम से रिपोर्ट दाखिल करके पुलिस ने कहा कि उस पर जानकारी लीक करने का लगाया गया आरोप झूठा और गलत तथ्यों पर आधारित है। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने रिपोर्ट को रिकार्ड पर लेते हुए कहा कि यह लोगों के लिहाज से महत्वपूर्ण मामला है और इस पर 27 सितंबर को सुनवाई होगी।

साइबर सेल यूनिट के उपायुक्त अन्येष राय ने हलफनामे में कहा कि दिशा रवि से जुड़े मामले में कोई भी सूचना या चैट मीडिया साझा नहीं किया गया है। जबकि दिशा रवि के वकील ने कहा कि मीडिया का दावा था कि उन्हें पुलिस से जानकारी मिली है।

वहीं, दिल्ली दंगा मामले में आरोपित जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्र आसिफ इकबाल तन्हा के आरोप पत्र से जुड़ी जानकारी मीडिया में कैसे लीक हुई, इसका पता लगाने में दिल्ली पुलिस विफल रही है। गुरुवार को न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता की पीठ के समक्ष दिल्ली पुलिस ने यह जवाब दाखिल किया।

दो साल बाद 16 अगस्त से खुलेगा दिल्ली विश्वविद्यालय

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- स्नातक, स्नातकोत्तर के विज्ञान वर्ग के छात्रों की चलेंगी कक्षाएं
- मानविकी और वाणिज्य वर्ग के छात्रों की कक्षाएं आनलाइन ही चलेंगी

कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने पर दिल्ली में मार्च 2019 में लाकडाउन लगाया गया। उच्च शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए। छात्रों को घर जाने की सलाह दी गई। मार्च माह में ही दिल्ली विवि भी बंद हुआ था। तब से लेकर अभी तक छात्र घर से ही आनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं एवं परीक्षाएं दे रहे हैं। लेकिन अब दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) खुल जाएगा। डीयू प्रशासन ने 16 अगस्त से ना केवल कैंपस बल्कि कालेजों को खोलने का निर्णय लिया है। स्नातक व स्नातकोत्तर के विज्ञान वर्ग के छात्रों की फिजिकल कक्षाएं चलेंगी व छात्र प्रयोगशालाओं में भी काम कर सकेंगे। मानविकी और वाणिज्य वर्ग के छात्रों की कक्षाएं अभी आनलाइन ही चलेंगी।

डीयू ने जारी किया आदेश : कुलसचिव ने सभी कालेजों, विभागों और केंद्रों को इस बाबत आदेश दे दिए हैं। कुलसचिव कार्यालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सभी कालेज, विभाग, केंद्र अब पूर्व की भांति ही कार्य करेंगे। सभी शिक्षण एवं गैर शिक्षण कर्मचारी कार्यालयों में आएंगे। स्नातक, स्नातकोत्तर के विज्ञान छात्रों को फिजिकल कक्षा और प्रायोगिक कार्य के लिए बुलाया जाएगा। 16 अगस्त से कालेजों, विभागों और केंद्रों में कक्षाएं चलेंगी।

छात्रों ने किया स्वागत : छात्र संघ अध्यक्ष अक्षित दाहिया ने डीयू के इस फैसले का स्वागत किया। कहा, आनलाइन कक्षाओं से पढ़ाई की गुणवत्ता प्रभावित हो रही थी। कालेजों, विभागों में आने वाले छात्रों के टीकाकरण की भी व्यवस्था होनी चाहिए। जिन छात्रों ने टीका नहीं लगवाया है, उनके लिए कैंप लगाए जाने चाहिए।

स्नातक पाठ्यक्रमों में एक लाख से अधिक पंजीकरण

चौथे दिन 20 हजार से अधिक छात्रों ने कराया पंजीकरण

पाठ्यक्रम	पंजीकरण
स्नातक	1,10,494
स्नातकोत्तर	87,912
पीएचडी-एमफिल	12, 539

दुष्कर्म व हत्या का मामला : शवदाह से पहले हो चुकी थी बच्ची की मौत!

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली कैंट के ओल्ड नांगलराय गांव में बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म व हत्या मामले में श्मशान भूमि से मिले अवशेष की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को मिल गई है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि शव को जलाए जाने से बच्ची की मौत हो चुकी थी। हालांकि, फोरेंसिक विशेषज्ञों की इस रिपोर्ट पर विशेषज्ञों के एक और पैनल को अपनी राय देनी है। इसके बाद ही अंतिम निष्कर्ष निकलेगा।

सूत्रों के अनुसार शव के अवशेषों के पोस्टमार्टम के नतीजों से इससे अधिक की उम्मीद फिलहाल नहीं की जा सकती है। घटनास्थल पर आरोपितों से उनके कपड़ों के नमूने, पुजारी के आराम कक्ष की चादर व अन्य सामान की फोरेंसिक जांच में कुछ नई बातें सामने आ सकती हैं। जांच में सबसे बड़ी समस्या यह है कि पीड़ित बच्ची ने घटना के दिन जो कपड़े पहने थे, वे शवदाह के दौरान पूरी तरह जल चुके हैं। हालांकि जले हुए कपड़े के अवशेष को जांच के लिए सुरक्षित रखवा दिया गया। संभव है कि इस अवशेष और आरोपितों के कपड़ों की जांच के नतीजों को जोड़कर कुछ निष्कर्ष निकाला जा सके। सूत्रों का कहना है कि यदि जरूरत पड़ी तो मौके पर फोरेंसिक विभाग में तैनात चिकित्सकों का दल भी मुआयना कर सकता है।

दिल्ली कांग्रेस पहुंची राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : ओल्ड नांगलराय गांव की दलित बेटी को न्याय दिलाने के लिए दिल्ली कांग्रेस ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का दरवाजा खटखटाया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी के निर्देशानुसार दिल्ली कांग्रेस के विधिक एवं मानव अधिकार विभाग की लीगल टीम ने गुरुवार को इस बाबत आयोग के सदस्य जस्टिस पीसी पंत के समक्ष शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने और जबरन उसका दाह संस्कार करने के मामले की जांच के लिए टीम गठित करने की मांग की गई है। यह भी अनुरोध किया गया है कि टीम वहां जाकर जांच करे कि पुलिस ने एफआइआर दर्ज करने में देरी क्यों की तथा जबरन बच्ची के माता पिता को घंटों पुलिस थाने में क्यों बिठाया गया। आयोग के सदस्य ने कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि इस मामले की संवेदनशीलता से जांच की जाएगी और दोषियों को सजा दिलाई जाएगी।

राहुल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने जयपुर में धरने पर बैठे भाजपा नेता

जागरण संवाददाता, जयपुर: दिल्ली के कैंट इलाके में पिछले दिनों दुष्कर्म की शिकार हुई नौ साल की बच्ची की पहचान उजागर करने के मामले को लेकर राजस्थान में राजनीति तेज हो गई है। भाजपा के प्रदेश पदाधिकारी व कार्यकर्ता गुरुवार को जयपुर के अशोक नगर पुलिस थाने में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज करवाने पहुंचे। लेकिन, पुलिस ने शहर के बाहर की वारदात होना बताकर रिपोर्ट दर्ज करने से इन्कार कर दिया। इस पर भाजपा के प्रदेश मंत्री जितेंद्र गोठवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ता थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। बाद पुलिस अधिकारियों ने रिपोर्ट ले ली लेकिन आधिकारिक रूप से रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। गोठवाल ने बताया कि कैंट इलाके में राहुल गांधी ने दुष्कर्म पीड़ित बच्ची की मां से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के फोटो उन्होंने इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट कर दिए थे। इससे बच्ची और उसके स्वजन की पहचान उजागर हो गई।

बेमिसाल

इंडिया बुक आफ रिकार्ड्स में दर्ज हुआ मामला, मां-बेटे दोनों स्वस्थ, महिला की ज्यादा उम्र होने से प्रत्यारोपण में थी कठिनाई

80 वर्षीय मां ने बेटे को किडनी दान कर दी नई जिंदगी

जागरण संवाददाता, नोएडा

मां के त्याग, बलिदान, समर्पण व प्यार को किसी तराजू में तौला नहीं जा सकता, और मां की तरह दुनिया में कोई हो नहीं सकता।

52 वर्ष पहले जिस बेटे को जन्म दिया था, आज उसी को अपनी किडनी देकर फिर से नया जीवन दिया है। यह कोई कहानी नहीं है, बल्कि हकीकत है। कैमरून (गिनी की खाड़ी, मध्य अफ्रीका) की रहने वाली 80 वर्षीय मेडेलीन ने सेक्टर-128 स्थित जेपी अस्पताल में अपने बेटे जोसेफ को किडनी देकर नई जिंदगी का तोहफा दिया है।

जेपी अस्पताल के यूरोलाजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट विभाग के डायरेक्टर डा. अमित देवड़ा ने बताया कि जोसेफ लंबे समय से किडनी की बीमारी से पीड़ित थे। बीमारी से उनकी किडनी फेल हो चुकी थी। बेटे की जिंदगी बचाने के लिए मां अपनी किडनी दान करने को तैयार हुई, लेकिन उनकी अधिक उम्र ट्रांसप्लांट में बड़ी चुनौती थी। जांच के बाद पाया गया कि मेडेलिन की किडनी प्रत्यारोपण के लिए फिट थी, लेकिन जिस किडनी को प्रत्यारोपित किया जाना था, उसमें एक छोटी पथरी भी मिली। ऐसे में प्रत्यारोपण की प्रक्रिया जटिल हो गई, लेकिन इस धरती पर लोगों की जान बचाकर चमत्कार करने वाले चिकित्सकों की विशेष टीम ने किडनी को जोसेफ के शरीर में प्रत्यारोपित कर दिया। दोनों को अस्पताल में आठ दिन निगरानी में रखने के बाद छुट्टी दे दी गई। हालांकि उनका फालोअप किया जा रहा है। प्रत्यारोपण करने में डा. विजय सिन्हा, डा. एलपी चौधरी, डा. रवि सिंह, डा. अनुज अरोड़ा, डा. खुशबू सिंह आदि शामिल थे।

दर्द कम करने के लिए की लेप्रोस्कोपी सर्जरी : किडनी लेप्रोस्कोपी के द्वारा निकाली गई। इसके बाद किडनी को बर्फ में रखकर पथरी को निकाला गया। हालांकि यह बेहद चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि जरा सी गलती से किडनी खराब हो सकती थी। जेपी अस्पताल पिछले साढ़े पांच वर्षों में 670 किडनी प्रत्यारोपित कर चुका है।

किडनी दान में अब वृद्धावस्था चुनौती नहीं: वृद्ध जीवित महिला के किडनी डोनेशन का यह मामला इंडिया बुक आफ रिकार्ड में दर्ज हुआ है। चिकित्सकों का कहना है कि इससे दुनिया में वृद्धावस्था में भी ट्रांसप्लांट की चुनौती को स्वीकार करने का रास्ता खुलेगा और हजारों रोगियों को उपचार के बाद नया जीवन मिल सकेगा।

नोएडा सेक्टर-128 स्थित जेपी अस्पताल में हुए आपरेशन में मां मेडेलीन (बाएं से तीसरे) ने बेटे जोसेफ (दाएं से दूसरे) को किडनी दिया। साथ में मौजूद हैं चिकित्सक। सौ. अस्पताल

नाइजीरियाई ड्रग तस्कर गिरोह की दो महिला सदस्य गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- पाकिस्तान और अफगानिस्तान से ड्रग लाकर कई शहरों में बेचे जाते थे
- पंजाब में एक तस्कर को सप्लाई के लिए जा रही दो किलो हेरोइन बरामद

दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने नाइजीरियाई नागरिकों द्वारा संचालित ड्रग तस्करी के मामले में दो महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है। दोनों महिलाएं दो किलो हेरोइन लेकर पंजाब के किसी तस्कर को आपूर्ति करने जा रही थी, तभी इन्हें द्वारका इलाके से गिरफ्तार कर हेरोइन जब्त की गई। संयुक्त आयुक्त क्राइम ब्रांच आलोक कुमार के मुताबिक गिरफ्तार की गई महिला ड्रग तस्करों के नाम कैरोलीन फोकसम व मधु है। कैरोलीन मूलरूप से बंगाल और मधु पंजाब की रहने वाली है।

पूछताछ में दोनों ने बताया कि वे अपने-अपने परिवार को छोड़कर साथ रह रही थी। कैरोलीन को 2013 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया था। मधु को भी उसी साल दिल्ली पुलिस ने धोखाधड़ी के एक मामले में गिरफ्तार किया था। तिहाड़ जेल में एक साथ रहने के दौरान दोनों अच्छी दोस्त बन गई। जेल में दोनों हेनरी नाम के एक नाइजीरियाई नागरिक के संपर्क में भी आई जो नशीले पदार्थों की तस्करी के मामले में सजा काट रहा था। उसने दोनों महिलाओं को पैसा कमाने का प्रलोभन देकर अपने गिरोह में शामिल कर लिया। दोनों जब जमानत पर जेल से बाहर निकली तो वे नशीले पदार्थों की तस्करी करने लगी। दोनों पिछले दो साल में दिल्ली पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में भारी मात्रा में ड्रग की आपूर्ति कर चुकी हैं।

नाइजीरियाई गिरोह अफगानिस्तान और पाकिस्तान से ड्रग्स मंगवा उसे देश के कई राज्यों में आपूर्ति करता है। तस्करों को प्रति ट्रिप एक-एक लाख रुपये मिलते थे।

12,600 करोड़ रुपये से अधिक की अचल शत्रु संपत्ति छोड़ गए हैं चीनी और पाकिस्तानी नागरिक। इन्हें भारत के शत्रु संपत्ति अभिरक्षक के तहत निहित किया गया है। चीन और पाकिस्तान की नागरिकता लेने वाले लोगों द्वारा छोड़ी गई संपत्तियां शत्रु संपत्तियां हैं।

'जासूसी का सुबूत देने में विपक्ष पूरी तरह विफल'

रविशंकर बोले ▶ पेगासस में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का नाम घसीटा गया, जबकि 2014 में ही सरेंडर कर दिया था मोबाइल नंबर

पूर्व आइटी मंत्री ने कहा, कांग्रेस संसद को तभी चलने देती है, जब 'राजवंश' की हितों की पूर्ति होती है

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

पेगासस मामले में ठोस सुबूत की कमी को लेकर जहां सुप्रीम कोर्ट ने ही सवाल उठा दिया है, वहीं विपक्ष की ओर से इस विवाद को तूल दिए जाने पर भड़की भाजपा ने आरोप लगाया कि यह कांग्रेस की उस कार्यसंस्कृति का हिस्सा है, जिसमें संसद को तभी चलने दिया जाता है, जब 'राजवंश' की हितों की पूर्ति होती है। पूर्व आइटी मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि विपक्ष इस मामले में एक भी प्रारंभिक सुबूत पेश करने में विफल रहा है। विपक्ष संसद में इस मुद्दे पर बहस की मांग कर रहा है, वहीं दूसरी ओर आइटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के हाथ से कागज छीनकर बयान देने से रोकने का भी काम करता है।

दरअसल, पेगासस मुद्दा सार्वजनिक करने वाली वेबसाइट द वायर ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश का एक मोबाइल नंबर जारी कर दावा किया कि उनकी भी जासूसी की जा रही थी। लेकिन यह मोबाइल उस समय का निकला, जब वे हाई कोर्ट में न्यायाधीश थे। उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि इस मोबाइल नंबर को वह 2014 में ही सरेंडर कर चुके हैं। पूर्व न्यायाधीश की इस बात से उनकी जासूसी कराए जाने के दावे की हवा निकल गई। रविशंकर ने कहा कि पूरे पेगासस मुद्दे को इसी तरह फर्जी दावे के आधार पर खड़ा किया गया है। उनके अनुसार पेगासस मुद्दे से जुड़े द वायर और एमनेस्टी इंटरनेशनल का मोदी विरोधी रुख जगजाहिर रहा है।

रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष पर बोला हमला। फाइल

उन्होंने कहा कि विपक्ष के इस रुख के कारण अब तक संसद का 130 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है। कांग्रेस शुरू से संसदीय मर्यादा व परंपरा को धता बताती रही है। कांग्रेस काल में किस तरह आपातकाल लगाया गया वह हर किसी को याद है। उसके बाद 1999 में भी वाजपेयी सरकार को अनैतिक तरीके से गिराया गया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के गुरूर को अब भी यह पच नहीं रहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार स्थायी रहकर जनता के हितों के लिए काम कर रही है। इसीलिए, ऐसे विवाद खड़े किए जा रहे हैं, जिसके खिलाफ उनके पास कोई सुबूत ही नहीं है।

राजनाथ ने दी जानकारी, निर्बाध आपूर्ति को आवश्यक रक्षा सेवाएं विधेयक जरूरी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच आर्डनेंस फैक्टि्यों के निगमीकरण से संबंधित विधेयक पारित
- प्रतिस्पर्धा और कार्यक्षमता में होगी वृद्धि, सरकार ने कर्मचारियों के हित का ख्याल रखा : रक्षामंत्री

राज्यसभा ने विपक्ष के हंगामे के बीच सशस्त्र सेनाओं की सैन्य जरूरतों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आर्डनेंस फैक्टि्यों के निगमीकरण से संबंधित आवश्यक रक्षा सेवाएं विधेयक 2021 को ध्वनिमत से गुरुवार को पारित कर दिया।

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने विधेयक पारित कराए जाने को सही ठहराते हुए कहा कि सरकार आर्डनेंस फैक्टि्यों की कार्यक्षमता, प्रतिस्पर्धा व स्वायत्तता को बढ़ाना चाहती है। इसीलिए, इनका निगमीकरण कर सुधार किया जा रहा है। सुधारों के क्रम में आयुध फैक्टि्यों के कर्मचारियों के भविष्य को लेकर जताई जा रही आशंकाओं को रक्षामंत्री ने निर्मूल बताते हुए कहा कि इनके निगमीकरण में सरकार ने इस बात का ख्याल रखा है कि कर्मचारियों की सेवा-शर्तों पर कोई प्रतिकूल असर न पड़े।

पेगासस जासूसी कांड के मसले पर संसद में जारी गतिरोध के बीच इस विधेयक को पारित कराए जाने पर विपक्ष के एतराज का जवाब देते हुए राजनाथ ने कहा कि तीनों सेनाओं के लिए सैन्य साजो-सामान की आपूर्ति किसी रूप में प्रभावित न हो यह सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा जरूरतों की चुनौतियों को देखते हुए सेनाओं को की जाने वाली आपूर्तियों में कोई अवरोध न हो इसके मद्देनजर यह बिल जरूरी है।

संसद के मानसून सत्र के दौरान गुरुवार को राज्यसभा में बोलते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। प्रेट्र

फैक्टि्यों का निगमीकरण करने के क्रम में हमने इसके सभी कर्मचारी संगठनों से सार्थक बातचीत भी की है। रक्षामंत्री ने यह कहा कि यह विधेयक केवल एक साल के लिए ही प्रभावी रहेगा और यह प्रभावी तभी होगा जब सरकार इसे लागू करने की घोषणा करेगी। राजनाथ ने उम्मीद जताई कि संभव है कि इस कानून को लागू करने की जरूरत ही नहीं पड़े।

आवश्यक रक्षा सेवाएं विधेयक पारित किए जाने से विरोध प्रदर्शन का अधिकार छिन जाने की बातों को रक्षामंत्री ने गलत ठहराया और कहा कि वह स्पष्ट करना चाहते हैं कि यह विधेयक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के अधिकार में कोई अड़चन नहीं डालता। यह विधेयक अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के कन्वेंशन के मानकों के अनुकूल भी है। रक्षा राज्यमंत्री अजय भट्ट ने जून में जारी आवश्यक रक्षा सेवाएं अध्यादेश की जगह इस विधेयक को सदन में पेश किया। नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, द्रमुक के षनमुगम व माकपा के ई. करीम ने इसका विरोध करते हुए इसे देश के कामगार वर्ग के खिलाफ बताया। लोकसभा ने मंगलवार को ही इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया था।

विपक्ष ने संसद में हंगामे को सही ठहराया

पेगासस जासूसी कांड समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर गुरुवार को संसद के मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में विपक्षी सदस्यों ने हंगामा किया। प्रेट्र

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- संसद में पेगासस कांड पर 13वें दिन जारी रहा विपक्ष का शोर-शराबा
- गतिरोध के बीच सरकार ने राज्यसभा से पारित कराए दो विधेयक
- नकवी ने विधेयकों को सदन में रखे जाने को कानून सम्मत बताया

पेगासस जासूसी कांड पर संसद में जारी घमासान को विपक्ष ने जायज ठहराते हुए इस पर दोनों सदनों में चर्चा कराए जाने की अपनी मांग से कोई समझौता नहीं करने का एक बार फिर साफ संदेश दे दिया है। विपक्ष के तेवरों के चलते संसद में लगातार 13वें दिन गतिरोध बना रहा तो सरकार ने आर्थिक सुधार समेत कुछ बड़े विधेयकों को पेश कर इन्हें पारित कराने की गति बढ़ा दी है। जासूसी कांड पर मचे संग्राम की अनदेखी कर अहम विधेयकों को पारित कराए जाने के सरकार के इस रुख का भी विपक्ष ने कड़ा विरोध किया है।

लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी हंगामे के चलते दिन भर कार्यवाही बार-बार स्थगित होती रही। मगर इसी शोर-शराबे में राज्यसभा ने अरुणाचल प्रदेश की अनुसूचित जनजाति की सूची में संशोधन से संबंधित विधेयक तथा आवश्यक रक्षा सेवाओं से संबंधित विधेयक पारित कर दिया। लोकसभा में लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने और टैक्स सुधारों से जुड़े अहम बिल सरकार ने पेश कर दिए। लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के टैक्स सुधार कानून में संशोधन संबंधित बिल पेश किए जाने पर एतराज जताते हुए कहा कि दिन की कार्यसूची में इसका उल्लेख नहीं था। अचानक अतिरिक्त कार्यसूची में इसे शामिल कर संसदीय लोकतंत्र की परंपरा को ध्वस्त किया जा रहा है। चौधरी ने कहा कि संसद में गतिरोध के बीच सरकार आनन-फानन में औसतन सात मिनट में एक विधेयक पारित कर रही है। आरएसपी के एनके प्रेमचंद्रन ने भी टैक्स सुधार संशोधन बिल पेश किए जाने का विरोध किया। हालांकि विपक्ष के हंगामे और एतराज के बावजूद लोकसभा में दोनों बिल पेश हो गए और सदन पूरे दिन के लिए स्थगित हो गया।

राज्यसभा में भी पेगासस कांड पर बहस को लेकर विपक्ष काफी उत्तेजित नजर आया और बुधवार को तृणमूल कांग्रेस के छह निलंबित सदस्यों के सदन स्थगित होने के बाद के व्यवहार पर भी हंगामा हुआ। सदन कई बार स्थगित भी हुआ। हंगामे के बीच नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पेगासस जासूसी कांड बेहद गंभीर मसला है और इस पर विपक्षी दलों की बहस की मांग जायज है। विपक्ष पर संसद को जाम करने के सत्ता पक्ष के आरोपों पर खड़गे ने कहा कि सदन में हंगामा भी लोकतांत्रिक विरोध का एक स्वरूप है।

खड़गे ने इस संदर्भ में अरुण जेटली के राज्यसभा में नेता विपक्ष रहते हुए दिए गए बयान का भी हवाला दिया। तब उप सभापति हरिवंश ने तत्काल सदन को कुछ देर के लिए स्थगित कर दिया। इसके बाद भी पूरे दिन हंगामा और व्यवधान का दौर चलता रहा और इस दरम्यान दो विधेयक पारित हुए। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने सदन में विपक्ष के गतिरोध को गैरवाजिब ठहराते हुए विधेयकों को सदन में रखे जाने के सरकार के रुख को पूरी तरह कानून सम्मत ठहराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आवश्यक रक्षा सेवाओं से संबंधित बिल पर जैसे ही ध्वनिमत से सदन की मुहर लगवाई वैसे ही राज्यसभा की कार्यवाही भी पूरे दिन के लिए स्थगित हो गई।

नक्सल प्रभावित इलाकों में 5,422 किलोमीटर सड़क बना रही सरकार

नई दिल्ली, प्रेट्र : नौ राज्यों के नक्सल प्रभावित इलाकों में केंद्र सरकार 8,673 करोड़ रुपये की लागत से 5,422 किमी सड़कें बना रही है। सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को लोकसभा में बताया कि 4,932 किलोमीटर सड़क का निर्माण हो चुका है और शेष पर तेजी से काम चल रहा है।

एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि भारतमाला परियोजना फेज-1 में 8,142 किलोमीटर की लंबाई समेत विकास के लिए पांच ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे और 17 संपर्क नियंत्रित राजमार्ग की परिकल्पना की गई है। एक अन्य सवाल के लिखित उत्तर में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश भर में 2020 में हुई 3,66,138 सड़क दुर्घटनाओं में 1,31,714 लोगों की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा के मुद्दे के समाधान के लिए उनके मंत्रालय ने बहुआयामी रणनीति अपनाई है। यह बहुआयामी रणनीति शिक्षा, इंजीनियरिंग (सड़क एवं वाहन दोनों), प्रवर्तन एवं आपात देखरेख पर आधारित है।

आम लोगों की आवाज दबाने का तरीका है पेगासस : राहुल

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

- पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने केंद्र सरकार पर जमकर साधा निशाना

पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कहा कि प्रधानमंत्री हिंदुस्तान की सच्चाई और आवाज दोनों को ही दबा रहे हैं। फिर वह आवाज चाहे किसानों की हो या आम आदमी की। पेगासस भी आवाज दबाने का ही एक तरीका है, लेकिन हिंदुस्तान के युवा की आवाज कोई नहीं दबा सकता है।

पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी गुरुवार को रायसीना रोड पर पेट्रोल-डीजल की कीमतों में वृद्धि और पेगासस समेत कई मुद्दों पर केंद्र सरकार के खिलाफ भारतीय युवा कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में शामिल थे। राहुल ने कहा कि देश में सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर कुछ नहीं बोलते। पीएम ने हर साल दो करोड़ रोजगार दिए जाने का वादा किया था, लेकिन इसके उलट लाखों करोड़ों युवाओं से उनका रोजगार छिन गया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता बेकाबू हो गए तो उनको तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। 28 महिलाओं, दो सांसदों और दो विधायकों सहित कुल 589 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने बताया कि प्रदर्शन के आयोजक श्रीनिवास बीवी को विरोध मार्च निकालने की अनुमति नहीं दी गई थी।

नई दिल्ली में राहुल गांधी पेगासस जासूसी कांड समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर केंद्र के खिलाफ भारतीय युवा कांग्रेस के प्रदर्शन में शामिल हुए। इस दौरान संबोधित करते राहुल गांधी। प्रेट्र

महाराष्ट्र के अफसरों की इजरायल यात्रा पर राज्य सरकार को नोटिस

मुंबई, प्रेट्र : बांबे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र के सूचना एवं जन संपर्क महानिदेशालय (डीजीआइपीआर) के अधिकारियों की 2019 की इजरायल यात्रा को लेकर दायर जनहित याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया।

लक्ष्मण बुरा और दिगंबर द्वारा दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि जगजाहिर हो चुके फोन टैपिंग मामलों और अधिकारियों की इजरायल यात्रा के बीच संभवतः तार जुड़े हुए हैं। जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि इस तरह की विदेश यात्रा की अनुमति देने वाले कई नियमों का इस प्रक्रिया में उल्लंघन किया गया है। याचिकाकर्ताओं के वकील तेजेश दांडे ने अदालत में कहा, इजरायल के पास वेब मीडिया (अध्ययन यात्रा का विषय) पर ऐसी कोई विशेषज्ञता नहीं है कि राज्य सरकार के अधिकारियों को इसका लाभ मिलता।

उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ताओं का मानना है कि इजरायल भेजने का मुख्य मकसद पेगासस जैसा जासूसी साफ्टवेयर हासिल करना था।

मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और जस्टिस जीएस कुलकर्णी की पीठ ने राज्य सरकार, डीजीआइपीआर और पांच अधिकारियों को चार हफ्तों में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। इन सभी को जनहित याचिका में पक्षकार बनाया गया है। याचिका में कहा गया है कि 15 नवंबर, 2019 को महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बाद डीजीआइपीआर के पांच चयनित वरिष्ठ अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल एडवांस वेब मीडिया का अध्ययन करने के लिए 10 दिनों की इजरायल यात्रा पर भेजा गया था। जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि उस अवधि में राज्य में सरकार गठन के लिए काफी व्यस्त बातचीत चल रही थी।

समान नागरिक संहिता लागू करने की समयसीमा तय नहीं

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने गुरुवार को राज्यसभा में एक सवाल के लिखित उत्तर में कहा कि यह संवेदनशील है और इसलिए इस मामले में गहन अध्ययन की जरूरत है। सवाल किया गया था कि क्या सरकार की देश में समान नागरिक संहिता को जल्द ही लागू करने की कोई योजना है।

कानून मंत्री ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 44 में यह प्रविधान है कि राज्य भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू कराने का प्रयास करेगा। रिजिजू के अनुसार मामले की संवेदनशीलता तथा विभिन्न समुदायों से संबंधित पर्सनल कानूनों के प्रविधानों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने विधि आयोग से समान नागरिक संहिता से संबंधित विभिन्न मुद्दों की जांच करने और उस पर सिफारिश करने का अनुरोध किया है।

3.79 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों में शौचालय सुविधा नहीं : महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने एक लिखित उत्तर में सदन को बताया कि देश में करीब 3.79 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों में शौचालय की सुविधा नहीं है। 1.88 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल सुविधा का अभाव है। देश भर में 13,87,432 आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं। इनमें से 13,84,997 केंद्रों के उपलब्ध आंकड़ों से पता चला है कि 10,05,257 आंगनबाड़ी केंद्रों में शौचालय की सुविधा और 11,96,458 केंद्रों में पेयजल की सुविधा है।

- कानून मंत्री ने कहा, संवेदनशील मामला होने के चलते गहन अध्ययन की जरूरत
- पूछा गया था, सरकार की समान नागरिक संहिता को जल्द लागू करने की योजना है

एक अन्य सवाल के जवाब में ईरानी ने कहा कि पिछले तीन साल के दौरान पोक्सो ई-बाक्स के माध्यम से करीब 356 शिकायतें मिली हैं। बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण (पोक्सो) ई-बाक्स बच्चों की यौन प्रताड़ना की शिकायत के लिए एक आनलाइन शिकायत बाक्स है।

एक अन्य सवाल के उत्तर में ईरानी ने कहा कि कर्ज सुविधा एजेंसी राष्ट्रीय महिला कोष को बंद करने का फैसला लिया गया है। विभिन्न सरकारी पहलों के मध्यम महिलाओं के लिए उपलब्ध हैं इसलिए यह अपना महत्व खो चुका है। 1993 में स्थापित राष्ट्रीय महिला कोष (आरएमके) एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है जिसका उद्देश्य महिलाओं का सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण है।

सभी विभागों के लिए स्थानांतरण नीति सार्वजनिक करना जरूरी

कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने एक लिखित उत्तर में कहा कि सभी केंद्र सरकार के सभी विभागों के लिए अपनी स्थानांतरण नीति सार्वजनिक करने की जरूरत है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक, सभी केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों के पास स्थानांतरण, पोस्टिंग, न्यूनतम कार्यकाल मुहैया कराने के लिए अपना दिशानिर्देश के साथ ही लोकसेवा बोर्ड को स्थानांतरण की सिफारिश करने के लिए एक तंत्र होना चाहिए।

कोझिकोड विमान हादसे की जांच इस महीने पूरी हो सकती है

नागरिक उड्डयन राज्यमंत्री वीके सिंह ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि केरल के कोझिकोड में पिछले साल एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की जांच इस महीने पूरी होने की संभावना है। पिछले साल सात अगस्त को एयर इंडिया एक्सप्रेस का बोइंग 737 विमान उतरने के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस हादसे में दो पायलट समेत 21 लोग मारे गए थे और कई लोग घायल हो गए थे। विमान ने दुबई से उड़ान भरी थी।

गांव को औसत 22.17 घंटे, शहरों को 23.36 घंटे बिजली मिली

ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने लोकसभा में कहा कि इस साल जून महीने के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों को रोजाना औसतन 22.17 घंटे और शहरी क्षेत्रों को 23.36 घंटे बिजली की आपूर्ति हुई। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र सर्वेक्षण के अनुसार, 2015-16 में ग्रामीण इलाकों में बिजली की उपलब्धता 12 घंटे औसत से बढ़कर 2020 में 20.50 घंटे तक पहुंच गई और शहरी इलाकों में बिजली की उपलब्धता बढ़कर 22.23 घंटे हो गई।

सरकार का किसी इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म पर रोक का इरादा नहीं

नई दिल्ली, प्रेट्र : सरकार का किसी इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म को रोकने (ब्लाक करने) का फिलहाल कोई इरादा नहीं है। हालांकि कुछ यूजर इंटरनेट मीडिया का इस्तेमाल देश में घृणा का माहौल बनाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन न कोई इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म और न ही कोई अन्य माध्यम देश के लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा सकता है। यह जानकारी केंद्रीय इलेक्ट्रानिक्स और आइटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने राज्यसभा में लिखित उत्तर में दी है।

मंत्री ने बताया है कि इंटरनेट मीडिया पर घृणास्पद पोस्ट को लेकर सरकार के पास बहुत सारी शिकायतें आती हैं। उन शिकायतों का उचित तरीके से निस्तारण भी किया जाता है। इस सिलसिले में सरकार इंटरनेट मीडिया कंपनियों के प्रतिनिधियों से अक्सर बात भी करती है। यूजर द्वारा पोस्ट सामग्री पर जवाबदेही तय करने के लिए समय-समय पर एडवाइजरी भी जारी की जाती है। चंद्रशेखर ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र संविधान की व्यवस्था से जुड़ा है। देश का संविधान ही प्रत्येक नागरिक को मूलभूत अधिकार देता है। इसलिए कोई इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म या अन्य माध्यम देश की लोकतांत्रिक विरासत को नुकसान नहीं पहुंचा सकता।

- घृणास्पद टिप्पणियों से लोकतंत्र को नुकसान नहीं होने वाला : चंद्रशेखर

आइटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर। फाइल

मंत्री ने कहा, इन्फार्मेशन टेक्नोलाजी एक्ट 2000 के सेक्शन 69 ए के अनुसार सरकार देश की संप्रभुता और अखंडता के लिए घातक व घृणा फैलाने वाले आनलाइन कंटेंट को रोक सकती है। इस प्रविधान में देश की सुरक्षा, किसी मित्र देश के खिलाफ दुष्प्रचार और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले आनलाइन कंटेंट या सर्विस को भी रोका जा सकता है।

ट्विटर ने नोडल कांटेक्ट परसन नियुक्त नहीं किया

ट्विटर ने भारत में अपनी व्यवस्था के तहत चीफ कंप्लायंस आफीसर और रेजीडेंट ग्रीवियांस आफीसर की नियुक्ति की है लेकिन नोडल कांटेक्ट परसन अभी तक नियुक्त नहीं किया। जबकि इस नियुक्ति को इंटरनेट मीडिया कंपनी के लिए 26 मई से लागू नियमों में अनिवार्य किया गया है। मामला अदालत में है। अदालत का आदेश आने पर नया कदम उठाया जाएगा। यह बात चंद्रशेखर ने राज्यसभा को बताई है।

कूटनीति

अफगान संकट पर यूएनएससी में भारत की अध्यक्षता में बैठक आज, तालिबान व उसे समर्थन देने वाली ताकतों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने की भारत की है कोशिश

अफगानिस्तान में सीजफायर पर होगा भारत का जोर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

अफगानिस्तान के कई इलाकों में सरकारी सुरक्षा बलों और तालिबान आतंकियों के बीच हिंसक झड़पों की खबरों के बीच शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में अफगानिस्तान को लेकर अहम बैठक होने जा रही है। यूएनएससी की इस बैठक की अध्यक्षता भारत करेगा और भारत की तरफ से यह भी कोशिश होगी कि हिंसा को बढ़ावा देने वाले तालिबान व उसे समर्थन देने वाली ताकतों के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव पारित किया जाए। दो दिन पहले ही अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने भारतीय विदेश मंत्री से बात की थी और यूएनएससी में इसे उठाने का प्रस्ताव किया था।

नई दिल्ली में अफगानिस्तान के राजदूत फरीद मामुंदजई ने कहा है कि, यूएन सुरक्षा परिषद में अफगानिस्तान पर आपातकालीन बैठक सकारात्मक कदम है। यूएन व दूसरे अंतरराष्ट्रीय समुदाय को तत्काल ठोस कदम उठाने की जरूरत है ताकि अफगानिस्तान में आतंकियों की तरफ से की जा रही हिंसा और अत्याचार को रोका जा सके।

मामुंदजई ने भारत की तरफ से इसमें अग्रणी भूमिका निभाने के लिए धन्यवाद भी दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि अफगानिस्तान के मुद्दे पर शुक्रवार को चर्चा होगी। भारत इसमें अपना पक्ष रखेगा और हमें उम्मीद है कि चर्चा से कोई न कोई सकारात्मक बात निकलेगी। उन्होंने यह भी कहा है कि भारत अफगानिस्तान के हालात पर करीबी नजर रखे हुए है। हम वहां शीघ्रता से शांति स्थापित करने के पक्ष में हैं।

बुधवार को यूएनएससी ने अफगानिस्तान पर जो बयान जारी किया है उससे साफ है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय में वहां के खराब होते हालात को लेकर निराशा व क्षोभ बढ़ता जा रहा है। इसमें तालिबान की तरफ से किए जा रहे हमलों को तत्काल रोकने, मानवाधिकार का उल्लंघन रोकने व पूरे देश में युद्ध जैसी स्थिति को खत्म करने की अपील है। यूएनएससी ने यह भी माना कि उसे इस बात की जानकारी है कि तालिबान की तरफ से जानबूझ कर नागरिकों के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है।

'रचनात्मक रही भारत-चीन के बीच वार्ता'

नई दिल्ली, प्रेट्र : विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि पूर्वी लद्दाख में गतिरोध पर भारत और चीन के बीच हाल ही में हुई सैन्य वार्ता रचनात्मक थी। दोनों पक्ष शेष मुद्दों का समाधान तेज गति से करने पर भी सहमत हुए। भारतीय सेना द्वारा 12वें दौर की सैन्य वार्ता के दो दिन बाद सोमवार को यहां जारी किए गए संयुक्त बयान में कहा गया था कि दोनों पक्षों के बीच सैनिकों को पीछे हटाने के मुद्दे पर विचारों का व्यापक आदान-प्रदान हुआ और बैठक से पारस्परिक समझ और मजबूत हुई।

आनलाइन संवाददाता सम्मेलन के दौरान भारत-चीन सैन्य वार्ता के बारे में पूछे जाने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने वार्ता के बाद जारी किए गए बयान का जिक्र किया और कहा कि यह संयुक्त प्रेस वक्तव्य था। उन्होंने कहा कि जैसा कि उसमें (बयान) उल्लेख था, वार्ता स्पष्ट और रचनात्मक थी। दोनों पक्ष शेष मुद्दों का समाधान मौजूदा समझौतों और प्रोटोकाल के अनुरूप तेज गति से करने तथा संवाद और चर्चा में गति बनाए रखने पर सहमत हुए। भारत और चीन की सेनाओं के बीच पिछले साल पांच मई को पैंगोंग झील क्षेत्र में हुई हिंसक झड़प के बाद से सीमा पर गतिरोध चला आ रहा है।

भारतीय छात्र की मौत के मामले की जांच कर रहे चीनी अधिकारी : भारत ने कहा कि चीनी अधिकारी चीन के तियानजिन शहर में भारतीय छात्र की मौत की परिस्थितियों की जांच कर रहे हैं। छात्र के पार्थिव शरीर को जल्द से जल्द घर लाने का प्रयास किया जा रहा है। तियानजिन फारेन स्टडीज यूनिवर्सिटी में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का छात्र अमन नागसेन 29 जुलाई को मृत पाया गया था। वह बिहार के गया का रहने वाला था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि परिवार के सदस्यों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं।

कह के रहेंगे माधव जोशी

20 सितंबर से 25 नवंबर के बीच दस चरणों में बिहार में हो सकते हैं। पंचायत चुनाव। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसके लिए राज्य सरकार से अनुमति मांगी है। आयोग के प्रस्ताव को बिहार सरकार ने अगर स्वीकार किया तो 20 अगस्त को चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 6 अगस्त, 2021

छोड़ा साथ, न सरकार और न ही कैप्टन के काम आए पीके

प्रशांत किशोर ने दिया मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार के पद से इस्तीफा

पांच माह में सिर्फ दो बार आए पंजाब, बैठकें की और चलते बने

कैलाश नाथ, चंडीगढ़

अमरिंदर सिंह और प्रशांत किशोर। फाइल

चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर (पीके) ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के प्रधान सलाहकार के पद से इस्तीफा दे दिया है। पांच माह के अपने कार्यकाल के दौरान वह न तो सरकार के काम आए और न ही मुख्यमंत्री के। पीके ने 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत में अहम भूमिका अदा की थी। इसे देखते हुए कैप्टन ने उन्हें अपना प्रधान सलाहकार नियुक्त किया था, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले ही वह चलते बने।

गौरतलब है कि इस साल एक मार्च को मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार नियुक्त हुए पीके को कैबिनेट रैंक दिया गया था। हालांकि, उनकी तनख्वाह एक रुपया ही तय की गई थी, लेकिन उन्हें सरकारी कोठी, सचिवालय में दफ्तर, सुरक्षाकर्मी, गाड़ी की सुविधा मिल रही थी। पांच माह के कार्यकाल में पीके महज दो बार ही पंजाब आए। इस दौरान उन्होंने एक बार प्रशासनिक अधिकारियों व दूसरी बार विधायकों के साथ बैठक की थी।

बताते हैं कि विधायकों के साथ बैठक के बाद ही उन्होंने मन बना लिया था कि पंजाब में काम नहीं करेंगे, क्योंकि बैठक में कई विधायकों ने ब्यूरोक्रेसी के अधिक हस्तक्षेप और चुनाव में किए वादे न निभाने का मुद्दा उठाया था। इसके बाद कुछ मंत्रियों से बातचीत में उन्होंने संकेत भी दिए थे कि वह पंजाब में काम नहीं करना चाहते।

पीके का इस्तीफा कैप्टन के लिए अच्छा नहीं माना जा रहा है, क्योंकि कैप्टन इस समय कई मोर्चों पर लड़ रहे हैं और ऐसे में उन्हें एक पेशेवर सलाहकार की जरूरत थी। माना जा रहा था कि पीके मुख्यमंत्री कैप्टन और नए प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के बीच की दूरी मिटाने में काफी मददगार हो सकते थे। 2022 में मुख्यमंत्री के रूप में चेहरा, बेअदबी कांड जैसे मुद्दे पर कैप्टन का भरोसा था कि पीके अपनी रणनीति से प्रभावहीन कर सकते थे।

भाजपा व शिअद ने उठाए सवाल : भाजपा के महासचिव सुभाष शर्मा का कहना है कि मुख्यमंत्री ने निजी हित के लिए प्रशांत किशोर को प्रधान सलाहकार नियुक्त किया था। उन्होंने पीके को कैबिनेट रैंक देकर सरकारी खजाने पर बोझ ही डाला। उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि इससे प्रदेश को क्या लाभ हुआ।

वहीं, शिरोमणि अकाली दल के प्रवक्ता डा. दलजीत सिंह चीमा का कहना है कि पीके को पता चल चुका था कि काठ की हांडी दूसरी बार नहीं चढ़ सकती। 2017 में पीके के जरिये कैप्टन ने जो झूठे वादे किए थे, वह पूरे नहीं हुए। इसलिए अब पीके किस मुंह से लोगों का सामना कर सकते हैं। ऐसे में मैदान छोड़ना ही उन्होंने मुनासिब समझा। इससे सरकारी खजाने को ही नुकसान हुआ। प्रदेश का कोई भला नहीं हुआ।

धामी की घेराबंदी होगी कांग्रेस का चुनावी हथियार

राज्य ब्यूरो, देहरादून : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब कांग्रेस के निशाने पर हैं। भाजपा ने दो मुख्यमंत्री बदलने के बाद तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में जिस तरह युवा पुष्कर सिंह धामी को कमान सौंपी है, उससे प्रमुख विपक्षी दल में अंदरखाने खलबली है। पार्टी के युवा नेताओं और विधायकों में भी भाजपा की इस रणनीति से छटपटाहट महसूस की जा रही है। ऐसे में कांग्रेस अब सीधे मुख्यमंत्री धामी और सरकार पर हमला बोलने की तैयारी में है।

2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा दोनों ने ही तैयारी प्रारंभ कर दी हैं। एक-दूसरे की रणनीतिक काट के लिए दोनों ही दलों की ओर से बड़े फेरबदल को अंजाम दिया जा चुका है। भाजपा ने धामी को मुख्यमंत्री बनाकर कांग्रेस के लिए नई चुनौती पेश कर दी है। कुमाऊं मंडल से युवा नेतृत्व को आगे करने के कदम को भाजपा मास्टर स्ट्रोक मान रही है। हालांकि धामी की काट के तौर पर कांग्रेस नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में गणेश गोदियाल को आगे कर चुकी है, लेकिन विधायकों के साथ ही युवा वर्ग में आगे बढ़ने को लेकर नया जोश उछाले मारने से पार्टी के भीतर खुशी के साथ उम्रदराज नेताओं में बेचैनी भी दिखाई दे रही है। प्रमुख विपक्षी दल ने भाजपा की इस दांव पर अपने ही अंदाज में नए तरीके से प्रहार शुरू कर दिए हैं। दो मुख्यमंत्रियों को बदलने के मुद्दे पर कांग्रेस हमलावर है ही, अब पुष्कर सिंह धामी की मुश्किलों में इजाफा करने के लिए, तैयारी शुरू कर दी गई है।

सीमा विवाद सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाने पर असम-मिजोरम राजी

आइजल, प्रेट्र : अंतरराज्यीय सीमा विवाद के मुद्दे पर असम और मिजोरम के प्रतिनिधियों ने गुरुवार को यहां बातचीत की और मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने पर सहमति जताई। बातचीत के बाद असम सरकार ने मिजोरम की यात्रा के खिलाफ पूर्व में जारी एडवाइजरी रद करने का भी फैसला किया है। दोनों राज्य सरकारों ने अंतर-राज्यीय सीमा क्षेत्रों में शांति बनाए रखने के लिए भारत सरकार द्वारा तटस्थ बल की तैनाती करने का भी स्वागत किया।

असम-मिजोरम सीमा विवाद के मुद्दे पर गुरुवार को आइजल में मिजोरम के गृह मंत्री लालचमलियाना की असम के सीमा सुरक्षा और विकास मंत्री अतुल बोरा के साथ बैठक हुई। प्रेट्र

दोनों पक्षों की ओर से संयुक्त रूप से जारी बयान के अनुसार राज्य की सीमा पर दोनों राज्य अपने-अपने वन और पुलिस बलों को गश्त, वर्चस्व, प्रवर्तन या उन क्षेत्रों में नए सिरे से तैनाती के लिए नहीं भेजेंगे, जहां हाल के दिनों में दोनों राज्यों के पुलिस बलों के बीच टकराव हुआ था। इसमें असम-मिजोरम सीमा पर असम के करीमगंज, हैलाकांडी, और कछार जिलों और मिजोरम के ममित और कोलासिब जिलों के विवाद वाले सभी क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा। इस संयुक्त बयान पर असम के सीमा सुरक्षा और विकास मंत्री अतुल बोरा और विभाग के आयुक्त और सचिव जीडी त्रिपाठी और मिजोरम के गृह मंत्री लालचमलियाना और गृह सचिव वनलालंगथसाका ने हस्ताक्षर किए।

असम के मंत्री अशोक सिंघल ने ट्विटर पर कहा कि दोनों राज्यों की सरकारों के प्रतिनिधि असम और मिजोरम में रहने वाले लोगों के बीच शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने, संरक्षित करने और बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने पर सहमत हैं।

सिंघल ने अपने ट्वीट में कहा कि दोनों पक्षों ने बड़ी उम्मीदों के साथ बातचीत की। हमने मिजोरम के गृह मंत्री लालचमलियाना और अन्य अधिकारियों के साथ सीमा विवाद के मुद्दे को हल करने पर चर्चा की। यह चर्चा असम के सीएम हिमंत बिस्व सरमा और मिजोरम के सीएम जोरमथांगा की वार्ताओं के क्रम में हुई। उल्लेखनीय है 26 जुलाई को पूर्वोत्तर के इन दोनों पड़ोसी राज्यों के बीच अंतर-राज्यीय सीमा संघर्ष में असम पुलिस के छह जवान मारे गए थे और कछार जिले के एसपी सहित 50 से अधिक लोग घायल हुए थे। दोनों राज्यों ने इस घटना में मारे गए लोगों की मौत पर भी शोक जताया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की।

मिजोरम के मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया, असम सरकार और मिजोरम सरकार ने गुरुवार को आइजल में विचार-विमर्श के बाद एक संयुक्त बयान पर सफलतापूर्वक हस्ताक्षर किए। दोनों सरकारें मौजूदा तनाव को दूर करने और चर्चा के माध्यम से स्थायी समाधान खोजने के लिए गृह मंत्रालय की पहल को आगे बढ़ाने के लिए सहमत हैं। दोनों राज्यों की अपनी क्षेत्रीय सीमा की अलग-अलग व्याख्याएं हैं। मिजोरम का मानना है कि इसकी सीमा 1875 में आदिवासियों को बाहरी प्रभाव से बचाने के लिए बनाई गई एक आंतरिक रेखा का हवाला देता है जबकि असम 1930 के दशक में जिलों के लिए किए गए सीमांकन को मान्यता देता है।

अखिलेश की साइकिल, जोश के पैडल और वोटबैंक का संतुलन

लखनऊ में गुरुवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री जनेश्वर मिश्र की जयंती के अवसर पर साइकिल रैली की अगुआई करते सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। ब्रजेश दंदेल

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

सत्ता के ट्रैक पर खूब रफ्तार से दौड़ी सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की साइकिल का हैंडल अब अखिलेश यादव के हाथ में है। खुद ही राह के रोड़े हटाने हैं और साइकिल भी चलानी है। निस्संदेह डगर चुनौती भरी है तो अखिलेश का 'पालिटिकल स्टेमिना' भी कम नहीं। भाजपा के चौड़े विजय रथ के किनारे से लोकभवन तक साइकिल पहुंचाने के लिए, संगठन कितना पैडल मार सकता है, यह गुरुवार को साइकिल यात्रा में दिखा। मंत्रोच्चार से ब्राह्मणों को हमराही बनाने के न्योते के साथ सांसद आजम खां के सहारे मुस्लिमों के लिए पसीना बहाकर वोटबैंक का अच्छा संतुलन भी सपा मुखिया ने दिखाया।

पांच महीने बाद उप्र के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपनी साइकिल लेकर विक्रमादित्य मार्ग से निकले तो उनके पहले सियासी मौसम भांपा, जातीय समीकरणों के लिहाज से शगुन भी देखा। यादव वोटबैंक पर भरोसा है और इन दिनों कसरत ब्राह्मण वोट को लेकर है, इसलिए, समाजवादी आंदोलन के लिए, पंडित जनेश्वर मिश्र की जयंती को चुना, जो गुरुवार को थी। फिर समाजवादी आंदोलन के प्रणेता लोहिया के पथ को पकड़ा और जनेश्वर मिश्र पार्क तक पहुंचे। डेढ़ घंटे में पूरी की गई साढ़े छह किलोमीटर की इस साइकिल यात्रा का मकसद संगठन की ताकत दिखाने के साथ ही सत्ता की राह बनाना था।

अपने परंपरागत वोट बैंक यादव व मुस्लिम को सहेजने के साथ ही अखिलेश ब्राह्मण समाज को भी जोड़ने की भरपूर जुगत में दिखे। जेपीएनआईसी गेट के सामने ब्राह्मणों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच अखिलेश का स्वागत किया और उन्हें राधा कृष्ण की प्रतिमा भेंट की, जिसका संदेश स्पष्ट था। साइकिल यात्रा में एक बार फिर वरिष्ठ नेता आजम खां का भी मुद्दा शामिल किया गया।

भाजपा से जनता नाराज, सपा को आएंगी 400 सीटें : अखिलेश

साइकिल यात्रा से पहले अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार को हर मोर्चे पर नाकाम बताया। उन्होंने कहा कि अभी तक तो हम 350 सीट जीतने की बात करते थे, लेकिन प्रदेश की जनता की भाजपा से नाराजगी को देखकर अब लगता है कि सपा आगामी विधानसभा चुनाव में 400 सीटें जीत लेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग 'मेनिफेस्टो' नहीं, 'मनीफेस्टो' बनाते हैं।

योगी को नहीं आता लैपटाप चलाना : अखिलेश ने सीएम योगी पर तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को लैपटाप चलाना नहीं आता है, इसलिए, उन्होंने लैपटाप नहीं बांटा। मुख्यमंत्री योगी के बयान- 'जो जय श्रीराम नहीं बोलता मुझे उसके डीएनए पर थोड़ा शक है', पर अखिलेश ने कहा कि मुख्यमंत्री को डीएनए के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्हें डीएनए का फुल फार्म भी नहीं पता होगा।

बदल देंगे सरकार : डिंपल

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी व पूर्व सांसद डिंपल यादव ने गुरुवार को कन्नौज में तिर्वा से साइकिल यात्रा को रवाना करते हुए कहा कि जो सरकार महिलाओं को सम्मान और युवाओं को रोजगार न दे सके, उसे हमें बदलना है।

कुशवाहा का बदला रुख, बोले-मोदी के बाद हैं नीतीश

राज्य ब्यूरो, पटना

उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार को बताया था 'पीएम मैटेरियल'। फाइल/इंटरनेट मीडिया

लोकसभा चुनाव में तीन साल की देरी है, लेकिन बिहार की राजनीति में 'पीएम मैटेरियल' की चर्चा होने लगी है। जदयू केंद्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम नीतीश कुमार को पीएम मैटेरियल बता कर इसे मुद्दा बना दिया। भाजपा ने यह कह कर उपेंद्र से असहमति जताई कि अभी पीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है। समझा जाता है कि भाजपा के रुख को देखते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने अपने वक्तव्य में संशोधन किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि नरेंद्र मोदी के बाद नीतीश कुमार पीएम मैटेरियल हैं। गुरुवार को उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट किया है- जातीय जनगणना से समानता आएगी। गरीब व शोषित वंचितों को लाभ होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति को नई दिशा दी है। सीमित संसाधनों के बावजूद सामाजिक न्याय के साथ विकास का मॉडल दिया है। नरेंद्र मोदी जी के बाद नीतीश कुमार जी हैं पीएम मैटेरियल।

भाजपा ने कुशवाहा के पीएम मैटेरियल वाले बयान को गंभीरता से लिया। पार्टी ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि इस समय देश में पीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है। सीएम नीतीश कुमार ने यह कह कर भाजपा की संभावित नाराजगी को कम करने की कोशिश की कि इन चीजों में उनकी कोई रुचि नहीं है। वह जितना बन सकता है, राज्य की सेवा कर रहे हैं। यही करना भी चाहते हैं। बीते सोमवार को जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में उन्होंने यह टिप्पणी की।

लालू की टिप्पणी रही संतुलित

राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद ने कुशवाहा के पीएम मैटेरियल वाले बयान पर बेहद संतुलित टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि इस पर भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोचें, लेकिन लोजपा के एक गुट के नेता और सांसद चिराग पासवान की तीखी प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा कि इससे पता चलता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश के इस बड़े पद पर काबिज होना चाहते हैं।

जातिगत जनगणना पर नीतीश ने पीएम से मांगा मिलने का समय

राज्य ब्यूरो, पटना

> पेगासस मामले में बोले, सुप्रीम कोर्ट कर रहा मामले की सुनवाई

जाति आधारित जनगणना पर चर्चा के लिए पीएम नरेंद्र मोदी से समय मिलने का इंतजार किया जा रहा है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बताया कि उन्होंने पीएम को इस बारे में पत्र भेज दिया है। वहां से समय मिलेगा तो उनसे मिलने जाएंगे। राज्य के बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण कर लौटने के बाद पटना में उन्होंने इसकी जानकारी दी।

नीतीश ने कहा कि जदयू सांसदों ने भी इस संबंध में पीएम से मिलने का समय मांगा था। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) से मिले निर्देश के तहत ही जदयू सांसदों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर उन्हें पार्टी के स्टैंड से संबंधित पत्र सौंपा। मालूम हो कि विपक्ष के नेताओं के साथ मुलाकात के क्रम में तय हुआ था कि जाति आधारित जनगणना के संबंध में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पीएम से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपेगा। इसके लिए भाजपा को भी सूचना दी गई थी। जदयू और संपूर्ण विपक्ष लगातार यह कहता रहा है कि जाति आधारित जनगणना जरूरी है। नीतीश का कहना है कि इससे समाज के सभी वर्गों को फायदा होगा। तनाव उत्पन्न होने की कोई बात नहीं। जाति आधारित जनगणना होगी या नहीं, यह फैसला केंद्र को करना है, लेकिन इस मुद्दे पर हमें विचार को रख देना चाहिए।

फोन टैपिंग प्रकरण (पेगासस मामला) के संबंध में पूछे जाने पर नीतीश ने एक बार फिर कहा कि सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई कर रहा है। सब कुछ सुप्रीम कोर्ट देखेगा। राजद प्रमुख लालू प्रसाद की फिर से सक्रियता के संबंध में प्रतिक्रिया मांगी गई तो नीतीश टालते हुए निकल गए। केवल यह कहा कि सबको अपना-अपना काम है।

पंजाब के केवल तीन विधायक ही खुद भरते हैं आयकर

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : पंजाब में विधायकों को मिलने वाले वेतन और भत्तों पर बनने वाले आयकर का भार उनके कंधे नहीं उठा पा रहे हैं। वेतन-भत्तों पर बनने वाले आयकर का सारा बोझ जनता के जिम्मे ही है और सरकारी खजाने से विधायकों का आयकर भरा जा रहा है। तीन विधायकों को छोड़ दें तो शेष 93 विधायकों का आयकर सरकार भर रही है।

यह हालात उस समय हैं जब तीन साल पहले फरवरी, 2018 में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विधायकों को मिलने वाले वेतन पर आयकर खुद भरने की अपील की थी। केवल तीन विधायकों पर ही इसका असर हुआ और वह अपना आयकर खुद भर रहे हैं, जबकि शेष विधायकों का आयकर सरकार अदा कर रही है। महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि 17 साल पहले विधायकों का आयकर भरने की सुविधा भी कैप्टन सरकार ने ही दी थी। साल 2002-2007 के कार्यकाल के दौरान कैप्टन सरकार ने तीन मार्च, 2004 को एक बिल पारित कर विधायकों व मंत्रियों को यह सुविधा दी थी कि उनका आयकर सरकार भरेगी।

माकपा ने माना, बंगाल विस चुनाव में 'बीजेमूल' नारे ने डुबोई लुटिया

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

> नारे ने लोगों को भ्रमित किया, जिससे वे पार्टी से कट गए

बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के 'खेला होबे' का नारा जहां सुपरहिट साबित हुआ और इसकी बदौलत वह तीसरी बार बंगाल की सत्ता पर काबिज हो गई, वहीं वाममोर्चा-कांग्रेस गठबंधन की ओर से दिया गया 'बीजेमूल' का नारा पूरी तरह फ्लाप रहा। इतना ही नहीं इस गठबंधन की उसने लुटिया भी डुबो दी। अब वाममोर्चा के प्रमुख घटक दल माकपा ने यह मान लिया है कि उक्त नारा उसकी करारी हार के प्रमुख कारणों में से एक रहा है। 'बीजेमूल' नारे का मतलब यह था कि भाजपा और तृणमूल मिले हुए हैं।

बंगाल विस चुनाव में माकपा समेत किसी भी वामदल को एक भी सीट नसीब नहीं हुई। कांग्रेस की झोली भी इस बार खाली रह गई। बंगाल विस चुनाव के इतिहास में यह पहला मौका है, जब कांग्रेस व वामदल, जिन्होंने वर्षों सूबे की सत्ता संभाली, उनका कोई प्रतिनिधि विधानसभा में नहीं है। माकपा की ओर से तैयार किए गए एक नोट में कहा गया है कि 'बीजेमूल' के नारे ने लोगों को भ्रमित किया, जिससे वे पार्टी से और कट गए। इस नारे के जरिये पार्टी की ओर से तृणमूल कांग्रेस और भाजपा में सांठगांठ की जो बात कही गई थी, वह लोगों को रास नहीं आई। अब माकपा भी कह रही है कि भाजपा व तृणमूल कांग्रेस में कोई मेल नहीं है।

सियासी विश्लेषकों का कहना है कि विस चुनाव में दुर्गति के बाद माकपा को यह बात अच्छी तरह से समझ में आ गई है कि भाजपा और तृणमूल को एक ही थैली के चट्टे-बट्टे कहकर जनता के सामने पेश करना बड़ी गलती थी। इसकी वजह से जनता का उससे पूरी तरह मोह भंग हो गया। 2024 के लोस चुनाव में भाजपा को रोकने के लिए वामदल तृणमूल कांग्रेस का साथ दे दें तो हैरानी की बात नहीं होगी। वाममोर्चा अध्यक्ष विमान बोस कह चुके हैं कि भाजपा जैसी सांप्रदायिक ताकत को रोकने के लिए वह किसी से भी हाथ मिलाने को तैयार हैं।

असम के विधायक की डिग्री संदिग्ध

जागरण संवाददाता, मेरठ : चौधरी चरण सिंह विवि, मेरठ ने असम के विधायक की डिग्री को संदिग्ध माना है। विधायक करीमउद्दीन बरभुइया ने विधानसभा चुनाव के दौरान नामांकन पत्र जमा करते समय खुद को चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से स्नातक बताया था। तीन महीने पहले विश्वविद्यालय ने इसका सत्यापन किया, जिसमें इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं मिला है। विश्वविद्यालय ने अपनी रिपोर्ट भेज दी थी, जिसे लेकर चार अगस्त को असम हाई कोर्ट में सुनवाई हुई।

आल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के उम्मीदवार करीमउद्दीन विधानसभा चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार को हराकर सोनाई के विधायक बने थे। आरोप है कि नामांकन के दौरान करीमउद्दीन ने खुद को 2019 में चौधरी चरण सिंह विवि से स्नातक बताया था। भाजपा उम्मीदवार अमीनुल हक ने इसे फर्जी बताते हुए सीसीएसयू में आरटीआइ दाखिल कर करीमउद्दीन की डिग्री की जानकारी मांगी थी। विवि की जांच में 2019 में इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं मिला, जिसकी डिग्री यहां से जारी हुई हो।

तृणमूल विधायक खोकन ने दिखाई नवाबी, वीडियो हुआ वायरल

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

विवाद

> पार्टी वीडियो में विधायक को दो कार्यकर्ता जूता पहनाते दिख रहे हैं
>
> विधायक ने दी सफाई, कहा-जूता पहनाने वाला व्यक्ति कोई आम आदमी नहीं है बल्कि मेरा भतीजा है

बंगाल में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के एक विधायक को दो पार्टी कार्यकर्ता जूता पहनाते दिख रहे हैं। विवादों में घिरे तृणमूल नेता बर्द्धमान दक्षिण विधानसभा सीट के विधायक खोकन दास हैं। हालांकि, विवाद सामने आने के बाद उनका दावा है कि उन्हें जूते पहनाने वाले उनके अपने लोग हैं। हालांकि, दैनिक जागरण वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है।

दरअसल, बुधवार को बर्द्धमान दक्षिण क्षेत्र में एक रक्तदान शिविर आयोजित किया गया था। इसका औपचारिक उद्घाटन विधायक खोकन दास ने किया। वहां पार्टी के दो कार्यकर्ताओं ने खोकन दास के जूते पहनाए। कुछ लोगों ने इसका वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दिया। विरोधियों का सवाल है कि क्या तृणमूल कांग्रेस के नेता जीत के मद में बंगाल की संस्कृति को भूल गए हैं। सभ्य समाज में कोई और भद्र व्यक्ति क्यों किसी से जूता पहनेगा। इसे लेकर इंटरनेट मीडिया पर जमकर विधायक को खरी-खोटी सुनाई जा रही है। इसके बाद तृणमूल विधायक ने स्थिति को संभालने के लिए, गुरुवार को प्रेस कांफ्रेंस बुलाई। खोकन दास ने कहा कि किसी भी सरकारी अधिकारी या आम आदमी ने ऐसा नहीं किया है। वह मेरा भतीजा है। उन्होंने कहा कि उनकी उम्र हो गई है और घुटने में दर्द रहता है। इस कारण वह झुक नहीं पाते हैं। मेरा भतीजा हमेशा मेरे साथ रहता है और मेरी मदद करता है। वह जूते के फीते भी बांधने में कभी-कभी मदद करता है। दास ने यह भी आरोप लगाया कि उनके जूते पहनाने का वीडियो साजिश के तहत वायरल किया गया है।

राजनीति

योजनाओं का लाभ देकर तीन करोड़ प्रदेशवासियों से सीधी जुड़ी सरकार, विपक्षी दलों के लिए आसान न होगी जाति के दांवपेच से वोटबैंक में सेंध

'लाभार्थी वोटबैंक' के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी भाजपा

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

भाजपा उप्र में अगले साल होने वाले विस चुनाव की तैयारी में जुटी है। फाइल

विरोधी दलों के जातीय वोटबैंक में गहरी सेंध लगा चुकी सत्ताधारी भाजपा ने ऐसा नया वोटबैंक तैयार किया है, जिसे वह अपनी सबसे बड़ी ताकत मान रही है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की सरकार की नीति के साथ संगठनात्मक रणनीति भी समानांतर चली। अब जब पार्टी चुनाव मैदान में उतरने जा रही है तो उसके पास 'लाभार्थी वोटबैंक' के रूप में वह मजबूत अस्त्र है, जिसकी काट इतनी आसान न होगी।

भाजपा सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ सीधे 80 लाख उत्तर प्रदेश वासियों को मिलने का दावा है। इसके साथ ही भाजपा के लाभार्थी वोटबैंक में इतने लोग सीधे तौर पर जुड़ गए। दरअसल, 2014 का लोकसभा चुनाव जीतने के बाद से ही मोदी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास का नारा देते हुए गरीबों के केंद्र में रखकर योजनाओं पर काम शुरू किया। 2017 में प्रदेश की कमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाली तो उन्होंने भी इसी नीति को आगे बढ़ाया। केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं पर तेजी से काम कर लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने पर सरकार का पूरा जोर रहा। भाजपा संगठन भी इस मुहिम में जुटा रहा। बेशक, सरकार ने यह योजनाएं बिना किसी भेदभाव के चलाई हैं, लेकिन इसके राजनीतिक परिणाम साफ नजर आते हैं। इन योजनाओं की पात्रता का आधार जातीय नहीं, बल्कि आर्थिक स्थिति है। लिहाजा, दलित और पिछड़ों की संख्या लाभार्थियों में सबसे अधिक है। सूबे की सियासत में इन दो वर्गों का खास महत्व है। भाजपा सपा और बसपा के इन जातीय वोटबैंक में पहले ही सेंधमारी कर चुकी है। अब इस वोट की वापसी के लिए दोनों दल हाथ-पैर मार रहे हैं, लेकिन भाजपा सरकार ने अपनी योजनाओं के माध्यम से इन्हें सीधे तौर पर जोड़ लिया है। शौचालय, प्रधानमंत्री आवास, सौभाग्य योजना में मुफ्त बिजली कनेक्शन, उज्ज्वला योजना में गैस कनेक्शन, आयुष्मान भारत योजना, मुख्यमंत्री जनआरोग्य योजना जैसी तमाम योजनाओं का लाभ सीधे गरीबों को मिला है। ऐसे में विपक्षी दलों के सामने इस मजबूत किले में छेद करना बड़ी चुनौती होगी।

भाजपा के प्रदेश महामंत्री व एमएलसी गोविंद नारायण शुक्ल कहते हैं कि मोदी-योगी सरकार की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित होने वालों की उत्तर प्रदेश में ही संख्या तीन करोड़ से अधिक है। केंद्र व राज्य सरकार ने बिना किसी भेदभाव के अपनी अंत्योदय की नीति पर चलते हुए गरीबों के कल्याण की योजनाएं लागू की हैं। सभी वर्गों को लाभ मिला है, इसलिए वह भाजपा के साथ हैं और रहेंगे।

अब झारखंड में स्थानीय लोगों को नौकरी में मिलेगी प्राथमिकता

राज्य ब्यूरो, रांची

> राज्य से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पास करने वाले को ही मिलेगी नौकरी
>
> कर्मचारी चयन आयोग एक ही परीक्षा से नियुक्ति प्रक्रिया को करेगा पूरा

झारखंड सरकार ने नियुक्तियों को लेकर तैयार आठ नियमावलियों को एक साथ संशोधित कर स्वीकृति प्रदान कर दी है। इनमें मैट्रिक से लेकर स्नातक स्तरीय परीक्षाओं के लिए अब एक जैसे संशोधन किए गए हैं। नए संशोधन के अनुसार झारखंड में मैट्रिक से लेकर स्नातक स्तरीय नौकरियों के लिए, यहां के मान्यता प्राप्त स्कूल से मैट्रिक अथवा इंटर की पढ़ाई की अनिवार्यता सुनिश्चित की गई है। हालांकि, झारखंड में आरक्षण का लाभ लेनेवालों के लिए इस नियम को शिथिल किया गया है। मतलब यह कि अगर झारखंड के आरक्षित श्रेणी का कोई व्यक्ति अन्यत्र से भी मैट्रिक पास है तो उसे परीक्षा और नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है।

कर्मचारी चयन आयोग प्रारंभिक और फाइनल परीक्षा की जगह एक ही परीक्षा से नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करेगा। राज्य कैबिनेट ने इसके साथ ही कुल 27 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

नियुक्ति परीक्षाओं के लिए कुछ नई शर्तें

नियुक्ति परीक्षाओं के लिए सरकार ने कुछ शर्तें भी निर्धारित की हैं। इनमें प्राथमिक शर्त यह है कि अभ्यर्थियों को स्थानीय रीति-रिवाज का ज्ञान होना अनिवार्य होगा। भाषा ज्ञान की परीक्षा में हिंदी और अंग्रेजी में पहले अलग-अलग 30 अंक लाने अनिवार्य होते थे, उसकी जगह अब दोनों विषयों को मिलाकर 30 प्रतिशत अंक लाने होंगे। यह अंक मेरिट लिस्ट बनाने के क्रम में नहीं जुड़ेंगे। वहीं, चिन्हित क्षेत्रीय भाषा में 30 प्रतिशत अंक और सामान्य ज्ञान में 30 प्रतिशत अंक लाने की अनिवार्यता बनी रहेगी। क्षेत्रीय भाषाओं में उर्दू, संथाली, बंगाली, हो, नागपुरी, पंच परगनिया, ओड़िया आदि भाषाएं शामिल हैं। जिला स्तरीय परीक्षाओं के लिए स्थानीय भाषा बदल भी सकती है।

7.5 फीसद कोटा मंजूर किया गया प्रोफेशनल कोर्स में नामांकन करवाने पर सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए। इससे पहले अंडरग्रेजुएट मेडिकल कोर्स में यह सुविधा दी गई थी।

भावुक हो गईं बबिता जब पीएम ने कहा–'मुझे राखी भेजिएगा'

अन्न महोत्सव का शुभारंभ करते हुए मोदी ने पांच लाभार्थियों से किया संवाद, अमलावती से भोजपुरी में कहा–'आशीर्वाद बनल रहे'

जागरण टीम, लखनऊ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को गरीब कल्याण अन्न महोत्सव का आनलाइन शुभारंभ करते हुए प्रदेश के पांच लाभार्थियों से न सिर्फ संवाद किया बल्कि उनसे केंद्रीय योजनाओं के बाबत जानकारी भी ली। इस दौरान उन्होंने सुलतानपुर की बबिता से राखी भेजने का आग्रह किया तो वह भावुक हो गईं। कुशीनगर की अमलावती पीएम के मुंह से भोजपुरी सुन निहाल थीं।

मोदी ने सुलतानपुर, वाराणसी, कुशीनगर, सहारनपुर और झांसी के लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद किया। इनमें चार महिलाएं थीं। सुलतानपुर की लक्ष्मणपुर गांव निवासी बबिता ने जैसे ही स्क्रीन पर प्रधानमंत्री को देखा, उनके हाथ स्वतः ही जुड़ गए। उन्होंने बताया कि वह खेती के साथ पशुपालन भी करती हैं। इस पर पीएम ने पूछा-'इस समय खेत में क्या तैयार हो रहा है। बबिता ने बताया कि धान की रोपाई की गई है। सम्मान निधि के प्रश्न पर बताया कि पूरा धन खाते में आ रहा है। बबिता तब भावुक हो गईं जब प्रधानमंत्री ने कहा कि राखी का त्योहार आ रहा है। मुझे राखी भेजिएगा। वाराणसी की बदामी देवी से प्रधानमंत्री ने पूछा कि घर आने पर खाना खिलाओगी तो बोली कि हम सब वोट देके जियावत रहब। नीति आयोग की ओर से देश के पहले प्रस्तावित माडल ब्लाक सेवापुरी के भीषमपुर गांव की बदामी ने पीएम से भोजपुरी में कहा कि परिवार में दो परानी (सदस्य) हई। आप के कृपा से मड़ई से पक्का घर हो गइल। हर महीने राशन मिलत हव। शौचालय, बिजली, गैस सब मिलल बा। गैस पर दाल, रोटी, भुझिया सब बनाई ला।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर में कादीपुर स्थित लक्ष्मणपुर गांव में अन्न महोत्सव में लाभार्थी बबिता यादव से नई दिल्ली से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जागरण

सहारनपुर की कमलेश के लिए गुरुवार अहम दिन बन गया। वह स्क्रीन को निहार ही रहीं थीं कि अचानक आवाज आई-'कमलेशजी नमस्कार, क्या आपको राशन समय पर मिल रहा है। जवाब मिला-'दो माह से मिल रहा है।' पीएम ने पूछा कि उनका मकान उनके तरीके से बना था या फिर सरकारी अफसर ने जबरन अपने तरीके से बनाया। कमलेश ने कहा कि मकान को उन्होंने अपने मन मुताबिक बनवाया।

कुशीनगर के कसया विकास खंड के गांव मैनपुर की मुसहर महिला मजदूर अमलावती देवी संवाद शुरू करते हुए प्रधानमंत्री बोले कि आपके आशीर्वाद बनल रहे कि ताकि आगे सब कार्य मैं कर सकूं। संवाद के दौरान भोजपुरी में ही बात करने वाली अमलावती ने भी कहा कि आपके आशीर्वाद से हमनी के ठीक बानी। पीएम ने पूछा ऐसा हुआ क्या कि कहीं जाने पर राशन नहीं मिला। अमलावती बोलीं-पिछले बार नौ महीना राशन मिलल। अबकी दू महीना से मिलत बाटे। तब प्रधानमंत्री बोले- अभी तो दिवाली तक मुफ्त राशन देने वाला हूं।

नई अयोध्या : 8,568 करोड़ की परियोजनाएं

जासं, अयोध्या

श्रीराम जन्मभूमि पर मंदिर के भूमि पूजन की प्रथम वर्षगांठ पर उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नई अयोध्या के निर्माण के प्रति संकल्पित दिखे। हालांकि कारसेवकपुरम के सामने का यह मंच प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन वितरित करने के लिए था, लेकिन गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में बताने के साथ मुख्यमंत्री नई अयोध्या के बारे में बताना नहीं भूले। उन्होंने राशन वितरण स्थल से वर्चुअली जुड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए याद दिलाया कि गत वर्ष भूमि पूजन के वक्त प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन मिलने के बाद नई अयोध्या की दिशा में कदम बढ़ाया गया और आज नई अयोध्या के लिए 138 करोड़ रुपये की 17 परियोजनाओं पर काम भी हो चुका है। नई अयोध्या की कई अन्य परियोजनाओं के लिए 8,568 करोड़ रुपये की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार है।

श्रीराम जन्मभूमि पर मंदिर के भूमि पूजन की प्रथम वर्षगांठ पर अयोध्या पहुंचे उप्र के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर निर्माण प्रक्रिया का जायजा लिया और मंदिर के मॉडल की पूजा-अर्चना की। प्रेट्र

भारत के ग्रोथ इंजन का पावर हाउस

प्रथम पृष्ठ से आगे

अयोध्या में मौजूद रहकर कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 'कर्मयोगी' बताने के साथ प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी अगुआई में संवर रहा उप्र भारत के ग्रोथ इंजन का पावर हाउस बन सकता है। भयमुक्त वातावरण में बड़ी कंपनियां यहां निवेश को लालायित हैं।

पिछड़ों और गरीब सवर्णों को दिया संदेश : प्रधानमंत्री ने शिक्षा से जुड़े केंद्र सरकार के दो ताजा फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि इंजीनियरिंग और तकनीकी शिक्षा को हिंदी सहित अनेक भारतीय भाषाओं में शुरू करने के फैसले से उत्तर प्रदेश के गांवों और गरीब परिवारों के बच्चे भी अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सकेंगे।

न्यूज गैलरी

पूर्व सीएम 86 वर्षीय चौटाला का 12वीं का परिणाम रुका

भिवानी : हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 12वीं ओपन का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया। बोर्ड ने सभी छात्रों को 34 अंक देकर उत्तीर्ण कर दिया है। मगर, इनेलो सुप्रीमो एवं पूर्व मुख्यमंत्री 86 वर्षीय ओम प्रकाश चौटाला सहित छह परीक्षार्थियों का परिणाम रोक दिया गया है। कारण यह है कि सभी ने नेशनल इंस्टीट्यूट आफ ओपन स्कूलिंग (एनआइओएस) से 10वीं पास की थी, लेकिन अंग्रेजी विषय में उत्तीर्ण नहीं थे। नियमानुसार 12वीं उत्तीर्ण करने के लिए 10वीं की अंग्रेजी विषय की परीक्षा पास करनी जरूरी है। (जासं)

घटे हुए पाठ्यक्रम के आधार होगी कंपार्टमेंट परीक्षा

नई दिल्ली : सीबीएसई की तरफ से 16 अगस्त से 15 सितंबर के बीच आयोजित होने जा रहीं कंपार्टमेंट परीक्षाएं घटे हुए पाठ्यक्रम के आधार पर होंगी। वहीं, बोर्ड केवल मुख्य विषयों की परीक्षा ही आयोजित करेगा। बोर्ड ने इस संबंध में 12वीं के 19 विषय भी चिह्नित किए हैं। परीक्षा के लिए सीबीएसई ने वेबसाइट पर सैंपल जारी किए हैं। (जासं)

राजद राज्यसभा सदस्य अमरेंद्र धारी सिंह को जमानत

नई दिल्ली : खाद घोटाला के मनी लांड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किए गए राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के राज्यसभा सदस्य अमरेंद्र धारी सिंह को दिल्ली हाई कोर्ट ने चिकित्सा आधार पर जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की पीठ ने कहा कि सिंह कैंसर समेत कई बीमारियों से पीड़ित हैं और इसके लिए दवा ले रहे हैं। (जासं)

पूर्व मंत्री बेग और विधायक के परिसरों पर छापेमारी

नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कर्नाटक के पूर्व मंत्री आर रोशन बेग और कांग्रेस के विधायक जमीर अहमद खान के ठिकानों पर गुरुवार को छापेमारी की। अधिकारियों ने बताया कि 4,000 करोड़ रुपये के आइएमए पोंजी घोटाले में मनी लांड्रिंग की जांच के सिलसिले में यह छापेमारी की गई। पार्टी विधायक जमीर का पक्ष लेते हुए कांग्रेस ने ईडी की छापेमारी को राजनीति से प्रेरित बताया है। (प्रेट्र)

देशमुख केस में सीबीआइ को धमका रही मुंबई पुलिस

मुंबई : महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रही सीबीआइ को राज्य सरकार का सहयोग नहीं मिल रहा है। यहां तक कि मुंबई पुलिस के अधिकारी सीबीआइ टीम को धमकियां भी दे रहे हैं। सीबीआइ ने यह शिकायत बांबे हाई कोर्ट से की है। देशमुख के खिलाफ सीबीआइ जांच उच्च न्यायालय के ही आदेश पर हो रही है। सीबीआइ के वकील अनिल सिंह ने युगल पीठ को सूचित किया है कि राज्य सरकार का सहयोग नहीं मिल रहा है। (राब्यू)

छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने उड़ाया निजी वाहन, एक की गई जान

हमला ▶ बारसूर–पल्ली मार्ग पर हुए आइईडी ब्लास्ट में 12 घायल, तेलंगाना जा रहे थे मजदूर

नईदुनिया, दंतेवाड़ा

छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा जिले के बारसूर-पल्ली मार्ग पर नक्सलियों ने गुरुवार सुबह करीब साढ़े सात बजे आइईडी ब्लास्ट कर एक निजी वाहन को उड़ा दिया। इस वारदात में मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के धन सिंह (30) की मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल हो गए हैं। पांच घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। अन्य को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। वारदात की सूचना मिलते ही दंतेवाड़ा एसपी डा. अभिषेक पल्लव खुद मौके पर पहुंचे हालात का जायजा लिया।

नारायणपुर से बारसूर होते हुए दंतेवाड़ा की सीधी दूरी सिर्फ 116 किमी की है, जबकि हाइवे होकर आने पर करीब 220 किमी का चक्कर काटना पड़ता है। वाहन चालक शार्टकट के चक्कर में बारसूर-पल्ली मार्ग पर निकला था। वाहन से बालाघाट (मप्र) और राजनांदगांव (छग) के 13 लोग मजदूरी करने तेलंगाना जा रहे थे। नारायणपुर घोटिया मोड़ पर सड़क निर्माण का काम चल रहा है।

दंतेवाड़ा में नक्सलियों द्वारा विस्फोट कर उड़ाया गया निजी वाहन। नईदुनिया

बारसूर-पल्ली मार्ग दोबारा शुरू होने से नक्सलियों के पूर्वी बस्तर डिवीजन को बड़ा झटका लगा है। इससे वे बौखला गए हैं। इस वारदात से नक्सलियों का असली चेहरा सामने आ गया है। वे नहीं चाहते कि लोगों को सुविधाएं मिलें और उनका जीवन आसान हो। -सुंदरराज पी, आइजी, बस्तर

बिहार में रेलवे स्टेशन, रेल सुरंग व मुंगेर किला ध्वस्त करने की तैयारी में थे

जागरण टीम, मुंगेर

शहीदी सप्ताह के मौके पर मंगलवार की रात नक्सली बिहार में भागलपुर जंक्शन के साथ मुंगेर किला, मुंगेर के ही जमालपुर व रतनपुर स्टेशन के बीच रेलवे सुरंग और जमालपुर स्टेशन को ध्वस्त करने की साजिश कर रहे थे। नक्सलियों ने जमालपुर रेल सुरंग की सुरक्षा में तैनात आरपीएफ जवान का अपहरण कर एक करोड़ से अधिक की फिरौती वसूलने की योजना भी बनाई थी। रेल और जिला पुलिस को समय से इसकी सूचना मिल गई। पुलिस की सतर्कता ने नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया।

गुरुवार को एएसपी (अभियान) राजकुमार राज ने बताया कि गिरफ्तार किए गए चिरैयाबाद निवासी नक्सली नंदन मंडल ने अपने चचेरे साले को फोन कर भागलपुर स्टेशन उड़ाने की बात कही थी। बीते बुधवार को नंदन को पकड़ा गया था। मोबाइल फोन ट्रैकिंग से भी जानकारी मिलने पर एसटीएफ व बरियारपुर थाना के पदाधिकारियों ने तीन अगस्त की रात से ही नक्सलियों की खोज शुरू कर दी। नक्सली बंदी की आखिरी रात तीन अगस्त को सूचना मिली थी कि देर रात नक्सली रेलवे सुरंग को टारगेट कर सकते हैं। सूचना के बाद रेल और जिला विशेष बल के अधिकारी-जवान कई वाहनों के साथ जमालपुर व रतनपुर स्टेशन के बीच रेलवे सुरंग के पास पहुंच गए। रातभर की निगरानी ने नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया।

प्रेमी समेत आठ पर मतांतरण और सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, बागपत

दो साल पहले एक युवती मुस्लिम युवक के साथ चली गई थी। अब लौटी युवती ने प्रेमी समेत आठ आरोपितों के खिलाफ शादी का झांसा देकर मतांतरण कराने, सामूहिक दुष्कर्म करने और गोमांस खिलाने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है।

बागपत की बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की युवती चार अगस्त की शाम कोतवाली पहुंची। युवती ने पुलिस को तहरीर में बताया कि इरशाद अली निवासी मलकपुर गांव, शामली अपना नाम सोनू बताकर हेयर सैलून की दुकान करता था। 26 जनवरी, 2019 को आरोपित ने घर पर ही उसके साथ दुष्कर्म किया और वीडियो बनाया। आरोपित ने वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया और शादी का दबाव बनाया। 23 फरवरी, 2019 को इरशाद, उसका भाई मोनू उर्फ अय्यूब, बहनोई बिल्लू घर पर आए और बहला फुसलाकर किसी स्थान पर उसे मुस्लिम बहुल मोहल्ले में ले गए, तो उसे इरशाद के मुस्लिम होने का पता चला। आरोपितों ने फर्जी निकाह के कागज तैयार करा लिए। इरशाद का भाई अय्यूब, बहनोई बिल्लू व महबूब उसे लोनी ले गए और वहां मौलवी ने उसका मतांतरण कराया और उसे गोमांस खिलाया। लोनी में इरशाद के बहनोई बिल्लू व महबूब ने उसके साथ दुष्कर्म किया। यहां से वह उसे कोताना गांव लेकर पहुंचे तो इरशाद के साले नौशाद ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इरशाद उसे अपने साथ सोनीपत में खरखौदा के पास ईंट भट्ठे पर ले गया और वहां इरशाद के बड़े बेटे समीर और भतीजे सोमीन ने उसके साथ दुष्कर्म किया। 20 जुलाई, 2021 को इरशाद व समीर भट्ठा बंद होने पर उसे मलकपुर, कांधला ले जा रहे थे। दोनों बड़ौत में केले खरीदने उतर गए, तो वह बस से उतर गई और अपने घर पहुंची और स्वजन को आपबीती बताई।

युवती ने कोर्ट में प्रेमी के साथ जाने की जताई थी इच्छा

सीओ आलोक सिंह ने बताया कि युवती के पिता ने फरवरी, 2019 में आरोपित इरशाद आदि के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में पुलिस ने युवती को कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट में युवती ने प्रेमी के साथ जाने की इच्छा जताई थी। अब युवती ने प्रेमी समेत आठ आरोपितों पर मतांतरण कराने, सामूहिक दुष्कर्म व गोमांस खिलाने का आरोप लगाया है।

'जज की मौत के मामले की गंभीरता देख जांच सीबीआइ को सौंपी गई'

नई दिल्ली, प्रेट्र : झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि धनबाद में एक जज को वाहन से कुचलने की घटना की गंभीरता को देखते हुए उसने मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला किया। केंद्रीय एजेंसी ने मामला दर्ज करने के बाद जांच शुरू कर दी है।

राज्य सरकार ने कहा कि डिस्ट्रिक एंड एडीशनल सेशन जज उत्तम आनंद की दुर्भाग्यपूर्ण मौत के मामले की जांच में वह केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) का पूरा सहयोग करेगी। झारखंड सरकार की स्थिति रिपोर्ट में कहा गया कि जांच सीबीआइ को हस्तांतरित किए जाने के बाद, चार अगस्त को केंद्रीय जांच एजेंसी ने मामला दर्ज किया और जांच अपने हाथों में ले ली। झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह और पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा ने वकील पल्लवी लांगर के मार्फत कोर्ट में यह स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है। स्टेटस रिपोर्ट में राज्य सरकार ने कहा है कि जज आनंद को एक निजी सुरक्षा कर्मी उपलब्ध कराया गया था। उनका नाम कांस्टेबल सौरभ साव है। कोर्ट ने इस घटना का स्वतः संज्ञान लिया है। इस विषय पर शुक्रवार को चीफ जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ सुनवाई करेगी। रिपोर्ट में कहा गया कि झारखंड सरकार ने सभी जिलों में न्यायिक अधिकारियों की आवासीय कालोनियों में सुरक्षा बल की व्यवस्था की है।

शिवपुरी में गलियों में आए मगरमच्छ, लोग ले रहे सेल्फी

नईदुनिया, ग्वालियर

मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में रिकार्ड बारिश से सांख्य सागर झील के साथ जाधव सागर और भुजरिया ताल भी लबालब हो गए हैं। ऐसे में यहां से पानी सड़कों पर आने से तालाबों से मगरमच्छ निकलकर गलियों में पहुंच रहे हैं। कुछ लोग इन मगरमच्छों को देखकर डर रहे हैं तो कुछ लोग साहस दिखाकर इन्हें पकड़कर इनके साथ सेल्फी ले रहे हैं। वन विभाग का कहना है आमतौर पर लगभग हर हफ्ते कहीं न कहीं से मगरमच्छ आने की सूचना मिलती रही है, लेकिन बारिश के बाद ऐसे मामले बढ़े हैं।

पिछले दिनों भुजरिया ताल और जाधव सागर से मगरमच्छ निकलकर मीट मार्केट और पुरानी शिवपुरी क्षेत्र में पहुंच गए थे। पिछले 10 दिन में चार बार मगरमच्छ शहर की सड़कों पर देखे जा चुके हैं। पुरानी शिवपुरी में करीब 15 फीट लंबा मगरमच्छ दिखाई देने पर स्थानीय लोगों ने ही इसे पकड़ लिया।

शिवपुरी में पकड़े गए मगरमच्छ को पकड़कर कंधे पर ले जाता युवक। सौ: इंटरनेट मीडिया

जिले के कुछ क्षेत्रों में अक्सर मगरमच्छ पहुंचने की सूचना मिलती है। कई बार घरों तक में घुस जाते हैं। लोगों को सतर्कता बरतनी चाहिए। यह ऐसा जानवर नहीं, जिसके साथ खिलवाड़ किया जाए। -अनिल सोनी, उपसंचालक, माधव राष्ट्रीय उद्यान, शिवपुरी

हिमाचल में नौ दिन बाद मिला बिहार के इंजीनियर का शव

जास, केलंग : हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहुल स्पीति के उदयपुर क्षेत्र के रंगवे नाला (तोजिंग) में बहे सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के लापता कनिष्ठ अभियंता (जेई) राहुल कुमार का शव नौ दिन बाद मलबे से क्षत-विक्षत हालत में मिला है। इसकी पहचान राहुल के चाचा विनय पांडे ने वर्दी व बाजू में बंधे धागे से की। वह बिहार के रहने वाले थे। गौरतलब है कि बादल फटने से रंगवे नाला में आई बाढ़ से 27 जुलाई देर शाम राहुल के साथ तीन अन्य मजदूर भी पोकलेन मशीन के साथ बह गए थे। सेना के स्निफर डाग की मदद से गुरुवार को एक क्षत-विक्षत शव मिला। राहुल कुमार पुत्र रामानुज पांडे, बिहार के लखीसराज जिले की तहसील सूर्यगढ़ा के रामपुर गांव रहने वाले थे। बीटेक करने के बाद इसी साल 12 अप्रैल को बीआरओ में कनिष्ठ अभियंता के पद पर तैनात हुए थे।

भारी बारिश के बावजूद नहीं भरे बांध

सुरेंद्र प्रसाद सिंह, नई दिल्ली: मानसून के दौरान अच्छी बरसात के बावजूद देश के ज्यादातर बांधों में पर्याप्त पानी नहीं भर सका है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब व छत्तीसगढ़ समेत नौ राज्यों के जलाशय अभी खाली रह गए हैं। इससे बिजली उत्पादन और सिंचाई के प्रभावित होने का अंदेशा है।

भारतीय मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक अगस्त में पश्चिमी मध्य प्रदेश, उससे लगे राजस्थान वाले क्षेत्रों, महाराष्ट्र के अंदरूनी हिस्सों, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, पंजाब के कुछ हिस्सों और हिमाचल प्रदेश में सामान्य से कम बारिश हो सकती है। स्पष्ट है कि अगस्त में भी उत्तरी राज्यों के बांधों में पर्याप्त पानी नहीं भर सकेगा। जून व जुलाई के दौरान 73 जिलों में अत्यधिक बरसात हुई है, जबकि 145 जिलों में सामान्य से अधिक बारिश हुई। 275 जिलों में सामान्य बरसात हुई है। देश के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित गुजरात के 17 और महाराष्ट्र के 25 बांध व जलाशयों में पिछले साल के मुकाबले अधिक पानी भर चुका है। दक्षिणी क्षेत्रों के सभी 37 बांधों में एक दशक के जलस्तर के मुकाबले ज्यादा जल स्तर है।

बगैर स्थायी पते के भी मिलेंगे उज्ज्वला कनेक्शन

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: सरकार जल्द ही उज्ज्वला योजना का दूसरा फेज लागू करने जा रही है। इसके तहत उन लोगों को भी एलपीजी कनेक्शन देने का इंतजाम होगा जिनके पास स्थायी पता नहीं है। इसका फायदा शहरों में रहने वाले गरीबों और देश के विभिन्न हिस्सों में रोजगार की तलाश में जाने वाले श्रमिकों को खास तौर पर होगा। इसे जल्द लागू करने की तैयारी है। इसके पहले फेज की शुरुआत मई, 2016 में की गई थी। उत्तर प्रदेश के बलिया से उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई थी, जिसके तहत गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन दिया जाता है। पेट्रोलियम मंत्रालय के तहत आने वाली सरकारी तेल कंपनियां अभी उज्ज्वला के दूसरे फेज का अंतिम प्रारूप तैयार कर रही हैं। इसमें जो बड़े बदलाव होंगे, उसमें स्थायी पता की जरूरत को कम किया जाएगा। दूसरा बदलाव यह होगा कि एक सीमित अवधि के बाद कनेक्शन आगे बढ़ाने या लौटाने का विकल्प मिलेगा। ये दोनों बदलाव दूरदराज इलाकों में काम करने वाले श्रमिकों की जरूरत को देखते हुए किया जा रहा है। इसके तहत एक करोड़ कनेक्शन दिए जाने की संभावना है। आम बजट 2021-22 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उज्ज्वला का विस्तार करने का एलान किया था।

आपरेशन करने तैरकर अस्पताल पहुंची डाक्टरों की टीम

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : बंगाल में हावड़ा जिले का उदयनारायणपुर ब्लाक बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए इलाकों में से एक है, जहां के ज्यादातर गांव पानी में डूबे हुए हैं। हालांकि, इतनी विकट स्थिति भी डाक्टरों और उनके सहायकों को उनके कर्तव्यों का निर्वहन करने से नहीं रोक पाई। गंभीर रूप से पीड़ित मरीज का आपरेशन करने तीन डाक्टर, दो नर्स और चार सहायक लगभग आधा किलोमीटर तैरकर उदयनारायणपुर जनरल अस्पताल पहुंचे।

मरीज का आपरेशन करने वाले डाक्टरों में से एक तारक दास ने कहा कि मरीज के गर्भाशय से खून बह रहा था और उसका तत्काल आपरेशन करने की जरूरत थी। हम अच्छे तैराक नहीं हैं लेकिन हमारे पास अस्पताल पहुंचने के लिए तैरने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।

शर्मनाक

गाली–गलौज, धमकी देने और जातिसूचक शब्द कहने का भी लगाया आरोप, भारतीय महिला हाकी टीम की खिलाड़ी हैं वंदना कटारिया, ओलिंपिक में सेमीफाइनल हारने पर पुरानी रंजिश के कारण पड़ोसियों ने फोड़े थे पटाखे

हाकी खिलाड़ी वंदना के स्वजन पर जातिसूचक टिप्पणी

जागरण संवाददाता, हरिद्वार

भारतीय महिला हाकी टीम की खिलाड़ी वदंना कटारिया के घर के बाहर पटाखे छोड़ने और जातिसूचक शब्द कहने वाले आरोपितों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने दो आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से एक विजयपाल सिंह भी हाकी खिलाड़ी है। वहीं, झबरेड़ा विधायक देशराज कर्णवाल समेत विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने वंदना कटारिया के घर में बैठक की। विधायक ने कहा कि खिलाड़ियों को अपमान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

टोक्यो ओलिंपिक में बुधवार को भारतीय महिला हाकी टीम का अर्जेंटीना से सेमीफाइनल मुकाबला था। बेहतरीन प्रदर्शन के बावजूद भारतीय टीम मैच हार गई। हाकी टीम की खिलाड़ी वंदना कटारिया के परिवार की नजरें सुबह से ही टीवी स्क्रीन पर लगी थी। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि भारतीय टीम यह मैच जीतेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे परिवार मायूस हो गया। ठीक इसी समय पुरानी रंजिश के चलते पड़ोस में रहने वाले कुछ व्यक्तियों ने वंदना के घर के बाहर पटाखे छोड़े। आरोप है कि उन्होंने खुशी मनाने के अंदाज में अतिशबाजी की। जिसके बाद दोनों पक्षों में कहासुनी हुई। वंदना के भाई चंद्रशेखर ने सिडकुल थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया कि रोशनाबाद निवासी सुमित चौहान, अंकुर और विजय पाल ने गाली-गलौज व मारपीट करते हुए धमकी दी और जातिसूचक शब्द भी कहे। बुधवार देर रात पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। सिडकुल थानाध्यक्ष लखपत बुटोला ने बताया कि आरोपित विजय पाल और अंकुर पाल निवासी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों सगे भाई हैं। एसएसपी सेंथिल अवूदई कृष्णराज एस ने बताया कि मुकदमे की जांच एएसपी सदर डा. विशाखा अशोक को सौंपी गई है।

दोनों परिवारों में चली आ रही रंजिश: वंदना कटारिया और विजय पाल के परिवार रोशनाबाद गांव में आसपास रहते हैं। उनके बीच कई सालों से रंजिश चली आ रही है। हालांकि कोई जमीन-जायदाद से जुड़ा विवाद दोनों परिवारों में नहीं है। मामूली छींटाकशी को लेकर दोनों परिवारों में कई बार झगड़ा हो चुका है। वंदना के भाई चंद्रशेखर कटारिया ने पुलिस को बताया कि आरोपित विजयपाल का परिवार उनके परिवार से रंजिश रखता है। इसके चलते उसने महिला हाकी टीम के हारे जाने के बाद उसके घर के सामने पटाखे छोड़ते हुए जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया।

आरोपितों ने पहले से की थी तैयारियां

प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि भारतीय टीम के हारने के कुछ ही देर बाद दूसरा पक्ष वंदना के घर के बाहर पहुंच गया। उन्होंने पटाखे भी फोड़े और चिढ़ाने के लिए डांस भी किया। आतिशबाजी को देखकर यह माना जा रहा है कि आरोपितों ने पहले से ही पूरी तैयारी कर रखी थी। हार के लिए खासतौर पर पटाखे खरीदे गए होंगे। आरोपितों की इस हरकत की हर कोई निंदा कर रहा है।

सेना में भर्ती होंगे कक्षा पांच पास बच्चे

जासं, लखनऊ : ऐसे छोटे बच्चे जो स्पोर्ट्स के साथ सेना में अपना करियर बनाना चाहते हैं। उनके लिए सेना अगले माह अपनी ब्वायज स्पोर्ट्स कंपनी में भर्ती होने के लिए ट्रायल आयोजित करेगी। रेजीमेंटल स्तर पर होने वाली इस भर्ती की प्रक्रिया अक्टूबर में पूरी की जाएगी। आठ से 14 साल की उम्र के बच्चों का चयन कर सेना उनको अपनी रेजीमेंट में प्रशिक्षण देगी। साथ ही उनकी पढ़ाई भी कराएगी। कक्षा 10 पास होने पर न्यूनतम साढ़े सत्रह साल की आयु में इन बच्चों को सेना में भर्ती किया जाएगा। इस कंपनी में भर्ती होने वाले बच्चों की आयु 20 से 23 सितंबर तक आठ से 14 वर्ष तक होनी चाहिए। साथ ही कक्षा पांच उत्तीर्ण होना चाहिए। मैकेनाइज्ड इंफेंट्री रेजीमेंटल सेंटर अहमदनगर (महाराष्ट्र) में 20 से 23 सितंबर तक सेना की ब्वायज स्पोर्ट्स कंपनी में बच्चों का ट्रायल लिया जाएगा। ट्रायल के समय स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट की मूल व प्रमाणित छायाप्रति, आयु प्रमाणपत्र, आदि सर्टिफिकेट देखे जाएंगे।

फीस जमा नहीं होने पर स्कूल से भगाया, आहत छात्रा ने दी जान

▶ पोस्टमार्टम में जहर मिलने की पुष्टि, प्रधानाचार्य पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप

जागरण संवाददाता, उन्नाव

उप्र के उन्नाव में आर्थिक तंगी के चलते पिता पूरी फीस नहीं भर सका तो 10वीं में पढ़ने वाली उसकी बेटी को स्कूल ने बेइज्जत कर भगा दिया। एग्जाम शीट के लिए छात्रा मिन्नतें करती रही, मगर प्रधानाचार्य ने एक नहीं सुनी। आहत छात्रा रोते हुए घर पहुंची और बेहोश हो गई। देखते देखते उसने दम तोड़ दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर मिलने की पुष्टि हुई। पिता की तहरीर पर कोतवाली में प्रधानाचार्य पर आत्महत्या के लिए उकसाने की रिपोर्ट दर्ज की गई है।

सदर कोतवाली क्षेत्र के आदर्श नगर निवासी सुशील कुमार अवस्थी हिरननगर स्थित एक तंबाकू फैक्ट्री में काम करते हैं। उन्होंने तहरीर में बताया, उनकी इकलौती संतान स्मृति एबी नगर स्थित सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कालेज में कक्षा 10 की छात्रा थी। आर्थिक तंगी की वजह वह उसकी फीस नहीं जमा कर सके थे। बुधवार को उसकी त्रैमासिक परीक्षा शुरू हुई तो वह एग्जाम शीट लेने गई। वहां प्रधानाचार्य ने उसे पांच माह की बकाया फीस जमा करने की बात कही। उसने यह बात घर में बताई तो मां रेनू ने दो हजार रुपये जमा कर दिए और बाकी के दो हजार पति का वेतन मिलने पर सात तारीख को जमा करने को कहा। बेटी गुरुवार को दोबारा गई, तो उसे स्कूल से भगा दिया गया। वह सबके सामने बेइज्जत होने से काफी आहत हुई और रोते हुए घर पहुंची और गिरकर बेहोश हो गई। उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। चाचा महेश के मुताबिक, कोरोना के दौरान फैक्ट्री बंद हुई, उसके बाद से आर्थिक संकट गहरा गया।

25 फीसद वैक्सीन निजी क्षेत्र के अस्पतालों के लिए कर दी गई थी आरक्षित। वैक्सीन नहीं खरीद पाने और धीमी रफ्तार की वजह से अब निजी क्षेत्र के हिस्से की वैक्सीन भी केंद्र सरकार ही खरीदेगी।

न्यूज गैलरी

टेस्टिंग फर्जीवाड़ा मामले में सरकार का प्रार्थना पत्र खारिज

नैनीताल : हाईकोर्ट ने हरिद्वार में कुंभ मेले में कोरोना टेस्टिंग फर्जीवाड़े के आरोपित मैक्स कॉरपोरेट सर्विसेज के सर्विस पार्टनर शरद पंत व मलिका पंत की याचिकाओं पर सुनवाई की। सरकार की तरफ से एक प्रार्थना पत्र देकर कोर्ट से अनुरोध किया कि पूर्व के आदेश को रिकाल किया जाए या वापस लिया जाए। कोर्ट ने प्रार्थना पत्र को निरस्त करते हुए कहा कि पुलिस ने गंभीर साक्ष्यों के आधार पर मुकदमा दर्ज किया है। (जासं)

मुआवजे को लेकर ममता सरकार को फटकार

कोलकाता : कोरोना योद्धाओं के स्वजन को अब तक मुआवजा नहीं मिलने पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने गुरुवार को ममता सरकार को फटकार लगाई। अदालत ने ऐसे लोगों की सूची भी मांगी है, जिनके स्वजन ने मुआवजा के लिए आवेदन किया है। हाई कोर्ट ने सरकारी वकील से पूछा कि कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर्स को मुआवजा क्यों नहीं मिला? राज्य सरकार के जवाब से असंतुष्ट कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल की खंडपीठ ने कहा कि 'मैं दूंगा' कहने से काम नहीं होगा। अभी तक पैसे क्यों नहीं दिए? सरकार ने मृतकों के स्वजन को 10-10 लाख रुपये मदद देने की घोषणा की थी। (राब्यू)

कोरोना के 50 फीसद से ज्यादा नए मामले अकेले केरल से आए

चिंताजनक ▶ देशभर में आए 42 हजार से अधिक मामले, 533 की मौत

नई दिल्ली, प्रेट्र : देश में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 42,982 नए मामले सामने आए हैं। वहीं अकेले केरल से 22,040 नए मामले सामने आए। इस तरह कुल नए मामलों में पचास फीसद से ज्यादा हिस्सेदारी अकेले इसी राज्य की है। इस दौरान देश भर में कोरोना से जहां 533 लोगों की मौत हुई वहीं केरल में 117 लोगों ने जान गंवाई। केरल में अब तक 34.93 लाख लोग इस बीमारी से संक्रमित हो चुके हैं। यह जानकारी एक सरकारी विज्ञप्ति में दी गई।

राज्यों के पास 2.69 करोड़ से अधिक वैक्सीन उपलब्ध : केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और निजी अस्पतालों के पास अभी भी 2.69 करोड़ से अधिक शेष और अप्रयुक्त कोरोना वैक्सीन की डोज उपलब्ध हैं। सभी स्रोतों के माध्यम से अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 51.01 करोड़ से अधिक वैक्सीन की डोज मुहैया कराई जा चुकी हैं। राज्यों को जल्द ही 7,53,620 और डोज उपलब्ध कराई जा रही हैं। मंत्रालय ने कहा कि इसमें से अपव्यय सहित कुल खपत 48,60,15,232 है।

देश में कोरोना की स्थिति	
24 घंटे में नए मामले	42,982
कुल सक्रिय मामले	4,11,076
24 घंटे में टीकाकरण	53.76 लाख
कुल टीकाकरण	49.05 करोड़

गुरुवार सुबह 08 बजे तक कोरोना की स्थिति	
नए मामले	42,982
कुल मामले	3,18,12,114
सक्रिय मामले	4,11,076
मौतें (24 घंटे में)	533
कुल मौतें	4,26,290
ठीक होने की दर	97.37 फीसद
मृत्यु दर	1.34 फीसद
पाजिटिविटी दर	2.58 फीसद
सा. पाजिटिविटी दर	2.37 फीसद
जांचें (मंगलवार)	16,64,030
कुल जांचें (बुधवार)	47,48,93,363

जम्मू कश्मीर ने केंद्र से मांगी 60 लाख अतिरिक्त वैक्सीन की डोज

राज्य ब्यूरो, जम्मू : जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव डा. अरुण कुमार मेहता ने केंद्र सरकार से कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन की साठ लाख अतिरिक्त डोज उपलब्ध करवाने को कहा ताकि सभी लोगों का जल्द टीकाकरण हो सके। केंद्रीय गृह सचिव, अजय भल्ला के साथ वीसार को उच्चस्तरीय बैठक में उन्होंने यह मांग की। इस मौके पर सभी केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की गई। उन्होंने टेस्ट के अलावा संक्रमितों के संपर्क में आने वालों की पहचान करने और उनके उपचार की रणनीति का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने संक्रमण से बचाव के लिए सभी के टीकाकरण पर भी जोर दिया। बैठक में मुख्य सचिव डा. अरुण कुमार मेहता के अलावा अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग अटल डुल्लू मौजूद थे। गृह सचिव ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेशों ने पिछले कुछ सप्ताह में मामलों में लगातार गिरावट देखी है। पिछले दो सप्ताह में 4244 नए मामले और 54 मरीजों की मौत हुई है।

कोवैक्सीन ने हासिल की बड़ी उपलब्धि, हंगरी ने दिया जीएमपी प्रमाण पत्र

हैदराबाद, प्रेट्र : देश में निर्मित पहली कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। हंगरी ने कोवैक्सीन को गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जीएमपी) अनुपालन प्रमाण पत्र प्रदान किया है।

भारत बायोटेक ने गुरुवार को एक ट्वीट में बताया, 'हमें एक और बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। कोवैक्सीन को हंगरी ने जीएमपी प्रमाण पत्र प्रदान किया है। यूरोपीय नियामक की तरफ से भारत बायोटेक को मिला यह पहला ईयूडीआरएजीडीआरएमपी अनुपालन प्रमाण पत्र है।' ट्विटर पर साझा किए गए नोट में कहा गया है कि हंगरी के नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फार्मेसी एंड न्यूट्रीशन ने कोवैक्सीन के निर्माण के लिए जीएमपी प्रमाण पत्र प्रदान किया है। भारत बायोटेक ने कहा कि जीएमपी प्रमाण पत्र ईयूडीआरएजीडीएमपी के डाटाबेस में सूचीबद्ध कर दिया गया है। यह यूरोपीयन कम्युनिटी आफ मैन्युफैक्चरिंग आथराइजेशन एंड सर्टिफिकेट के जीएमपी संग्रह का एक रिकार्ड है। भारत बायोटेक ने कहा कि कंपनी दुनिया के अन्य देशों में वैक्सीन के आपातकालीन प्रयोग की इजाजत के लिए दस्तावेज जमा करने की तैयारी में है। कंपनी के अनुसार, 'इस अनुमोदन के साथ ही भारत बायोटेक ने वैश्विक गुणवत्ता मानक के अनुरूप वैक्सीन के निर्माण में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है।

चरणबद्ध और सतर्कता के साथ खोले जाएं स्कूल

नई दिल्ली, एएनआइ

अप्रैल-मई में आई कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद देश में महामारी पीड़ितों की संख्या लगातार कम हुई है। ऐसे में स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से खोला जा सकता है। लेकिन इसके लिए शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को कोविड से बचाव का टीका लगा होना अनिवार्य होना चाहिए। यह बात क्रिश्चियन मेडिकल कालेज, वेल्लोर में प्रोफेसर और देश की शीर्ष वायरोलाजिस्ट डा. गगनदीप कंग ने कही है। वह महामारी से बचाव की तैयारी के लिए सरकार के बनाए बोर्ड की उप प्रमुख भी हैं।

डा. कंग ने कहा, स्कूलों को खोलने में अब कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन इन्हें चरणबद्ध तरीके से और अच्छी तरह से सेनेटाइज करने के बाद खोला जाना चाहिए। स्कूलों का सेनेटाइजेशन नियमित तौर पर होना चाहिए। कक्षाओं को शिफ्टों में लगाना चाहिए। क्लास रूम में बच्चों के लिए फेस मास्क जरूरी होना चाहिए और उनके बीच शारीरिक दूरी के नियम का पालन भी होना चाहिए। शिक्षक और बाकी के स्टाफ को वैक्सीन लगी होनी चाहिए। जो बच्चे जुकाम-खांसी से पीड़ित हैं, उनकी और खास ध्यान दिए जाने की जरूरत होगी। उन्हें स्वस्थ होने तक स्कूल न आने की छूट दी जाए।

एक व्यक्ति को दी जा सकती दो तरह की वैक्सीन

डा. कंग ने कहा कि वैक्सीन की उपलब्धता में कमी की स्थिति में कोविड से बचाव के लिए एक व्यक्ति को दो तरह की वैक्सीन लगाई जा सकती है। पहली खुराक किसी वैक्सीन की और दूसरी खुराक अन्य वैक्सीन की। इसका कोई नुकसान नहीं है। अभी तक के जो नतीजे हैं उनके अनुसार इस प्रयोग से रोग प्रतिरोधक क्षमता और बेहतर हो सकती है। कई देशों में दोनों खुराकें में अलग-अलग वैक्सीन देने और एक ही खुराक में दो तरह की वैक्सीन मिलाकर देने पर प्रयोग चल रहे हैं। रूस की स्पूतनिक फाइव वैक्सीन को एस्ट्राजेनेका के साथ मिलाकर इस्तेमाल का प्रयोग हो रहा है।

वैरिएंट पर निर्भर होगा तीसरी लहर का असर: डा. कंग ने कहा, कोविड की तीसरी लहर आने की आशंका है। इसके असर को लेकर अभी संशय है। तीसरी लहर में संक्रमण की गंभीरता कोरोना वायरस के वैरिएंट पर निर्भर करेगी। अगर वह ज्यादा संक्रामक हुआ तो पीड़ितों की संख्या बढ़ सकती है।

भारतीय नस्ल के कुत्तों में भी है कोरोना को पहचानने की क्षमता

वैभव शर्मा, हिसार: भारतीय नस्ल के कुत्ते विदेशी कुत्तों से कमतर नहीं हैं। दक्षिण भारत में पाया जाने वाला चिप्पीपराई कुत्ता कोरोना वायरस को सूंघकर पता लगाने में सक्षम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ समय पहले अपने रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' में देसी नस्ल के इन कुत्तों पर ध्यान आकर्षित किया तो इधर ध्यान गया।

केंद्र सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आइसीएआर) को सरकार ने 15 करोड़ रुपये का शोध प्रोजेक्ट दिया है। प्रोजेक्ट में विज्ञानी देसी नस्ल के कुत्तों की विशेषताएं पता लगाने का काम तो करेंगे ही, साथ ही इन नस्लों का पंजीकरण भी कराएंगे। करनाल स्थित राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो के माध्यम से अभी तक तीन भारतीय नस्ल के कुत्तों की ब्रीड को पंजीकृत कराया गया है। इनमें राजपलयम, चिप्पीपराई आदि शामिल हैं। मगर देश की 13 नस्लें और बाकी हैं जिनकी खासियतें और उन्हें पहचान दिलानी जरूरी है। भारतीय नस्ल के कुत्तों की खासियत है कि इन्हें अच्छा भोजन न मिले फिर भी यह अपने आप को अच्छे तरीके से रख सकते हैं।

भारतीय छात्रा ने बनाया कोरोना वायरस को मारने वाला मास्क, गूगल ने सराहा

जागरण विशेष

दिगंतिका बसु के प्रयोग को गूगल आनलाइन म्यूजियम में मिला स्थान, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने भी की प्रशंसा

हृदयानंद गिरि • दुर्गापुर

कोरोना से बचाव के लिए देश-दुनिया में हो रहे प्रयोगों के बीच 12वीं की छात्रा दिगंतिका बसु का इनोवेशन खास है। बंगाल के पूर्व बर्द्धमान जिले के मेमारी की रहने वाली 17 वर्षीय छात्रा ने ऐसा मास्क बनाने का दावा किया है, जो न सिर्फ कोरोना वायरस को शरीर में जाने से रोकता है, बल्कि उसे बाहर ही नष्ट कर डालता है। सर्च इंजन गूगल ने इस मास्क को इनोवेशन कैटेगरी में अपने आनलाइन म्यूजियम में स्थान दिया है।

अभी तक बाजार में ऐसे मास्क ही उपलब्ध हैं जो हमारे मुंह और नाक को ढककर वायरस को भीतर जाने से रोकते हैं। दिगंतिका का मास्क वायरस को नष्ट भी करता है। इस मास्क को पहनने वाला व्यक्ति यदि पहले से कोरोना पीड़ित है तो सांस के जरिये बाहर आने वाले वायरस भी मास्क तक पहुंचते ही नष्ट हो जाएंगे।

इनोवेशन की हो रही सराहना: दिगंतिका एकमात्र भारतीय है, जिसके मास्क को विशिष्ट मानते हुए गूगल ने इनोवेशन कैटेगरी में अपने आनलाइन म्यूजियम में स्थान दिया है। दुनिया भर से केवल 10 इनोवेशन ही इसके लिए चुने जाते हैं। आनलाइन म्यूजियम में मास्क की तस्वीर लगाई गई है। गूगल ने दिगंतिका को भविष्य का विज्ञानी बताते हुए शुभकामना दी है। मास्क की प्रशंसा केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट आफ साइंस एंड टेक्नोलाजी के नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने भी की है। उसने ऐसे मास्क तैयार करने के लिए छात्रा से चर्चा भी की है।

तीन सौ रुपये से कम होगी कीमत: दिगंतिका बताती हैं कि ट्रायल के बाद जब मास्क बाजार में आएगा तो 300 रुपये से भी कम कीमत होगी। वह कहती हैं कि इंडिया इनोवेशन फाउंडेशन की प्रतियोगिता में अपना प्रोजेक्ट भेजा तो वहां सराहना हुई और पुरस्कार मिला।

> कोरोना को मारने वाला मास्क बनाकर दिगंतिका ने विद्यालय का नाम रोशन किया है। कोरोना वारियर्स व संक्रमितों के लिए यह बहुत अहम हो सकता है। मैं दिगंतिका के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं।
>
> सुब्रत चटर्जी, प्राचार्य, विद्यासागर मेमोरियल इंस्टीट्यूशन यूनिट दो, पूर्व बर्द्धमान

> दिगंतिका के बनाए मास्क की जानकारी मिली है। छात्रा को किसी प्रयोग के लिए लैब की जरूरत होगी तो हम मदद करेंगे।
>
> प्रो. राजीव बनर्जी, प्राचार्य, डा. बीसी राय इंजीनियरिंग कालेज, दुर्गापुर

पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से डा. एपीजे अब्दुल कलाम इग्नाइट अवार्ड लेती दिगंतिका बसु (फाइल फोटो) • सौ. स्वयं

राष्ट्रपति के हाथों भी पुरस्कृत

दिगंतिका का सपना भविष्य में विज्ञानी बनना है। जब वह कक्षा चार में थी तब स्कूल में साइंस प्रोजेक्ट के तहत मोबाइल की बैटरी को चार्ज करने का प्रोजेक्ट बनाया था। नौवीं कक्षा में उसने डस्ट कलेक्टिंग अटैचमेंट फार ड्रिल मशीन बनाई थी। इसके लिए उसे तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने डा. एपीजे अब्दुल कलाम इग्नाइट अवार्ड दिया था। कोरोना वायरस को मारने वाली वाटर गन भी बनाई थी। रीजनल साइंस सेंटर भोपाल ने इस इनोवेशन के लिए वर्ष 2020 में दिगंतिका बसु को सम्मानित किया था।

इस तरह काम करता है यह मास्क

मास्क में तीन चैंबर हैं। पहले से धूल कण रुकेंगे। दूसरे व तीसरे चैंबर में विशेष रसायन भरा है। मास्क में लगे एक छोटे निगेटिव आयन जेनरेटर में धूलकणों को रोककर मास्क के मुख्य हिस्से तक हवा पहुंचाने की व्यवस्था है। मास्क में दो छोटे चैंबर हैं, जिसमें रखे रसायन या साबुन-पानी के मिश्रण में वायरस नष्ट हो जाएगा। सांस लेते और छोड़ते समय हवा दोनों चैंबरों से होकर गुजरेगी और वायरस मुक्त हो जाएगी। अगर मास्क को कोरोना संक्रमित पहनता है तो सांस के जरिये बाहर निकलने वाली हवा में मिश्रित वायरस दूसरे वाले चैंबर के तरल पदार्थ में नष्ट हो जाएगा। ऐसे में बाहर छोड़ी जाने वाली सांस भी वायरस रहित होगी, जिससे दूसरों के संक्रमित होने का खतरा भी नहीं रहेगा।

इस खबर को विस्तार से पढ़ने के लिए स्कैन करें

'टीके की दोनों खुराक लेने वालों को निर्बाध यात्रा की छूट पर हो विचार'

मुंबई, प्रेट्र : बांबे हाई कोर्ट ने गुरुवार को कोविड-19 महामारी के बीच आम जनजीवन को पटरी पर लौटाने के पहले चरण के बारे में अहम सुझाव दिए हैं। अदालत ने कहा कि सरकार वैक्सीन की दोनों खुराक ले चुके लोगों की पहचान कर उन्हें अन्य लोगों से अलग करने और 'कामन कार्ड' देने पर विचार करे, ताकि वे बिना रोक-टोक यात्रा व कोविड पूर्व गतिविधियां कर सकें।

चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता व जस्टिस जीएस कुलकर्णी की पीठ ने कहा कि महाराष्ट्र व केंद्र सरकार एक 'कामन कार्ड' जारी करने पर जरूर विचार करें। पीठ मुंबई की लोकल ट्रेनों में यात्रा करने के लिए वकीलों, न्यायिक क्लर्कों व कर्मचारियों, पत्रकारों और वैक्सीन की दोनों खुराक लगवा चुके अन्य लोगों को अनुमति देने के लिए दाखिल जनहित याचिकाओं के एक समूह पर सुनवाई कर रही थी।

जम्मू-कश्मीर में बदलाव के 2 साल

370 से आजादी

5 अगस्त 2019

73 वां और 74वां संविधान संशोधन लागू होने से लोकतंत्र की नींव मजबूत हुई

513 करोड़ रुपये मौजूदा वर्ष के बजट में केवल खेलों के लिए रखे गए हैं

50 हजार करोड़ के निवेश से औद्योगिक क्षेत्र में आएगी क्रांति

एक साल की खास उपलब्धियां

- नई फिल्म नीति से जम्मू कश्मीर को फिल्म शूटिंग का फिर से केंद्र बनाने की योजना। सिंगल विंडो से सभी प्रोजेक्ट मंजूर होंगे। टेलेंट पूल बनेगा और फिल्म निर्माताओं को आर्थिक सहयोग के साथ विश्वस्तरीय सुविधाएं प्रदान करने की योजना है।
- खेती और बागवानी के विकास के साथ किसानों की आय दोगुनी करने के कदम उठाए गए हैं। कश्मीरी केसर को जीआइ टैग मिलने से यहां के केसर को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली है।
- एक साल में 50 नए कालेज और कालेजों में 20 हजार अतिरिक्त सीट जोड़ी गई हैं। इसके अलावा फाउंडेशन कोर्स और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
- युवाओं को मुख्यधारा से जोड़े रखने के लिए मिशन यूथ को गति दी जा रही है। उन्हें व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रदेश सरकार मदद दे रही है।
- खेल गतिविधियों के विकास के लिए पर्याप्त सुविधाएं मुहैया करवाते हुए छह लाख युवाओं को खेलों से जोड़ा जा रहा है।
- नई उद्योग नीति की घोषणा से जम्मू कश्मीर में 50 हजार करोड़ का निवेश जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। 20 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव पाइप लाइन में हैं और ढाई हजार करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी दी जा चुकी है।

- उद्योगों के लिए 3375 एकड़ का लैंड बैंक तैयार किया गया है ताकि नए उद्योग के लिए तुरंत भूमि का आवंटन किया जा सके। 2031 तक निवेश पर उद्योगों को विशेष अनुदान की घोषणा की गई है।

श्रीनगर में वीरवार को जम्मू कश्मीर की पहली फिल्म नीति के शुभारंभ के मौके पर दीप प्रज्वलित करते उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। सौजन्य : सूचना विभाग

बहुत कुछ बदला, पर अभी और कसनी होगी लगाम

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन और 370 से आजादी के बाद जम्मू कश्मीर में हालात तेजी से बदले और अलगाववादी तत्वों पर लगाम लगी। आज नए कश्मीर का उदय हो रहा है। निश्चित तौर पर 370 से आजादी ने हालात बदल दिए पर यह भी तय है कि वास्तव में केंद्र सरकार और राज्य प्रशासन ने अति सक्रियता दिखाते हुए कड़े कदम न उठाए होते तो फिर से हिंसक झड़पों और प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू होने से इन्कार नहीं किया जा सकता था। अभी भी चुनौती युवा शक्ति को सही राह पर लेकर जाते हुए उसके सकारात्मक इस्तेमाल की है। रोजगार के अवसर बढ़ाने के साथ-साथ युवाओं को अलगाववादी विचारधारा के भ्रमजाल से बचाने की चुनौती भी बड़ी है।

इस दौर में पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक से लेकर पहले उपराज्यपाल जीसी मुर्मू के बाद वर्तमान में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बदलाव की कोशिशों को निरंतर आग बढ़ाने का प्रयास किया। मनोज सिन्हा एक साल का कार्यकाल पूरा कर रहे हैं और यह सही मायनों में कई बदलाव का कार्यकाल रहा। पुराने 250 कानून खत्म हुए और 800 से अधिक केंद्रीय कानून जम्मू कश्मीर में लागू हुए। तकनीक के इस्तेमाल से पारदर्शी प्रशासन की राह पर हम तेजी से कदम बढ़ाने में सफल रहे। खेल से लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े बदलाव से आमजन बदले हालात को साफ महसूस कर रहा है।

नए दौर में नई सियासत की ओर जम्मू कश्मीर कदम बढ़ा रहा है पर वास्तव में अभी भी खानदानी सियासत का कोई विकल्प मौजूद नहीं है। यही वजह है कि जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कश्मीर के नेताओं संग बैठक में कश्मीर की आवाज शुरू करने का प्रयास किया गया। बेलगाम नौकरशाही और जर्जर प्रशासनिक ढांचे को पूरी तरह से पटरी पर लाना अभी भी चुनौती है। पिछली सरकारों के चहेते रहे नौकरशाहों की नकेल कसे बिना जवाबदेह शासन संभव नहीं हो सकता। आने वाले दिनों में यह बदलाव नजर आएगा।

जम्मू-कश्मीर से अनु. 370 हटाए जाने की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर गुरुवार को श्रीनगर में भाजपा के वरिष्ठ नेता तरुण चुग और समर्थकों ने केक काटकर खुशी मनाई। एएनआइ

अनुच्छेद 370 हटने के दो साल बाद जम्मू में जश्न का माहौल रहा। इनमें काफी संख्या में युवतियां भी शामिल रहीं। जागरण

हिंसक प्रदर्शनों का दौर थमा

वर्ष 2008 से 2018 तक कश्मीर के हालात अत्यंत उथल-पुथल वाले रहे हैं। वर्ष 2008, 2009, 2010 और 2016 में यहां चार बार सिलसिलेवार हिंसक प्रदर्शनों का दौर चला है। मार्च 2015 में पीडीपी के सत्ता संभालने के बाद वादी में जगह जगह तलाशी अभियानों या मुठभेड़ों के दौरान सुनियोजित हिंसक झड़पें और पथराव की घटनाएं भी तेज हो गई। सुरक्षाबलों की चुनौतियां बढ़ने लगी थीं पर अब वह आज आतंकी और उनके कमांडर खौफ में पहाड़ों में छिप रहे हैं।

जम्मू-कश्मीर ने मनाया 370 हटाने का जश्न

जेएनएन, श्रीनगर

जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के दो साल पूरे होने पर गुरुवार को जम्मू कश्मीर में तिरंगा रैलियां निकालीं गईं। दक्षिण कश्मीर में भी लोगों में खासा उत्साह दिखा। जम्मू तिरंगों से पटा रखा। जगह-जगह तिरंगा रैलियां, मैराथन और खुशी में मिठाइयां भी बांटी गईं। वहीं श्रीनगर के लालचौक समेत कई जगहों पर बंद भी रहा। कश्मीर में किसी जगह प्रशासनिक पाबंदी नहीं थी और न रास्ता बंद किया गया था। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में भाजपा नेता रूमैसा रफीक के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रध्वज लेकर रैली निकाली। यह रैली खन्नाबल चौक में सपन्न हुई। इसके अलावा कई जगह राष्ट्रध्वज फहराए गए।

गुपकार ने फिर अलापा 'बहाली' का राग

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

पीपुल्स एलायंस फार गुपकार डिक्लेरेशन (पीएजीडी) ने अनुच्छेद 370 की बहाली का राग फिर अलापना शुरू कर दिया है। पीएजीडी जम्मू कश्मीर में पांच अगस्त, 2019 से पूर्व संवैधानिक स्थिति की बहाली और अनुच्छेद 370 को वापस पाने के लिए संसद व देश की जनता का द्वार भी खटखटाएगा। यह फैसला गुरुवार सुबह नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डा. फारूक अब्दुल्ला के आवास पर हुई पीएजीडी के घटक दलों के वरिष्ठ नेताओं की बैठक में लिया।

सुबह करीब 11 बजे डा. फारूक अब्दुल्ला के निवास पर पीएजीडी की उपाध्यक्ष महबूबा मुफ्ती और संयोजक मोहम्मद यूसुफ तारीगामी पहुंचे। अवामी नेशनल कांफ्रेंस के कार्यवाहक अध्यक्ष मुजफ्फर शाह भी कुछ ही देर में अपने मामा फारूक के घर पहुंच गए। करीब दो घंटे तक चली बैठक में मौजूदा हालात और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के खिलाफ अदालत में दायर याचिकाओं की मौजूदा स्थिति पर विचार विमर्श हुआ। बैठक में तय किया कि पीएजीडी प्रत्येक नागरिक के दरवाजे पर दस्तक देगा। --

370 हटने की वर्षगांठ पर सड़क पर उतरीं महबूबाः पीडीपी अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती इसके खिलाफ सड़क पर उतर आईं। इसे मातम का दिन बताते हुए जुलूस का नेतृत्व किया।

जम्मू कश्मीर में दुनियाभर के फिल्म निर्माताओं को न्योता

रजिया नूर, श्रीनगर

कश्मीर की कली, सिलसिला, बेमिसाल, बेताब, जब-जब फूल खिले और जब तक है जान। इसी तरह कई सुपर हिट फिल्मों की सफलता का एक बड़ा कारण इनका घाटी के अद्भुत नजारों के बीच फिल्माया जाना भी माना जाता है। गुरुवार को सार्वजनिक की गई फिल्म नीति से लोगों को नई उम्मीदें जगी हैं।

कश्मीर की बेमिसाल सुंदरता ने हमेशा बालीवुड को अपनी तरफ खींचा है। यहां के पहाड़, चिनार के लंबे-लंबे पेड़, बर्फ से ढकी चोटियां, डल झील समेत अन्य लोकेशन पर बालीवुड शुरू से फिदा रहा है। घाटी के लोग भी हिंदी सिनेमा के दीवाने हैं।

आतंकवाद के दौर में भी जारी रहा नाता : 1989 में घाटी में फूटे आतंकवाद के दौर ने बालीवुड को घाटी से दूर कर दिया, लेकिन यहां के फिल्म प्रेमियों ने बालीवुड के साथ नाता बनाए रखा और सिनेमाघर बंद रहने के बावजूद वीसीआर, वीसीडी व केबल पर फिल्मों का आनंद उठाते रहे। बीच-बीच में फिल्मों की शूटिंग जारी रही।

फिल्म व्यवसाय पूरी तरह गतिशील होने की उम्मीद : अनुच्छेद 370 हटने के बाद घाटी की स्थिति में सुधार आने के साथ ही बालीवुड ने फिर यहां का रुख किया और यहां की फिजाओं में फिर से रोल, कैमरा और एक्शन की आवाज गूंजने लगी। अब जम्मू कश्मीर के लिए फिल्म नीति जारी होने के बाद उम्मीद की जा रही है कि प्रदेश में फिल्म व्यवसाय पूरी तरह गतिशील होगा।

पेशेवर लोगों को मिले प्रमोट करने की जिम्मेदारी : हैदर, लैला मजनू, बैंड बाजा बारात, हरुद, बोस्ट कार्ड आदि में अभिनय का लोहा मनवा चुके स्थानीय अभिनेता अख्तर हुसैनी ने कहा, हम इस फिल्म नीति का स्वागत करते हैं। अच्छी शुरुआत है। इससे कश्मीर और बालीवुड के बीच रिश्ता और मजबूत होगा। साथ ही यहां अभिनय, फिल्म निर्माण, निर्देशन, कोरियोग्राफी आदि में रुचि रखने वाले लोगों के साथ अन्य बेरोजगार लोगों को भी फायदा मिलेगा। लेकिन पालिसी तब ही सफल होगी जब सही लोगों के हाथों में दी जाएगी। अख्तर ने कहा, पेशेवर लोगों का पैनल बनाकर प्रमोट करने की जिम्मेदारी सौंपी जाए।

नई शुरुआत

स्थानीय कलाकारों को मिले मौका

फिल्म बजरंगी भाई जान, फेनटम, केसरी, जोली एलएलबी-2, केदामथ जैसी फिल्मों में अपने अभिनय की धाक जमाने वाले अभिनेता सरवर ने कहा कि नई नीति से फिल्म व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा। सरवर ने कहा, मेरा सुझाव है कि शुरुआत में स्थानीय कलाकारों, फिल्म निर्माताओं व निर्देशकों को इसमें शामिल किया जाए।

फ्यूचर ग्रुप मामले में अमेजन की याचिका पर फैसला आज

नई दिल्ली : रिटेल कारोबार के लिए फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस के सौदे के खिलाफ अमेजन की याचिका में सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को फैसला आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट इस संबंध में फैसला देगा कि 24 हजार करोड़ से ज्यादा के इस सौदे को रोकने का सिंगापुर इमरजेंसी आर्बिट्रेटर का फैसला भारतीय कानून के तहत वैध है या नहीं। कोर्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, जस्टिस आरएफ नरीमन और बीआर गवई की पीठ सुबह साढ़े दस इस मामले में फैसला सुनाएगी। (प्रेट्र)

रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को खत्म करने के लिए लाए गए विधेयक से निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा। यह दुखती रग थी और इसीलिए सरकार ने यह विधेयक लाने का फैसला किया।

— तरुण बजाज, राजस्व सचिव

सेंसेक्स	निफ्टी	सोना प्रति दस ग्राम	चांदी प्रति किलोग्राम	डॉलर	क्रूड (ब्रेंट) प्रति बैरल
54,492.84 ▲ 123.07	16,294.60 ▲ 35.80	₹46,680 ▼ ₹312	₹65,889 ▼ ₹1,037	₹74.17 ▼ ₹0.02	$ 70.89

रिलायंस बीपी मोबिलिटी और स्विगी में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए समझौता

जाब्यू, नई दिल्ली : रिलायंस बीपी मोबिलिटी लिमिटेड और फूड डिलीवरी एप स्विगी ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत डिलीवरी के लिए स्विगी के वाहनों को इलेक्ट्रिक किया जाएगा। इसके लिए बैट्री स्वैपिंग की जरूरत को देखते हुए रिलायंस बीपी मोबिलिटी बैट्री स्वैपिंग स्टेशन भी लगाएगी।

इस साझेदारी का उद्देश्य एक नए बिजनेस माडल के माध्यम से डिलीवरी वाहनों के बेड़े को वातावरण के अनुकूल और किफायती बनाना है। स्विगी की सहायता से विभिन्न स्थानों पर जियो-बीपी बैट्री स्वैपिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। स्विगी डिलीवरी पार्टनर्स और स्विगी स्टाफ को रिलायंस बीपी मोबिलिटी बैट्री स्वैपिंग से संबंधित तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण देगी। रिलायंस बीपी मोबिलिटी लिमिटेड के सीईओ हरीश सी मेहता ने कहा, 'हम मजबूत और टिकाऊ बुनियादी ढांचा स्थापित कर रहे हैं जिसमें ईवी चार्जिंग हब और बैट्री स्वैपिंग स्टेशन शामिल हैं।'

महंगाई के बावजूद विकास दर पर बना रहेगा रिजर्व बैंक का फोकस

आज मौद्रिक नीति समीक्षा जारी करेंगे आरबीआइ गवर्नर शक्तिकांत दास

तैयारी

- अगले छह महीने ब्याज दरों को स्थिर रखने पर होगा जोर
- जून की समीक्षा में भी नीतिगत दरों को स्थिर रखा था केंद्रीय बैंक ने
- बैंकिंग व्यवस्था में तरलता की स्थिति काफी अच्छी है

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के सदस्य फिर उसी यक्ष प्रश्न का उत्तर तलाशने की कोशिश कर रहे हैं कि महंगाई थामने को ब्याज दरों को बढ़ाया जाए या फिर आर्थिक मंदी को दूर करने के लिए ब्याज दरों को नरम ही रखा जाए। दो दिनों से मंथन चल रहा है। इस बारे में बनी सहमति की घोषणा आरबीआइ गवर्नर शक्तिकांत दास शुक्रवार को करेंगे। आर्थिक विशेषज्ञों व शोध एजेंसियों का कहना है कि महंगाई के तेवर देखने के बावजूद एमपीसी की तरफ से कम से कम अगले पांच-छह महीनों तक ब्याज दरों को स्थिर रखने की ही कोशिश होगी, ताकि कोरोना की लहर से अर्थव्यवस्था को उबारने की कोशिशों को कोई धक्का नहीं लगे।

गुरुवार को यस बैंक की तरफ से जारी आर्थिक रिपोर्ट में कहा गया है कि जून, 2021 की एमपीसी की बैठक के बाद महंगाई की स्थिति बिगड़ी है। हालांकि हमारा अनुमान है कि अगले कुछ महीनों में यह कम होने लगेगी। अब अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी कीमतों में स्थिरता आ गई है और आयातित वस्तुओं के कारण महंगाई का खतरा काफी कम हो गया है। वैसे बाजार (बैंकिंग व्यवस्था) में तरलता (फंड की उपलब्धता) की स्थिति काफी अच्छी है। तरलता को कम करने का कोई भी कदम काफी सोच समझकर उठाना होगा कि कहीं इसका उलटा असर न हो। कोरोना की दूसरी लहर के बाद आर्थिक रिकवरी का दौर अभी चल रहा है। ऐसे में उम्मीद है कि आरबीआइ आर्थिक विकास दर को बढ़ाने में मदद करेगा और ब्याज दरों को लेकर नरम रवैया अपनाएगा।

जून, 2021 की समीक्षा में अल्पकालिक अवधि के कर्ज की दरों को प्रभावित करने वाली वैधानिक दरों को आरबीआइ ने स्थिर रखा था। रेपो रेट चार फीसद पर है। हाल के दिनों में अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक समेत कई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक एजेंसियों ने 2021-22 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर के लक्ष्य को घटा दिया है। दो माह पहले की समीक्षा में आरबीआइ गवर्नर ने वादा किया था कि अगर जरूरत पड़ी तो ब्याज दरों को नीचे लाने का भी कदम उठाया जा सकता है। श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस के एमडी व सीईओ वाईएस चक्रवर्ती का कहना है कि मार्च, 2021 के बाद से अधिकांश सेक्टर में मांग की स्थिति में बहुत सुधार नहीं हुआ है। अभी ब्याज दरों को कम रखना जरूरी है ताकि दोपहिया वाहनों व दूसरे उद्योगों में मांग बढ़ाने में मदद मिले।

सरकार ने बल्क ड्रग पार्क पर अब तक नहीं बढ़ाए कदम

क्रियान्वयन में देरी

- तीन बल्क ड्रग पार्क और चार मेडिकल उपकरण पार्क शुरू करने की हुई थी घोषणा
- निर्माण के लिए राज्यों का नहीं हो पाया है चयन, 2023 से शुरू होना है उत्पादन

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : देश में दवाओं के कच्चे माल यानी बल्क ड्रग के उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए सरकार ने पिछले साल तीन बल्क ड्रग पार्क शुरू करने की घोषणा की थी, लेकिन अब तक इन पर कोई फैसला नहीं हो पाया है। तीन पार्क के लिए 3000 करोड़ की वित्तीय सहायता दी जानी है। बल्क ड्रग के मामले में भारत काफी हद तक आयात पर निर्भर है। तीन बल्क ड्रग पार्क के साथ चार मेडिकल उपकरण पार्क के लिए भी 4000 करोड़ की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की गई थी।

दवा उद्यमियों ने बताया कि इस स्कीम के तहत वर्ष 2023 से बल्क ड्रग का उत्पादन शुरू करने का लक्ष्य है, अब तक पार्क किन-किन राज्यों में बनेंगे, इसे लेकर ही अंतिम फैसला नहीं हो पाया है। पार्क के निर्माण के लिए राज्यों के चयन के बाद उसे विकसित करने में कम से कम डेढ़ से दो साल का समय लग जाएगा। इस स्कीम की अवधि छह साल की है। बल्क ड्रग पार्क के निर्माण के लिए सरकार ने राज्यों से आवेदन मांगे थे। जो राज्य पार्क लगाने के लिए अधिक से अधिक सुविधा देगा, वहां में पार्क लगाने के लिए केंद्र की तरफ से वित्तीय सहायता दी जाएगी। सुविधाओं की श्रेणी को लेकर केंद्र की तरफ से सूची बनाई गई है।

सूत्रों के मुताबिक, बल्क ड्रग और मेडिकल उपकरण पार्क के लिए 17 राज्यों ने केंद्र के समक्ष अपनी दिलचस्पी दिखाई है। इनमें हिमाचल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा मानी जा रही है।

उद्यमियों ने बताया कि उन्होंने सरकार से पहले से काम कर रही बल्क ड्रग इकाइयों को ही इस स्कीम के तहत आर्थिक सहायता देने की मांग की थी। ऐसा होने पर पहले से काम कर रही या बंद पड़ी बल्क ड्रग इकाइयों में उत्पादन का काम आरंभ हो जाता। पिछले साल कोरोना महामारी के दौरान चीन से बल्क ड्रग की सप्लाई चेन प्रभावित होने पर देश में ही बल्क ड्रग के उत्पादन को बढ़ाने के प्रयास शुरू किए गए, जिसके तहत फार्मा पार्क बनाने का फैसला किया गया था।

शेयर बाजारों में नए शिखर का सफर जारी

मुंबई, प्रेट्र : घरेलू शेयर बाजारों में गुरुवार को भी नई ऊंचाई का सफर जारी रहा। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समीक्षा से पहले आइटी, टेलीकाम और एफएमसीजी स्टाक्स में तेजी रही। हालांकि मुनाफावसूली से बाजार बढ़ी बढ़त से चूक गए।

बीएसई का सेंसेक्स 123.07 अंक चढ़कर 54,492.84 के नए शिखर पर बंद हुआ। दिन के कारोबार में यह 54,717.24 तक चढ़ गया था। बाद में मुनाफावसूली के कारण बाजार ने कुछ बढ़त गंवा दी। एनएसई का निफ्टी 35.80 अंक बढ़कर 16,294.60 के सर्वोच्च स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स में भारती एयरटेल ने सबसे ज्यादा 4.30 फीसद की बढ़त हासिल की। कर्ज में डूबी वोडाफोन आइडिया के चेयरमैन पद से कुमार मंगलम बिड़ला के हटने के बाद से कंपनी के शेयरों में तेज गिरावट आई है। इसका फायदा टेलीकाम सेक्टर की अन्य कंपनियों को हुआ। इनके अलावा, आइटीसी, टेक महिंद्रा, टाटा स्टील, एचसीएल टेक और एचडीएफसी के शेयर भी बढ़त में रहे। दूसरी ओर, एसबीआइ, इंडसइंड बैंक, बजाज फाइनेंस, आइसीआइसीआइ बैंक, बजाज फिनसर्व और अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयर गिरावट में बंद हुए। रिलायंस सिक्युरिटीज के स्ट्रेटजी हेड बिनोद मोदी ने कहा, 'आइटी और मेटल ने बाजार को नई ऊंचाई पर पहुंचने में मदद की।

एफएमसीजी स्टाक्स और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी इस तेजी में योगदान दिया। हालांकि मिडकैप और स्मालकैप में मुनाफावसूली भी साफ नजर आई।' जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के रिसर्च हेड विनोद नायर ने कहा, 'रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समीक्षा से पहले बैंकिंग शेयरों में दबाव देखा गया।' मौद्रिक नीति समीक्षा शुक्रवार को जारी होगी।

आर्थिक सुधारों पर नहीं ठिठकेंगे सरकार के कदम

जयप्रकाश रंजन • नई दिल्ली

अहम फैसले

- कानून संशोधन कर वोडाफोन, केयर्न इनर्जी को राहत देने का निर्णय
- साधारण बीमा कंपनियों के निजीकरण का विधेयक पारित
- सरकारी तेल कंपनियों में सौ फीसद एफडीआइ को मंजूरी

पुराने मामलों पर कर यानी रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स मामले के पिछले एक दशक से चल रहे विवाद को विराम देकर मोदी सरकार ने फिर दिखाया है कि बड़े आर्थिक सुधारवादी कदम उठाने का राजनीतिक माद्दा वह खूब रखती है। पिछले एक पखवाड़े में विपक्ष की लामबंदी के बीच सरकार ने आर्थिक सुधारों की गति को बढ़ाया है।

रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स मामले में जो कानूनी संशोधन प्रस्तावित किया गया है, उसे भी विपक्ष निश्चित तौर पर सरकार पर हमले के लिए इस्तेमाल करेगा, लेकिन यह फैसला इसलिए किया गया है कि कोरोना के बाद बदले माहौल में जब वैश्विक कंपनियां निवेश के लिए भारत की तरफ देखें तो उनके सामने टैक्स को लेकर कोई अनिश्चितता न हो। वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा भी है कि विदेशी निवेश को आकर्षित करने को लेकर भारत अभी बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर है।

सरकार की तरफ से संकेत है कि आने वाले दिनों में आर्थिक सुधारों और इकोनामी को मजबूत बनाने को लेकर कुछ और बड़े फैसले किए जाएंगे। दो दिन पहले ही संसद ने सरकार की तरफ से प्रस्तावित द जनरल इंश्योरेंस बिजनेस (संशोधन) विधेयक, 2021 को मंजूरी दी है, जो अब साधारण बीमा कंपनियों में सरकार को अपनी हिस्सेदारी 51 फीसद से भी नीचे ले जाने की इजाजत देती है। आम बजट 2021-22 में दो सरकारी बैंकों के साथ एक साधारण बीमा कंपनी के निजीकरण का एलान किया गया था।

अभी तक के कानून के मुताबिक साधारण बीमा कंपनियों में सरकारी हिस्सेदारी 51 फीसद से नीचे नहीं की जा सकती थी। इसके कुछ ही दिन पहले कैबिनेट ने सरकारी क्षेत्र की तेल व गैस कंपनियों में सौ फीसद विदेशी निवेश की छूट देने का फैसला किया है।

यह फैसला पहली बार देश की किसी सरकारी कंपनी को पूरी तरह से विदेशी कंपनी को बेचने का रास्ता साफ करेगा। सरकार चालू वित्त वर्ष में भारत पेट्रोलियम (बीपीसीएल) का विनिवेश करना चाहती है। इस फैसले से बीपीसीएल को पूरी तरह से किसी विदेशी एनर्जी कंपनी को बेचा जा सकेगा।

वित्त मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स विवाद को हमेशा के लिए विराम देने का कदम भारत को दुनिया के बेहतरीन निजी निवेश ठिकानों के तौर पर स्थापित करने की दिशा में अहम है। इसे 2019-20 में कारपोरेट टैक्स की दर को घटाकर 25 फीसद करने के फैसले के अगले कदम के तौर पर देखा जाना चाहिए।

कोरोना महामारी के बाद दुनिया में नई वैश्विक सप्लाई व्यवस्था बनती नजर आ रही है। इससे संभावनाओं के नए द्वार खुलेंगे। इस नई व्यवस्था में कई बड़ी विदेशी कंपनियां मौजूदा देशों को छोड़कर अन्य आकर्षक निवेश स्थलों की खोज कर रही हैं। अपने विशाल बाजार व प्रशिक्षित श्रम की वजह से भारत इन कंपनियों का पसंदीदा स्थल बन सकता है। कंपनियों के समक्ष यहां कर व्यवस्था में अनिश्चितता का सवाल नहीं होना चाहिए। भारत की प्रतिस्पर्धा सिर्फ एशियाई व लैटिन अमेरिकी देशों से नहीं है। अमेरिका व कुछ यूरोपीय देश भी फिर से मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की रणनीति अपना रहे हैं। 2020-21 में भारत में 81.32 अरब डालर का विदेशी निवेश आया था, जो 2019-20 के मुकाबले 10 फीसद ज्यादा था।

अधिक खर्च वाली नीतियों पर ध्यान दे केंद्र : अभिजीत बनर्जी

सलाह

- यूरोप और अमेरिका जैसी अर्थव्यवस्थाओं की तरह नीतियां अपनाने की जरूरत
- महामारी के कारण बने दबाव के बीच घाटे को काबू करने पर विचार जरूरी नहीं

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी ने गुरुवार को कहा कि केंद्र सरकार को घाटे पर काबू पाने की अधिक चिंता किए बिना यूरोप और अमेरिका जैसी अन्य अर्थव्यवस्थाओं की तरह अधिक खर्च वाली नीतियों पर ध्यान देना चाहिए। बंगाल के वैश्विक सलाहकार बोर्ड (जीएबी) के प्रमुख बनर्जी ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत की।

उन्होंने कहा, राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, सीधे देश की अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार से संबंधित है। बनर्जी ने केंद्र द्वारा पिछले साल समय-समय पर सेस में बढ़ोतरी पर कहा, सरकार के सामने राजकोषीय समस्या है और उसे खुलकर खर्च करने वाली नीतियों की तुलना में बजट को संतुलित करने पर अधिक भरोसा हो सकता है। सरकार अपने पास मौजूद एक उपाय का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है क्योंकि अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी होने से कर संग्रह गिरा है। वह इसका इस्तेमाल बजट को संतुलित करने को कर रही है। लेकिन यह वह दिशा नहीं है, जो सरकार को नहीं लेनी चाहिए। उन्होंने कहा, 'सरकार को अधिक खुलकर खर्च करना चाहिए। मुझे लगता है कि केंद्र वह करने के लिए तैयार नहीं है, जो अमेरिका या यूरोपीय अर्थव्यवस्थाएं कर रही हैं- नोट छापना और खर्च करना। वर्तमान संदर्भ में यह एक बेहतर नीति होती।'

राष्ट्रीय फलक

फेमा के उल्लंघन पर फ्लिपकार्ट को 10,600 करोड़ का नोटिस

> हम भारतीय कानूनों का पालन करते हैं, ईडी के साथ सहयोग करेंगे : फ्लिपकार्ट

नई दिल्ली, प्रेट्र : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विदेशी मुद्रा कानून के कथित उल्लंघन के लिए ई-कामर्स कंपनी फ्लिपकार्ट और उसके प्रमोटरों को करीब 10,600 करोड़ रुपये का कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) की विभिन्न धाराओं के तहत पिछले महीने 10 लोगों को नोटिस जारी किया गया था, जिनमें फ्लिपकार्ट, उसके संस्थापक सचिन बंसल और बिन्नी बंसल शामिल हैं। सूत्रों ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद नोटिस जारी किया गया और कंपनी पर लगे आरोपों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) नियमों का उल्लंघन और बहु-ब्रांड खुदरा को विनियमित करना शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि वालमार्ट के स्वामित्व वाली कंपनी और उसके अधिकारी अब न्यायिक फैसले का सामना करेंगे। एजेंसी के चेन्नई स्थित निदेशक रैंक के अधिकारी इस कार्यवाही का संचालन करेंगे। उधर फ्लिपकार्ट ने कहा है कि कंपनी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) नियमों सहित भारतीय कानूनों का अनुपालन करती है और फेमा के कथित उल्लंघन को लेकर भेजे गए नोटिस पर प्रवर्तन निदेशालय के साथ सहयोग करेगी।

सूत्रों ने गुरुवार को कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने फ्लिपकार्ट और उसके प्रवर्तकों को विदेशी मुद्रा कानून के कथित उल्लंघन के लिए 10,600 करोड़ रुपये का कारण बताओ नोटिस जारी किया है। संपर्क करने पर फ्लिपकार्ट ने कहा कि वह एफडीआइ नियमों सहित भारतीय कानूनों और विनियमों का अनुपालन करती है। ई-कामर्स कंपनी ने कहा कि अधिकारी नोटिस के अनुसार 2009-2015 की अवधि से संबंधित मामले की जांच करेंगे। कंपनी के संस्थापकों से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है।

अंटीलिया मामले में कोर्ट ने वाझे को जमानत देने से किया इन्कार

मुंबई, प्रेट्र : मशहूर उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर (अंटीलिया) के पास विस्फोटक लदी कार खड़ी किए जाने के मामले में विशेष अदालत ने गुरुवार को बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाझे की जमानत के लिए दाखिल अर्जी खारिज कर दी।

अदालत ने मामले की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) को आरोप पत्र दाखिल करने के लिए और एक महीने की मोहलत दी है। इससे पहले नौ जून को कोर्ट ने एनआइए को आरोप पत्र दाखिल करने के लिए दो महीने की मोहलत दी थी। केंद्रीय एजेंसी ने यह कहते हुए और एक महीने की मोहलत मांगी थी कि मामले की जांच जारी है। दूसरी तरफ, वाझे ने जमानत की मांग करते हुए कहा था कि जांच एजेंसी तय समय सीमा में आरोप पत्र दाखिल करने में विफल रही है, इसलिए वह मुक्त किए जाने का पात्र है। विशेष एनआइए अदालत ने यह कहते हुए वाझे की याचिका खारिज कर दी कि उसमें कोई दम नहीं है। अदालत उसकी एक ऐसी ही याचिका जून में भी खारिज कर चुकी है।

पोर्न वीडियो मामले में राज कुंद्रा की जमानत अर्जी खारिज

मुंबई, एएनआइ : मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पोर्न वीडियो मामले में बुधवार को अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति व कारोबारी राज कुंद्रा तथा सहयोगी रयान थोर्पे की जमानत अर्जियां खारिज कर दीं। अदालत ने कहा कि आरोपितों को छोड़े जाने से जांच बाधित हो सकती है और कथित अपराध समाज के लिए घातक है। समाचार एजेंसी प्रेट्र के अनुसार, कुंद्रा व थोर्पे ने गुरुवार को सत्र अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की है। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सोनाली अग्रवाल ने अभियोजन पक्ष को 10 अगस्त तक जवाब दाखिल करने को कहा है।

अदालत ने अपने आदेश में कहा, 'किसी भी मामले में जमानत देने अथवा इन्कार करने का आधार अपराध की प्रकृति और उसकी गंभीरता होती है। कथित अपराध बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित करता है।

देवर-जेठ के नाम जमीन नहीं की तो लगाया 40 लाख रुपये जुर्माना

> बेटी के घर शरण लेने पर 80 वर्षीय महिला को समाज ने किया बहिष्कृत
>
> खाप पंचायत की शिकायत लेकर भीलवाड़ा पुलिस थाना पहुंची बुजुर्ग

संवाद सूत्र, उदयपुर

राजस्थान में भीलवाड़ा जिले के करौईखेड़ा गांव में देवर व जेठ के नाम जमीन नहीं करने पर खाप पंचायत ने अस्सी साल की बुजुर्ग झमकू देवी पर चालीस लाख रुपये जुर्माना लगा दिया और उन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया। इसके बाद झमकू देवी ने अपनी बेटी के घर शरण ली तो उसे भी समाज से बहिष्कृत कर दिया गया। अपनी पीड़ा लेकर पहुंची झमकू देवी की आपबीती सुनने के बाद भीलवाड़ा के पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने इस मामले में कारोई थानाधिकारी को जांच एवं कार्रवाई के आदेश किए हैं।

पीड़ित झमकू बाई ने पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा को बताया कि उनके पति की चार साल पहले मौत हो गई थी। उनके तीन बेटियां तथा एक बेटा थे। बेटे की मौत पहले हो चुकी और तीनों बेटियों की शादी हो चुकी है। उनके पास बारह बीघा भूमि है, जिसमें से वह अपनी तीनों बेटियों के नाम तीन-तीन बीघा भूमि करना चाहती थी, जो उनके रिश्तेदारों को रास नहीं आया। जाति पंचों से मिलकर उन पर दबाव बनाया जा रहा था कि वह अपनी भूमि देवर तथा जेठ के नाम कर दें, जिसके लिए वह तैयार नहीं थीं। कई बार इस मसले पर पंचायत बुलाई गई और पंचायत ने भूमि देवर और जेठ के नाम करने का आदेश सुनाया। इसके लिए वह सहमत नहीं हुईं तो उन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने बेटी के घर शरण ली तो उसे भी समाज से निकाल दिया और चालीस लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया। भीलवाड़ा पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा का कहना है कि थानाधिकारी को जांच सौंपी गई है।

खेल जागरण

जेम्स एंडरसन ने कराई इंग्लैंड की वापसी

जेम्स एंडरसन • एएनआइ

भारत ने 125 रन तक गंवाए चार विकेट, राहुल का अर्धशतक, जेम्स ने सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में की कुंबले की बराबरी

सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट

गेंदबाज	टीम	टेस्ट	विकेट
मुथैया मुरलीधरन	श्रीलंका	133	800
शेन वार्न	आस्ट्रेलिया	145	708
अनिल कुंबले	भारत	132	619
जेम्स एंडरसन	इंग्लैंड	163	619

स्कोर बोर्ड

टास : इंग्लैंड (बल्लेबाजी) इंग्लैंड (पहली पारी) : 183 (65.4 ओवर)

भारत (पहली पारी) 125/4 (46.4 ओवर)

	रन	गेंद	चौके	छक्के
रोहित शर्मा का. कुर्रन बो. रोबिनसन	36	107	06	00
केएल राहुल नाबाद	57	151	09	00
पुजारा का. बटलर बो. एंडरसन	04	16	00	00
विराट कोहली का. बटलर बो. एंडरसन	00	01	00,	00
अजिंक्य रहाणे रन आउट	05	05	00	00
रिषभ पंत नाबाद	07	08	01	00

अतिरिक्त : (बा-5, लेबा-3, नोबा-8) 16, **कुल** : 46.4 ओवर में चार विकेट पर 125 रन, **विकेट पतन** : 1-97 (रोहित, 37.3), 2-104 (पुजारा, 40.2), 3-104 (कोहली, 40.3), 4-112 (रहाणे, 43.2) **गेंदबाजी** : एंडरसन 13.4-7-15-2, ब्राड 11-1-45-0 ओली रोबिनसन 15-5-32-1 सैम कुर्रन 7-1-25-0

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली : तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने नाटिंघम में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन गुरुवार को ना सिर्फ इंग्लैंड की वापसी कराई, बल्कि सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने के मामले में दिग्गज भारतीय स्पिनर अनिल कुंबले की बराबरी भी कर ली। हालांकि, जब भारत ने पहली पारी में चार विकेट पर 125 रन बनाए थे तो खराब रोशनी की वजह से खेल रोकना पड़ा। इसके कुछ देर बाद बारिश शुरू हो गई और चायकाल की घोषणा कर दी गई। उस समय सलामी बल्लेबाज केएल राहुल 148 गेंदों पर नौ चौकों की मदद से 57 रन बनाकर खेल रहे थे, जबकि रिषभ पंत सात रन बनाकर नाबाद थे। एंडरसन ने 15 रन देकर दो विकेट अपने नाम किए। चायकाल के बाद बारिश बंद होने के बाद जब खेल शुरू हुआ तो दो गेंद ही फेंकी गई थी कि फिर बारिश आ गई और मैच रोकना पड़ा। कुछ देर के इंतजार के बाद खेल आगे नहीं होता देख अंपायरों ने दिन का खेल समाप्त घोषित कर दिया।

भारत ने दूसरे दिन की शुरुआत बिना नुकसान के 21 रन से आगे की। रोहित शर्मा (36) और राहुल की सलामी जोड़ी ने इंग्लिश गेंदबाजों को सफलता के लिए तरसाए रखा, लेकिन जब दोनों के बीच 97 रन की साझेदारी हो चुकी थी तो रोहित की एकाग्रता भंग हुई और वह ओली रोबिनसन (1/32) की गेंद पर स्क्वायर लेग पर सैम कुर्रन को कैच दे बैठे। रोहित के आउट होते ही भोजनकाल की घोषणा कर दी गई।

भोजनकाल के बाद चेतेश्वर पुजारा (4) को एंडरसन ने जमने का कोई मौका नहीं दिया और विकेट के पीछे जोस बटलर के हाथों कैच कराकर इंग्लैंड को दूसरी सफलता दिलाई। एंडरसन यहीं नहीं रुके और अगली गेंद पर भारतीय कप्तान विराट कोहली (0) को भी विकेट के पीछे लपकवाकर बड़ा विकेट हासिल किया और टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में अनिल कुंबले की बराबरी कर ली। अब दोनों के 619 विकेट हो गए हैं और सिर्फ आस्ट्रेलिया के शेन वार्न और श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन इन दोनों से आगे हैं।

नए बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे (5) ने एंडरसन को हैट्रिक लेने से तो रोक दिया, लेकिन खुद क्रीज पर ज्यादा देर नहीं रुक सके और रन आउट होकर पवेलियन लौट गए।

ओलिंपिक रिकार्ड से क्राउजर ने जीता स्वर्ण

टोक्यो, एपी : अमेरिका के शाटपुट (गोला फेंक) चैंपियन खिलाड़ी रेयान क्राउजर ने टोक्यो ओलिंपिक में ओलिंपिक रिकार्ड ध्वस्त करते हुए इतिहास रच दिया। फाइनल में उन्होंने अपने देश के विश्व चैंपियन जो कोवाक्स को हराया। क्राउजर ने टोक्यो की भीषण गर्मी के बीच 23.30 मीटर की दूरी पर गोला फेंकते हुए नया ओलिंपिक रिकार्ड बनाया और लगातार दूसरा स्वर्ण भी जीता। 2016 रियो ओलिंपिक में भी क्राउजर ने इस स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। वहीं 22.65 मीटर की दूरी पर शाटपुट फेंकते हुए अमेरिका के ही जो कोवाक्स ने रजत पदक, जबकि 22.47 मीटर के साथ न्यूजीलैंड के टामस वाल्श ने कांस्य पदक अपने नाम किया।

मेसी व बार्सिलोना का छूटा साथ

मैड्रिड, रायटर : फुटबाल जगत की सबसे बड़ी हलचल स्पेन में मची हुई है, जहां यूरोप के शीर्ष फुटबाल क्लब बार्सिलोना और उसके सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी लियोन मेसी की राहें आखिरकार जुदा हो गईं।

फुटबाल इतिहास के महानतम खिलाड़ियों में से एक मेसी और बार्सिलोना का करीब 21 वर्षों का सफर खत्म हो गया। दिग्गज अर्जेंटीनी खिलाड़ी का स्पेनिश क्लब के साथ करार इस साल जून में खत्म हो गया था, जिसके बाद से ही उनके भविष्य को लेकर अटकलें लगाई जा रही थीं। माना जा रहा था कि क्लब और मेसी के बीच में बदली हुई शर्तों के साथ नए करार को लेकर समझौता हो जाएगा, लेकिन बार्सिलोना की ओर से गुरुवार को पुष्टि की गई कि मेसी का क्लब के साथ करार नहीं हो पाया। क्लब के अनुसार, दोनों के बीच वित्तीय बाधाओं (स्पेनिश ला लीगा नियमों) के कारण ऐसा नहीं हो सका। इसके कारण मेसी बार्सिलोना क्लब के साथ नहीं जुड़ पाएंगे और हम दोनों को ही इसका दुख है और क्लब उनके बिना पूरा नहीं होगा। क्लब की उन्नति में योगदान देने के लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं और भविष्य के लिए उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। जून के अंत में करार समाप्त होने के बाद मेसी अन्य क्लबों के साथ करार करने के लिए स्वतंत्र थे, लेकिन बार्सिलोना ने हमेशा कहा था कि वह क्लब के साथ रहना चाहते हैं। मेसी 13 साल की उम्र में क्लब की युवा टीम में शामिल हुए थे। उन्होंने अपना पूरा क्लब करियर बार्सिलोना के साथ बिताया है। वह क्लब के शीर्ष स्कोरर हैं। उन्होंने सभी प्रतियोगिताओं में 778 मैचों में 672 गोल किए हैं।

आज उतरेंगे बजरंग और सीमा

टोक्यो, प्रेट्र : भारत के पदक के दावेदारों में शामिल स्टार पहलवान बजरंग पूनिया जब शुक्रवार को मैट पर उतरेंगे तो सभी की चाह उनसे पदक की रहेगी। वहीं, सीमा बिसला (50 किग्रा) अपने पहले ओलिंपिक में छाप छोड़ना चाहेंगी।

पुरुष वर्ग में अब पदक की आखिरी उम्मीद बजरंग (65 किग्रा फ्रीस्टाइल) से ही हैं जो विश्व स्तर पर काफी सम्मानित पहलवान हैं। बजरंग ने अपने पिछले 10 अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में छह स्वर्ण, तीन रजत और एक कांस्य पदक जीता है। उनका अंतिम-16 में सामना किर्गिस्तान के एर्नाजर अक्मातालिएव से होगा। बजरंग का स्टेमिना उनका पलड़ा भारी करता है, लेकिन उनके पैर के रक्षण की परीक्षा होगी। उनके वर्ग में काफी कड़ी प्रतिस्पर्धा है।

जो विचार व्यवहार में न लाया जा सके वह बेकार है

न थमने वाला जाति का मंथन

नई खेल संस्कृति का नतीजा

टोक्यो ओलिंपिक अभी जारी है और भारत ने दो रजत पदक समेत कुल पांच पदक अपनी झोली में कर लिए हैं। यदि कुछ और पदक मिल जाते हैं, जिनकी उम्मीद भी है, तो भारत के लिए टोक्यो ओलिंपिक सर्वश्रेष्ठ साबित हो सकता है। आशा की जानी चाहिए ऐसा ही होगा। अभी तक जिन भी खिलाड़ियों ने पदक हासिल किए हैं, वे बधाई और प्रशंसा के हकदार हैं। उन्होंने अपने साथ देश का नाम भी ऊंचा किया है और यह उम्मीद जगाई है कि आने वाले समय में भारत खेल जगत की एक बड़ी ताकत बन सकता है। अब तो यह भी लग रहा है कि उन खेलों में भी हमारे खिलाड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं, जिनमें कुछ समय पहले तक कोई खास उम्मीद नहीं नजर आती थी, जैसे कि एथलेटिक्स। इसी तरह आखिर किसने कल्पना की थी कि हाकी की पुरुष और महिला, दोनों ही टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी? आखिरकार ऐसा ही हुआ और पुरुष हाकी टीम ने तो 41 साल बाद ओलिंपिक में कांस्य पदक अपने नाम किया। यह स्वर्णिम आभा वाला कांस्य पदक है, क्योंकि हर देशवासी भारतीय हाकी के उत्थान के सपने संग जी रहा था। हाकी में मिला कांस्य पदक देश में इस खेल का कायाकल्प करे, इस उम्मीद के साथ यह भी कामना करनी चाहिए कि महिला हाकी टीम भी एक नया इतिहास लिखे।

उत्साहजनक और संतोषजनक केवल यह नहीं है कि टोक्यो गए हमारे अनेक खिलाड़ी उम्मीदों पर खरे उतर रहे हैं, बल्कि यह भी है कि वे देश में एक नई खेल संस्कृति विकसित हो जाने की गवाही भी दे रहे हैं। भले ही अपने प्रदर्शन से देश-दुनिया का ध्यान खींचने वाले कुछ खिलाड़ी पदक तालिका में अपना नाम अंकित न कर सके हों, लेकिन वे अपनी हिम्मत और कौशल से बेहतर भविष्य की मुनादी कर रहे हैं। यह नतीजा है उस नई खेल संस्कृति का, जो हाल के वर्षों में विकसित की गई और जिसके तहत खिलाड़ियों को कहीं बेहतर सुविधाओं के साथ समुचित प्रशिक्षण दिया गया। जहां कुछ खिलाड़ियों को विदेशी प्रशिक्षक उपलब्ध कराए गए, वहीं कुछ को विशेष प्रशिक्षण के लिए विदेश भी भेजा गया। यह सब इसीलिए हो पाया, क्योंकि खेल संघों पर काबिज तमाम ऐसे लोगों को किनारे कर पेशेवर व्यक्तियों को लाया गया, जो उन्हें अपनी जागीर की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। इसके चलते खेल और खिलाड़ियों को वह प्राथमिकता नहीं मिल पाती थी, जो जरूरी थी। टोक्यो ओलिंपिक के समापन के वक्त भारत की झोली में चाहे जितने ज्यादा पदक हों, यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि खेल एवं खिलाड़ियों को और अच्छे से विकसित करने के लिए अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है।

रोजगार की राह

झारखंड सरकार ने स्थानीय लोगों को रोजगार देने के वादे की ओर कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। इसकी शुरुआत नियमावली में सुधार और सभी वर्गों को एक समान अवसर मुहैया कराने के सोच के साथ होने जा रही है। कई विभागों में नियोजन के लिए नई नियमावली बना दी गई है और कुछ विभागों में संशोधन का काम चल रहा है। तमाम प्रयासों में सरकार की स्पष्ट मंशा दिखती है कि झारखंड में रहनेवाले लोगों को अधिक से अधिक अवसर मुहैया कराया जाए। यह सोच पूर्व के कई निर्णयों में भी देखने को मिला है। अगली कड़ी में राज्य सरकार झारखंड से पढ़ाई करनेवाले युवाओं को तरजीह देने की कोशिशों में जुटी दिख रही है। सरकार की कोशिश है कि झारखंड से मैट्रिक और इंटर की पढ़ाई करनेवालों को तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों में प्राथमिकता दी जाए। इसके लिए प्रस्ताव भी तैयार हो चुका है और इस प्रस्ताव पर विधि विभाग, वित्त विभाग से लेकर महाधिवक्ता तक के परामर्श लिए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि इन सभी के परामर्श के बाद जो व्यवस्था बनेगी वह पूरी तरह से दुरुस्त होगी। नियुक्ति नियमावली तैयार होने के बाद रोजगार की राह के रोड़े भी खत्म होंगे और कानूनी अड़चनों को भी समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। इन तमाम प्रक्रियाओं का लाभ यह होगा कि आनेवाले दिनों में नियुक्तियों को लेकर सरकार के सामने कम से कम चुनौती होगी और आसानी से नियोजन का मार्ग प्रशस्त होगा। साथ ही झारखंड कर्मचारी चयन आयोग भी सही तरीके से काम कर सकेगा। सरकार ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहती जैसी जेपीएससी का परिणाम जारी करने के क्रम में हुई। नियुक्ति नियमावली में संशोधन के माध्यम से पहली बार यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कर्मचारी चयन आयोग अलग-अलग प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा न लेकर एक ही परीक्षा से सभी को नियुक्ति देने की प्रक्रिया को पूरी करे। यह कहना गलत नहीं होगा कि कैबिनेट से यह प्रस्ताव पास होने के बाद झारखंड में नियोजन और रोजगार की राह में एक नए अध्याय की शुरुआत होगी।

> नियुक्ति की नई नियमावली बनाने में जुटी झारखंड सरकार पुरानी विसंगतियों को दूर कर कई सराहनीय कदम उठाने जा रही है

प्रदीप सिंह

> विडंबना यह है कि जातियों की जनगणना की मांग में सबसे आगे वे लोग हैं जो कभी जातिविहीन समाज की बात किया करते थे

अवधेश राजपूत

जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान, पर देश में इस समय जाति पूछने का शोर है। यह सही है कि जाति भारतीय समाज की वास्तविकता है, मगर सवाल है कि इस वास्तविकता ने समाज को दिया क्या है? जो जातियों को अलग-अलग खांचों में बांटकर देखना चाहते हैं, वे भूल जाते हैं कि इस विविधता को जोड़ने वाली कोई एकता भी तो होनी चाहिए, क्योंकि जाति समग्रता में ही जीवित रह पाएगी। जो लोग जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं, वे शायद समझ नहीं रहे हैं कि इससे जो विष निकलेगा, वह दूर ही मारेगा।

पश्चिम के युग प्रवर्तक विचारक रूसो ने कहा था कि किसी भी समाज में गुटों के बनने से हमेशा नुकसान होता है, पर यदि गुट बन ही गए हों तो, जितने ज्यादा बन जाएं, उतना अच्छा। जातीय जनगणना के पक्षधर लोगों के मन में कई तरह की अवधारणाएं हैं, जो जातियों की अनुमानित संख्या की ही तरह किसी ठोस धरातल पर नहीं खड़ी हैं। पिछड़े वर्ग के जो नेता इसकी मांग कर रहे हैं, वे यह मानकर चल रहे हैं कि बीपी मंडल ने मंडल आयोग की सिफारिशें करते समय पिछड़े वर्ग की जो कुल जनसंख्या बताई थी, वह कम है। मंडल ने कहा था कुल आबादी का 52 फीसदी पिछड़े वर्ग के लोग हैं। जातीय जनगणना से असलियत सामने आ जाएगी और फिर उन्हें आरक्षण का कोटा बढ़ाने का आधार मिल जाएगा।

सवर्ण जाति के लोगों के मन में यह डर है कि उनकी संख्या जो अभी बताई जाती है, उससे कम निकलेगी। इन दोनों की उम्मीद और आशंका का आधार 1931 की आखिरी जातीय जनगणना के आंकड़े हैं। उनका अब कोई अर्थ नहीं है। उस समय देश की आबादी 27 करोड़ थी और आज के पाकिस्तान और बांग्लादेश भी इसमें शामिल थे। विडंबना यह है कि जातियों की जनगणना की मांग में सबसे आगे वे लोग हैं जो कभी जातिविहीन समाज की बात किया करते थे। पिछड़ा वर्ग को आरक्षण की सुविधा देने के लिए जरूरी है कि उनकी जातियों की सही संख्या का पता हो। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि 1931 की जनगणना के आंकड़े को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसी वजह से 2010 में संप्रग सरकार ने पिछड़ी जातियों की गणना का मन बनाया, लेकिन फिर पीछे हट गई। मोदी सरकार ने भी 2018 में संसद में कहा कि 2021 की जनगणना में पिछड़ों की गिनती कराई जाएगी, पर अब कह रहे हैं कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं है। मार्च 2011 में तत्कालीन गृहमंत्री पी. चिदंबरम ने लोकसभा में कहा था कि यह बहुत उलझा हुआ मुद्दा है। पिछड़े वर्ग की जातियों की एक केंद्रीय सूची है, एक राज्यों की सूची है। कुछ राज्यों में ऐसी सूची है ही नहीं। कुछ राज्यों के पास पिछड़ी जातियों और अति पिछड़ी जातियों की सूची है। रजिस्ट्रार जनरल ने कहा है कि इसके अलावा अनाथ और निराश्रित बच्चे हैं। कुछ जातियों के नाम पिछड़ा और अनुसूचित जाति, दोनों सूची में हैं। ईसाई या इस्लाम में मतांतरित लोगों के बारे में अलग-अलग राज्यों की अलग-अलग नीति है। एक राज्य से दूसरे राज्य जाने वालों की समस्या अलग है। इसके अलावा अंतरजातीय विवाह से उत्पन्न बच्चों की समस्या है।

संप्रग सरकार ने सामाजिक-आर्थिक जातीय जनगणना करवाई, जिसके जाति के अलावा बाकी आंकड़े 2016 में सार्वजनिक किए गए। सामाजिक न्याय मंत्रालय ने ये आंकड़े नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पानगड़िया की अध्यक्षता वाले विशेषज्ञ समूह को सौंप दिए। उसकी शुरुआती रिपोर्ट के बाद क्या हुआ, पता नहीं। अक्टूबर 2017 में गठित जस्टिस जी रोहिणी की अध्यक्षता वाले आयोग ने फरवरी 2021 में अपनी अंतरिम रिपोर्ट में कहा कि पिछड़ा वर्ग की जातियों की जनगणना जरूरी है। आयोग ने पिछड़ा वर्ग को चार उपभागों में विभाजित करने का सुझाव दिया है। आयोग ने पाया कि केंद्रीय सूची में शामिल पिछड़ा वर्ग की 2633 जातियों में से आरक्षण की मलाई ऊपर की सौ जातियां ले गईं। एक तिहाई जातियों को तो शिक्षा और नौकरी में कोई लाभ मिला ही नहीं। सारा पेंच यहीं है। जातीय गणना के बाद अति पिछड़ी जातियां अपने हक के लिए पिछड़ों की ही प्रभावशाली जातियों के खिलाफ उठ खड़ी होंगी। इसकी जमीन तीन दशक पहले सामाजिक न्याय के नाम पर सभी पिछड़ों के नेता बनने वालों ने तैयार कर दी है। मुलायम सिंह यादव और लालू यादव अब पिछड़ों के नहीं यादवों के नेता रह गए हैं। इन दोनों ने अपने समय में एक-एक कुर्मी नेता क्रमशः नीतीश कुमार और बेनी प्रसाद वर्मा को साथ लिया। दोनों ने बाद में अपना अलग रास्ता पकड़ लिया। हालांकि बेनी ने औपचारिक रूप से ऐसा नहीं किया। तो जब पिछड़ों के कोटे का फायदा लेना था तो सबको जोड़ लिया और सत्ता मिली तो बाकी को भूल गए। रामधन ने एक बार कहा था कि बड़े घटक ने छोटे घटक को गटक लिया। जातीय जनगणना के आंकड़े आने के बाद यह गटका हुआ उगलना पड़ेगा, क्योंकि परमाणु विखंडन की ही तरह समाज के गुटों के विखंडन की प्रक्रिया एक बार शुरू हो जाती है तो वह रुकती नहीं। यह प्रक्रिया अब रुकने वाली नहीं है। जनगणना से पहले ही उसके संकेत नजर आ रहे हैं। कहीं निषाद अपना हिस्सा मांग रहे हैं तो कहीं राजभर। छोटे-छोटे जाति समूह सत्ता में अपनी हिस्सेदारी के लिए सामने आ रहे हैं। सामाजिक क्रांति के पुरोधा मुलायम हों या लालू, अब उन्हें भी इन जाति समूहों से सौदेबाजी करनी होगी। इस बदलाव की आहट को नरेंद्र मोदी ने पहले से समझ लिया था। पिछले सात सालों में संख्या में छोटी जातियों को भाजपा में जगह ही नहीं मिली, बल्कि उन्हें संगठन और सत्ता में हिस्सेदारी भी मिली है।

कहते हैं कोई असफल करने का तरीका यही है कि उसे होने दिया जाए। इसलिए इस सामाजिक विखंडन को रोकने का भी यही तरीका है कि उसे होने दिया जाए, क्योंकि एक बार यह हो गया, तब संख्या में छोटे-छोटे इन जाति समूहों को भी अहसास होगा कि सौदेबाजी की राजनीति का सिलसिला लंबे वक्त तक नहीं चल सकता। तब इस विविधता को एकता की जरूरत महसूस होगी, पर इस उपक्रम में समाज में कितना विष निकलेगा व कितना अमृत (अगर निकला) यह किसी को पता नहीं है, पर इस जाति मंथन को अब न रोका जा सकता है और न ही रोका जाना चाहिए।

(लेखक राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

कमजोर धुरी पर टिकी विपक्षी एकता

आशुतोष झा

> दिल्ली आईं ममता बनर्जी यही दोहराती दिखीं कि सोनिया गांधी से उनके अच्छे रिश्ते हैं, मगर राहुल को लेकर मौन रहीं

दस जनपथ की देहरी पर ममता बनर्जी। फाइल

मई के पहले सप्ताह में बंगाल चुनाव के नतीजे आए, जिसमें ममता बनर्जी ने अभूतपूर्व जीत हासिल की और उसके साथ ही पूरे देश खासकर उत्तर भारत में भाजपा के खिलाफ एक मजबूत विपक्षी मोर्चा तैयार करने की बहस छिड़ गई। विपक्ष मजबूत रहे, यह लोकतंत्र के लिए अच्छा है, लेकिन रोचक बात यह है कि यह बहस राजनीतिक स्तर पर बाद में छिड़ी, इंटरनेट मीडिया पर पहले शुरू हो गई। बाद के दिनों में राजनीतिक स्तर पर भी हलचल दिखी। राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा और क्षेत्रीय राजनीतिक मजबूरी के बीच अक्सर फंसे दिखे शरद पवार ने दिल्ली में अपना प्रभुत्व दिखाने की कोशिश की और कांग्रेस को छोड़कर अन्य विपक्षी दलों और अलग-अलग क्षेत्र के लोगों के साथ राजनीतिक परिदृश्य पर चर्चा की। फिर ममता बनर्जी ने दिल्ली में अपनी धमक दिखाई, पर अब तक यह साफ नहीं हो पाया है कि इस कथित विपक्षी एका के लिए, क्या दल वास्तव में तैयार हैं? वे दल कौन से हैं, जो इस मोर्चे का अंग हो सकते हैं? इस संभावित मोर्चे का स्वरूप क्या होगा? देश में अब तक अलग-अलग तरह के कई प्रयोग हो चुके हैं और किसी को कोई भ्रम नहीं है कि एकजुटता के लिए, धुरी का मजबूत होना जरूरी है। फिलहाल क्षेत्रीय दलों की ओर से जिस तरह राजनीतिक ताकत दिखाने की कोशिश हो रही है, उससे परिधि के मजबूत और धुरी के कमजोर होने का ही अहसास होता है।

विपक्षी एकजुटता की बात होते ही सबसे पहले 1977 ही उभरता है, जब आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ विपक्ष एकजुट नहीं, बल्कि एक हो गया था। उस वक्त अभूतपूर्व स्थिति बनी थी। देश में आपातकाल लागू हो गया था। मूल अधिकार खत्म कर दिए गए थे, लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया था, विपक्षी नेताओं, पत्रकारों, एक्टिविस्टों को जेल में बंद कर दिया गया था। इन घटनाओं का प्रभाव राजनीति तक सीमित नहीं था। जनता के अंदर खौफ था। लिहाजा कुछ दल, जिनमें जनसंघ भी बड़ा घटक था, एक हो गए। इस विलय से दलों ने अपना स्वतंत्र अस्तित्व खो दिया और नाम पड़ा जनता पार्टी। इस विपक्षी एकजुटता को जनता का समर्थन भी मिला था, लेकिन दक्षिण भारत में इसका असर नहीं दिखा। आपात स्थिति में अभूतपूर्व विलय के बावजूद आंतरिक दबाव भारी पड़ा और दो साल के अंदर सरकार चरमरा गई। जाहिर है आज के दिन ऐसी एकजुटता और ऐसे किसी विकल्प पर विचार संभव ही नहीं है। जनता पार्टी के असफल प्रयोग के बाद वह चाहे वीपी सिंह की राष्ट्रीय मोर्चा सरकार हो या फिर 1996-98 तक दो प्रधानमंत्रियों के साथ चली संयुक्त मोर्चा सरकार, उसने बार-बार साबित किया कि धुरी कमजोर हो तो बिखराव तय है। एक और बात जो हर किसी के ध्यान में है कि विपक्ष एक स्वर से आवाज उठा रहा हो तो राजनीति पर असर कुछ और होता है। अगर अंदर से ही आरोप उठने लगें तो सरकार के लिए स्थिति विकट हो जाती है। बोफोर्स का जो भूत अब तक कांग्रेस के सिर से नहीं उतर पाया है, वीपी सिंह सरकार उसी की उपज थे, लेकिन उनकी सरकार बाहर से समर्थन दे रही भाजपा के रहमोकरम पर टिकी थी। वीपी सिंह के बाद चंद्रशेखर सरकार कांग्रेस की मोहताज बनी और वह चार माह भी नहीं चल सकी।

इसके कुछ अंतराल के बाद कांग्रेस की मेहरबानी से बनी संयुक्त मोर्चा सरकार बार-बार ध्वस्त हुई। पहले देवगौड़ा की सरकार गई, फिर गुजराल सरकार। गुजराल सरकार महज इसलिए चली गई थी, क्योंकि जैन आयोग ने राजीव गांधी की हत्या के मामले में द्रमुक को कठघरे में खड़ा कर दिया, जो उस गठबंधन सरकार में शामिल था। यानी एक क्षेत्रीय दल पर आई आंच प्रधानमंत्री पर भारी पड़ी। वही कांग्रेस अब तमिलनाडु में द्रमुक की बगलगीर बनी हुई है।

इसमें शक नहीं कि अपनी राजनीतिक गति और रणनीति से चमक रही भाजपा के खिलाफ विपक्ष एकजुट होना चाहता है, लेकिन उसे इतिहास भी याद है और आज के दिन विचारधारा से लेकर रणनीति तक के स्तर पर आपसी टकराव की जानकारी भी। चुनाव पूर्व गठबंधन के साथ बनी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार और फिर मनमोहन सिंह की दो सरकारों की सफलता जरूर उन्हें उत्साहित कर रही होगी, लेकिन तब और अब में एक बड़ा अंतर केंद्रबिंदु का ही है। दोनों के कार्यकाल में मुख्य पार्टी तो मजबूत थी ही, खुद नेतृत्व को लेकर गठबंधन में आपत्ति नहीं थी। वे स्वीकार्य थे। आज यही सबसे बड़ा सवाल है, जिसे साथी दलों को सबसे पहले सुलझाना होगा। हाल में दिल्ली आईं ममता बनर्जी बार-बार दोहराती दिखीं कि सोनिया गांधी से उनके अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन राहुल गांधी के सवाल पर वह चुप ही रहीं। कांग्रेस के एक प्रवक्ता का यह बयान अवश्य आया कि नेतृत्व का सवाल बाद में आना चाहिए। बताने की जरूरत नहीं कि यह एकजुटता के लिए जरूरी मूल सवाल को टालने के अलावा और कुछ नहीं है।

कांग्रेस के अंदर की समस्या अभी खत्म नहीं हुई है। औपचारिक नेतृत्व का बड़ा सवाल मुंह बाएं खड़ा है। चूंकि कांग्रेस में राहुल गांधी ही औपचारिक और अनौपचारिक नेता हैं इसलिए, उन्होंने भाजपा के खिलाफ एकजुट रणनीति बनाने के लिए हाल में विपक्षी दलों को नाश्ते पर बुलाया। बसपा और आम आदमी पार्टी को छोड़कर 14 दल उपस्थित हुए। पहली बार तृणमूल कांग्रेस के नेता भी आए। यह कांग्रेस को उत्साहित कर रहा होगा, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि सदन के अंदर तृणमूल ही सबसे ज्यादा विपक्षी दल दिखने की कोशिश कर रहा है। यह भी देखें कि एकजुटता की कोशिश में विपक्ष जनता के मुद्दे को ही भूल गया। न महंगाई मुद्दा बना, न कोरोना। बस वह पेगासस छाया रहा, जो विपक्ष को जोड़ने और जनता को आकर्षित करने का काम नहीं कर सकता।

(लेखक दैनिक जागरण के राष्ट्रीय ब्यूरो प्रमुख हैं)

response@jagran.com

पाप की सजा

पुण्यार्जन के लिए मनुष्य को सत्कर्म करने पड़ते हैं। सत्कर्म का मार्ग कठिन जरूर होता है, पर जिनका मन पवित्र और सच्चाई से सराबोर होता है, उनके लिए यह सरल हो जाता है। इसी के कारण उनकी गणना लौकिक संसार में अच्छे व्यक्तियों में की जाती है। उन्हें सदा मान-सम्मान और पद-प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती रहती है। पुण्य की प्रबलता ही व्यक्ति के जीवन को सफल और सार्थक बनाती है, जबकि पाप की प्रबलता मनुष्य को दुखों की दलदल में सजा भोगने के लिए धकेल देती है। निज स्वार्थ के लिए बेईमानी, हत्या, चोरी, निंदा और झूठ-फरेब का सहारा लेना सबसे बड़ा पाप है। प्रकृति में ईश्वरीय विधान अकाट्य है। गलत की सजा गलत और अच्छाई का फल पुरस्कार के रूप में प्राप्त होता है। अर्थात पुण्य का फल कर्म के उपहार स्वरूप सुख-शांति के रूप में प्राप्त होता है और पाप की सजा कष्ट-दुख के रूप में भोगनी पड़ती है।

व्यक्ति पाप मानसिक और शारीरिक, दोनों रूप में करता है। इससे नैतिकता का हनन एवं व्यक्ति का मन कलुषित तथा वातावरण दूषित-कलंकित होता है। इसका परिणाम जीवन और समाज में अशांति, दुख, अनाचार, अत्याचार, प्राकृतिक आपदा के रूप में दृष्टिगोचर होता है। व्यक्ति समझता है कि हम बुराई कर रहे हैं, कोई देख नहीं रहा है, पर हमारी गलती हमारे आत्मा से छुपी नहीं रहती है। हम पाप जितना भी छुपकर करें, पर ईश्वर व्यक्ति के अंतरात्मा की नेत्र से जरूर देख लेता है। जाहिर है व्यक्ति पाप करके पुलिस-कानून से भले बच जाए, पर ईश्वर से नहीं बच सकता है।

हालांकि हमारा आत्मा पाप करने से हमें रोकता है, पर हमारा आसुरी मन लोभ-मोह और अहंकार में अंधा होकर पाप में प्रवृत्त हो जाता है। ऐसे में हमें अपने मन को नियंत्रण में रखने के प्रयास करने चाहिए। यह मानव जीवन पाप-कुकर्म के लिए नहीं, पुण्य-सत्कर्म करके निज का उद्धार, जन-जन की भलाई के लिए प्राप्त हुआ है।

मुकेश ऋषि

खिलाड़ियों की जाति नहीं, समर्पण देखें

सोनम लववंशी

> खिलाड़ियों को खिलाड़ी ही रहने दें, वरना उनको जाति और धर्म के बंधन में बांधने लगेंगे तो देश में खेलों का विकास अवरुद्ध हो जाएगा

हाल में गूगल द्वारा जारी किए गए डाटा से पता चला है कि टोक्यो ओलिंपिक में कांस्य पदक जीतने के बाद देश में कुछ लोग पीवी सिंधू के खेल से कहीं ज्यादा उनकी जाति सर्च करने में लगे हुए थे। दूसरे शब्दों में कहें तो ये लोग उनकी मेहनत और खेल के प्रति उनके समर्पण के बारे में चर्चा करने से ज्यादा यह जानने में लगे थे कि वह किस जाति से हैं। चिंता की बात है कि यह किसी एक खिलाड़ी के साथ नहीं हुआ है। इस सूची में ढेरों खिलाड़ियों के नाम हैं। वैसे देश की राजनीति में जातिवाद का जहर किसी से छिपा नहीं है, लेकिन जब यही खेलों में भी शुरू हो जाए तो कई सवाल खड़े होते हैं। यह कितने दुर्भाग्य की बात है कि जब भी खिलाड़ी अपने बेहतर खेल प्रदर्शन से देश का मान बढ़ाते हैं तो फिर कुछ लोग उनके प्रदर्शन की चर्चा न करके उनकी जाति जानने में दिलचस्पी लेने लगते हैं। जब खिलाड़ी आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहे होते हैं तब कोई उनकी जाति नहीं पूछता, मजहब नहीं जानना चाहता और न ही उनकी सुध लेता है, लेकिन जैसे ही वे पदक जीतते हैं तो फिर उनको जाति-धर्म के सांचे में बांटने की फितरत जन्म ले लेती है। क्या जातियों में बांटकर हम खेलों में शीर्ष पर पहुंच पाएंगे? आखिर यह जाति जाती क्यों नहीं? वैसे तो हम नारा बुलंद करते हैं संप्रभु भारत का, फिर बीच में जाति-धर्म और राज्य कहां से आ जाते हैं? क्या इन खिलाड़ियों की विदेश में पहचान उनके राज्य से होती है? नहीं न, तो फिर ऐसी ओछी मानसिकता क्यों?

सच्चाई तो यह है कि हमारे देश में ऊंच-नीच, अमीर-गरीब, छोटे-बड़े और स्त्री-पुरुष, बल्कि यह कहें कि हर जगह भेदभाव की कभी न मिटने वाली एक लकीर खींच दी गई है। इसकी जड़ें वर्तमान दौर में और गहरी होती जा रही हैं। तमाम दल अपने-अपने सियासी लाभ के लिए, जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। हमारे संविधान-प्रदत्त अधिकार और कानूनी प्रविधान भी जातीय भेदभाव, उत्पीड़न और अन्याय को खत्म करने में बहुत सफल नहीं होते प्रतीत हो रहे हैं, क्योंकि देश की राजनीति को संचालित करने वाली कुछ शक्तियां ही नहीं चाहतीं कि देश से जातिवाद खत्म हो।

दुख की बात है कि हाल के कुछ वर्षों में सियासत ने खेलों में भी जातियों की घुसपैठ करा दी है, जो बेहद खतरनाक है। हमें पता होना चाहिए कि खिलाड़ी सिर्फ एक खिलाड़ी होता है। वह अपनी मेहनत, लगन, संघर्ष और अपने खेल के दम पर देश का मान बढ़ाता है। हमारे लिए तो देश का गौरव बढ़ाने वाले हर खिलाड़ी जाति-धर्म से ऊपर होने चाहिए। हम खिलाड़ियों को खिलाड़ी ही रहने दें, वरना उनको जाति और धर्म के बंधन में बांधने लगेंगे तो जिस तरह से जातिवाद में फंसकर देश का विकास अवरुद्ध हो गया है, उसी तरह खेलों का विकास भी बाधित हो जाएगा।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

फारूक-महबूबा का गैर जिम्मेदार रवैया

'नई सुबह की ओर जम्मू-कश्मीर' शीर्षक से लिखे अपने लेख में प्रो. रसाल सिंह ने सही लिखा है कि पांच अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 और धारा 35ए की समाप्ति के बाद जम्मू-कश्मीर भेदभाव के अभिशाप से मुक्त हो गया है। भारत का संविधान पूरी तरह से लागू होने के बाद वहां भी विकास का सपना साकार हो रहा है। मोदी सरकार के इस कदम से प्रदेश को अपनी जागीर समझने वाले कुछ दलों में बौखलाहट देखी जा रही है। दरअसल इससे उन्हें अपनी राजनीति खत्म होती नजर आ रही है। परिणामस्वरूप नेशनल कांफ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की मुखिया महबूबा मुफ्ती समय-समय पर भारत सरकार को राय देते हैं कि उसे कश्मीर समस्या के हल के लिए पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। जम्मू-कश्मीर में जबसे प्रशासनिक ढांचे में आमूलचूल बदलाव किया गया है तबसे ये दोनों और भी अधिक आक्रामक रुख दिखा रहे हैं। इस क्रम में ये भारत की गौरवशाली सेना की क्षमता पर सवाल उठाकर इसके मनोबल को कमजोर करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। शायद ये भूल गए हैं कि हमारी सेना ने कई बार पाकिस्तान को धूल चटाई है। एक और बात, पाकिस्तान से तो सरकार नाममात्र की है। वहां की सरकार तो पाकिस्तानी सेना और उसकी खुफिया एजेंसी आइएसआइ की कठपुतली है। ऐसे में फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को बताना चाहिए कि वे किसके संपर्क में हैं-पाकिस्तानी सरकार या सेना के? उन्हें यह भी बताना चाहिए भारत सरकार को किससे बात करनी चाहिए? वरना इन्हें इस तरह गैरजिम्मेदाराना बयान देने से बाज आना चाहिए।

भूषण शरण महेश, एडवोकेट, मुजफ्फरनगर

मेलबाक्स

उन्नति के पथ पर कश्मीर

संपादकीय पेज पर प्रकाशित प्रो. रसाल सिंह का लेख नई सुबह की ओर जम्मू-कश्मीर दो वर्ष पहले के कश्मीर और आज के कश्मीर में बेहद सार्थक तुलना करने वाला है। पांच अगस्त, 2019 से पहले कश्मीर में आतंकवादियों और उनके समर्थकों के हौसले बुलंद थे। घाटी में आम लोग यहां तक कि स्कूल-कालेज में पढ़ने वाले छात्र भी सुरक्षाबलों पर पत्थर बरसाते थे। उद्योग धंधे पूरी तरह तबाह हो गए थे। आए दिन हिंसा के कारण शैक्षिक संस्थान आमतौर पर बंद ही रहते थे। ऐसे में अनुच्छेद 370 और 35ए, जिनके चलते कश्मीर के लिए अलग विधान था, हटाए जाने से माहौल काफी हद तक बदला है। जिन हाथों में पत्थर थे, उन हाथों में अब पुस्तकें हैं। बच्चों के हाथों में बैट बाल देखकर प्रसन्नता होती है। पंचायती राज स्थापित हो चुका है। कुल मिलाकर बीते दो वर्षों में कश्मीर के समुचित विकास की सुदृढ़ नींव डल चुकी है। यदि कश्मीर के लोगों ने अपेक्षित सहयोग दिया तो कश्मीर त्वरित उन्नति अवश्य करेगा।

सीपी बंसल, दिल्ली

विवि प्रबंधन छात्र हित का रखे ध्यान

दिल्ली विश्वविद्यालय के डा. भीमराव आंबेडकर कालेज में पत्रकारिता विभाग के द्वितीय वर्ष में शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम अभी तक नहीं आए हैं। जबकि दिसंबर 2020 में ही परीक्षा दिया गया था। करीब आठ महीने बाद भी परिणाम का कोई अतापता नहीं है। वहीं प्रथम वर्ष के छात्र जिनकी परीक्षा इसी वर्ष फरवरी में हुई थी उनके परिणाम जुलाई में ही आ गए। इस बाबत छात्रों ने परीक्षा नोडल अधिकारी और विश्वविद्यालय प्रशासन से भी संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। ऐसे में यह कैसे सुनिश्चित किया जाए कि सभी बच्चे दूसरे वर्ष के तृतीय और चतुर्थ सेमेस्टर में उत्तीर्ण हो गए हैं। अब तो अंतिम वर्ष की कक्षाएं भी शुरू हो गई हैं। ऐसे में परिणाम का घोषित न होना छात्रों को तनाव में डाल रहा है। छात्रों की समस्याओं को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रबंधन को अतिशीघ्र इस पर ध्यान देने की जरूरत है। ताकि बैक लगने या फेल होने की जानकारी होने पर छात्र उसकी तैयारी कर सकें। एक तो आनलाइन शिक्षा, ऊपर से देर से परिणाम छात्रों के भविष्य को अंधकार में डालने वाला है।

अमन जायसवाल, दिल्ली विश्वविद्यालय

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें : दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण, डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721

1893 में डूरंड लाइन अस्तित्व में आया, जिसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय सीमा के रूप में रेखांकित किया गया है। हालांकि अफगानिस्तान की किसी भी सरकार ने इसे मान्यता नहीं दी।

आजकल

सतीश कुमार
प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान, इग्नू, नई दिल्ली

अशांत अफगान और बारूद के ढेर पर पाक

पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा करीब 2670 किमी लंबी है। यह सीमावर्ती क्षेत्र पूरी तरह से आतंकियों के कब्जे में है। पाकिस्तान की तरफ का क्षेत्र टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के प्रभाव में है, जबकि यहां बहुसंख्यक आबादी पश्तूनों की है। पाकिस्तान टीटीपी को 'बैड तालिबान' के नाम से पुकारता है, क्योंकि बीते कुछ वर्षों में इसने पाकिस्तान के भीतर 32 से ज्यादा घातक आतंकी हमलों को अंजाम दिया है। लिहाजा अफगानिस्तान तो फिलहाल अशांत है ही, पाकिस्तान भी उसके रूप में अपने लिए बारूद जमा कर रहा है जो उसी के लिए घातक होगा

अफगानिस्तान में भारतीय हितों को आघात पहुंचाने के लिए अपने ही अहित पर आमादा पाकिस्तान। इंटरनेट मीडिया

अफगानिस्तान एक जमाने में भारत का ही अभिन्न अंग था। बाद में औपनिवेशिक शक्तियों ने भारतीय उपमहाद्वीप को अशांत और प्रभावित करने की कोशिश शुरू कर दी। सबसे पहले धर्म को हथियार बनाया। हिंदू-मुसलमान का बंटवारा किया। क्षेत्रीय विषमताओं को विघटनकारी तत्वों में तब्दील करने की योजना बताई गई। लेकिन भारत इन तमाम विसंगतियों से स्वयं को निकालने में सफल रहा। भारत निरंतर कोशिश में है कि उन देशों में शांति व्यवस्था बनी रहे। अफगानिस्तान में भारत के ज्यादातर प्रोजेक्ट विकास की धुरी से जुड़े हुए हैं। तकरीबन तीन अरब डालर के साथ भारत ने पिछले 20 वर्षों में स्कूल, कालेज, अस्पताल, हाइवे और तकनीकी जरूरतों को पूरा करने का काम किया है।

भारत की कोशिश रही है कि अफगानिस्तान में समाज निर्माण बाहरी ताकतों के दबाव में नहीं, बल्कि उनके द्वारा स्वाभाविक रूप से बनाया जाए। कभी रूस और कभी अमेरिका तो कभी अन्य देश अपने निहित स्वार्थ के जरिये कैसे किसी देश में युद्ध की स्थिति पैदा कर देते हैं, अफगानिस्तान इसका ज्वलंत उदाहरण है। बांग्लादेश एक अलग उदाहरण है। हालांकि हिंसा और आतंक का दौर लोगों की सोच से बदलना शुरू हुआ। आज बांग्लादेश दक्षिण एशिया के अन्य देशों से ज्यादा रफ्तार से प्रगति कर रहा है। पाकिस्तान की नियति डूबने की है। उसका उन्माद अशांति और खून खराबे में अटका हुआ है। यही कारण है कि पाकिस्तान में आतंकवाद की जितनी घटनाएं होती हैं, उतनी कहीं और नहीं होतीं। उसका नुकसान भी उसे ही झेलना पड़ता है। वहीं सच्चाई यह है कि तालिबान की जीत को पाकिस्तान विजय के रूप में देखा जा रहा है। ऐसा देखने का कारण भी है। तालिबान को पोषित और संचालित करने का काम पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसी आइएसआइ के इशारे पर हुआ है। यहां तक 2020 का 'दोहा पीस डील' भी पाकिस्तान के कारण सफल हुआ। दरअसल 'दोहा समझौते' को एक समझौता नहीं, बल्कि एक डील कहा जा सकता है, जिसमें अमेरिका द्वारा एकतरफा समर्पण किया गया और तालिबानियों की हर जिद की जीत हुई। चीन की बढ़ती गिरफ्त से पाकिस्तान का वजूद और मजबूत बनता गया। तुर्की, ईरान और रूस भी अमेरिकी वापसी से खुश हैं। यानी हर तरफ से पाकिस्तानी रणनीति कामयाब साबित होती दिख रही है। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। भौगोलिक-राजनीतिक संघर्ष की भीतरी परत को अगर गंभीरता से देखा जाए तो सबसे बेहतर स्थिति पाकिस्तान की दिख रही है। ऐसा होने का पुख्ता कारण और सबूत भी है। अल्पावधि में भले ही पाकिस्तान की यह जीत कही जाए, लेकिन दीर्घावधि में पाकिस्तान की बेचैनी स्पष्ट रूप से नजर आ रही है।

पाकिस्तान और अफगानिस्तान का इतिहास भी बहुत पेचीदा है। दोनों देशों के बीच की सीमा को 'डूरंड लाइन' कहा जाता है, लेकिन उसकी मान्यता अफगानिस्तान की किसी भी हुकूमत ने नहीं दी है। वर्ष 1893 में तैयार की गई इस रेखा का दर्द आज भी अफगानिस्तान में बखूबी जिंदा है। सौ वर्षों के बाद यानी 1993 में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के पश्तूनों ने आंदोलन शुरू किया था कि पाकिस्तान का वृहत क्षेत्र 'पख्तूनख्वा' को अफगानिस्तान में विलय की इजाजत दे दी जाए। यह क्षेत्र पाकिस्तान के कुल क्षेत्रफल का 60 प्रतिशत हिस्सा है। अगर यह क्षेत्र पाकिस्तान से अलग बन गया तो पाकिस्तान का करीब दो तिहाई हिस्सा हाथ से निकल जाएगा।

पिछली सदी के सातवें-आठवें दशक में पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात थे। शीत युद्ध के समीकरण ने पाकिस्तान को दोहरे आघात से बचा लिया था। जिस समय पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश के रूप में एक अलग देश बन गया था, ठीक उसी दौरान पश्तूनिस्तान के भी अलग होने की स्थिति पैदा हो गई थी। जुल्फिकार अली भुट्टो ने बचने के लिए जिस तरह से इस्लामिक कार्ड खेलना शुरू किया था, वहीं से अफगानिस्तान में इस्लामिक कट्टरपंथ की शुरुआत हुई।

अफगानिस्तान मीडिया को पढ़ें और देखें तो उसमें भी पाकिस्तान का विरोध ही दिखता है। वहां के लोग आतंकवाद और खून खराबे के लिए, पाकिस्तान को दोषी मानते हैं। दरअसल अफगानिस्तान का स्वरूप एक जनजातीय राज्य के रूप में है, जिसमें पश्तून सबसे बड़ा समुदाय है। लेकिन उसके अलावा ताजिक, हजारा और दर्जनों अलग अलग समुदाय के लोग भी हैं। भाषा और रहन-सहन भी एक दूसरे से भिन्न है। तालिबान केवल पश्तून की पहचान के साथ अफगानिस्तान को नियंत्रित नहीं कर सकता। शिया मुसलमानों की एक अलग हुजूम है जिसकी सीमा ईरान से मिलती है। अन्य जनजातियां तालिबान के साथ पाक विरोधी भी हैं।

चीन और रूस इस्लामिक आतंकवाद से पीड़ित हैं। अफगानिस्तान की शांति दोनों के लिए अहम है। लेकिन पाकिस्तान के समीकरण के तहत गृह युद्ध की आशंका ज्यादा मुखर है। अफगान-पाक सीमा पर मादक पदार्थों की तस्करी का अड्डा है। पूरे इलाके में गरीबी-बेरोजगारी है। अफगानिस्तान में आर्थिक संसाधन का मुख्य आधार अमेरिकी अनुदान था, जो अब संभव नहीं। पाकिस्तान की स्थिति भी बदतर है। चीन केवल अपने व्यापार और सामरिक समीकरण के कारण जुड़ा हुआ है। अर्थात हर तरीके से नुकसान पाकिस्तान को ही होगा।

इस बीच मध्य एशिया के भीतर अगर अफगानिस्तान के कारण अशांति फैलती है तो रूस का तेवर उग्र होगा। ऐसे में चीन भी शांत नहीं रह सकता है। स्वाभाविक है कि दहशतगर्दों की जमात से शांति और विकास की बात नहीं बन सकती। अफगानिस्तान से भारत को दूर करने के प्रयास में पाकिस्तान स्वयं बारूद के ढेर पर खड़ा होता जा रहा है। ऐसे में आज नहीं तो कल विस्फोट होना सुनिश्चित है।

काबुल हवाई अड्डे की सुरक्षा का सवाल

राम यादव
वरिष्ठ पत्रकार

अमेरिका ने अफगानिस्तान के उन नागरिकों को अपने यहां ले जाना शुरू कर दिया है, जो अब तक वहां तैनात अमेरिकी सेना के लिए स्थानीय कर्मचारियों और दुभाषियों के तौर पर काम कर रहे थे। अमेरिका को इस बात का डर है कि अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होते ही उन्हें मार दिया जाएगा। उनकी संख्या लगभग 1300 है। उनके साथ उनके परिवारों को भी अमेरिका में शरण दी जाएगी।

दरअसल दो दशक पूर्व तालिबान को काबुल से खदेड़ने के बाद से इस शहर का विस्तार काफी तेजी से हुआ। यहां की जनसंख्या अनुमानित रूप से लगभग 50 लाख है। काबुल में ही देश का एकमात्र अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। हालांकि वहां दिन भर में 25 से अधिक विमानों का आना-जाना नहीं हो पाता। फिर भी अमेरिका और उसके साथी नाटो देशों के सैनिकों के 11 सितंबर तक अफगानिस्तान खाली कर देने के बाद काबुल हवाई अड्डे की सुरक्षा एक चुनौती बन जाएगी।

उल्लेखनीय है कि गत 14 जून को बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में स्थित नाटो के मुख्यालय में इस सैन्य संगठन का शिखर सम्मेलन हुआ था। उस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने नाटो के एकमात्र मुस्लिम सदस्य देश तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन से काबुल हवाई अड्डे की सुरक्षा के बारे में बातचीत की थी। बाइडन चाहते थे कि तुर्की काबुल हवाई अड्डे की सुरक्षा करे। एर्दोगन ने संकेत दिया कि इसके लिए वे सैद्धांतिक रूप से तैयार हैं, पर उनकी अपनी भी कुछ शर्तें होंगी। इन शर्तों पर बातचीत चल रही है। पहली शर्त यह है कि तुर्की ने नाटो गठबंधन का सदस्य होते हुए भी नाटो के नियमों की अवहेलना करते हुए, जुलाई 2019 में रूस से एस 400 नामक जो मिसाइल प्रतिरक्षा प्रणाली खरीदी है, उस कारण अमेरिकी संसद द्वारा उस पर थोपे गए प्रतिबंध हटाए जाएं। दूसरी मुख्य शर्त के बारे में अरब मीडिया में कहा जा रहा है कि एर्दोगन अपने नहीं, भाड़े के ऐसे सैनिक काबुल भेजना चाहते हैं जिनके लिए पैसा अमेरिका को देना होगा। ये सैनिक संभवतः सीरिया के ऐसे जिहादी होंगे जिन्हें तुर्की उत्तरी सीरिया में कुर्दों से लड़ने के लिए इस्तेमाल करता रहा है। तुर्की इन भाड़े के टट्टुओं के लिए अमेरिका से प्रति व्यक्ति तीन हजार डालर मासिक चाहता है। नाटो के यूरोपीय सदस्य देश चाहते हैं कि चाहे जैसे भी हो, इस बला से छुटकारा मिले।

नाटो के कुल 30 सदस्य देशों में अमेरिका के बाद तुर्की की सेना ही दूसरी सबसे बड़ी सेना है। नाटो का सदस्य होने के नाते तुर्की ने पहले से ही अपने 500 सैनिक अफगानिस्तान में तैनात कर रखे हैं। लेकिन साथ ही वह पूरे समय तालिबानी लड़ाकों के साथ किसी टकराव से बचता भी रहा है। तुर्की काबुल हवाई अड्डे की सुरक्षा के ठेके को इस्लामी जगत में अपनी पैठ बढ़ाने के एक सुअवसर और साथ ही अफगानिस्तान के नाम से ऊब चुके नाटो के सदस्य देशों को भी खुश रखने की एक चाल के तौर पर देखता है। यह बात कोई रहस्य नहीं है कि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन सुन्नी इस्लामी जगत की अगुआई सऊदी अरब से छीनने और एक नया खलीफा बनने की महत्वाकांक्षा रखते हैं। काबुल में तुर्की की लंबी उपस्थिति के लिए उसे भू-राजनीतिक दृष्टि से भी कई लाभ दिखते हैं। अफगानिस्तान के साथ-साथ पाकिस्तान में भी तुर्की का दबदबा बढ़ेगा और भारत केवल मूकदर्शक रह जाएगा।

हालांकि काबुल हवाई अड्डे की सुरक्षा के प्रश्न पर तुर्की और अमेरिका के बीच बातचीत अब भी चल रही है, कोई निर्णय नहीं हो पाया है। अमेरिका चाहता तो है कि काबुल हवाई अड्डे की सुरक्षा का कार्यभार तुर्की संभाले, पर तुर्की उससे जो पैसा तथा कूटनीतिक व लाजिस्टिक सहायता मांग रहा है, अमेरिका उसके लिए राजी नहीं दिखता।

खरी-खरी

विचारों के संक्रमण से बचके रहना

डा. डीएन पचौरी

हमारे एक मित्र हैं। उन्हें कोरोना काल के खाली समय में चित्रकार होने की लत लग गई। जी हां लत। उन्होंने आड़ी-तिरछी रेखाएं खींचकर उनमें रंग भरना शुरू कर दिया और इस संसार की सबसे बुरी पेंटिंग्स बनाने लगे। समाज में विघ्न संतोषी और मजे लेने वालों की कमी नहीं इसलिए किसी ने उनके कान भर दिए कि महान चित्रकार पिकासो भी ऐसी ही आड़ी-तिरछी लकीरें खींचकर चित्र बनाते थे।

एक दिन उनके घर के सामने से मेरा गुजरना हो गया। उन्होंने देखा और पूरे सम्मान से अपने घर में ले गए। कुछ देर तो हमारा सम्मान तेल लेने चला गया और वे हमसे पेंटिंग देखने की जबरदस्ती पर उतर आए। वे घर के अंदर गए और हाथों में तैलचित्र लिए नमूदार हुए। उन्होंने हमें कुछ दिखाया, जिसे वे अपनी पेंटिंग कह रहे थे। हम 'बढ़िया है भाईसाब' कहकर वहां से निकल लेना चाहते थे, लेकिन उन्होंने तभी कूची की नोक पर लगभग हमें धमकाते हुए रोक लिया- ऐसे कैसे चले जाएंगे। अभी तो मुझे आपका चित्र बनाना है।

एक बार मेरी ऐसी ही धैर्य-परीक्षा एक कवि-मित्र ने ले डाली। उनके संपूर्ण जीवन में उन्होंने चार कुछ ऊटपटांग सी चीजें लिखीं, जिन्हें वे कविता कहते हैं। बीते 20 साल से वे इन्हें ही सुना रहे हैं। गलती से उन्होंने ये कविताएं उनके बड़ी बेटी को देखने आए मेहमानों को सुना दी थीं। लड़का ऐसा बिदका कि उसने ब्याह से मना कर दिया, क्योंकि कवि महोदय ने बेटी का नाम भी कविता ही रख रखा था। लड़के की दहशत जायज थी कि जब कविताएं ऐसी हैं, तो कविता जी कैसी होंगी?

उनकी एक कविता है- दीवार पर लटकी हुई तस्वीर कुछ कहती है। अब क्या कहती है यह वे भी नहीं जानते। जब एक श्रोता ने दूसरे से पूछा की ये तस्वीर क्या कहती है, तो दूसरा श्रोता जो कविता की मारक क्षमता से झल्लाया हुआ था बोला- ये तस्वीर यही कहती है तुम मेरी जगह किसी हुक में रस्सी डालकर इस कवि को लटका दो, तो मुझे भी मुक्ति मिले। उस दिन उनकी सारी कविता सुनने के बाद मैं संक्रमित-सा हो गया। और उस संक्रमण की कोई वैक्सीन भी नहीं बनी है।

ट्वीट-ट्वीट

आज हाकी की जीत टोक्यो में मिली और उसकी गूंज मुझे रात के दो बजे न्यूयार्क में सुनाई दी। भारतीय खिलाड़ियों ने एक ऐसा इतिहास रचा है, जिसका असर आने वाली पीढ़ियों पर सालों साल रहेगा और उन्हें प्रेरित भी करेगा। हाकी में 41 साल के बाद की जीत से लगता है कि देश बदल गया है। जय भारत।
अनुपम खेर@AnupamPKher

हाकी में हमारी लड़कियां ब्रिटेन से हार गईं तो लड़कों ने ब्रिटेन को हरा दिया। लड़के आस्ट्रेलिया से हारे तो लड़कियों ने आस्ट्रेलिया को हराया। लड़कियां अर्जेंटीना से हार गईं तो उनसे पहले लड़के अर्जेंटीना पर भारी पड़े। लड़कियां जर्मनी से हारीं तो लड़कों ने उसे हराकर कांस्य पदक अपने नाम कर लिया। एकदम संतुलित रवैया। भारत की अलहदा खासियत।
एचजीएस धालीवाल@hgsdhaliwalips

कुछ प्रशासनिक नवीन पटनायक का भी हो जाए। चाहे दुनावों में महिलाओं को अधिक टिकट देने हों, केंद्र से सहयोग के समय प्रधानमंत्री के साथ सम्मानजनक रूप से समन्वय करना हो या फिर आवश्यकता के वक्त भारतीय हाकी टीमों का समर्थन, उन्होंने राजनीतिक नेतृत्व की एक उम्दा मिसाल पेश की है।
अद्वैता काला@AdvaitaKala

स्वर्ण, रजत और कांस्य तो बस अलग-अलग धातुओं के रंग हैं। हमारी भारतीय हाकी टीम के खिलाड़ी असल चैंपियन हैं। वे बहुत ही दिलेर निकले।
संजय झा@JhaSanjay

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर आने की आशंका गहरा रही है?

हां	71
नहीं	21.9
कह नहीं सकते	7.1

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या पेगासस मामले में सुप्रीम कोर्ट का सवाल विपक्ष के लिए झटका है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

अबकी भारत को फला फिर से पांच अगस्त,
किया जर्मनी टीम को जब हॉकी में पस्त।
जब हॉकी में परस्त देश था कब का भूखा,
चार दशक के बाद मिटा मेडल का सूखा!
वहे खुशी के अश्रु आंख पनियाई सबकी,
भारत के 'ब्लू बॉय' ला रहे खुशियां अबकी।
-ओमप्रकाश तिवारी

प्रदीप शुक्ला
स्थानीय संपादक, झारखंड

झारखंड डायरी

ओबीसी आरक्षण पर बढ़ी सरगर्मी

राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) जातियों का आरक्षण बढ़ाने को लेकर राजनीतिक सरगर्मी एकाएक बढ़ गई है। खुद को ओबीसी जातियों का मसीहा साबित करने में हर दल दूसरे से बाजी मारने की जुगत में जुट गया है। हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के सभी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद तो इसे जोर-शोर से उठा ही रहे हैं, भाजपा और सहयोगी आजसू भी इस संवेदनशील मसले पर खुद को पिछड़ने नहीं देना चाह रहे। कांग्रेस, आजसू सहित अन्य कुछ दलों ने जातिगत मतगणना के लिए भी दबाव बनाना शुरू कर दिया है।

जातियों का अंकगणित राजनीतिक दलों को हमेशा लुभाता रहा है। हालांकि इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि समय-समय पर विभिन्न जातीय समूहों के हक की आवाज उठाने के पीछे का एक बड़ा उद्देश्य बड़े वोट बैंक को रिझाना भी होता है। झारखंड में ओबीसी का आरक्षण 14 प्रतिशत है, जो बिहार समेत अन्य पड़ोसी राज्यों की तुलना में कम है। इसे बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने की मांग बहुत पुरानी है। वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में भी इस मांग को उभार कर सभी राजनीतिक दलों ने मतदाताओं को लुभाने का भरसक प्रयास किया था। लिहाजा अब यह मांग जोर पकड़ रही है कि सरकार इस वादे को पूरा करने की दिशा में प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। दिलचस्प बात यह है कि सत्तारूढ़ गठबंधन के अहम सहयोगी दल कांग्रेस ने ही इस मुद्दे को हवा दी है, जिसे देखते हुए अन्य राजनीतिक दलों ने भी सुर में सुर मिलाना आरंभ कर दिया है। कांग्रेस ने बाकायदा इसे लेकर मुहिम आरंभ करने की घोषणा की है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी और पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री आरपीएन सिंह के निर्देश पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डा. रामेश्वर उरांव ने यह मांग उठाई है। भाजपा ने कांग्रेस को कठघरे में खड़ा करते हुए कटाक्ष किया है कि सरकार में शामिल दल को मांग उठाने की बजाय इसे पूरा करने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। भाजपा भी सरकार पर ओबीसी जातियों का आरक्षण बढ़ाने के लिए दबाव बना रही है।

राज्यपाल रमेश बैस को ज्ञापन सौंपते पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के लोग। जागरण

फिलहाल राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी का आरक्षण मिलाकर 50 प्रतिशत है। इसमें अनुसूचित जनजाति को 26 प्रतिशत और अनुसूचित जाति को 10 प्रतिशत आरक्षण मिलता है। इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण है। सरकार को इसका अंदाजा है कि यदि ओबीसी का कोटा बढ़ाते हैं तो यह कानूनी पेच में फंस सकता है, लेकिन मुसीबत यह है कि चुनाव में बढ़-चढ़ कर वादा किया गया था और ऐसी स्थिति में इससे पूरी तरह मुकरा भी नहीं जा सकता। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा भी इस पक्ष में है कि आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाया जाए।

ओबीसी संगठनों ने आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने की मांग को लेकर सरकार के साथ-साथ राजभवन का दरवाजा खटखटाना आरंभ कर दिया है। आने वाले दिनों में ऐसे समूह और मुखर होकर सामने आ सकते हैं। ओबीसी जातियों को चिन्हित करने का मसला भी इसकी एक कड़ी है। केंद्र सरकार ने अब इसका जिम्मा राज्यों पर डालने का निर्णय किया है। इससे भी राज्य सरकारों की जिम्मेदारी बढ़ेगी। पहले केंद्र के पाले में गेंद डालकर राज्य सरकारें बच जाती थीं, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। गठबंधन सरकार को यह बखूबी पता है कि ओबीसी समुदाय को रिझाने की कवायद में इस मुद्दे को सुलझाने में जरा से भी चूक हो गई तो इसका बड़ा राजनीतिक खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। इसकी पूरी संभावना है कि विधानसभा के मानसून सत्र में भी यह मुद्दा जोर-शोर से उठेगा।

सीबीआइ को जज हत्याकांड की जांच का जिम्मा : धनबाद के जज उत्तम आनंद हत्याकांड की जांच सीबीआइ के सुपुर्द कर दी गई है। इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस घटना का स्वतः संज्ञान लेना बड़ी वजह माना जा रहा है। हालांकि राज्य सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए, तत्काल अपर पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में विशेष जांच दल का गठन कर दिया था। विशेष जांच दल ने इस हत्याकांड से जुड़े संदिग्ध लोगों और साक्ष्यों की पड़ताल भी की। पुलिस की कई टीमें इस जांच में जुटी रहीं, लेकिन कोई ठोस निष्कर्ष पर पहुंचती नहीं दिखीं। इस बीच उच्च न्यायालय लगातार इसकी निगरानी और पूछताछ कर रही थी।

मंथन

पंकज कुमार
निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष, इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन

अवसर तलाश आगे बढ़े उद्योग

उद्योगों के प्रति उत्तर प्रदेश सरकार के संवेदनशील होने के कारण उद्यमियों को दशकों पुरानी चुनौतियों से छुटकारा मिला है और प्रदेश में औद्योगिक निवेश के लिए नया माहौल बना है

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को उत्तर प्रदेश सरकार से मिल रही अनेक प्रकार की राहत। प्रतीकात्मक

कोरोना की दूसरी लहर में उत्तर प्रदेश सरकार का माडल उद्योगों के लिए संजीवनी साबित हो रहा है। अनेक समस्याओं के बावजूद सरकार ने इंडस्ट्रियल लाकडाउन नहीं किया। नए उद्यमियों ने इस त्रासदी में भी उद्यमिता का परिचय देते हुए एक अवसर की तलाश की। अनेक उद्यमियों ने आक्सीजन प्लांट, आक्सीजन कंसन्ट्रेटर जैसे उपकरणों का निर्माण शुरू किया। कोरोना संक्रमण की पहली लहर में मास्क और पीपीई किट बनाने का हमारे उद्यमियों ने भरपूर प्रयास किया था। इस बार आक्सीजन कंसन्ट्रेटर, थर्मल स्कैनर, यूवी चैंबर, वेंटीलेटर आदि उपकरण बनाने की दिशा में उद्यमियों का प्रयास 'मेक इन इंडिया' की परिकल्पना को साकार करता है। भविष्य में हम दवाओं, जीवन रक्षक उपकरणों का पर्याप्त निर्माण कर पाएंगे, जो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में सार्थक कदम होगा।

कोरोना कर्फ्यू के दौर में भी उद्योगों को आंशिक तौर पर छूट मिलने से उद्यमियों ने उत्पादन की प्रक्रिया को चालू रखा। इस दौर में खानपान की चीजों के उत्पादन पर कोई रोक नहीं होने के कारण फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में सरकार की मंशा के अनुरूप काफी काम आगे बढ़ा है। एक्सपोर्ट सेक्टर में कोरोना की दूसरी लहर में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा है। इस आपदा काल में सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि सर्विस सेक्टर में हुई है। अब आनलाइन एप के माध्यम से घरों में आवश्यक चीजों की आपूर्ति करने का प्रचलन बढ़ा है। संक्रमण में आइसोलेशन के कारण कोई भी व्यक्ति सामान्य रूप से बाहर निकलने से परहेज करता है, लेकिन उद्यमियों के प्रयास से अधिकांश वस्तुएं मसलन दवाएं, फल, सब्जी, घरेलू सामान आदि घर पर ही डिलीवर हो जाते हैं। इस प्रकार आइटी का प्रयोग करके सर्विस सेक्टर में डोर स्टेप डिलीवरी से संबंधित व्यवसाय में काफी वृद्धि हुई है। इतना ही नहीं, जो उद्यमी विनिर्माण सेक्टर में कार्य करते थे, उन्होंने अपना विस्तार सर्विस सेक्टर में किया है।

आइआइए ने आइआइए मार्ट नामक पोर्टल बनाया है, जो एमएसएमई के बीच उनके द्वारा उत्पादित माल की खरीद और बिक्री का एक सशक्त और उपयोगी माध्यम है। सूक्ष्म, लघु उद्यमियों के लिए आइटी एक अवसर के रूप में सामने आया है, जिसका अधिकतम इस्तेमाल करने के बारे में हमें सोचना चाहिए। कोरोना काल में हमने समय समय पर शासन-प्रशासन को सुझाव दिए हैं, जो कारगर सिद्ध हुए हैं। आइआइए ने राष्ट्रीय स्तर पर और पूरे प्रदेश में चैप्टर लेवल पर कोविड हेल्प डेस्क की एक ऐसी प्रणाली विकसित की है, जिससे किसी भी पीड़ित व्यक्ति तक तुरंत सहायता पहुंचाई जा सकती है। हमने चिकित्सकों का एक पैनल भी बनाया है, जिससे पूरे प्रदेश में एमएसएमई इंडस्ट्री के श्रमिक, मजदूर और स्टाफ लाभान्वित हुए हैं। सरकार ने कोरोना से संबंधित कुछ वस्तुओं की जीएसटी में भी कमी की है। इससे एमएसएमई का हौसला बढ़ा है। सरकार ने सब्सिडी की भी घोषणा की है। ब्याज दर में भी कमी किए जाने के आसार हैं। लेकिन अब भी कुछ चुनौतियां हैं, जिनके बारे में सरकार के सहयोग की आवश्यकता है।

केंद्र और राज्य सरकार ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए उद्यमियों के हित में संजीदगी से निर्णय लिए हैं। केंद्र सरकार ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत उद्यमियों को पूंजीगत लाभ पहुंचाने के प्रयास किए। पूर्व में दिए गए लोन की ब्याज की अदायगी में मोरेटोरियम के तहत स्थगन दिया गया। अतिरिक्त देय ब्याज को लोन में बदलते हुए उद्यमियों को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया गया। इसका फायदा यह हुआ कि लगभग बंदी के कगार पर पहुंच गए उद्योग-धंधे भी चलने की स्थिति में आ गए। केंद्र सरकार की विभिन्न सरकारी परियोजनाओं को चलाने के आश्वासन से उद्योगों को बल मिला।

योगी सरकार ने नीति निर्धारण स्तर पर अनेक सार्थक कदम उठाए। इसके तहत पूर्व में स्थापित इकाइयों के उन्नयन, उद्यमियों की समस्याओं के निराकरण के लिए, संवेदनशील, प्रशासकीय व्यवस्था देने और इज आफ डूइंग बिजनेस के लिए अनुकूल औद्योगिक परिवेश बनाने के तहत औद्योगिक भूखंडों के समय विस्तारण को सुगम बनाने का प्रयास किया गया। उद्यमियों को देरी से भुगतान अहम समस्याओं में से एक रही है। इस दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार ने पहल करते हुए प्रदेश के सभी मंडलों में फेसिलिटेशन काउंसिल का गठन किया। भूजल नीति के तहत उद्योगों को जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के क्रम में राज्य जल बोर्ड द्वारा जारी नियमावली में भूजल निष्कर्षण में एमएसएमई को किसी लाइसेंस की अनिवार्यता से मुक्त किया गया। इससे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमियों को ईज आफ डूइंग बिजनेस के तहत राहत मिली है। यूपी सरकार ने प्रादेशिक औद्योगिक नीति 2020 का एक प्रस्ताव तैयार किया, जिसमें विभिन्न औद्योगिक संगठनों के माध्यम से इस विषय पर सुझाव मांगे गए। प्रदेश के सभी औद्योगिक क्षेत्रों की समीक्षा करते हुए खाली पड़े औद्योगिक भूखंडों को नए उद्यम को उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास शुरू किए गए हैं। राज्य में औद्योगिक निवेश बढ़ाने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है।

3.93 करोड़ से ज्यादा मुकदमे लंबित हैं निचली व अधीनस्थ अदालतों में। राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर 30 जुलाई तक उपलब्ध सूचना के आधार पर कानून मंत्री ने लोकसभा में यह जानकारी दी।

उत्तराखंड

आपदा प्रबंधन हेतु जनोपयोगी पहल

दैवीय आपदा पर किसी का वश नहीं है, लेकिन बेहतर प्रबंधन से इसके असर को न्यून किया जा सकता है। इस लिहाज से उत्तराखंड ने एक पहल की है। जनसामान्य को भूकंप की चेतावनी देने के उद्देश्य से सरकार ने आइआइटी रुड़की के वैज्ञानिकों के माध्यम से उत्तराखंड भूकंप अलर्ट एप तैयार कराया है। बुधवार को इसे लांच किया गया। यह एप राज्य में कहीं भी भूकंप आने पर तुरंत अलर्ट कर देगा, ताकि सतर्कता बरतते हुए जान-माल के नुकसान को कम किया जा सके। उत्तराखंड भूकंप के अति संवेदनशील जोन पांच एवं संवेदनशील जोन चार के अंतर्गत है। ऐसे में जरूरी है कि यहां विशेष एहतियात बरती जाए। अति संवेदनशील जोन पांच की बात करें तो इसमें रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली व उत्तरकाशी जिले शामिल हैं। ऊधमसिंह नगर, नैनीताल, चंपावत, हरिद्वार, पौड़ी व अल्मोड़ा जोन चार में हैं, जबकि देहरादून व टिहरी जिले ऐसे हैं, जो दोनों जोन के अंतर्गत आते हैं।

आपदा से निपटने के मद्देनजर आधुनिक तकनीकी का अधिक से अधिक उपयोग करने के साथ ही जनोपयोगी शोध कार्य निरंतर जारी रखने की जरूरत है

हालांकि भूकंप का पूर्वानुमान बताने वाली कोई तकनीक अभी विकसित नहीं हुई है, लेकिन भूकंप आने पर इसके असर को न्यून करने की दिशा में तो कदम बढ़ाए जा सकते हैं। इसे देखते हुए आइआइटी रुड़की के विज्ञानी लंबे समय से कोशिशों में जुटे थे और अब उत्तराखंड भूकंप अलर्ट एप के रूप में इसकी परिणति सामने आई है। आइआइटी के विज्ञानियों ने भूकंप की दृष्टि से उत्तराखंड के जिलों में कई उपकरण लगाएं हैं, जो इस एप से कनेक्ट हैं। निर्धारित परिमाण से अधिक का भूकंप आने पर यह एप तुरंत अलर्ट जारी कर देगा। यद्यपि इसका समय कम होगा, मगर संभावित जान-माल की क्षति को न्यून करने के लिए लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होगा। निश्चित रूप से इसका फायदा राज्यवासियों को मिलेगा। इसी तरह का अर्ली वार्निंग सिस्टम अन्य क्षेत्रों में भी विकसित करने की जरूरत है। अतिवृष्टि, बादल फटने की निरंतर हो रही घटनाओं से भी उत्तराखंड त्रस्त है। हालांकि इसके लिए डाप्लर रडार महत्वपूर्ण है। इनमें से एक मुक्तेश्वर में लग चुका है, जबकि सुरकंडा में इसकी स्थापना का कार्य जारी है। डाप्लर रडार से मौसम का सटीक पूर्वानुमान मिलता है। लिहाजा इससे मिलने वाली जानकारियां भी आमजन तक पहुंचें, इसके लिए भी भूकंप अलर्ट एप जैसी पहल की जरूरत है। आपदा से निबटने के मद्देनजर आधुनिक तकनीकी का अधिक से अधिक उपयोग करने के साथ ही जनोपयोगी शोध कार्य निरंतर जारी रखने होंगे। इसके लिए सरकार को आइआइटी समेत अन्य संस्थानों से बेहतर समन्वय स्थापित कर कदम उठाने होंगे। ज्यादा से ज्यादा जनोपयोगी शोध होंगे तो इसका फायदा उत्तराखंड के साथ ही देश को भी मिलेगा।

हिमाचल प्रदेश

नशे के खिलाफ सराहनीय पहल

जब भी नारी शक्ति एकजुट हुई है समाज में बदलाव आया है। सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन में महिलाओं की अहम भूमिका रही है। नशा समाज को घुन की तरह चाट रहा है। नशे के समूल नाश के लिए कई अभियान भी चलाए गए, लेकिन उनके सकारात्मक परिणाम नहीं देखे गए हैं। गांवों की दहलीज तक नशा पहुंच चुका है। हद तो यह है कि शराब के ठेकों के अलावा चाय व अन्य छोटी दुकानों पर भी शराब बिक रही है।

बेशक पुलिस इनके खिलाफ कार्रवाई भी करती है, लेकिन इस पर रोक नहीं लग पाई है। कई जगह महिलाओं ने शराब ठेके खोलने के खिलाफ भी मोर्चा खोला, लेकिन एक जगह से हटाकर दूसरी जगह पर शराब ठेका खोल दिया जाता है। नशे के कारण कई घरों में शांति भंग हो चुकी है तो कई परिवार बिखर गए हैं। कई परिवारों को नशे के कारण रोजी रोटी की दिक्कत हो रही है। नशे के खिलाफ कई अभियान भी चलाए जाते हैं, लेकिन इसमें भी सफलता नहीं मिल पा रही है। सरकार ने भी समाज के उत्थान के लिए कई योजनाएं चलाई हैं, लेकिन इनका भी अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है। युवा पीढ़ी भी

नशे का सेवन करने वालों के नाम बीपीएल की सूची से हटाने की सराहनीय पहल। प्रतीकात्मक

नशे के खिलाफ महिला शक्ति की पहल सराहनीय है। जिसके पास नशा करने के लिए पैसे हैं, वह गरीब कैसे हो सकता

नशे की चपेट में आ रही है। गांव में शराब के कारण झगड़े भी बढ़ गए हैं। इसी बीच यह राहत की खबर है। मंडी जिला के करसोग उपमंडल की महिलाओं ने सराहनीय पहल की है। छह महिला मंडलों की सदस्यों ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर पंचायत की ग्रामसभा में प्रस्ताव रखा कि जो लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं और नशे का सेवन करते हैं, उनका नाम गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों (बीपीएल) की सूची से हटा दिया जाए। मातृ शक्ति के इस प्रस्ताव को ग्राम सभा ने भी स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही महिलाओं ने शराब बेचने वालों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाने का फैसला लिया है। इन महिलाओं का दावा था कि गांव में कई परिवार ऐसे हैं, जो राशन के लिए पैसे न होने की बात करते हैं, लेकिन शराब खुलकर पीते हैं। ऐसे लोग गांव का माहौल भी खराब करते हैं। इस तरह के फैसले पहले भी राज्य के कुछ गांवों में लिए गए हैं। राज्य में और गांवों में भी इस तरह के फैसले लिए जाएंगे। उम्मीद की जानी चाहिए कि नशा मुक्त हिमाचल की दिशा में यह अहम पहल होगी।

बिहार

अनियंत्रित रफ्तार पर लगे लगाम

इस बात की सराहना होनी चाहिए कि राज्य सरकार सड़क हादसों को नियंत्रित करने के उपाय में जुट गई है। राज्य में आए दिन दुर्घटनाओं की खबरें सुर्खियां बनती हैं। लोगों की जान जाती है और परिवार बिखर जाते हैं। कई बार तो हादसों में बच जाने के बाद भी व्यक्ति आजीवन अपंगता का शिकार हो जाता है। हादसों के लिए कई चीजें जिम्मेदार होती हैं, उनमें हाईवे व अन्य मुख्य मार्गों पर बने ब्लैक स्पाट प्रमुख हैं। यह सुकून की बात है कि राज्य सरकार ने इन स्थानों को चिह्नित कर लिया है। राज्य में कुल 1400 से अधिक ऐसे स्थान चिह्नित किए गए हैं, जहां सर्वाधिक दुर्घटनाएं हो रही हैं। इनमें तिराहे और चौराहों की संख्या अधिक है।

इसके अलावा उन स्थानों पर अधिक दुर्घटनाएं हो रही हैं, जहां एक से अधिक सड़कों का मिलान होता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर परिवहन विभाग ने सड़कों के मिलान बिंदु पर साइनेज, स्पीड ब्रेकर, जेब्रा क्रासिंग और पेंटिंग जैसे काम किए जाने का फैसला लिया है। परिवहन विभाग की यह

जब तक हम स्वयं अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक नहीं होंगे, तब तक सड़क हादसे होते रहेंगे

एक से अधिक सड़कों के मिलान वाली जगहों पर होती है दुर्घटना की अधिक आशंका। फाइल

अच्छी पहल है। निश्चित रूप से इससे दुर्घटनाओं पर काबू पाने में मदद मिलेगी। हालांकि इसकी भी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि शहर व गांवों में कई दुर्घटनाएं अतिक्रमण की वजह से भी हो रही हैं। अधिकतर शहरों में सड़कों पर लोग कब्जा जमाए बैठे हैं, जिससे सड़कों की चौड़ाई कम हो गई है। सड़कों पर ही वाहनों के खड़े करने से भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। ऐसे में न सिर्फ जाम लगता है, बल्कि हादसे भी होते रहते हैं। बेहतर होता कि जिला प्रशासन ऐसे लोगों पर कार्रवाई करता और सड़कें खाली करवाने की कोशिश होती। आम लोगों को भी इसके प्रति संजीदा होने की जरूरत है। हादसे के बाद सड़क जाम करने की परिपाटी पर सख्ती से रोक लगनी चाहिए।

अमूमन फोरलेन से लेकर ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य मार्गों पर ओवरलोडेड जर्जर वाहन फर्राटा भरते दिखते हैं। कायदे से इन्हें सड़क पर आना ही नहीं चाहिए। इसी तरह अनियंत्रित रफ्तार पर लगाम लगानी होगी। जब तक हम खुद अपनी सुरक्षा के प्रति सजग नहीं होंगे, तब तक सड़क हादसे होते रहेंगे। अपने और स्वजनों की खुशी के लिए सुरक्षित यात्रा का संकल्प सभी को लेना होगा।

बंगाल

पीएम किसान निधि पर सियासत

बंगाल में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर शुरू से ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सियासत करती आ रही हैं, जो अब भी जारी है। पहले तो इसे बंगाल में लागू नहीं होने दिया, क्योंकि इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा को लाभ मिल जाता। जब विधानसभा चुनाव सिर पर आया और भाजपा नेताओं ने इसे मुद्दा बनाया तो कहीं सियासी नुकसान न हो जाए तो अनमने तरीके से ममता ने पत्र लिखकर योजना लागू करने पर सहमति जताई। विधानसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी से लेकर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह तक यह कहते रहे कि ममता सरकार किसानों की सूची नहीं भेज रही है।

चुनाव में तीसरी बार जीत मिलने और सीएम बनने के बाद ममता ने किसानों की सूची केंद्र सरकार को भेजी। उसी अनुसार पीएम मोदी ने विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार के बाद भी देश के अन्य राज्यों के साथ-साथ बंगाल में भी किसान सम्मान निधि योजना के तहत पहली किस्त के रूप में सात लाख से अधिक किसानों के खाते में दो-दो हजार रुपये भेजे। उस समय भी ममता ने सवाल उठाया था कि दो-दो हजार रुपये ही क्यों भेजे गए? किसानों को पिछला बकाया जोड़कर 18 हजार रुपये मिलने चाहिए थे। वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष की ओर से सवाल उठाया गया कि बहुत सारे असली किसानों का नाम छोड़कर तृणमूल नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के नाम भेजे गए हैं, जिसकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि एम्फन तूफान पीड़ितों को राहत देने में भी ऐसे ही फर्जीवाड़ा सामने आए थे, जिसमें असली पीड़ितों को रुपये नहीं मिले और राहत राशि तृणमूल नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के खाते में पहुंच गए थे। यही वजह था कि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के आरोप गंभीर माने जा रहे थे। अब कहा जा रही है कि बंगाल सरकार ने केंद्र को 44.8 लाख किसानों के नाम की सूची भेजी थी, जिनमें से 9.5 लाख नामों को खारिज कर दिया गया है।

देश के अन्य राज्यों के साथ-साथ बंगाल में भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत पहली किस्त के रूप में सात लाख से अधिक किसानों के खाते में दो-दो हजार रुपये भेजे गए

इस बाबत ममता सरकार ने नाराजगी जताते हुए केंद्र को पत्र लिखा है, जिसमें पुनर्विचार करने अनुरोध किया गया है। परंतु यहां सवाल यह उठ रहा है कि आखिर एक साथ 9.5 लाख नाम खारिज क्यों हुए? यह जरूरी है कि एक भी असली किसान इस योजना से वंचित नहीं हो। क्योंकि सियासी नफा-नुकसान देखने की वजह से पहले ही बंगाल के 70 लाख से अधिक किसानों को किसान सम्मान निधि नहीं मिल सका था। अब जब योजना शुरू हुई है तो इस पर राजनीति बंद होनी चाहिए और केंद्र व राज्य सरकार को चाहिए कि योजना के लाभ से कोई वंचित न हो।

श्रद्धा का महासावन

भक्ति एवं उल्लास का मास

श्रवण नक्षत्र में उत्पन्न सावन का महीना चांद्र वर्ष के 12 महीनों में पांचवां है। यह शरीर पंचभौतिक है। शरीर में शिव पृथ्वी तत्व के रूप में विद्यमान हैं। इसलिए शिव के पार्थिव-पूजन का विधान है। शिव के पांच मुख हैं, जिन्हें तत्पुरुष, अघोर, सद्योजात, वामदेव और ईशान नाम से जाना जाता है। अघोर शिव के मुख से ही सभी तंत्रों-मंत्रों का कथन हुआ है। व्रतों-पर्वों वाला सावन शिव की भक्ति एवं भावोल्लास का मास है। इसमें पृथ्वी-प्रकृति हरी भरी हो जाती है। सावन शिव के आह्लाद-प्रसन्नता का सूचक है। प्रकृति भी पृथ्वी तत्व की मूल धरा का अभिसिंचन कर उसे रसवंती बनाकर शिवत्व प्रदान करती है। शिवभक्तों में बोल बम से नया उत्साह स्फूर्त होने लगता है। रुद्राभिषेक एवं पार्थिव-पूजन शिव-सायुज्य का प्रदाता है। दुग्धाभिषेक करने वालों को सर्पों-ज्वरों और विष का भय नहीं होता, क्योंकि शिव नीलकंठ हैं। कामनानुसार विविध पदार्थों से शिवाभिषेक विशेष फल प्रदायी है। महानिर्वाणतंत्र-मेरुतंत्र, शिवरहस्य, ईशानसंहिता-सूत संहिता, शिवपुराण-लिंगपुराण में शिव के विविध रूपों की उपासना-प्रयोग बताए गए हैं। भस्म त्रिपुंड या श्वेत मलयागिरि चंदन, रुद्राक्ष, श्वेतवस्त्र धारण करके श्वेत पदार्थों से ही पूजन करने की अनिवार्यता है। गोधूलि बेला की पूजा लाभकारी होती है। इस समय शिवतांडव स्तोत्र का पाठ श्रीप्रद होता है। कुशोदक अभिषेक नैरोग्य प्रदायक है। शिव की आठ मूर्तियां हैं। पूर्व में पृथ्वी रूप, ईशानकोण में जलरूप, उत्तर में अग्निरूप, वायव्यकोण में वायुरूप, पश्चिम में आकाशरूप, नैऋत्य में यजमानरूप, दक्षिण में चंद्ररूप और अग्निकोण में सूर्य रूप का स्थापन-आह्वान करना चाहिए। अभिषेक में गणेश-गौरी, नंदी-वीरभद्र, कार्तिकेय-कुबेर, कीर्तिमुख तथा सर्पों का ध्यान पूजन आवश्यक होता है।

डा. रामानंद शुक्ल
शास्त्रज्ञ एवं प्रमुख
कालिकुलालयम, अयोध्या

स्कैन करें और पढ़ें 'श्रावण मास' से संबंधित सभी सामग्री

संगठित अपराध पर नियंत्रण के लिए मप्र सरकार लाएगी उप्र जैसा गैंगस्टर एक्ट

- मुख्यमंत्री के निर्देश पर गृह और विधि विभाग के अधिकारियों ने की बैठक
- उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के प्रविधानों का किया जा रहा है अध्ययन

नईदुनिया, भोपाल

मध्य प्रदेश में अवैध व मिलावटी शराब, मानव तस्करी, नकली दवा, अवैध हथियारों का निर्माण-व्यापार और अवैध खनन जैसे संगठित अपराधों पर सख्ती के साथ नियंत्रण के लिए शिवराज सरकार गैंगस्टर एक्ट लाएगी। यह उत्तर प्रदेश के गुंडा नियंत्रण अधिनियम की तरह होगा। इसमें कुछ प्रविधान महाराष्ट्र कंट्रोल आफ आर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट के भी शामिल किए जा सकते हैं। इनका अध्ययन किया जा रहा है। इसमें पुलिस को ज्यादा अधिकार मिलेंगे। पूछताछ के लिए रिमांड अवधि 50 दिन तक हो सकती है। आरोपित की संपत्ति जब्त करने का अधिकार मिलेगा। आरोपित को जमानत भी आसानी से नहीं मिल पाएगी।

प्रदेश में पिछले दिनों अवैध रेत खनन और मिलावटी शराब से जुड़े कई मामले सामने आए हैं। मिलावटी शराब का कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए विधानसभा के मानसून सत्र में आबकारी अधिनियम संशोधन विधेयक भी प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें मिलावटी शराब के सेवन से किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर आरोपित को मृत्युदंड की सजा का प्रविधान रहेगा।

शिवराज सिंह चौहान। फाइल/इंटरनेट मीडिया

इसके साथ ही संगठित अपराध पर नियंत्रण के लिए उत्तर प्रदेश की तर्ज पर गुंडा नियंत्रण अधिनियम सख्त कानून लागू करने की तैयारी है।

दरअसल, मौजूदा प्रविधानों में आरोपितों को राहत मिल जाती है। जबकि, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में जो प्रविधान हैं, उनमें पुलिस को कई अधिकार मिले हुए हैं। उनमें आसानी से जमानत नहीं मिल पाती है। पुलिस को पूछताछ के लिए अतिरिक्त समय भी मिलता है। यही वजह है कि शिवराज सरकार ने सख्त कानून बनाकर संगठित अपराध पर नकेल कसने की तैयारी शुरू की है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर गृह विभाग अधिनियम बनाने के लिए सक्रिय हो गया है। इस संबंध में विधि विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक भी हो चुकी है। अपर मुख्यसचिव डा. राजेश राजौरा ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर इस विषय पर काम शुरू हो गया है।

गृह विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस अधिनियम के दायरे में वे सभी अपराध शामिल किए जाएंगे, जिसमें एक से अधिक व्यक्ति की भूमिका होती है। मानव तस्करी, जाली नोट, नकली दवाओं का व्यापार, अवैध हथियारों का निर्माण और व्यापार, अवैध खनन, मिलावटी शराब का कारोबार, फिरौती के लिए अपहरण जैसे अपराधों को इस श्रेणी में रखा जाएगा। विधानसभा से विधेयक पारित होने के बाद इसे केंद्र सरकार को अनुमति के लिए भेजा जाएगा। माना जा रहा है कि संगठित अपराध पर अंकुश लगाने में प्रदेश सरकार के इस कदम को केंद्र सरकार का भी साथ मिलेगा। यदि नौ अगस्त से प्रारंभ होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र तक यह तैयार हो जाता है तो इसे प्रस्तुत किया जा सकता है अन्यथा यह नवंबर-दिसंबर के शीतकालीन सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा।

बादल फटने के कारण और रोकथाम के खोजे जाएंगे उपाय

रमेश चंद्रा, नैनीताल

- पीएम 2.5 पर नजर रखने को लगाए जाएंगे सीयूपीआइ उपकरण
- भारत-जापान के विज्ञानी मिलकर आकाश योजना के तहत करेंगे काम

हिमालयी क्षेत्र में बढ़ रही बादल फटने की घटनाओं के कारण व उसकी रोकथाम के अब वैज्ञानिक उपाय तलाश जाएंगे। इसके लिए आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान (एरीज) हिमालय क्षेत्र में पार्टिकल्स पाल्यूशन या पार्टिकुलेट मैटर (पीएम) 2.5 मापन के लिए अत्याधुनिक उपकरण लगाने जा रहा है। इस 'आकाश योजना' को भारत व जापान के विज्ञानी संयुक्त रूप से अमलीजामा पहनाएंगे।

आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान (एरीज) के वरिष्ठ वायुमंडलीय विज्ञानी डा. नरेंद्र सिंह ने बताया कि बीते कुछ सालों से हिमालयी क्षेत्रों में बादल फटने की घटनाओं में वृद्धि हुई है। हालांकि प्रथम दृष्टया इसका कारण मौसम परिवर्तन को माना जा रहा है, लेकिन यह पता लगाना भी जरूरी है कि इन घटनाओं में प्रदूषण कितना बड़ा कारण है। इसके लिए भारत-जापान मिलकर हिमालय से लगे उत्तराखंड के कई हिस्सों में कांपेक्ट यूजफुल पार्टिकुलेट मैटर इन्फार्मेशन (सीयूपीआइ) उपकरण लगाने जा रहे हैं। इस कार्य का जिम्मा एरीज को सौंपा गया है। उपकरण स्थापित किए जाने का कार्य सितंबर में शुरू कर दिया जाएगा। फिलहाल इसके लिए स्थान चयनित किए जा रहे हैं, जिसमें अधिक प्रदूषण उत्सर्जित करने वाले इलाकों को शामिल किया जा रहा है। डा. नरेंद्र सिंह के अनुसार, सीयूपीआइ स्थापित किए जाने का कार्य अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा। उपकरणों की कीमत करीब 25 लाख है।

इन पर होगा काम : सीयूपीआइ से पीएम 2.5 से मौसम पर पड़ रहे असर का सटीक आकलन किया जा सकेगा। मानव स्वास्थ्य पर पड़ रहे प्रभाव का भी पता चल सकेगा। इससे कृषि में सुधार लाने के उपाय भी तलाशे जा सकेंगे।

आकाश योजना में एरीज समेत देश के कई संस्थान शामिल : आकाश राष्ट्रीय योजना है, जिसमें एरीज समेत देश के कई विश्वविद्यालयों व अनुसंधान केंद्रों को शामिल किया गया है। इस सामूहिक योजना से वायु प्रदूषण पर व्यापक स्तर पर नजर रखी जा सकेगी, जिससे भविष्य में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण कर पाना आसान हो जाएगा।

उत्तराखंड मे कम है पीएम 2.5 प्रदूषण : देश के अन्य राज्यों की तुलना में उत्तराखंड पीएम 2.5 उत्सर्जित करने वालों में काफी नीचे है। दो साल पहले काशीपुर में पीएम 2.5 की मात्रा दो सौ जा पहुंची थी। मानसून के दौरान यह प्रदूषण कम हो जाता है, लेकिन शीतकाल में बढ़ जाता है।

जीते-जी नहीं मिला विमल को न्याय, मरने के बाद बताया निर्दोष

प्रभजोत कौर, आगरा

- एसआइटी की जांच में फर्जी बताई गई थी बीएड की डिग्री, बीएसए ने थमाया था बर्खास्तगी का नोटिस
- पत्नी की याचिका पर कुलाधिपति कार्यालय ने मांगा विवि से जवाब तो डिग्री बताई असली

खुद को सही साबित करने के लिए विमल आफिस-आफिस दौड़ते रहे। अफसरों की मनुहार करते रहे। किसी के पैर पकड़े, तो किसी के सामने मिन्नतें कीं। सभी ओर से उन्हें 'फर्जी डिग्री वाला' ही बता दिया गया। नौकरी पर खतरा और सार्वजनिक रूप से शर्मसार होने की वजह से उन्होंने चारपाई पकड़ ली। कुछ दिन बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। पति की 'लड़ाई' को जब सीमा कुमारी ने आगे बढ़ाया, तो कुलाधिपति के स्तर से जांच कराई गई। पता चला, विमल निर्दोष हैं। उनकी डिग्री असली है।

मामला डा. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा का है। विश्वविद्यालय से सत्र 2004-05 में बड़ी संख्या में बीएड की फर्जी डिग्री जारी की गई थीं। विशेष जांच दल (एसआइटी) की जांच में इसका राजफाश हो चुका है। एसआइटी ने टैंपर्ड और फर्जी डिग्री की सूची जारी की। इसमें आगरा के एत्मादपुर निवासी और खेरागढ़ के रुधऊ प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक विमल किशोर का भी नाम था। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने मार्च, 2019 में विमल को नोटिस दिया।

> विमल की पत्नी ने विश्वविद्यालय के खिलाफ मुकदमा किया है। जांच कराई गई तो पता चला कि डिग्री न तो फेक है और न ही टैंपर्ड है। अब नियमानुसार कार्रवाई होगी।
> -डा. अरुण दीक्षित, विवि के अधिवक्ता

इसके बाद जुलाई में रिमाइंडर देते हुए नौकरी से बर्खास्तगी की चेतावनी दे दी गई। विमल ने अपनी बीएड की डिग्री को सही साबित करने के लिए अफसरों के यहां चक्कर काटे। बीएसए के स्तर से निस्तारण न होने पर विश्वविद्यालय में भी चक्कर लगाए। परेशान होकर वह बीमार हो गए। मार्च, 2020 में विमल की मृत्यु हो गई। विमल की पत्नी सीमा कुमारी ने सितंबर, 2020 में स्थायी लोक अदालत में याचिका दायर की। इस पर कुलाधिपति ने विश्वविद्यालय से जानकारी मांगी। जून, 2021 में विवि ने कुलाधिपति को भेजे पत्र में स्पष्ट कर दिया कि विमल किशोर की बीएड की डिग्री न तो फर्जी है और न ही टैंपर्ड।

मृतक आश्रित कोटे से नहीं मिली नौकरी

सीमा ने मृतक आश्रित नौकरी के लिए आवेदन किया। विभाग ने यह कहकर इन्कार कर दिया कि उनके पति विमल का मामला फर्जी और टैंपर्ड डिग्री का है। इसके बाद ही सीमा ने मुकदमा किया।

सीमा की पीड़ा

पिछले साल फरवरी में पति (विमल) का वेतन रोक दिया गया। उन्होंने खाना-पीना छोड़ दिया। विवि के न जाने कितने ही चक्कर काटे, पर सुनवाई नहीं हुई। अगर उन्हें फर्जीवाड़ा करना ही था तो डिग्री फर्स्ट डिवीजन की बनवाते, थर्ड डिवीजन ही क्यों रह गए? 2005 में बीएड करने के बाद नौकरी 2016 में मिली क्योंकि मेरिट नहीं थी। 2011 में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) क्वालीफाई भी किया।

गोबर और कचरा जमा करिए, बदले में मिलेगा गैस सिलेंडर

पूर्णेंदु कुमार, समस्तीपुर : कचरा और गोबर के बदले गैस सिलेंडर देने की योजना बिहार के मधुबनी जिले में सफल रही है। डा. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा (समस्तीपुर) अब इसकी शुरुआत मोकामा (पटना) में करने जा रहा है। पटना बिहार का दूसरा जिला होगा, जहां यह योजना शुरू की जाएगी। इससे गरीब महिलाओं को भोजन बनाने के दौरान धुएं से मुक्ति मिलेगी, वहीं लोगों को रोजगार भी मिलेगा और खेतों के लिए जैविक खाद भी तैयार होगी।

मोकामा प्रखंड के औटा गांव में इस तकनीक को आगे बढ़ाने के लिए मोकामा घाट ट्रस्ट को जिम्मेदारी दी गई है। इस संबंध में पूसा कृषि विवि के साथ ट्रस्ट की पारुल त्रिपाठी ने एक समझौता किया है। ट्रस्ट ग्रामीणों को जागरूक कर रहा है। पांच दर्जन से अधिक परिवार इससे जुड़ गए हैं। उन्हें गीला और सूखा कचरा अलग-अलग रखने के लिए हरे और नारंगी रंग की डस्टबिन दी जा रही है। इस योजना से जुड़े पूसा कृषि विवि के विज्ञानी डा. शंकर झा का कहना है कि इस महीने के अंतिम सप्ताह से कार्य शुरू हो जाएगा। पूरे प्रोजेक्ट की लागत तकरीबन 20 लाख रुपये है।

मोदी सरकार के कार्यकाल में चोरी 75 फीसद विरासत मिलीं वापस

- केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने राज्य सभा में दी जानकारी
- नेहरू-गांधी परिवार अपनी व्यक्तिगत संपति बढ़ाने में लगा रहा

नई दिल्ली, एएनआइ : मोदी सरकार के पिछले सात साल के कार्यकाल में देश भर से चोरी गई विरासतों में से 75 फीसद को दोबारा हासिल कर लिया गया है।

यह जानकारी केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने राज्य सभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में दी है। रेड्डी ने बताया कि 1976 से अब तक कुल 54 प्राचीन काल की वस्तुएं (एंटीक्विटीज) प्राप्त की गई हैं। उन्होंने बाद में राज्यसभा में कहा कि यह बड़े गर्व की बात है कि चोरी की गई विरासतों को हमें दोबारा हासिल करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई। 2014 से हमें इस कार्य में विशेष सफलता मिली है। मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान 41 प्राचीन वस्तुएं प्राप्त की गईं, जो समय-समय पर हमारे देश से चोरी की गई थीं। यानी हमने चोरी गई विरासतों में से 75 फीसद को प्राप्त कर लिया। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि इन प्राचीन वस्तुओं की देश को दोबारा प्राप्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत संबंधों के कारण ही संभव हुई, जिनके विभिन्न देशों के प्रमुखों से बहुत अच्छे संबंध हैं।

जी किशन रेड्डी। फाइल/इंटरनेट मीडिया

केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि पूर्व में सत्ता में नेहरू-गांधी परिवार के लोग अपनी व्यक्तिगत संपत्ति को बढ़ाने में ही लगे रहे। इन्होंने भारत की सांस्कृतिक संपदा की कोई चिंता नहीं की। 1976 से कांग्रेस के 25 साल के कार्यकाल में मात्र 10 प्राचीन काल की वस्तुएं (विरासत) दोबारा हासिल की जा सकीं।

बांग्लादेश में मिली भगवान विष्णु की दुर्लभ प्रतिमा

ढाका, प्रेट्र : बांग्लादेश में पुलिस ने एक हजार साल पुरानी काले पत्थर की भगवान विष्णु की दुर्लभ प्रतिमा बरामद की है। यह प्रतिमा एक अध्यापक के घर मिली है। स्थानीय मीडिया के अनुसार, बांग्लादेश के कोमिल्ला जिले के बोरो गोआली गांव में मिली यह प्रतिमा 23 इंच ऊंची और 9.5 इंच चौड़ी है। इसका वजन 12 किलो है। पुलिस ने बताया कि मूर्ति यहां रहने वाले एक अध्यापक अबु युसुफ को डेढ़ माह पहले जमीन की खोदाई में मिली थी। उसने इसकी जानकारी स्थानीय प्रशासन को नहीं दी और चुपचाप घर में रख ली। गोपनीय सूचना के आधार पर अब मूर्ति हासिल कर ली गई है। पुलिस को अबु युसुफ ने बताया कि मूर्ति तालाब की खोदाई के दौरान उसे मिली थी। काम में व्यस्त रहने के कारण वह पुलिस को जानकारी नहीं दे सका। पुरातत्व विभाग के अनुसार, भगवान विष्णु की यह प्रतिमा दुर्लभ है। प्रतिमा एक हजार साल से ज्यादा पुरानी है। इसे सुरक्षित रखने और उचित देखभाल के लिए मैनावती संग्रहालय को सौंपा जाएगा।

81 देशों में फैल चुका है कोरोना का गामा वैरिएंट, जबकि अल्फा वैरिएंट 182 देशों में पहुंच चुका है। कोरोना के मामले दुनिया में एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं।

लश्करगाह में जंग तेज, तालिबान को खदेड़ने की कोशिश

बढ़ता संकट ▸ अफगान सेना ने मारे 303 तालिबान आतंकी, नागरिकों की हत्या और पलायन से यूएन चिंतित

अपनी स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए अफगान सेना ने किए हवाई हमले

काबुल, एएनआइ : अफगानिस्तान में प्रांतीय राजधानियों पर कब्जे के लिए चल रही लड़ाई के दौरान लश्करगाह में खून-खराबा बढ़ गया है। मौजूदा स्थिति में 17 प्रांतों की राजधानी खतरे में हैं। इधर अफगान सरकार ने दावा किया है कि उसने 24 घंटे में 303 तालिबान आतंकियों को ढेर कर दिया है।

हेलमंद प्रांत की राजधानी लश्करगाह में आठ दिन से लगातार जंग चल रही है। अफगान सेना को यहां कब्जा बरकरार रखने के लिए पूरी ताकत लगानी पड़ रही है।

प्रांतीय परिषद के प्रमुख अताउल्लाह अफगान ने टोलो न्यूज को बताया कि लश्करगाह के पीडी 1 में पुलिस मुख्यालय, गवर्नर कार्यालय और जेल के पास तालिबान आतंकियों से अफगान सेना का आमने-सामने युद्ध चल रहा है। इसका नागरिक भी शिकार हो रहे हैं। अब तक यहां 40 से ज्यादा नागरिकों की हत्या कर दी गई है, 100 से ज्यादा घायल हुए हैं। अफगान सेना ने अपनी मजबूत स्थिति बनाए रखने के लिए हवाई हमले भी किए हैं। यहां 75 से ज्यादा आतंकी मारे जाने का दावा किया गया है।

अफगान रक्षा मंत्रालय के अनुसार, पिछले 24 घंटे के दौरान जमीन पर चल रही लड़ाई के साथ सेना ने हवाई हमले भी किए हैं। इसमें 303 आतंकियों को मार दिया गया। 125 आतंकी घायल हुए हैं। आतंकियों के मरने का यह आंकड़ा सभी प्रांतों का है। मंत्रालय ने हवाई हमले के दो वीडियो भी साझा किए हैं।

हजारों लोग फंसे हुए हैं युद्ध में : संयुक्त राष्ट्र (यूएन) महासचिव एंटोनियो गुतेरस ने लश्करगाह में चल रहे युद्ध पर चिंता व्यक्त की है। गुतेरस ने कहा है कि यहां नागरिकों की हत्या हो रही है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि हजारों लोग युद्ध में फंसे हुए हैं। अमेरिका ने भी लश्करगाह को लेकर चिंता जताई है।

अफगानिस्तान में तालिबान से लड़ाई तेज हो गई है। तालिबान और अफगान सेना के जवान कई स्थानों पर आमने-सामने हैं। हेलमंद प्रांत की राजधानी लश्करगाह में पसरे सन्नाटे के बीच सड़क से गुजरता एक मोटरसाइकिल सवार। एपी

बुर्का न पहनने पर बल्ख जिले में 21 साल की लड़की की गोली मारकर हत्या

एएनआइ के अनुसार, अफगानिस्तान में तालिबान के अत्याचारी फरमान शुरू हो गए हैं। तालिबान ने बल्ख जिले में एक कार से 21 साल की लड़की नाजनीन को बाहर खींच लिया और उसकी सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी। नाजनीन का जुर्म इतना था कि वह बुर्का नहीं पहने हुए थी। जिलों पर कब्जा करने के बाद तालिबान ने 1996 से 2001 के शासन में लागू अपने पुराने कानून फिर लागू कर दिए हैं। यहां महिलाओं को अकेले और बिना बुर्का के घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी है। पुरुषों को दाढ़ी रखना जरूरी कर दिया है। कोई महिला अपने घर के पुरुष के बिना बाहर नहीं निकल सकती है। दुकानों पर महिलाओं के बैठने पर भी रोक लगा दी गई है।

तालिबान का एलान, अफगान अधिकारियों को निशाना बनाते रहेंगे

काबुल, एएनआइ : काबुल में कार्यवाहक रक्षा मंत्री को निशाना बनाकर किए गए कार बम विस्फोट और फायरिंग के बाद तालिबान ने कहा है कि वह ऐसे हमले करता रहेगा। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने ट्वीट कर कहा कि यह आत्मघाती हमला तो शुरूआत है। तालिबान अफगानिस्तान सरकार के हर बड़े नेता को निशाना बनाएगा। ज्ञात हो कि एक दिन पहले अफगान सरकार के कार्यवाहक रक्षा मंत्री बिसमिल्लाह मोहम्मदी के आवास के पास ही कार बम विस्फोट किया गया था। यहां तालिबान के चार आतंकियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। बाद में चारों आतंकी मार गिराए गए। आइएएनएस के अनुसार, अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कार्यवाहक रक्षा मंत्री के आवास के पास हुई आतंकी कार्रवाई की निंदा की है।

50 तालिबान आतंकियों ने समर्पण किया

आइएएनएस के अनुसार, जौजान प्रांत में युद्ध के दौरान 50 आतंकियों ने अफगान सेना के सामने समर्पण कर दिया। यह घटना ख्वाजा दोकोह जिले की है। रक्षा मंत्रालय के उप प्रवक्ता फवाद अमान ने इसकी पुष्टि की है।

प्रख्यात कवि और इतिहासकार अब्दुल्लाह अतीफी की तालिबान ने की हत्या

एएनआइ के अनुसार, तालिबान आतंकियों ने उरुजगन प्रांत के चोरा जिले में प्रख्यात कवि और इतिहासकार अब्दुल्लाह अतीफी की हत्या कर दी है। उनकी हत्या घर के सामने ही की गई है।

ईरानी राष्ट्रपति के कार्यक्रम में शामिल होंगे अशरफ गनी

एएनआइ के अनुसार, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ईरान के निर्वाचित राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के कार्यभार ग्रहण करने के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में 73 देशों के सौ से अधिक अतिथि मौजूद रहेंगे। रईसी 18 जून को हुए राष्ट्रपति चुनाव में 62 फीसद मतों के साथ विजयी हुए थे।

पाक अफगान शरणार्थियों के लिए अपनी सीमा खोले : अमेरिका

एएनआइ के अनुसार, अमेरिका ने कहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान की हिंसा बढ़ने से पाकिस्तान की सीमा पर शरणार्थियों की संख्या बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान को इन शरणार्थियों के लिए सीमा खोल देनी चाहिए। ज्ञात हो कि पाकिस्तान ने पहले ही कह दिया है कि वह शरणार्थियों के लिए अपनी सीमा नहीं खोलेगा।

पाक में मंदिर पर हमले का भारत ने किया कड़ा विरोध

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

पाक के रहीमयार खान में गणेश मंदिर हमले को भारत सरकार ने बेहद गंभीरता लिया है। भारत ने नई दिल्ली स्थित पाक उच्चायोग के सबसे वरिष्ठ अधिकारी को तलब किया और रोष से अवगत कराया।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि हमने गणेश मंदिर पर हमले का बेहद परेशान करने वाला वीडियो देखा है। भीड़ ने मंदिर पर हमला किया है, प्रतिमाओं को नष्ट किया है। वहां आस पास रहने वाले हिंदू लोगों के घरों पर भी हमला किया गया है। पाकिस्तान में जनवरी, 2020 में हमने पाक के सिंध प्रांत में माता रानी मंदिर और गुरुद्वारे पर हमले को देखा है।

इस क्रम में बागची ने आगे बताया कि गुरुवार दोपहर को पाकिस्तान उच्चायोग के वरिष्ठ अधिकारी (चार्ज डी'एफेयर्स जो उच्चायुक्त के न होने पर उच्चायोग के प्रशासनिक अधिकारी होते हैं) को सम्मन कर इस बारे में अपनी गंभीर चिंता से अवगत कराया है। पाक अधिकारी से चिंता जताई कि वहां अल्पसंख्यक समुदाय पर लगातार हमला हो रहा है और उनकी धार्मिक आजादी छीनी जा रही है। भारत ने मांग की है कि वहां के अल्पसंख्यकों को पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाए।

पाक को आतंकी देश घोषित किया जाए : विहिप

नई दिल्ली, एएनआइ : पाकिस्तान में मंदिर पर हमले के बाद हिंदू संगठनों में जबर्दस्त उबाल है। विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के अंतरराष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा है कि पाकिस्तान को आतंकी राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। इस देश की सभी विदेशी सहायता पर रोक लगानी चाहिए। ये चिंता की बात है कि पाकिस्तान में हिंदुओं व उनके पूजा स्थलों पर लगातार घटनाएं हो रही हैं।

पाकिस्तान हिंदू मंदिरों की पवित्रता बनाए रखने में विफल

प्रथम पृष्ठ से आगे

एएनआइ के अनुसार हिंदू मंदिरों पर हमले तेजी से बढ़ रहे हैं। दिसंबर, 2020 में सैकड़ों लोगों की भीड़ ने खैबरपख्तूनख्वा के कराक जिले में एक हिंदू मंदिर को बुरी तरह क्षतिग्रस्त करते हुए आग लगा दी थी। हाल ही में पाक सुप्रीम कोर्ट को अल्पसंख्यकों के पूजा स्थल की एक रिपोर्ट सौंपी गई है। इसमें कहा गया है कि पाकिस्तान मंदिरों की पवित्रता बनाए रखने में पूरी तरह असफल रहा है।

चीफ जस्टिस ने अफसरों को किया तलब : प्रेट्र के अनुसार पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने सांसद रमेश कुमार वंकवानी की शिकायत पर संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के मुख्य सचिव और पंजाब पुलिस प्रमुख को तलब किया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के विशेष सहायक डा. शहबाज गिल ने स्थानीय प्रशासन को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

सीरिया में आतंकी गतिविधियों की अनदेखी का जोखिम नहीं उठा सकता विश्व : भारत

संयुक्त राष्ट्र, प्रेट्र : भारत ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय सीरिया और क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियों को नजरअंदाज करने का जोखिम नहीं उठा सकता। भारत ने इलाके में आतंकवादी समूहों के फिर से सिर उठाने और रासायनिक हथियारों तक उनकी पहुंच बनाने की आशंका को लेकर आ रही खबरों पर चिंता जताई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने सीरिया (रासायनिक हथियार) पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सम्मेलन में यह टिप्पणी की।

तिरुमूर्ति ने कहा, 'इस साल जनवरी में परिषद में शामिल होने के बाद से भारत आतंकवादी समूहों और कुछ लोगों के रासायनिक हथियारों तक पहुंच बनाने की आशंका के खिलाफ लगातार आगाह करता रहा है। हम क्षेत्र में आतंकी समूहों के फिर से सिर उठाने की बार-बार आ रही खबरों को लेकर चिंतित हैं।'

▸ सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष तिरुमूर्ति ने रासायनिक हथियारों तक आतंकी पहुंच की आशंका पर चिंता जताई

संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति। जागरण आर्काइव

तिरुमूर्ति अगस्त के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने कहा, 'हमने अतीत में आतंकवाद के खिलाफ शांत रुख अपनाने के परिणामों से जो सीखा है, उसे देखते हुए अंतरराष्ट्रीय समुदाय सीरिया और क्षेत्र में आतंकी गतिविधियों को नजरअंदाज करने का जोखिम नहीं उठा सकता।'

भारतीय राजदूत ने कहा कि भारत किसी के भी जरिये, कहीं पर भी, किसी भी वक्त और किसी भी परिस्थिति में रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल करने के खिलाफ है।

उन्होंने कहा कि भारत लगातार यह स्पष्ट करता आ रहा है कि रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल की जांच निष्पक्ष, विश्वसनीय और उद्देश्यपरक होगी।

अमेरिका में छह माह बाद मिले एक लाख से ज्यादा नए केस

वाशिंगटन, रायटर : अमेरिका में कोरोना महामारी फिर बढ़ती जा रही है। इस बार कोरोना का डेल्टा वैरिएंट कारण बन रहा है। नतीजन पीड़ितों की दैनिक संख्या में उछाल आ गई है। बीते 24 घंटे में देशभर में एक लाख से ज्यादा नए मामले पाए गए। छह माह बाद एक दिन में इतनी बड़ी संख्या में नए संक्रमित मिले हैं।

समाचार एजेंसी रायटर के डाटा के मुताबिक, अमेरिका में बुधवार को एक लाख से ज्यादा नए संक्रमित पाए गए। बीते एक हफ्ते में रोजाना औसतन 94 हजार से ज्यादा केस मिले हैं। महज एक माह में दैनिक मामलों में पांच गुना बढ़ोतरी आई है। इधर, अमेरिका के संक्रामक रोग विशेषज्ञ एंटोनी फासी ने कहा कि आने वाले दिनों में डेल्टा वैरिएंट के चलते दैनिक मामलों का आंकड़ा दो लाख के पार पहुंच सकता है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, 'जो लोग टीका नहीं लगवा रहे हैं, वे गलती कर रहे हैं।' अमेरिकी स्वास्थ्य एजेंसी सेंटर्स फार डिजीज कंट्रोल एंड प्रीवेंशन के अनुसार, देश में नए मामलों में 83 फीसद डेल्टा के हैं, जबकि व्हाइट हाउस की कोरोना रिस्पांस टीम ने बताया कि कोरोना के गंभीर मामलों में 97 फीसद टीका नहीं लगवाने वाले लोग हैं।

● डेल्टा के चलते आगामी दिनों में दो लाख पार पहुंच सकते हैं दैनिक मामले

अमेरिका में कोरोना के डेल्टा वैरिएंट का खतरा बढ़ रहा है। इसके बाद भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं। इस गंभीर खतरे के बीच मिसौरी स्थित आसेज समुद्र तट पर मौज-मस्ती करते लोग। एएफपी

चीन में भी डेल्टा से बढ़े मामले : समाचार एजेंसी एएनआइ के अनुसार, कोरोना महामारी की शुरुआत का केंद्र रहे चीन के कई शहरों में अब डेल्टा ने पांव पसार दिया है। देशभर में गुरुवार को 85 नए मामले पाए गए। संक्रमण की रोकथाम के लिए वुहान समेत कई शहरों में सख्त कदम उठाए गए हैं।

जापान में मिले 15 हजार नए केस : समाचार एजेंसी एपी के मुताबिक, जापान में कोरोना संक्रमण फिर बढ़ गया है। देशभर में बुधवार को 15 हजार से ज्यादा नए केस पाए गए। इनमें से पांच हजार से अधिक राजधानी टोक्यो में मिले। यह शहर इस समय ओलिंपिक खेलों की मेजबानी कर रहा है।

एशियाई अमेरिकियों में बहुत ही लोकप्रिय है हिंदी

वाशिंगटन, प्रेट्र : अमेरिका में भी हिंदी का बोलबाला है। हिंदी विशेषतौर पर एशियाई अमेरिकी लोगों में बहुत ही लोकप्रिय है। यहां के लोगों में बोली जाने वाली शीर्ष पांच भाषाओं में हिंदी का नाम है। भाषा विशेषज्ञों ने यह जानकारी सीनेट में दी है। एशियन-अमेरिकन एडवांसिंग जस्टिस के अध्यक्ष जान यांग ने सीनेट की होमलैंड सिक्योरिटी एंड गवर्नमेंटल अफेयर कमेटी के सदस्यों को भाषा के संबंध में पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अमेरिका में दो तिहाई एशियाई अमेरिकन जनसंख्या प्रवासियों की है। इनमें से 52 फीसद प्रवासी अंग्रेजी में सीमित दक्षता रखते हैं। एशियाई अमेरिकी नागरिकों में हिंदी, चीनी, वियतनामी, तगालोग, कोरियन भाषा बोली जाती हैं। सीनेट में इन सभी भाषाओं के प्रवासियों की भाषाई दक्षता की भी जानकारी दी गई। एशियाई अमेरिकी लोगों में हिंदी की लोकप्रियता इस कदर है कि वे अधिकांश अवसरों पर हिंदी का ही प्रयोग करना पसंद करते हैं।

अमेरिका निकालेगा अवैध आव्रजकों के बच्चों को नागरिकता देने की राह

वाशिंगटन, प्रेट्र : अमेरिका में बाइडन प्रशासन अवैध आव्रजकों के बच्चों को कानूनी तरीके से नागरिकता प्रदान करने का रास्ता तलाश रहा है। इस संबंध में व्हाइट हाउस ने कहा कि उन्होंने यह फैसला तब लिया जब भारतीय बहुल वाले युवाओं के एक समूह ने जब यह डर जताया कि 21 वर्ष का होने पर उन्हें प्रत्यर्पित किया जा सकता है।

इन बच्चों को दस्तावेजों में नागरिकता के संभावितों के रूप में देखा जाता है। यह अमेरिका में लंबे समय से गैर आव्रजक एच-1बी कर्मचारियों समेत वीजा धारकों के आश्रितों के रूप में रहते हैं। एच-1बी वीजा एक गैरआव्रजक वीजा है जिससे अमेरिकी कंपनियों को विशिष्ट क्षेत्रों में विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने की छूट मिलती है। तकनीकी कंपनियां इस वीजा के जरिये भारत और चीन जैसे देशों से दसों हजार कर्मचारियों को प्रति वर्ष नियुक्त करती हैं।

व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडन चाहते हैं कि अमेरिका की आव्रजन प्रणाली में सुधार लाया जाए। इसमें वीजा प्रक्रिया में सुधार को भी शामिल किया जाएगा। आव्रजन बिल को कांग्रेस के पास इसे मंजूर करने के लिए भेजा जाएगा। इस बिल में एच-1बी वीजा धारकों और उनके बच्चों को प्रमाणिकता देने में उनकी उम्र पार नहीं होने दी जाएगी।

▸ बाइडन प्रशासन इसके लिए नया कानून लाएगा

▸ इससे अधिकांश भारतीय बच्चों को होगा नागरिकता मिलने का लाभ

माता-पिता पर आश्रित बच्चों पर आव्रजन में होती है छूट

'इम्प्रूव द ड्रीम' नामक एक समूह ने ऐसे दो लाख बच्चों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें अधिकांश भारतीय बच्चे हैं। अमेरिकी कानून के मुताबिक, माता-पिता पर आश्रित बच्चों पर आव्रजन में छूट होती है, लेकिन उनके 21 साल के होते ही उन्हें नागरिकता नहीं मिल पाने की सूरत में उन्हें अमेरिका से प्रत्यर्पित कर दिया जाता है। ऐसे माता-पिता लंबे समय से ग्रीन कार्ड के इंतजार में अमेरिका में बने रह जाते हैं। ग्रीन कार्ड अमेरिका में स्थायी निवासी कार्ड होता है। यह दस्तावेज उन वैध आव्रजकों को मिलता है जिन्हें अमेरिका में स्थायी निवासी बनने का अवसर मिल जाता है।

डेल्टा वैरिएंट का बढ़ रहा कहर, 135 देशों में पहुंचा

संयुक्त राष्ट्र, प्रेट्र : दुनिया में कोरोना के डेल्टा वैरिएंट का कहर तेज गति से बढ़ रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने बताया कि यह बेहद संक्रामक वैरिएंट अब 135 देशों में पहुंच गया है। डेल्टा की भारत में सबसे पहले पहचान हुई थी। समाचार एजेंसी रायटर के डाटा के अनुसार, बुधवार को कोरोना मरीजों का वैश्विक आंकड़ा 20 करोड़ के पार पहुंच गया, जबकि अब तक 42 लाख से ज्यादा पीड़ितों की मौत हुई है।

डब्ल्यूएचओ के ताजा डाटा के मुताबिक, कोरोना के बीटा वैरिएंट के मामले अब तक 132 देशों में पाए गए हैं। गामा वैरिएंट 81 देशों में दस्तक दे चुका है, जबकि अल्फा वैरिएंट 182 देशों में पहुंचा है। बीते एक हफ्ते के दौरान दुनिया में कोरोना के 40 लाख से ज्यादा नए मामले पाए गए। ये मामले 26 जुलाई से एक अगस्त के दौरान मिले। हालांकि, इस अवधि में मरने वालों की संख्या में थोड़ी कमी आई है। इससे पहले वाले सप्ताह में 64 हजार पीड़ितों की जान गई थी।

टेड्रोस अदनोम घेबरेसस। फाइल/इंटरनेट मीडिया

डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम घेबरेसस ने गरीब देशों में टीकाकरण में तेजी लाने पर जोर दिया। उन्होंने बुधवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अमीर देशों में इस समय हर 100 लोगों पर वैक्सीन की 100 डोज लग रही हैं, जबकि गरीब देशों में हर 100 लोगों पर महज डेढ़ डोज लगाई जा रही हैं। इस अंतर को पलटने की जरूरत है। टेड्रोस ने कहा, 'हमारा लक्ष्य है कि सितंबर तक हर देश में 10 फीसद आबादी का टीकाकरण पूरा हो जाए।'

वैक्सीन लगवाए भारतीयों को ब्रिटेन के होटल में नहीं होना होगा क्वारंटाइन

लंदन, प्रेट्र : ब्रिटेन ने कोविड-19 के कड़ी नियमावली के तहत भारत को राहत देते हुए अब 'रेड' लिस्ट से निकालकर अब 'एम्बर' लिस्ट में डाल दिया है। इससे कोरोना से बचाने के लिए दो टीके लगवा चुके भारत के हवाई यात्रियों को अब होटल में 10 दिन के अनिवार्य क्वारंटाइन में नहीं रहना पड़ेगा, बल्कि अब भारतीयों समेत एम्बर सूची के लोग घर में ही 10 दिन क्वारंटाइन नियमों का पालन कर सकते हैं।

ब्रिटेन के परिवहन मंत्री ग्रांट शैप्स ने ट्वीट करके बताया यूएई, कतर, भारत और बहरीन को लाल सूची से निकालकर एम्बर सूची में डाल दिया गया है। यह फैसला खासकर ब्रिटेन में बसे भारतीयों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। वह काफी समय से भारत और ब्रिटेन के बीच यात्रा नियमों में छूट की मांग कर रहे थे। एम्बर सूची के तहत यात्रियों को विमान के रवाना होने से तीन दिन पहले कोविड टेस्ट कराना होगा और दो कोविड टेस्ट की बुकिंग एडवांस में करानी होगी, ताकि इंग्लैंड वापस लौटने पर फिर से कोविड टेस्ट कराया जा सके।

कोविड प्रोटोकाल

▸ ब्रिटेन ने हवाई यात्रा के लिए भारत को रेड से एम्बर लिस्ट में डाला

कोरोना से जंग में टीका महत्वपूर्ण हथियार है। फाइल फोटो इंटरनेट मीडिया

अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए भी ब्रिटिश ट्रैफिक लाइट प्रणाली अपनाई

ग्रांट ने बताया कि ब्रिटिश ट्रैफिक लाइट प्रणाली को ही अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए भी अपनाया गया है। ब्रिटिश परिवहन विभाग की ओर से यह बदलाव रविवार को स्थानीय समय के अनुसार सुबह चार बजे से घोषित किया गया है।

इब्राहीम रईसी ने संभाला ईरान के राष्ट्रपति का पद

तेहरान, एपी : ईरान में गुरुवार को इब्राहीम रईसी ने राष्ट्रपति पद ग्रहण कर लिया। संसद में आयोजित समारोह में काले रंग की परंपरागत पगड़ी बांधे रईसी ने कुरान पर दाहिना हाथ रखकर राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारियां पूरी ईमानदारी से निभाने की शपथ ली। रईसी की पहचान एक कट्टरपंथी विद्वान की है, जिसका असर आने वाले दिनों में सरकार के कामकाज में देखने को मिल सकता है। वह ईरान के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं।

रईसी अमेरिका समेत ज्यादातर पश्चिमी देशों के खिलाफ सोच रखने वाले नेता हैं। ऐसे में जबकि ईरान की 2015 में हुए परमाणु समझौते को पुनर्जीवित करने के लिए अमेरिका और अन्य देशों से वार्ता चल रही है, उस पर विपरीत असर पड़ने की आशंका है। रईसी ने अपने शुरुआती भाषण में इसके संकेत दे दिए। उन्होंने कहा, समझौते को पुनर्जीवित करने के लिए अमेरिका को पहले अपने लगाए प्रतिबंध हटाने होंगे। इसके लिए होने वाली राजनयिक पहल का वह समर्थन करेंगे।

▸ कट्टरपंथी नेता ने किया सैन्य ताकत में इजाफा करने का एलान

अपने भाषण में रईसी ने दबी जुबान में सऊदी अरब को हद रहने की ताकीद की। नए राष्ट्रपति ने इलाके में शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए ईरान की सैन्य क्षमता बढ़ाने का भी एलान किया। अमेरिका, यूरोप का जिक्र करते हुए कहा, जहां भी जुल्म होगा-उसके खिलाफ वह आवाज उठाएंगे। उनका चुनाव दुनिया की घमंडी ताकतों को जवाब है। कोरोना संक्रमण के बीच ईरान में हुए कम मतदान प्रतिशत वाले चुनाव में रईसी ने भारी मतों से जीत दर्ज कराई थी। शपथ ग्रहण समारोह में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई भी मौजूद थे। उन्होंने रईसी को देश के गरीबों और देश की करेंसी को मजबूत करने की सलाह दी। अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप के 2018 में लगाए प्रतिबंधों से ईरान की आर्थिक दशा खस्ता हाल में है। वहां की मुद्रा रियाल कमजोर होती जा रही है।

भारतीय नवविवाहिता का अमेरिका में पति ने दहेज के लिए किया उत्पीड़न

वाशिंगटन, प्रेट्र : अमेरिका में एक भारतीय नवविवाहिता अपने ही पति के उत्पीड़न का शिकार होकर परदेस में मदद के लिए दर-दर की खाक छान रही है। वह इसी साल मार्च में अमेरिका पहुंची थी और पति के दहेज की मांग के साथ घर से निकालने के बाद से उसके पास वहां पर न सिर छिपाने की कोई जगह है और न ही भारत वापस लौटने के पैसे हैं। वह पिछले कई हफ्तों से अमेरिका में विभिन्न एजेंसियों के सामने न्याय की गुहार लगा रही है, लेकिन अब तक उसे कोई मदद नहीं मिली है।

वाशिंगटन में भारतीय दूतावास और सैन फ्रांसिस्को स्थित कांसुलेट में भारतीय अधिकारियों के पास भेजे जाने के बाद बिहार की राजधानी पटना से आई पीड़िता ने बताया कि उसके पति ने बिना किसी वित्तीय सहायता के उसे छोड़ दिया है। मेरे पास जाने के लिए अब कोई जगह नहीं है। भारत में मेरे माता-पिता ने मेरे ससुर से मदद मांगी है, लेकिन वह मेरे पति के मुझे वापस अपने जीवन में लेने के लिए दहेज देने की मांग कर रहे हैं।

अनामिका (बदला हुआ नाम) ने अमेरिकी विदेश विभाग से भी संपर्क साधा है। चूंकि इसी विभाग ने उसके पति को एफ-1 वीजा जारी किया है। और फ्रेडी मैक के जरिये वह आप्शनल प्रेक्टिकल ट्रेनिंग (ओपीटी) के जरिये अस्थायी रोजगार कर रहा है। पीड़िता को अब तक कहीं से भी न्याय नहीं मिल सका है। नवविवाहिता के खिलाफ उत्पीड़न और दुर्व्यवहार इस हद तक बढ़ गया कि 15 जून को वाशिंगटन डीसी के उपनगरीय क्षेत्र वर्जीनिया की पुलिस को उसके पति के घर मैकलेन के अपार्टमेंट में बुलाना पड़ गया। पीड़िता ने अपनी शिकायत में लिखा है कि पुलिस ने उसकी मदद कैब से जाने में की थी। स्थानीय फेयरफैक्स काउंटी पुलिस ने उसके पति के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज की है। पीड़िता ने बताया कि उसका जीवन खतरे में था, उस दिन पुलिस ने ही उसे वहां से निकालकर उसकी जान बचाई।

उसने बताया कि वह अमेरिका अपने पति के साथ एक मार्च, 2021 को पहुंची और वर्जीनिया के मैक्लीन में रहने लगी। फिर उसके पति ने उसके माता-पिता से दहेज मांगते हुए उसे घरेलू हिंसा का शिकार बनाना शुरू कर दिया। पीड़िता ने बताया कि उसका पति उसे वाशरूम खुला रखने के लिए उसे मजबूर करता था और उस पर गर्भधारण रोकने के लिए कुछ करने का आरोप लगाता था। जब इस बारे में पीड़िता की पति से फोन पर पूछताछ की गई तो उसने आरोप झूठे होने की बात कही और फोन काट दिया। पीड़िता फिलहाल अपने नजदीकी रिश्तेदारों के पास सिएटल में रह रही है।

परदेस में घरेलू हिंसा

▸ शादी के बाद पति के साथ पटना से एक मार्च को पहुंची थी वाशिंगटन

▸ स्थानीय पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर घर से सुरक्षित बाहर निकाला

माइक पोंपिओ को जापान से मिली कीमती व्हिस्की की बोतल गायब

वाशिंगटन : अमेरिका का विदेश विभाग जापान सरकार से तोहफे में मिली एक कीमती व्हिस्की की बोतल को तलाश रहा है। बेहतरीन किस्म की व्हिस्की की यह बोतल 5,800 डालर (करीब चार लाख 30 हजार रुपये) की है। यह 2019 में अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोंपिओ के लिए उपहार में दी गई थी।

दरअसल, विदेश विभाग अन्य देशों से मिले उपहारों का मूल्यांकन कर उन्हें दस्तावेज में दर्ज कर रहा है। अमेरिकी कानून के अनुसार 390 डालर (करीब 29 हजार रुपये) तक के उपहार पद पर बैठे व्यक्ति अपने पास रख सकते हैं। इससे अधिक के मूल्यांकन वाली वस्तुओं को जमा कराना पड़ता है। यदि किसी को उपहार पसंद है तो वह मूल्यांकन के बाद उसकी कीमत अदा करके ले सकता है।

अमेरिकी संविधान के अनुसार, किसी भी अमेरिकी अधिकारी के द्वारा तोहफा स्वीकार करना गैरकानूनी है। यदि उपहार मिलता है तो वह अमेरिका की सरकारी संपत्ति होता है। अब यह कीमती व्हिस्की की बोतल पूर्व विदेश मंत्री के गले की हड्डी बन गई है। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि पूर्व विदेश मंत्री पोंपिओ को यह उपहार कब मिला था। दस्तावेज में जो दिन दर्ज है, उस दिन 24 जून, 2019 को माइक पोंपिओ सऊदी अरब की यात्रा कर रहे थे।

इस मामले में चल रही जांच में पूर्व विदेश मंत्री माइक पोंपिओ ने अपने वकील विलियम ए बर्क के माध्यम से कहा है कि उन्हें व्हिस्की की बोतल मिलने की याद नहीं है, न ही इसके बारे में यह जानकारी है कि उसके साथ क्या हुआ या किसको दी गई। उन्हें यह भी पता नहीं है कि यह व्हिस्की कैसी थी।

माइक पोंपिओ।

करीब चार लाख 30 हजार रुपये है रकम, अमेरिका में चल रही इस मामले की जांच

भारतीय हाकी का पुनर्जन्म

- दद्दा जहां भी होंगे, अब बहुत खुश होंगे
- भारत ने जर्मनी को हराकर जीता कांस्य
- श्रीजेश ने बचाई आखिर में पेनाल्टी

अभिषेक त्रिपाठी • नई दिल्ली

भारतीय पुरुष हाकी टीम ने ओलिंपिक में अपने स्वर्ण पदक का अभियान 1928 में एम्सटर्डम ओलिंपिक से शुरू किया था। हाकी के जादूगर और 'दद्दा' के नाम से मशहूर मेजर ध्यानचंद ने अपनी हाकी स्टिक से ऐसा जादू चलाया कि 1928 से 1936 तक भारत ने स्वर्णिम हैट्रिक लगा दी थी। हाकी में भारत ने लगातार 10 पदक जीते लेकिन 1980 में मास्को ओलिंपिक में स्वर्ण जीतने के बाद ऐसा सूखा आया कि टीम को पदक जीतने के लिए 41 साल तक इंतजार करना पड़ा। इस दौरान कितने दिग्गज आए और गए, लेकिन ओलिंपिक में पदक नहीं आया। अब टोक्यो में भारतीय हाकी का पुर्नजन्म हुआ है।

अतीत की मायूसियों से निकलकर कप्तान मनप्रीत सिंह की टीम ने पिछड़ने के बाद जबरदस्त वापसी करते हुए रोमांच की पराकाष्ठा पर पहुंचे मैच में जर्मनी को 5-4 से हराकर कांसे का तमगा जीता। वहीं, बेल्जियम ने स्वर्ण व आस्ट्रेलिया ने रजत पदक जीता। मैच के आखिरी छह सेकेंड में जर्मनी को पेनाल्टी मिल गई और उस समय जर्मनी की कोशिश मैच को पेनाल्टी शूटआउट में ले जाने की थी लेकिन गोलकीपर पीआर श्रीजेश ने यह पेनाल्टी बचाकर टीम को ऐतिहासिक जीत दिला दी। हाकी के गौरवशाली इतिहास को नए सिरे से दोहराने के लिए मील का पत्थर साबित होने वाली इस जीत ने पूरे देश को भावुक कर दिया। इस जीत के कई सूत्रधार रहे जिनमें सिमरनजीत सिंह (17वें मिनट, 34वें मिनट), हार्दिक सिंह (27वां मिनट), हरमनप्रीत सिंह (29वां मिनट) व रूपिंदर पाल सिंह (31वां मिनट) तो थे ही, लेकिन इस पूरे टूर्नामेंट में एक हीरो था जो दीवार बनकर खड़ा रहा और उसका नाम है पीआर श्रीजेश।

मां की याद आई तो सुमित ने मंगवाया अपना लकी लाकेट

दीपक गिजवाल • सोनीपत

हाकी टीम के खिलाड़ी सुमित ने मां-बाप के संघर्ष को सफल कर दिया। वह आशीर्वाद के लिए अपनी स्वर्गीय मां की फोटो लगा लाकेट पहनकर मैच में उतरे। सुमित ने ये लाकेट अपनी मां के झुमकों को तुड़वाकर बनवाया था। सुमित को उम्मीद थी कि इससे उनका भाग्य चमकेगा। सुमित ने घर पर रखे लाकेट को ओलिंपिक के बीच में टोक्यो मंगवा लिया था। ओलिंपिक से करीब छह माह पहले सुमित की मां का निधन हो गया था। सुमित के बड़े भाई जयसिंह ने बताया कि मां का सपना था कि सुमित ओलिंपिक में खेले। अब टीम ने कांस्य पदक जीतकर मां का सपना पूरा किया है। मां के झुमकों से जो लाकेट बनवाया है, उसमें सुमित ने मां की फोटो लगवा रखी है। पिता प्रताप ने बताया कि एक दिन सुमित का फोन आया। उसे मां की याद आ रही थी। उसने लाकेट टोक्यो भिजवाने को कहा। इसके बाद भाई ने लाकेट टोक्यो पहुंचाया।

लाकेट में लगा सुमित की दिवंगत मां का फोटो • सौजन्य अमित

> भारत में लोग हाकी को भूल रहे थे। वे हाकी को प्यार करते हैं लेकिन उन्होंने यह उम्मीद छोड़ दी थी कि हम जीत सकते हैं। वे भविष्य में हमारे से और अधिक उम्मीदें लगा पाएंगे। हमारे ऊपर विश्वास रखें।
> **रूपिंदर पाल सिंह**, ड्रैग फ्लिकर

> दो गोल से पिछड़ने के बाद भी हमने हार नहीं मानी थी और एक दूसरे से यही कह रहे थे कि यही हमारे पास कुछ कर गुजरने का आखिरी मौका है, बाद में पूरी जिंदगी पछताना नहीं है।
> **हरमनप्रीत सिंह**, उप कप्तान

यह पदक चिकित्सकों को समर्पित : मनप्रीत

टोक्यो : पदक जीतने के बाद भावुक हुए भारतीय कप्तान मनप्रीत सिंह ने इस ऐतिहासिक पदक को देश के चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों को समर्पित किया जिन्होंने कोविड-19 के दौरान जीवन बचाने के लिए बिना थके काम किया। मनप्रीत ने कहा, 'मुझे नहीं पता कि अभी मुझे क्या कहना चाहिए, यह शानदार था। मुझे लगता है कि हम इस पदक के हकदार थे। पिछले 15 महीने हमारे लिए भी मुश्किल रहे, हम बेंगलुरु में थे और हमारे कुछ लोग कोविड से संक्रमित हुए। हम इस पदक को चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों को समर्पित करना चाहते हैं जिन्होंने भारत में इतनी सारी जान बचाई।'

इनामों की वर्षा

₹2.5 करोड़ : हरियाणा सरकार राज्य के प्रत्येक हाकी खिलाड़ी को देगी। उन्हें खेल विभाग में नौकरी और रियायती दर पर प्लाट दिए जाएंगे

₹1.0 करोड़ : मप्र सरकार विवेक व नीलाकांता को एवं उप्र सरकार ललित को देगी

₹1.0 करोड़ : पंजाब सरकार अपने राज्य के प्रत्येक खिलाड़ी को देगी। एसजीपीसी हाकी टीम को एक करोड़ रुपये देने के साथ पंजाब के खिलाड़ियों को पांच-पांच लाख रुपये देगी

गोलपोस्ट को नमन करते श्रीजेश • प्रेट्र

21 साल का अनुभव झोंक दिया : पीआर श्रीजेश

टोक्यो : भारतीय गोलकीपर श्रीजेश ने कहा, 'यह पुनर्जन्म है। 41 साल हो गए। अब हमने पदक जीत लिया जिससे युवा खिलाड़ियों को हाकी खेलने की प्रेरणा और ऊर्जा मिलेगी। यह खूबसूरत खेल है। हमने युवाओं को हाकी खेलने का एक कारण दिया है।' जीत के बाद भारतीय खिलाड़ी जहां रोते हुए एक-दूसरे को गले लगा रहे थे, वहीं, श्रीजेश गोलपोस्ट पर बैठ गए थे। उन्होंने कहा, 'मैं आज हर बात के लिए तैयार था क्योंकि यह 60 मिनट सबसे महत्वपूर्ण थे। मैं 21 साल से हाकी खेल रहा हूं और मैंने खुद से इतना ही कहा कि 21 साल का अनुभव इस 60 मिनट में दिखा दो।'

पहला क्वार्टर : भारत के लिए मुकाबले की शुरुआत अच्छी नहीं रही। जर्मनी ने शुरुआत में ही दोनों छोर से हमले करके भारतीय रक्षा पंक्ति को दबाव में डाला। दूसरे ही मिनट में ओरूज ने गोल कर दिया। पहले क्वार्टर में जर्मनी की टीम मनमाफिक तरीके से भारतीय डी में प्रवेश करने में सफल रही। श्रीजेश ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जर्मनी को बढ़त दोगुनी करने से रोका और उसके दो हमलों को नाकाम किया। जर्मनी को अंतिम मिनट में लगातार चार पेनाल्टी कार्नर मिले, लेकिन अमित रोहिदास ने विरोधी टीम को सफलता हासिल नहीं करने दी।

दूसरा क्वार्टर : सिमरनजीत ने इस क्वार्टर के दूसरे ही मिनट में नीलाकांता शर्मा से डी में मिले लंबे पास पर रिवर्स शाट से जर्मनी के गोलकीपर को छकाकर गोल किया और भारत को 1-1 से बराबरी दिला दी। जर्मनी ने दो मिनट में दो गोल दागकर 3-1 की बढ़त बना ली। भारत को 27वें मिनट में पेनाल्टी कार्नर मिला। ड्रैगफ्लिकर हरमनप्रीत के प्रयास को गोलकीपर ने रोका लेकिन रिबाउंड पर हार्दिक ने गोल कर दिया। एक मिनट बाद फिर पेनाल्टी कार्नर मिला और इस बार हरमनप्रीत ने ड्रैगफ्लिक से गोल कर 3-3 से बराबरी दिला दी।

तीसरा क्वार्टर : पहले ही मिनट में जर्मनी के डिफेंडर ने मनदीप सिंह को गिराया जिससे भारत को पेनाल्टी स्ट्रोक मिला। रूपिंदर ने स्टेंडलर के दायीं ओर से गेंद को गोल में डालकर भारत को पहली बार मैच में आगे कर दिया। टोक्यो ओलिंपिक में रूपिंदर का यह चौथा गोल है। भारत ने इसके बाद दायीं छोर से एक ओर मूव बनाया और डी के अंदर गुरजंत के पास पर सिमरनजीत ने गेंद को गोल में डालकर भारत को 5-3 से आगे कर दिया। भारत को इसके बाद लगातार तीन और जर्मनी को भी लगातार तीन पेनाल्टी कार्नर मिले, लेकिन दोनों ही टीमें गोल करने में नाकाम रही।

चौथा क्वार्टर : तीसरे मिनट में जर्मनी को एक और पेनाल्टी कार्नर मिला और इस बार लुकास विंडफेडर ने श्रीजेश के पैरों के बीच से गेंद को गोलपोस्ट में डालकर स्कोर 4-5 कर दिया। भारत को 51वें मिनट में गोल करने का स्वर्णिम मौका मिला। लंबे पास पर गेंद कब्जे में लेने के बाद मनदीप इसे डी में ले गए लेकिन विफल रहे। श्रीजेश ने इसके बाद एक और पेनाल्टी कार्नर को नाकाम किया। जर्मनी अंतिम पांच मिनट में बिना गोलकीपर के खेली। आखिरी छह सेकेंड बचे थे और जर्मनी को पेनाल्टी कार्नर मिला, लेकिन भारत की दीवार श्रीजेश ने जर्मनी को गोल करने नहीं दिया।

पदक के साथ भारतीय टीम के खिलाड़ी और सहयोगी स्टाफ • एएनआइ

> गोल मेरी स्टिक से भले ही निकले हो, लेकिन यह टीम के प्रयास का नतीजा होता है। हमने दिखा दिया कि हम क्या कर सकते हैं। **सिमरनजीत सिंह**

ओलिंपिक में हाकी टीमों के कुल पदक

टीम	पदक
भारत	12
जर्मनी	11
आस्ट्रेलिया	9
नीदरलैंड्स	9

ओलिंपिक में भारतीय टीम का सफर

1928 एम्सटर्डम : ब्रिटिश हुकूमत के दौरान भारतीय टीम ने फाइनल में नीदरलैंड्स को 3-2 से हराकर पहली बार हाकी का स्वर्ण पदक जीता। भारतीय हाकी को ध्यानचंद के रूप में नया सितारा मिला जिन्होंने 14 गोल दागे

1932 लास एंजिलिस : टूर्नामेंट में सिर्फ तीन टीमें भारत, अमेरिका व जापान थीं। भारतीय टीम 42 दिन का समुद्री सफर तय करके पहुंची व दोनों टीमों को हराकर खिताब जीता

1936 बर्लिन : ध्यानचंद की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने मेजबान जर्मनी को 8-1 से हराकर लगातार तीसरी बार खिताब जीता

1948 लंदन : आजाद भारत का पहला ओलिंपिक खिताब जिसने दुनिया के खेल मानचित्र पर भारत को पहचान दिलाई। ब्रिटेन को 4-0 से हराकर भारतीय टीम लगातार चौथी बार ओलिंपिक चैंपियन बनी और बलबीर सिंह सीनियर के रूप में हाकी को एक नया नायक मिला

1952 हेलसिंकी : नीदरलैंड्स को हराकर भारत फिर चैंपियन। भारत के 13 में से नौ गोल बलबीर सिंह सीनियर के नाम रहे, जिन्होंने फाइनल में सर्वाधिक गोल करने का रिकार्ड भी बनाया

1956 मेलबर्न : पाकिस्तान को फाइनल में एक गोल से हराकर भारत ने लगातार छठी बार ओलिंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर अपना दबदबा कायम रखा

1960 रोम : फाइनल में एक बार फिर चिर प्रतिद्वंद्वी भारत और पाकिस्तान आमने-सामने थे। इस बार पाकिस्तान ने एक गोल से जीतकर भारत के अश्वमेधी अभियान पर नकेल कसी

1964 टोक्यो : पेनाल्टी कार्नर पर मोहिंदर लाल के गोल की मदद से भारत ने पाकिस्तान को हराकर एक बार फिर ओलिंपिक स्वर्ण जीता

1968 मेक्सिको : ओलिंपिक के अपने इतिहास में भारत पहली बार फाइनल में जगह नहीं बना सका। सेमीफाइनल में आस्ट्रेलिया से मिली हार

1972 म्यूनिख : भारत सेमीफाइनल में पाकिस्तान से हारा, लेकिन प्लेआफ में नीदरलैंड्स को 2-1 से हराकर कांस्य पदक जीता

> हम सेमीफाइनल हार गए थे। पूरी टीम दुखी थी, लेकिन हमने साथ मिलकर एक-दूसरे का मनोबल बढ़ाया। हम हमेशा से टीम सबसे पहले मानसिकता पर जोर देते आए हैं। सेमीफाइनल में हार के बाद आज इस तरह से वापसी करना जबरदस्त था। यह ओलिंपिक सबसे अलग था। कोरोना की वजह से सब कुछ बदला हुआ था। इन खिलाड़ियों ने काफी मेहनत की है और बलिदान भी दिए हैं। **ग्राहम रीड**, कोच

1976 मांट्रियल : पहली बार एस्ट्रो टर्फ का इस्तेमाल हुआ। भारत ग्रुप चरण में दूसरे स्थान पर रहा और 58 साल में पहली बार पदक की दौड़ से बाहर होकर सातवें स्थान पर रहा

1980 मास्को : नौ टीमों के बहिष्कार के बाद ओलिंपिक में सिर्फ छह हाकी टीमें। भारत ने स्पेन को 4-3 से हराकर स्वर्ण पदक जीता जो उसका आठवां और अब तक का आखिरी स्वर्ण था

1984 लास एंजिलिस : 12 टीमों में भारत पांचवें स्थान पर रहा

1988 सियोल : परगट सिंह की अगुआई वाली भारतीय टीम का औसत प्रदर्शन। पाकिस्तान से क्लासीफिकेशन मैच हारकर छठे स्थान पर रही

1992 बार्सिलोना : भारत को सिर्फ दो मैचों में अर्जेंटीना और मिस्र के खिलाफ मिली जीत। निराशाजनक प्रदर्शन कर टीम सातवें स्थान पर रही

1996 अटलांटा : भारत के प्रदर्शन का ग्राफ लगातार गिरता रहा व इस बार आठवें स्थान पर रहा

2000 सिडनी : इस बार भी क्लासीफिकेशन मैच तक खिसका भारत, सातवें स्थान पर रहा

2004 एथेंस : धनराज पिल्लै का चौथा ओलिंपिक। भारत ग्रुप चरण में चौथे और कुल सातवें स्थान पर रहा

2008 बीजिंग : भारतीय हाकी के इतिहास का सबसे काला पन्ना। चिली के सैंटियागो में क्वालीफायर में ब्रिटेन से हारकर भारतीय टीम 88 साल में पहली बार ओलिंपिक के लिए क्वालीफाई नहीं कर सकी

2012 लंदन : भारतीय हाकी टीम एक भी मैच नहीं जीत सकी। ओलिंपिक में पहली बार 12वें और आखिरी स्थान पर रही

2016 रियो : भारतीय टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची, लेकिन बेल्जियम से हारी। आठवें स्थान पर रही

2020 टोक्यो : तीन बार की चैंपियन जर्मनी को 5-4 से हराकर भारत ने 41 साल बाद ओलिंपिक में पदक जीता। मनप्रीत सिंह की कप्तानी में भारतीय टीम ने कांस्य जीत कर रचा इतिहास

भारत के आज के मैच

पदक के मुकाबले

हाकी (महिला) : कांस्य पदक का मैच, सुबह 7:00 बजे से, बनाम ग्रेट ब्रिटेन

एथलेटिक्स : 20 किमी पैदल चाल (महिला वर्ग) : फाइनल, दोपहर 1:00 बजे, **खिलाड़ी** : प्रियंका गोस्वामी और भावना जाट

- 50 किमी पैदल चाल (पुरुष वर्ग) : फाइनल, दोपहर 2:00 बजे

खिलाड़ी : गुरप्रीत सिंह

अन्य मुकाबले

कुश्ती : अंतिम-16, सुबह 8:00 बजे

- पुरुष : बजरंग पूनिया
- महिला : सीमा बिसला

एथलेटिक्स : पुरुष 4 गुना 400 मीटर रिले राउंड-1 हीट-2, शाम 5:07 बजे

गोल्फ : महिला व्यक्तिगत स्ट्रोक प्ले राउंड 3, सुबह 4:00 बजे से

खिलाड़ी : अदिति अशोक और दीक्षा डागर

प्रसारण : सोनी नेटवर्क पर

शांत तूफान

- भारतीय पहलवान रवि दहिया ने ओलिंपिक में जीता रजत पदक
- हमेशा शांत दिखने वाले रवि स्वर्ण पदक के मुकाबले में हारे

योगेश शर्मा • नई दिल्ली

अगर आप विराट कोहली के हाव-भाव से परिचित हैं तो यह बताने की जरूरत नहीं कि खिलाड़ी जीतने और हारने पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं देते हैं लेकिन टोक्यो में रजत पदक जीतने वाले पहलवान रवि दहिया न जीतने पर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और न ही हारने पर दुखी। छत्रसाल स्टेडियम में उनके साथी उन्हें शांत तूफान के नाम से बुलाते हैं। 23 साल के रवि टोक्यो में पदक के दावेदारों में शामिल नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने पहले ही ओलिंपिक में रजत जीतकर सभी को चौंका दिया। हालांकि वह 57 किग्रा भारवर्ग के फाइनल में देश के सबसे युवा ओलिंपिक चैंपियन बनने से चूक गए। रूसी ओलिंपिक समिति (आरओसी) के मौजूदा विश्व चैंपियन जावुर युवुगेव ने उन्हें 7-4 से हरा दिया। इससे पहले युवुगेव ने 2019 में विश्व चैंपियनशिप में भी उन्हें हराया था।

बेटा हंस भी ले : रवि 12 साल की उम्र में सोनीपत के गांव नाहरी से निकलकर दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम आए। रवि के मौजूदा कोच प्रवीण दहिया ने बताया, 'उन्हें स्टेडियम में एक छोटा सा कमरा मिला हुआ था और उनके साथ दो पहलवान और भी थे। पहलवानों की कुल संख्या के अनुसार यहां पर कमरे दिए जाते हैं। हालांकि अब उन्हें अलग कमरा मिल जाएगा क्योंकि उन्होंने ओलिंपिक में पदक जीता है। वह हमेशा से शांत ही रहता है। हम बोलते थे कि बेटा थोड़ा हंसना भी सीख ले।' रवि जब छत्रसाल आए थे तब से वह अपने गुरु सतपाल और पूर्व कोच वीरेंद्र कुमार के मार्गदर्शन में ट्रेनिंग करते रहे। ओलिंपिक से कुछ महीने पहले वीरेंद्र का छत्रसाल से ट्रांसफर हो गया, लेकिन रवि छत्रसाल में ही रहे। फिर वह सतपाल, दो बार के ओलिंपिक पदक विजेता सुशील कुमार और कोच प्रवीण दहिया के साथ अभ्यास करते रहे।

60 किलोमीटर से दूध और दही : राकेश 60 किलोमीटर दूर अपने गांव से अखाड़े में दूध और दही देने आते थे। वह लगभग 12 साल तक ऐसे ही करते रहे हैं। अब उनकी यह मेहनत रंग लाई। दहिया ने 2015 में अंडर-23 विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था जिससे उनकी प्रतिभा की झलक दिखी थी। अब सुशील कुमार और योगेश्वर दत्त के बाद सभी जगह रवि दहिया के चर्चे हैं और वह भारत के नए स्टार बन गए हैं।

पदक तालिका

देश	स्वर्ण	रजत	कांस्य	कुल
चीन	34	24	16	74
अमेरिका	29	35	27	91
जापान	22	10	14	46
आस्ट्रेलिया	17	5	19	41
आरओसी	16	22	20	58
ग्रेट ब्रिटेन	16	18	17	51
जर्मनी	9	9	16	34
फ्रांस	7	11	9	27
इटली	7	10	18	35
नीदरलैंड्स	7	9	10	26
भारत	0	2	3	5

नोट: भारत तालिका में 65वें स्थान पर है। आरओसी (रूसी ओलिंपिक समिति)

4 करोड़ रुपये की राशि रवि दहिया को हरियाणा सरकार से मिलेगी। इसके अलावा क्लास-1 नौकरी और रियायती दर पर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का एक प्लाट भी दिया जाएगा। उनके गांव नाहरी में इंडोर कुश्ती स्टेडियम भी बनेगा

> मैं रजत के लिए टोक्यो नही आया था। इससे मुझे संतुष्टि नही मिलेगी। शायद इस बार मैं रजत का ही हकदार था क्योंकि विपक्षी पहलवान बेहतर था। उसकी शैली बहुत अच्छी थी। उसके खिलाफ मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। - **रवि दहिया**

सतपाल बोले, अलग से होती थी ट्रेनिंग

सतपाल ने बताया कि वह टोक्यो के लिए क्वालीफाई कर चुका था, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि उसे अखाड़े में अभ्यास के दौरान चोट नहीं लगे और कोरोना से भी बचा रहे। हमने उसे गांव नहीं जाने दिया और उसे छह से आठ घंटे तक अभ्यास कराया। उनके वजन और वजन से ज्यादा के भी पहलवान अभ्यास के लिए दिए गए। जब वह छत्रसाल आया था तब मैंने ही उसका चयन किया था क्योंकि मुझे पता था कि यह लड़का ओलिंपिक में पदक जीतेगा। टोक्यो जाने से पहले मैंने उससे कहा था कि कोई भी दबाव नहीं लेना है।

फाइनल मुकाबले के दौरान रूसी पहलवान के ऊपर चढ़े रवि • एएफपी

विनेश हुई चित, दीपक और अंशू भी बाहर

टोक्यो : स्वर्ण पदक के दावेदारों में शामिल विनेश फोगाट चित होकर ओलिंपिक से बाहर हो गई जबकि युवा पहलवान दीपक पूनिया का पोडियम पर पहुंचने का सपना पूरा नहीं हो पाया। उधर, अंशू मलिक को 57 किग्रा के रेपचेज में रूस की वालेरा कोबलोवा ने हराकर घर वापसी करा दी। विनेश को 53 किग्रा के क्वार्टर फाइनल में बेलारूस की वेनेसा कालादजिंसकाया ने चित करके बाहर किया। इस तरह से उनके ओलिंपिक अभियान का निराशाजनक अंत हुआ। विनेश को रियो ओलिंपिक 2016 में चोट के कारण क्वार्टर फाइनल मुकाबला बीच में ही छोड़ना पड़ा था।

अदिति पदक की दौड़ में बरकरार

टोक्यो, प्रेट्र : भारतीय महिला गोल्फर अदिति अशोक गुरुवार को यहां दूसरे दौर में पांच अंडर 66 के शानदार स्कोर के साथ टोक्यो खेलों की महिला गोल्फ स्पर्धा में ऐतिहासिक ओलिंपिक पदक की दौड़ में बनी हुई हैं। 23 साल की भारतीय खिलाड़ी ने कासुमिगासेकी कंट्री क्लब में दूसरे दौर में पांच बर्डी की और नौ अंडर 133 के कुल स्कोर से डेनमार्क की नेना कोर्स्ट्ज मैडसन (64) और एमिली क्रिस्टीन पेडरसन (63) के साथ संयुक्त दूसरे स्थान पर चल रही हैं। वह शीर्ष पर चल रही दुनिया की नंबर एक खिलाड़ी अमेरिका की नेली कोर्डा से चार शाट पीछे हैं। दीक्षा डागर एक ओवर 72 के स्कोर से कुल छह ओवर 148 के स्कोर के साथ 53वें स्थान पर हैं।

उजियारा लाया है ये पदक

टॉर्नेडो

41 साल का इंतजार, दर्द आखिरकार खत्म हो गया। कांस्य पदक जीतने की दिशा में इस मजबूत इच्छाशक्ति वाली टीम ने क्या जबरदस्त जज्बा दिखाया। व्यक्तिगत रूप से इस पदक ने सिडनी ओलिंपिक की दिल तोड़ने वाली हार के दुख को भी कुछ हद तक कम किया है जो मुझे अभी तक सालती है। जैसे ही अंपायर ने मैच खत्म होने का संकेत दिया, मैं अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सका। मैं खुद को जाहिर करने की कोशिश कर रहा था लेकिन मुझे शब्द नहीं मिल रहे थे। सेमीफाइनल में मिली हार के बाद वापसी करना कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन इस टीम ने मानसिक व शारीरिक तौर पर खुद को अलग ही सांचे में ढाल लिया। जर्मनी के खिलाफ कभी न हार मानने के जज्बे ने उन्हें पदक की मंजिल तक पहुंचाने में अहम योगदान दिया। दुनिया के लोगों को कोविड-19 के चलते काफी कुछ झेलना पड़ा है और भारत भी इससे काफी प्रभावित हुआ है। इन अंधियारे दिनों में ये कांस्य पदक देश को उजियारा देगा। ठीक वैसे ही जैसे अन्य खेलों में हमने अभी तक पदक जीते हैं। भारत में हाकी सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि ये भावनाओं का जुनून है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व खेल मंत्री समेत पूरे देश ने टीम को अपार समर्थन दिया है। एक एथलीट को और क्या ही चाहिए होता है। बेशक टीम के सदस्यों ने अपना दिल निकालकर प्रदर्शन किया व कोचों ने योजनाओं को अच्छी तरह लागू किया, लेकिन अगर मैं इतने वर्षों से टीम को मिलते आ रहे समर्थन को नजरंदाज करूंगा तो ये गलत होगा।

हाकी एक टीम गेम है और आपको सभी क्षेत्रों में समर्थन की दरकार होती है। इस मामले में आर्थिक मजबूती अहम होती है। हाकी में कारपोरेट फंडिंग साल 2003 में आई थी जब सहारा इंडिया परिवार के सुब्रत राय ने टीम को समर्थन देना शुरू किया था। कुछ साल पहले ही मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की ओडिशा सरकार ने हाकी की ओर हाथ बढ़ाया। न केवल उन्होंने पैसों से मदद की बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी मुहैया कराया। 2018 हाकी विश्व कप जैसा बड़ा आयोजन कराया। इससे भारत को सर्वश्रेष्ठ टीमों से भिड़ने की दिशा में बेहतर तैयारी करने का मौका मिला। इस टीम को इस पल के लिए तैयार होने में कई साल लगे। टर्निंग प्वाइंट साबित हुई 2016 जूनियर विश्व कप में मिली जीत, जो हरेंद्र सिंह की कोचिंग में लखनऊ में मिली। (टीसीएम)

दैनिक जागरण
सप्तरंग
मनोरंजन की दुनिया का
शुक्रवार, 6 अगस्त, 2021

वेब सीरीज 7 कदम का पोस्टर

वेब सीरीज बाम्बर्स का पोस्टर

चर्चा में

जीतना सिखाती हैं खेलों से जुड़ी कहानियां

टोक्यो ओलिंपिक में खिलाड़ी देश के लिए पदक जीतने की जीतोड़ कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच खिलाड़ियों के निजी जीवन की उतार-चढ़ाव भरी दिलचस्प कहानियां भी लोगों के सामने आ रही हैं। हिंदी सिनेमा में 'चक दे इंडिया', 'मैरीकाम', 'भाग मिल्खा भाग' और 'एम एस धौनी- द अनटोल्ड स्टोरी' जैसी फिल्मों में खिलाड़ियों के जुनून और खेल के मैदान से जुड़े जज्बातों को एक ओर जहां बखूबी दर्शाया गया है, वहीं दूसरी ओर 'इनसाइड एज', 'सेलेक्शन डे' और 'बाम्बर्स' जैसी वेब सीरीज में डिजिटल प्लेटफार्म पर खिलाड़ियों के जज्बे और रिश्तों को गहराई से दिखाया गया। आने वाले दिनों में 'इनसाइड एज 3' और टेनिस खिलाड़ी महेश भूपति और लिएंडर पेस की जोड़ी पर आधारित 'ब्रेक प्वाइंट' समेत कई वेब सीरीज कतार में हैं। खेलों पर आधारित कंटेंट के निर्माण की चुनौतियों और तैयारियों की पड़ताल कर रहे हैं दीपेश पांडेय...

वेब सीरीज इनसाइड एज का पोस्टर

वेब सीरीज सेलेक्शन डे का दृश्य

फिल्में हों या वेब सीरीज, खेलों पर आधारित कहानियों में दर्शकों की दिलचस्पी हमेशा रही है। खेल के मैदान की हलचल के साथ ही खिलाड़ियों की निजी जिंदगी में चल रहे उतार-चढ़ाव से दर्शक खुद को जोड़ते हैं और फिर कहानी के बहाव के साथ आगे बढ़ते हैं।

हर पल मिलता है रोमांच: वेब सीरीज 'इनसाइड एज' के निर्देशक करण अंशुमन कहते हैं, 'स्पोर्ट्स ड्रामा कहानियां दर्शकों को दिलचस्प लगती हैं, क्योंकि खेल में हर मिनट रोमांच होता है। दर्शकों में उत्सुकता रहती है कि आगे क्या होने वाला है। खेल के दौरान खिलाड़ियों की भावनाओं के ग्राफ के साथ-साथ दर्शकों की भावनाओं में भी उतार-चढ़ाव आता है। स्पोर्ट्स ड्रामा देखते समय दर्शकों के इमोशंस भी डबल हो जाते हैं। हमारे शो में क्रिकेट के साथ-साथ राजनीति, ग्लैमर, रोमांस और महिला सशक्तीकरण समेत कई चीजें दिखाई गई हैं। इन चीजों के साथ मिलकर दर्शकों की भावनाएं डबल हो जाती हैं।' इस संबंध में वेब सीरीज '7 कदम' में कोच का किरदार निभाने वाले रोनित राय कहते हैं, 'स्पोर्ट्स ड्रामा में सिर्फ खेल को नहीं दिखाते हैं। खेलों के विकल्प तो दर्शकों के पास मौजूद रहते हैं। वेब सीरीज में खेलों को कहानी में पिरोया जाता है, उसमें अलग-अलग जज्बात मिलाए जाते हैं तो कहानी दिलचस्प बन जाती है। दर्शक ऐसी ही चीजें पसंद करते हैं।'

एक्टर्स ढूंढ़ना बड़ी चुनौती: खिलाड़ी का किरदार निभाने के लिए ऐसे कलाकार चाहिए होते हैं, जो शारीरिक तौर पर और जीवनशैली के स्तर पर भी खिलाड़ियों की तरह ही लगें। इस बाबत करण अंशुमन कहते हैं, 'स्पोर्ट्स ड्रामा के लिए अच्छा एक्टर ढूंढ़ना ही काफी नहीं है। किरदार निभाने वाले कलाकार को खुद भी स्पोर्ट्स में अच्छा होना चाहिए। कास्टिंग के वक्त यह सुनिश्चित करना होता है कि वह कलाकार स्क्रीन पर संबंधित खेल को अच्छी तरह से खेल सकता है। इसके अलावा खेल पर आधारित शो को कैमरे पर शूट करना भी एक बड़ी चुनौती होती है। शूटिंग के दौरान सिनेमैटोग्राफी के नजरिए से रियल और सिनेमैटिक दोनों चीजों का संतुलन जरूरी होता है।'

जानकारी होना जरूरी: स्पोर्ट्स आधारित वेब सीरीज के लिए कलाकारों को भी काफी मेहनत करनी पड़ती है। उन्हें पेशेवर खिलाड़ियों की तरह प्रशिक्षित किया जाता है ताकि कैमरे के सामने कोई कमी न दिखे। इस बाबत वेब सीरीज 'बाम्बर्स' में फुटबाल खिलाड़ी का किरदार निभाने वाले अभिनेता प्रिंस नरूला बताते हैं, 'ऐसे किरदार में कलाकार की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अपने पहले शो में मैं कुश्ती लड़ने वाला पहलवान बना था। इसके लिए मैंने 22 किलो वजन बढ़ाया था। 'बाम्बर्स' में मैंने फुटबाल खिलाड़ी का किरदार निभाया था। उसके लिए फुटबाल की ट्रेनिंग ली। उसके नियम कायदे समझे, क्योंकि इसके अभाव में मैं अच्छा काम नहीं कर पाता।' इस संबंध में रोनित राय कहते हैं, 'हर कलाकार को अपने किरदार का हुनर सीखना पड़ता है। अगर आपका किरदार फुटबाल खिलाड़ी है तो उसे फुटबाल का खेल सीखना ही पड़ेगा। मैं तो स्कूल में फुटबालर था। अपने स्कूल के कोच को याद करते हुए मुझे अपना किरदार निभाने में ज्यादा दिक्कत नहीं आई। '7 कदम' में अमित साध ने मुझसे ज्यादा ट्रेनिंग ली थी, क्योंकि उन्हें खेलना था।'

बांधकर रखती है रिश्तों की डोर: स्पोर्ट्स ड्रामा कहानियों में खेल के साथ-साथ खिलाड़ियों के व्यक्तिगत रिश्तों की कशमकश को भी बखूबी दिखाया जाता है। खिलाड़ियों में अनुशासन होता है जो रिश्तों के लिए जरूरी होता है। अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट्स के लिए खिलाड़ी अक्सर माता-पिता, पत्नी और बच्चों से दूर देश के बाहर भी जाते रहते हैं। इसलिए उनके लिए रिश्तों की अहमियत बढ़ जाती है। उनकी कहानियों में रिश्ते अच्छी तरह से उभरकर सामने आते हैं। इस बारे में वेब सीरीज 'सेलेक्शन डे' में कोच का किरदार निभाने वाले अभिनेता राजेश तैलंग कहते हैं, 'जब तक आप खिलाड़ियों के व्यक्तिगत संबंधों की बात नहीं करेंगे, तब तक न तो कहानी बनती है न ही किरदार। फिर जीत और हार से किसी को फर्क ही नहीं पड़ता है। खिलाड़ियों के रिश्तों की गहराई में जाना जरूरी होता है ताकि उनसे जुड़कर दर्शकों के लिए भी उनकी जीत-हार जरूरी हो जाए।'

नई प्रतिभाओं के लिए प्रेरणा: हार-जीत, गिरना-उठना, संभलना और आगे बढ़ना, सफलता के लिए हर वक्त प्रयासरत रहना ये सब चीजें खेलों का अहम हिस्सा होती हैं। राजेश तैलंग कहते हैं, 'खिलाड़ियों की बायोपिक से खिलाड़ी बनने की चाह रखने वाले बच्चों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। खेलों में उनकी रुचि पैदा होती है। फिल्म 'चक दे इंडिया' के बाद हो सकता है ऐसी बहुत सी बच्चियां हों, जिन्होंने हाकी खेलना शुरू किया हो।' इस संबंध में प्रिंस नरूला का कहना है, 'स्पोर्ट्स पर आधारित ज्यादातर कहानियां हिट होती हैं, क्योंकि दर्शक उन लोगों की अहमियत समझते हैं जो अपने ऊपर मेहनत करते हैं और देश का प्रतिनिधित्व करते हैं।'

बढ़ जाता है खर्च: स्पोर्ट्स ड्रामा शो बनाने के लिए खिलाड़ियों की ट्रेनिंग से लेकर, स्टेडियम, दर्शक, खेल के साजोसामान और तकनीकी कौशल समेत कई अतिरिक्त चीजों की जरूरत पड़ती है। लिहाजा ऐसे शो आम ड्रामा शो की तुलना में ज्यादा खर्चीले होते हैं। इस बारे में करण अंशुमान कहते हैं, 'स्पोर्ट्स ड्रामा में भीड़, स्टेडियम, ग्राफिक्स आदि बनाने में वीएफएक्स का बहुत इस्तेमाल होता है। इसके अलावा कलाकारों को खिलाड़ियों की तरह पेशेवर ट्रेनिंग भी दिलानी पड़ती है। इसमें समय और पैसा दोनों लगते हैं। एक रेगुलर ड्रामा बनाने की तुलना में खेलों से जुड़ी कहानी बनाना कहीं ज्यादा खर्चीला होता है, लेकिन उसका फल भी अच्छा मिलता है।'

भविष्य में बढ़ सकती है संख्या: आगामी दिनों में क्रिकेट और उसके पीछे होने वाले तमाम दांव पेंच पर आधारित 'इनसाइड एज 3' और टेनिस में विंबलडन खिताब जीतने वाली लिएंडर पेस और महेश भूपति की पहली भारतीय जोड़ी की जिंदगी को दिखाती वेब सीरीज 'ब्रेक प्वाइंट' कतार में हैं। इन दिनों टोक्यो में चल रहे ओलिंपिक खेलों में मेडल के लिए प्रयास कर रहे कई खिलाड़ियों की दिलचस्प कहानियां सामने आ रही हैं। इससे भविष्य में खेलों पर आधारित कई नए शो की घोषणा की जा सकती है। फिल्म निर्माता और ट्रेड एनालिस्ट गिरीश जौहर कहते हैं, 'हर खिलाड़ी की एक स्टोरी होती है। वह किन परिस्थितियों से जूझता हुआ अपने मुकाम पर पहुंचता है, यह देखना दिलचस्प होता है। इसे अलग-अलग निर्माता-निर्देशक अपने तरीके से गढ़ते हैं। फिलहाल ओलिंपिक चल रहे हैं तो देश में खेल का माहौल है। हमारे खिलाड़ी पदक जीत रहे हैं। ऐसे में भविष्य में और भी कई स्पोर्ट्स ड्रामा वेब सीरीज का ऐलान संभव है।'

पी वी सिंधु की बायोपिक

टोक्यो ओलिंपिक में अपना दूसरा पदक जीतने वाली भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी पी वी सिंधु की बायोपिक बनाने की घोषणा अभिनेता सोनू सूद पहले ही कर चुके हैं। कोरोना की वजह से फिलहाल यह प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि पी वी सिंधु के दूसरा पदक जीतने के बाद यह फिल्म किस दिशा में जाती है। उनकी भूमिका कौन सी अभिनेत्री निभाती हैं।

मुलाकात

सेना का अनुशासन बहुत प्रेरक है

एंथोलाजी फिल्म 'लस्ट स्टोरीज', 'कबीर सिंह', 'गुड न्यूज' से सफलता का स्वाद चखने वाली किआरा आडवाणी लगातार बड़े बैनर की फिल्म कर रही हैं। उनकी फिल्म 'शेरशाह' 12 अगस्त को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी। यह फिल्म कारगिल युद्ध के नायक विक्रम बत्रा की बायोपिक है। फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा विक्रम बत्रा बने हैं जबकि कियारा उनकी प्रेमिका डिंपल चीमा की भूमिका में हैं। इसके बाद कियारा फिल्म 'भूल भुलैया 2', 'जुग जुग जियो' में नजर आएंगी। करियर, फिल्म और अन्य मुद्दों पर कियारा की स्मिता श्रीवास्तव से बातचीत:

आपने कहा था कि करियर की शुरुआत में किसी चीज को खोने का डर नहीं था। अब इस मुकाम पर क्या कहेंगी?

अब सच कहूं तो है। जब आपके पास कुछ खोने को नहीं होता है तो आप निडर होकर काम करते हो, लेकिन जब थोड़ी सी रिस्पांसिबिलिटी आपके कंधों पर आ जाती है तो समझ आता है कि आप क्या करना चाहते हो? लोग जानना चाहते हैं कि आपका अगला प्रोजक्ट क्या होगा? मैं कोशिश कर रही हूं कि उन चीजों को प्रेशर के तौर पर न लूं। मैं अब भी पहले जैसी इनोसेंस और फीयरलेसनेस से काम कर रही हूं। आज भी मैं स्क्रिप्ट पसंद आने पर ही स्वीकृति देती हूं। कुछ फैसले अच्छे होते हैं, कुछ फैसले बाद में ऐसे लगते हैं कि ओके। पर्सनली हर फिल्म ने मुझे आगे बढ़ाने में मदद की है।

...लेकिन इंडस्ट्री में गला काट प्रतियोगिता है। ऐसे में दबाव होना स्वाभाविक है?

मेरे हिसाब से अगर कंप्टीशन नहीं होता तो आप कभी इंस्पायर ही नहीं होते। मैं किसी और की फिल्म में कुछ अच्छा देखती हूं तो मन में आता है कि यह इतना अच्छा रोल था। काश मैं कर पाती, यह चीज हमेशा प्रेरणा देने वाली होती है। यहां दबाव इस बारे में ज्यादा है कि आप अपनी पिछली फिल्म से कितना आगे जा सकते हैं। मुझे कुछ ऐसा काम करना है जिसे किसी ने देखा न हो। मैं अपने काम को रिपीट न करूं। जब 'कबीर सिंह' रिलीज हुई तब मुझे पता था कि छह महीने बाद 'गुड न्यूज' आने वाली है। उसके बाद 'गिल्टी' आ गई। मेरा काम देखकर सब चौंके थे। जिन डायरेक्टर ने मुझे कास्ट किया उन्हें मुझमें पोटेंशियल दिखा होगा। शायद मैंने भी खुद में वह न देखा हो। उनके विश्वास से मुझमें यह विश्वास आया कि मैं कोशिश तो जरूर करूंगी। सौभाग्य से दर्शकों को मेरा काम पसंद आया।

'शेरशाह' का ट्रेलर कारगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर द्रास में सैन्य कर्मियों की मौजूदगी में लांच किया गया। वहां का कैसा अनुभव रहा?

(मुस्कुराते हुए) यह जिंदगी में एक बार मिलने वाला अनुभव है। मेरी खुशकिस्मती है कि ऐसी फिल्म का हिस्सा हूं जिसकी वजह से मुझे कारगिल जाने का मौका मिला। विजय दिवस पर भारतीय सेना के सामने अपना ट्रेलर पेश करना अलग अनुभव था। सेना का अनुशासन बहुत प्रेरक है।

फिल्म को करने से पहले आपकी डिंपल से मुलाकात हुई?

जी हां। फिल्म की शूट से पहले ही मुलाकात हुई थी। ऐसा लग रहा था कि दो लड़कियां एकदूसरे के साथ अपनी लाइफ शेयर कर रही हैं। वह अपनी रिलेशनशिप के किस्से मेरे साथ साझा कर रही थीं। वह जो बातें बता रहीं थीं उसे हमने अपनी फिल्म में दर्शाया भी है। बहुत सारे डायलाग ऐसे हैं जिन्हें कैप्टन विक्रम बत्रा ने बोला था। उसे फिल्म में रीक्रिएट किया गया है। जिन जगहों पर विक्रम और डिंपल मिले उन लोकेशन पर जाकर हमने शूट किया। विष्णु वर्धन सर (निर्देशक) ने उसे बहुत विश्वसनीय बनाया है। एक प्वाइंट पर मुझे लगा कि मैं वाकई डिंपल चीमा हूं और सिद्धार्थ विक्रम बत्रा। हमें लगा कि एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन भावनाओं का अहसास कर रहे थे जो उन्होंने अनुभव किया होगा।

'कबीर सिंह' में प्यार में दीवानगी पागलपन की हद तक थी। 'शेरशाह' में प्यार में त्याग है। प्यार की सीमाओं को लेकर क्या कहेंगी?

यह स्वार्थ रहित प्यार है। एक आर्मी आफिसर के सपनों को सपोर्ट करना, यह जानने के बावजूद कि बहुत ही जोखिम वाला जाब है। उनकी ड्यूटी के बारे में आप पूछ भी नहीं सकते हैं कि दिन कैसा रहा? उनके अपने प्रोटोकाल होते हैं। उन सीमाओं को आप पार नहीं कर सकते हैं। चंद पल जो आपको मिलते हैं उनके साथ बात करने के। कई बार एकदूसरे से मिलने का बहुत कम समय मिलता है। उसके बावजूद प्यार में कमी नहीं आती।

विक्रम के शहीद होने के बाद डिंपल ने शादी नहीं की...

डिंपल स्ट्रांग महिला है जो अपने निर्णय खुद लेती हैं। उन्होंने प्यार को सबसे ऊपर रखा। मैं चाहूंगी कि मुझे भी ऐसा प्यार हो। जब भी वह कैप्टन विक्रम बत्रा के बारे में बात करती हैं तो बहुत सारा गर्व, प्यार और खुशी का अहसास उनकी आंखों में झलकता है। उन्हें लगता है कि विक्रम उनके साथ हैं।

आपके जन्मदिन पर तमिल फिल्मकार एस शंकर के निर्देशन में एक फिल्म की घोषणा हुई। फिल्म को तीन भाषाओं में बनाया जाएगा...

यह फिल्म खास है मेरे लिए। पहली बार मैं शंकर सर के साथ काम करूंगी। मैं बहुत एक्साइटेड हूं। इस फिल्म से एक गैप के बाद तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में मेरी एक तरह से वापसी भी हो रही है। उसके लिए मैं सही मौके का इंतजार कर रही थी। अब मौका मिला है तो अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करूंगी।

बातचीत

मैं अपने रास्ते चलता हूं

डिजिटल प्लेटफार्म जी5 पर आज रिलीज हुई फिल्म 'डायल 100' में मनोज बाजपेयी पुलिस अधिकारी निखिल सूद का किरदार निभा रहे हैं। 31 अगस्त को साल 1994 में रिलीज हुई मनोज की डेब्यू फिल्म 'द्रोहकाल' के 27 वर्ष पूरे हो जाएंगे। हिंदी सिनेमा में ढाई दशक से भी अधिक के सफर के अनुभवों, इस फिल्म और उनके व्यक्तिगत जीवन को लेकर मनोज से बातचीत के अंश:

इस फिल्म में आपके लिए खास आकर्षण क्या रहा?

इस फिल्म का नाम 'डायल 100' सुनते ही मुझे अंदाजा लग गया था कि यह कोई बढ़िया थ्रिलर फिल्म है। यह नाम बहुत ही अनोखा और आकर्षक था। थ्रिलर के अलावा यह फिल्म एक सामाजिक विषय पर भी बात करती है कि कैसे अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करें और उनको किसी गलत चक्कर में फंसने से बचाएं। आज इससे सभी माता-पिता जूझ रहे हैं। इस फिल्म में दिखाया गया है कि एक 15-16 साल का बच्चा अपने माता-पिता को क्यों विलेन मानकर चलता है।

आप बच्चों की किस तरह की परवरिश में यकीन करते हैं?

नैतिक मूल्य और संस्कार बच्चों की परवरिश में होने जरूरी हैं। बच्चों को यह संस्कार देना जरूरी है कि समाज का हर वर्ग समान है। उनमें वे भेद न करें। समानता में विश्वास करें। हमेशा व्यक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, उसका ओहदा या पैसा नहीं। इन्हीं चीजों में मैं यकीन करता हूं और अपनी बेटी को भी यही सब सिखाने का प्रयास करता हूं।

फिल्म की कहानी एक फोन काल के इर्दगिर्द घूमती है, क्या आप भी कभी अनचाहे या अनजाने फोन काल का शिकार बने हैं?

अब तो मैं अनजान फोन काल उठाता ही नहीं हूं। पहले सभी के फोन काल रिसीव कर लिया करते थे। कई लोग सिर्फ मजे लेने के लिए फोन करते थे। कुछ लोग तो सिर्फ मेरी प्रतिक्रिया जानने के लिए फोन पर धमकियां भी देते थे कि देखते हैं इस पर मनोज बाजपेयी क्या कहेंगे। अब तो मैं रात सात बजे के बाद किसी का भी फोन नहीं उठाता हूं।

यह फिल्म बदले की भावना पर भी केंद्रित है। आप इस पर कितना यकीन करते हैं?

मैं बदले की भावना से प्रेरित शख्स नहीं हूं। मैं अपने रास्ते चलता रहता हूं, जिसको जो कहना है कहे, जो बोलना है बोले, जो समझना है समझे। मेरे साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो भी मैं उस शख्स को माफ कर देता हूं, लेकिन हां, अगर कोई ज्यादा उत्पात या गलत करता है तो आपको उसके खिलाफ खड़ा होना पड़ता है। वो बदले की भावना नहीं होती है। वो प्रतिक्रिया किसी को सबक सिखाने के लिए होती है ताकि वह चेत जाए कि वह जो कर रहा था वह गलत था।

पुलिस के इर्दगिर्द बुनी कहानियों में निर्माताओं और दर्शकों की दिलचस्पी बरकरार रहने का आप क्या कारण मानते हैं?

पुलिस का काम बहुत चुनौती भरा होता है। इस काम की जिम्मेदारियों और समय की कोई सीमा नहीं होती है। इतनी जिम्मेदारियों के साथ-साथ वे लोगों के विश्वास और अविश्वास के बीच से होकर अपना काम करते हैं। इसलिए उनके बीच से कहानियां बहुत निकलती हैं। आप किसी पुलिसकर्मी के पास बैठ जाएं, उसके अपने कम से कम ऐसे 40 अनुभव होंगे, जिन पर फिल्में बन सकती हैं। इस डिपार्टमेंट से जुड़ा कोई शख्स आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है और जांच के घेरे में भी आ सकता है। पूरे पुलिस विभाग में नाटकीयता बहुत होती है। इसलिए लोगों की दिलचस्पी ऐसी कहानियों में बनी रहती है।

अपने 27 साल के सफर में सिनेमा के साथ-साथ खुद में क्या बदलाव देखते हैं?

सिनेमा लगातार बदलता रहा है और अब भी बदल रहा है। इसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, लेकिन अगर हम उसका सामना करते हैं तो उससे हमारी अपनी कला का विकास होता है। अपनी बात करूं तो मैं पहले से ज्यादा अच्छा कलाकार बन गया हूं। बीतते वक्त के साथ मैंने जीवन को ज्यादा देखा। अपनी कला पर लगातार काम करता रहा, उससे मेरा भी विकास हुआ। आगे भी मैं इसी तरीके से एक अभिनेता और इंसान के तौर पर अपने विकास के लिए काम करता रहूंगा। बस इसी मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा हूं।

दीपेश पांडेय

बंदेमातरम् समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया गया

1906 में आज ही देशबंधु चितरंजन दास, सुबोध चंद्र मलिक, बिपिन चंद्रपाल ने इसका प्रकाशन कोलकाता (कलकत्ता) में शुरू किया। अंग्रेजों की भारत विरोधी नीति के प्रति लोगों को जागरूक करना इसका एजेंडा रहा। इसके चलते 1908 में अंग्रेजों ने इसे बंद करा दिया।

Bande Mataram
Weekly Edition

नासा के विज्ञानियों ने मंगल पर जीवन की संभावना जताई

1996 में आज ही नासा ने मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना जताई थी। मंगल से गिरे उल्कापिंड के परीक्षण के बाद संस्था इस निष्कर्ष पर पहुंची थी। इसके बाद ही मंगल पर अभियानों की बाढ़ आई और कई रोवर भेजे गए।

भारत के जलपुरुष के नाम से विख्यात हैं राजेंद्र सिंह

भारत के आधुनिक भगीरथ कहे जाने वाले राजेंद्र सिंह का जन्म आज ही 1959 में उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में हुआ था। उन्होंने सामाजिक कार्यों के लिए 28 साल की उम्र में सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। अलवर में 1975 में तरुण भारत संघ का गठन किया। इसके माध्यम से जल संरक्षण के लिए आठ हजार से ज्यादा तालाब बनाने में मदद की। राजस्थान के एक हजार गांवों में पानी की आपूर्ति और वहां की पांच नदियों को पुनर्जीवित किया। सामुदायिक नेतृत्व के लिए उन्हें 2001 में रेमन मैग्सेसे और 2015 में स्टाकहोम वाटर प्राइज मिला।

इधर-उधर की

पुलिसवाले के डांस के आगे बड़े-बड़े अभिनेता भी फेल

मुंबई, प्रेट्र : एक पुलिसकर्मी जो अपनी ड्यूटी पूरी निष्ठा से निभाने के साथ ही डांस से भी लोगों के बीच छाए हुए हैं। मुंबई के नायगांव पुलिस मुख्यालय में तैनात 38 साल के पुलिस नायक अमोल कांबले अपने डांस से इंटरनेट मीडिया पर स्टार बन गए हैं। वायरल वीडियो में वह डांस के साथ ही मास्क के लिए भी जागरूक करते दिख रहे हैं। 2004 में मुंबई पुलिस ज्वाइन करने वाले कांबले ने कहा, पुलिसकर्मी होने के नाते कानून व्यवस्था बनाए रखना मेरी प्राथमिकता है। खाली समय में डांस करता हूं। पुलिसकर्मियों के एक कार्यक्रम में वह अभिनेता ऋतिक रोशन के साथ भी डांस का टैलेंट दिखा चुके हैं।

ऋतिक रोशन के साथ भी डांस कर चुके हैं अमोल कांबले • इंटरनेट मीडिया

कैंसर के इलाज का खोजा नया तरीका

शोध ▶ ऊतकों को कैंसरग्रस्त बनाने वाले एक नए प्रोटीन की हुई पहचान

इस प्रोटीन को लक्ष्य कर विकसित की जा सकती है नई दवा

वाशिंगटन, एएनआइ : कैंसर के इलाज की दिशा में एक नई कामयाबी मिली है। विज्ञानियों ने कैंसर के ट्यूमर में एक ऐसे प्रोटीन की खोज की है, जो सामान्य ऊतकों को कैंसर ग्रस्त बनाने में अहम भूमिका निभाता है। अब इस प्रोटीन को लक्षित कर कैंसर का इलाज किया जाना संभव हो सकता है। यह खोज मस्तिष्क, रक्त, त्वचा तथा किडनी जैसे अंगों के कैंसर के लिए खासतौर पर अहम हो सकता है, जहां कैंसर बहुत तेजी से फैलता है। यह शोध मोलेक्युलर सेल जर्नल में प्रकाशित हुआ है।

यह खोज यूनिवर्सिटी आफ कैंब्रिज के वेलकम सेंगर इंस्टीट्यूट तथा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के विज्ञानियों ने की है। उनके मुताबिक, इस प्रोटीन को खत्म करने वाली या इसके बनने को रोकने वाली दवा विकसित कर कैंसर का प्रभावी इलाज किया जा सकता है। चूहों पर किए गए प्रयोग में पाया गया कि इस प्रोटीन को रोकने से कैंसर सेल नष्ट हुआ और स्वस्थ कोशिकाओं को कोई नुकसान भी नहीं हुआ।

इलाज के लिए नई दवा की आस। फाइल फोटो

यह शोध इस बात को सुनिश्चित करने वाला है कि एमईटीटीएल1 नामक इस प्रोटीन को बनने से आरएनए-माडीफाइंग आधारित दवा विकसित कर रोका जा सकता है, जिससे कैंसर का एक नया इलाज मिल सकता है। एमईटीटीएल फैमिली में आरएनए-माडीफाइंग प्रोटीन कोशिकाओं के वृद्धि में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये प्रोटीन कुछ खास प्रकार के कैंसर सेल में पाए जाते हैं। इनमें मस्तिष्क, रक्त, अग्नाशय (पैंक्रियाज) तथा त्वचा के कैंसर भी शामिल हैं।

शोधकर्ता डाक्टर त्जेलेपिस ने यूनिवर्सिटी आफ कैंब्रिज तथा वेलकम सैंगर इंस्टीट्यूट के अपने सहयोगियों के साथ मिलकर सीआरआइपीआर-सीएएस9 नामक तकनीक के इस्तेमाल से कैंसर सेल के कमजोर स्थानों की खोज की थी। अगले चरण में शोधकर्ताओं ने एमईटीटीएल1 जीन की पहचान की, जो आरएनए-माडीफाइंग एमईटीटीएल1 प्रोटीन का उत्पादन करता है। अब एक ऐसी दवा विकसित की जानी है, जो इसे निशाना बना सके। शोधकर्ताओं ने एक नए अध्ययन में यह भी पाया है कि एमईटीटीएल1 जीन में म्यूटेशन से उच्चतर स्तर का एमईटीटीएल1 प्रोटीन बनता है, जो कोशिकाओं को बहुत तेजी से बढ़ाता है और इसी कारण ट्यूमर भी तेजी बढ़ता है।

शोधकर्ताओं ने जब उक्त जीन को बाहर कर एमईटीटीएल1 प्रोटीन का बनना रोक दिया तो पाया कि कैंसर ग्रस्त कोशिकाओं की वृद्धि रुक गई और सबसे खास बात यह कि इससे सामान्य या रोग मुक्त कोशिकाओं को कोई नुकसान भी नहीं हुआ। ये दोनों ही प्रयोग इस बात के संकेत हैं कि कैंसर के इलाज में इसे नष्ट करना एक सटीक लक्ष्य हो सकता है।

इतना ही, शोधकर्ताओं की टीम ने हाल ही में एक ऐसे ही प्रोटीन- एमईटीटीएल3 को बनने से रोकने वाले एक मोलेक्युल इन्हिबिटर भी विकसित कर लिया है, जिससे रक्त और बोनमैरो के गंभीर कैंसर (एक्यूट मायेलायड ल्यूकेमिया) के इलाज में मदद मिली है और 2022 में इसका क्लिनिकल ट्रायल भी किए जाने की संभावना है। इससे यह उम्मीद जग रही है कि आगे के शोध में कोई ऐसी दवा विकसित की जा सकेगी, जो एमईटीटीएल1 को खत्म करने में सक्षम होगी और कैंसर का एक नया इलाज उपलब्ध होगा। कैंसर सेल में एमईटीटीएल1 प्रोटीन की बढ़ी हुई मात्रा की वजह से उसका इस्तेमाल एक बायोमार्कर की तरह भी किया जा सकता है और उससे इलाज का बेहतर प्रबंधन किया जा सकेगा। दवा के विकास में क्लिनिकल ट्रायल में भी मदद मिलेगी कि किस रोगी पर दवा का कितना असर होगा।

आराम करते गजराज...

दक्षिण-पश्चिम चीन के युन्नान प्रांत में सोता हुआ एशियाई हाथियों का झुंड। पेट भरने के बाद ये नजदीक के जंगल में आराम कर रहे हैं। इन छोटे-बड़े हाथियों ने यहां मक्का, गन्ना और केले के खेतों को काफी नुकसान पहुंचाया है। एक साल से यह झुंड नेचर रिजर्व से निकलकर आसपास के क्षेत्रों में घूम रहा है। जहां से भी गुजरते हैं, सामने पड़ने वाली फसलों को नष्ट कर देते हैं। इनकी ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। खदेड़े जाने पर ये हिंसक भी हो जाते हैं। एएफपी

कोरोना से बचाव में कारगर हो सकता है फ्लू का टीका

अनुसंधान

बचाव का एक और टीका। फाइल फोटो

कोरोना वायरस (कोविड-19) से मुकाबले के लिए फ्लू के टीके को लेकर एक बड़े पैमाने पर अध्ययन किया गया है। इसका दावा है कि सालाना तौर पर लगने वाली यह इंफ्लुएंजा वैक्सीन कोरोना पीड़ितों में इस खतरनाक वायरस के गंभीर प्रभावों से बचाव में कारगर हो सकती है। यह वैक्सीन लगने से स्ट्रोक, सेप्सिस, रक्त का थक्का बनने समेत कई गंभीर प्रभावों का खतरा कम हो सकता है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी आफ मियामी मिलर स्कूल आफ मेडिसिन के शोधकर्ताओं के अनुसार, फ्लू के खिलाफ टीका लगवाने वाले कोरोना मरीजों को आइसीयू में भर्ती करने की जरूरत भी कम पड़ती है। प्रमुख शोधकर्ता और मिलर स्कूल के प्रोफेसर देविंदर सिंह ने बताया, 'मेरी टीम ने फ्लू टीके का संबंध पीड़ितों में कोरोना के गंभीर प्रभावों के खतरे में कमी से पाया है।' पीएलओएस वन पत्रिका में गत तीन अगस्त को प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक, यह निष्कर्ष अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, इजरायल और सिंगापुर के डाटा के विश्लेषण के आधार पर निकाला गया है। शोधकर्ताओं ने मरीजों के दो समूहों की पहचान की। एक समूह के लोग संक्रमित होने से फ्लू का टीका लगवा चुके थे। जबकि दूसरे समूह के लोग भी कोरोना से पीड़ित पाए गए, लेकिन उन्होंने फ्लू के खिलाफ टीका नहीं लगवाया था। -प्रेट्र

भूकंप से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए अलर्ट एप

जागरण संवाददाता, रुड़की

उपलब्धि

- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की ने विकसित किया है उत्तराखंड भूकंप अलर्ट एप
- गढ़वाल व कुमांऊ मंडल में लगे सेंसर से 5.5 तीव्रता से अधिक के भूकंप आने पर करेगा सतर्क

भूकंप से होने वाले नुकसान को कम करने की दिशा में उत्तराखंड सरकार ने अहम कदम बढ़ाया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी), रुड़की के माध्यम से 'उत्तराखंड भूकंप अलर्ट' एप तैयार किया है। बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह के हाथों लांच इस एप के जरिये रिक्टर पैमाने पर 5.5 तीव्रता से अधिक के भूकंप आने पर संभावित इलाकों में लोगों को सतर्क किया जा सकेगा। ऐसे में सुरक्षात्मक उपाय तत्काल शुरू किए जा सकेंगे।

आइआइटी, रुड़की के विज्ञानी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम फार नादर्न इंडिया प्रोजेक्ट पर 2014 से काम कर रहे हैं। भू-विज्ञान विभाग के प्रोफेसर एवं प्रोजेक्ट के प्रिंसिपल इंवेस्टीगेटर प्रो. कमल के अनुसार भूकंप आने पर तत्काल अलर्ट के लिए गढ़वाल और कुमांऊ में 165 सेंसर लगाए गए हैं। चमोली से उत्तरकाशी तक कुल 82 और पिथौरागढ़ से लेकर धारचूला तक 83 सेंसर लगाए गए हैं। इसकी अगली कड़ी में मोबाइल एप पर 2017 से कार्य शुरू किया गया था।

ऐसे करेगा एप काम : भूकंप आने पर चंद सेकंड में ही मोबाइल पर डाउनलोड यह एप सायरन व वायस मैसेज के जरिये सचेत करेगा। इस एप पर दो निशान बने हैं। 'मुझे मदद चाहिए' दर्शाने वाला लाल निशान क्लिक करते ही मुसीबत में फंसे व्यक्ति की लोकेशन मिलेगी। हरा निशान 'मैं सुरक्षित हूं' का संकेत देगा। वर्तमान में भूकंप से अलर्ट के लिए प्रदेश के विभिन्न संवेदनशील इलाकों में लगाए गए सेंसर से डाटा आइआइटी रुड़की के अर्ली वार्निंग सिस्टम कंट्रोल रूम तक पहुंचता है। यह एप इस कंट्रोल रूम के सर्वर से जुड़ा रहेगा।

ऐसे पहुंचेगा एप से अलर्ट : भूकंप आने की स्थिति में यह एप अलार्म बजाएगा। तीन से चार बार अलार्म के बाद वायस मैसेज देकर सतर्क करेगा।

एक मिनट में दिल्ली होगी सतर्क : उत्तराखंड के जिन क्षेत्रों में सेंसर लगे हैं, यदि वहां भूकंप आता है तो उसका अलर्ट देहरादून तक 15 सेकंड, रुड़की तक 20 सेकंड और दिल्ली तक लगभग एक मिनट तक पहुंच जाएगी।

ऐसे करें डाउनलोड

इस एप के दो वर्जन-एंड्रायड और आइओएस दोनों प्लेटफार्म के लिए उपलब्ध हैं। गूगल प्ले स्टोर में यह उत्तराखंड भूकंप अलर्ट के नाम से उपलब्ध है। प्ले स्टोर पर सर्च करने पर यह पीले रंग के लोगो के साथ दिखेगा। इसे डाउनलोड करने के लिए यह कुछ बेसिक जानकारी मांगेगा। जैसे-नाम, मोबाइल नंबर, स्वजन व उनके घर से कुछ दूरी पर रहने वाले किसी भी चिर-परिचित या दोस्त का मोबाइल नंबर। जानकारी देने के बाद संबंधित व्यक्ति के मोबाइल में एप इंस्टाल हो जाएगा। यह एप हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है।

स्क्रीन शॉट

अगली फिल्म में माता-पिता को गोद लेंगे राजकुमार

आगामी दिनों में फिल्म बधाई दो में नजर आएंगे राजकुमार। इंस्टाग्राम

हिंदी सिनेमा में कुछ कलाकार विषयों के साथ लगातार प्रयोग करने के लिए जाने जाते हैं। रूही, छलांग और शाहिद जैसी फिल्मों के अभिनेता राजकुमार राव भी ऐसे ही कलाकारों में गिने जाते हैं। वह अभिनेत्री भूमि पेडणेकर के साथ अपनी आगामी फिल्म बधाई दो की शूटिंग पूरी कर चुके हैं। अब वह अपनी अगली फिल्म की तैयारी में जुटे हैं। उनकी अगली फिल्म अभिनेत्री कृति सैनन के साथ होगी। हालांकि अभी तक इस फिल्म का नाम नहीं तय है। बताया जा रहा है कि जहां सामान्यतः माता-पिता बच्चे गोद लेते हैं। वहीं इस फिल्म में राजकुमार और कृति माता-पिता गोद लेते हुए नजर आएंगे। फिल्म से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, इस फिल्म में राजकुमार और कृति ऐसे विवाहित जोड़े के किरदार में हैं, जो अपने जीवन में माता-पिता के प्यार की कमी महसूस करते हैं। इस कमी को दूर करने के लिए यह जोड़ा एक बुजुर्ग दंपती को माता-पिता के तौर पर गोद लेता है। फिल्म में रत्ना पाठक और परेश रावल दोनों के माता पिता के किरदार में हैं। फिल्म के बारे में फिलहाल कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन इस बारे में कृति ने दैनिक जागरण के सहयोगी अखबार मिड डे से बातचीत में कहा, 'मिमी में मैंने एक बच्चे को जन्म दिया था और इसमें हम दोनों माता-पिता गोद ले रहे हैं। यह फिल्म एक खूबसूरत सामाजिक संदेश वाली फिल्म है, जिसमें मैंने पहली बार रत्ना मैम और परेश सर के साथ काम किया है, उनके साथ काम करते हुए मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला।'

हमारे यहां फिल्मकार जाति से संबंधित मुद्दे उठाने से बचते हैं : अमोल पालेकर

सिनेमा में अक्सर समाज से जुड़े कई मुद्दे उठाए जाते रहे हैं। हालांकि, गोलमाल और श्रीमान श्रीमती जैसी फिल्मों के अभिनेता अमोल पालेकर का मानना है कि अब भी हमारे फिल्मकार जातिगत समस्याओं से संबंधित मुद्दों को उठाने से बचते हैं। अमोल आगामी दिनों में सच्ची घटना पर आधारित फिल्म 200 हल्ला हो में एक रिटायर्ड न्यायाधीश के किरदार में नजर आएंगे। यह फिल्म साल 2004 में हुई घटना पर आधारित है, जब 200 दलित महिलाओं ने एकजुट होकर दुष्कर्मी भारत कालीचरण उर्फ अक्कू यादव को भरी अदालत में पीट-पीट कर मार डाला था। 20 अगस्त को जी 5 पर रिलीज हो रही इस फिल्म का गुरुवार को ट्रेलर रिलीज किया गया। इस मौके पर आयोजित वर्चुअल कांफ्रेंस में अमोल पालेकर ने कहा, 'हमारे यहां बनने वाली फिल्मों में हम लड़का-लड़की के मिलने वाले पैटर्न से बाहर बहुत कम जाते हैं। यह फिल्म कोई लव स्टोरी नहीं है, यही वजह है कि मुझे पसंद आई। हमारे यहां कुछ गिनी-चुनी फिल्मों को छोड़कर जाति से संबंधित समस्याओं पर बात करने से फिल्म मेकर्स बचते हैं। इस फिल्म में निर्देशक ने कोई भी तथ्य छुपाने या किसी चीज से बचने की कोशिश नहीं की है। फिल्म में मेरा किरदार एक रिटायर्ड जज का है, जो खुद दलित परिवार से है।' इस फिल्म में अभिनेता साहिल खट्टर अक्कू यादव से प्रेरित किरदार निभा रहे हैं। फिल्म में रिंकू राजगुरु और इंद्रनील सेनगुप्ता भी अहम भूमिकाओं में हैं।

फिल्म 200 हल्ला हो में रिटायर्ड जज के किरदार में नजर आएंगे अमोल। इंस्टाग्राम

शादी के बाद मेरी नहीं, संकेत की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं : सुगंधा मिश्रा

अक्सर कहा जाता कि शादी के बाद पति-पत्नी दोनों की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। हालांकि, कुछ महीने पहले कामेडियन संकेत भोसले के साथ परिणय सूत्र में बंधीं कामेडियन, अभिनेत्री और गायिका सुगंधा मिश्रा के मामले में यह अलग है। सुगंधा शादी के बाद अपनी जिम्मेदारियों में हल्कापन महसूस कर रही हैं। दैनिक जागरण से बातचीत में सुगंधा ने बताया, 'अब मेरी ज्यादातर जिम्मेदारियां संकेत साझा करते हैं। मैं काफी आराम से रहती हूं। मेरा परिवार पंजाब में रहता है, तो मुंबई में अकेले रहकर मुझे हर काम खुद करना पड़ता था, लेकिन शादी के बाद अब ज्यादातर काम संकेत देखते हैं। मैं सिर्फ बैठकर आर्डर करती हूं। वह बहुत ख्याल रखने वाले इंसान हैं। सेट पर शूटिंग करते हुए मैं अक्सर काम में इतना ज्यादा व्यस्त हो जाती हूं कि खाने-पीने पर ध्यान ही नहीं रहता है। हमारे समाज में अक्सर देखा जाता है पत्नी पति से वक्त-वक्त पर उनके खाने-पीने के बारे में पूछती रहती हैं। हमारे मामले में उल्टा है। संकेत मेरे लिए खाना आर्डर कर देते हैं और हमेशा यह सुनिश्चित करते हैं मैं सही वक्त पर खाना खाऊं। मैं बहुत खुश हूं।(हंसते हुए) शादी के बाद मेरी नहीं, मेरे पति की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। महामारी की वजह से शादी के बाद हम कहीं बाहर घूमने नहीं जा पाए हैं। शादी के बाद हमने पूरा वक्त संकेत के कल्याण (मुंबई से सटे शहर) स्थित घर पर उनके परिवार के साथ ही बिताया।'

जिम्मेदारियों में हल्कापन महसूस कर रही हैं सुगंधा। टीम स्वयं

...तो इसलिए काजोल ने करण जौहर से खुद पर चिल्लाने के लिए कहा

सिंगिंग रियलिटी शो में बतौर अतिथि पहुंचे करण। टीम सोनी

दोस्ती के कई रूप होते हैं। कभी समझाना, कभी चिल्लाना तो कभी प्यार जताना। अभिनेत्री काजोल और फिल्मकार करण जौहर की दोस्ती हिंदी सिनेमा की सबसे अच्छी दोस्ती में गिनी जाती है। करण ने काजोल के साथ अपनी दोस्ती के कुछ किस्से साझा किए सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 12 के मंच पर। जहां वह आगामी सेमीफाइनल एपिसोड की शूटिंग के लिए बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। इस शो से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, शो में मंगलोर के प्रतिभागी निहाल तौरो ने करण की फिल्म कुछ कुछ होता है के गाने लड़की बड़ी अनजानी है.. पर परफार्म किया। बतौर निर्देशक अपनी पहली फिल्म का गाना सुनकर करण को कुछ किस्से याद आ गए, जिसे उन्होंने मंच पर साझा किया। उन्होंने बताया कि 'यह 24 साल पहले की बात है। कुछ कुछ होता है के पहले शेड्यूल की शूटिंग का पहला दिन था। मेरी पुरानी दोस्तों में से एक काजोल मेरे रूम में आईं और मुझसे कहा कि देखो करण तुम एक साफ्ट इंसान हो। इतनी बड़ी पिक्चर डायरेक्ट कर रहे हो तो सेट पर सभी लोगों को रूआब के साथ निर्देश कैसे दे पाओगे? फिर मैंने उनसे पूछा कि तुम क्या सलाह देना चाहोगी? इस पर काजोल ने कहा कि देखो मेरी रेपुटेशन की वजह से लोग वाकई में मुझसे घबराते हैं। तो पहले दिन तुम मेरे पास आओगे और मुझ पर चिल्लाओगे। मेरे जवाब के बाद तुम कहना कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई और तुमने रिहर्सल क्यों नहीं की? काजोल के मुताबिक, यदि मैं उन पर चिल्लाता तो सेट पर बाकी सभी मेरी इज्जत करने लगते और बाद में कोई मुझे तंग नहीं करता।' इस एपिसोड का प्रसारण इस सप्ताहांत में सोनी चैनल पर होगा।

करियर जिंदगी का छोटा सा हिस्सा है : अतुल कुलकर्णी

लाल सिंह चड्ढा फिल्म के लेखक भी हैं अतुल • जागरण आर्काइव

सात सवाल

रंग दे बसंती, हे राम, चांदनी बार जैसी फिल्मों में अभिनय कर चुके अभिनेता अतुल कुलकर्णी डिजिटल प्लेटफार्म पर भी सक्रिय हैं। हाल ही में उनकी वेब सीरीज सिटी आफ ड्रीम्स का दूसरा सीजन डिज्नी प्लस हाटस्टार पर रिलीज हुआ है। अतुल की बतौर लेखक लाल सिंह चड्ढा फिल्म की शूटिंग भी आखिरी शेड्यूल में है। उनसे हुई बातचीत के अंश।

• इस शो का दूसरा सीजन एक अंतराल के बाद आया है। ऐसे में पहले सीजन में अपने किरदार को दोबारा देखने की जरुरत पड़ी थी?

-दूसरे सीजन की जो स्क्रिप्ट थी, वह मैंने पहले ही पढ़ ली थी। शूटिंग जब करीब थी, तो पहला सीजन भी देख लिया था, ताकि खुद को उस किरदार की याद दिला पाऊं। पूरा सीजन नहीं देखना पड़ा।

• क्या आप वेब सीरीज में अभिनय करने के बाद, उसे देखने में भी उतना ही वक्त दे पाते हैं?

-हां, बिल्कुल। अपना मनोरंजन करने के लिए हमारे पास वक्त की कमी नहीं होनी चाहिए। फिर वक्त भले ही हम अपने जरूरी कामों के बाद निकालें। अगर खुद के लिए ही खाली वक्त नहीं निकाल पा रहे हैं, तो काम क्यों कर रहे हैं। आप भले ही कोई भी काम कर रहे हों, कहानियां जरूर सुनना चाहते हैं।

• शो की कहानी राजनीति के आसपास रची गई है। राजनीति में आपको खुद कितनी दिलचस्पी रही है?

-मुझे स्कूल से ही बहुत ज्यादा दिलचस्पी रही है। हम अक्सर पसंद और उस पसंद में शामिल होने के बीच का फर्क नहीं समझ पाते हैं। राजनीति में दिलचस्पी जरूर है, लेकिन उसमें शामिल होने की जरूरत मुझे नहीं है। मुझे लगता है राजनीति कई लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा होती है।

• इतने लंबे करियर में किरदारों को रिपीट न करना यकीनन चुनौतीपूर्ण रहा होगा?

-हां, लेकिन फिर यहां आपका इतने वर्षों का अनुभव ही काम आता है। करियर को तो मैंने अपनी जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा माना है। बाकी जिंदगी जो हम जीते हैं, जिनके साथ उठते-बैठते हैं, जो आपके आसपास राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तौर पर होता है, उसका परिणाम आप पर भी होता है। इसकी वजह से बतौर इंसान आप बदलते हैं। हम कलाकार हैं, हमारा दिमाग और शरीर ही हमारे उपकरण हैं। हम बदल रहे हैं, तो इन उपकरणों को इस्तेमाल करने का तरीका भी बदल ही जाएगा। किरदारों की पसंद पर जरूर असर पड़ता है। कहानियों को सुनते हैं, चुनते हैं, लेकिन उसमें कई और चीजें होती हैं कि अब तक क्या किया, क्या नहीं किया, क्या करना चाहते हैं, आर्थिक हालात क्या हैं। इन सबका एक मिश्रण होता है।

• फिल्म का कामर्शियल एंगल प्रभावित करता है?

-हां, बिल्कुल करता है। हम सिनेमा और वेब सीरीज में काम कर रहे हैं, यह महंगी कला है। मैं कामर्शियल नजरिये को भी महत्व देता हूं। आप जो कहानी कहना चाह रहे हैं, वह इसलिए ही कह रहे हैं कि लोगों को वह पसंद आए। कहानी ज्यादा लोगों को पसंद आएगी, तो उसका प्रभाव आपकी सफलता और उससे जुड़े अन्य पहलुओं पर दिखेगा। दोनों ही चीजें एक-दूसरे से जुड़ी हैं।

• आप ट्विटर पर बिना किसी का नाम लिए, अपनी बातें लिख जाते हैं। मुद्दों पर अपनी राय रखना जरूरी मानते हैं?

-जरूरी नहीं मानता हूं, लेकिन इंटरनेट मीडिया का प्लेटफार्म बना ही लिखने के लिए है। पहले मैं अखबारों के लिए लेख लिखा करता था। अब तकनीक, समय बदल गया है। खुद को व्यक्त करने का तरीका भी बदल गया है। जब आप कुछ लिखते हैं, तो वह कोई एक क्षण नहीं होता है। वह पूरी एक सोच होती है, जो आपके दिमाग में चलती रहती है। आप एक जिंदगी जी रहे होते हैं, ऐसे में अगर आप अपनी आंखें, कान और दिमाग को खुला रखकर रखेंगे, तो जरूर कुछ न कुछ आपके दिमाग में चलता रहेगा। लिखना उसका अंतिम स्वरूप होता है। जो लिखना चाहे, वह लिखें, जो नहीं लिखना चाहते हैं, वह न लिखें। सबकी अपनी पसंद है। अपनी पसंद के हिसाब से सबको लिखना चाहिए।

• लाल सिंह चड्ढा फिल्म पर काम कहां तक पहुंचा है? क्या कोरोना काल के बाद स्क्रिप्ट में कोई बदलाव किए गए हैं?

-फिल्म की शूटिंग अपने आखिरी शेड्यूल में है। अब इस फिल्म की शूटिंग बहुत ही कम बची है। स्क्रिप्ट में जहां तक बदलाव की बात है, तो जब वक्त आएगा, इसके बारे में जरूर बात करेंगे।

(प्रियंका सिंह)

डेढ़ सौ करोड़ के बजट में बनेगी बालाकोट हवाई हमले पर फिल्म

वास्तविक कहानियां कई फिल्ममेकर्स को काफी भा रही हैं। इन वास्तविक कहानियों में कई मेकर्स की पसंद हैं शौर्य की वह कहानियां, जिस पर पूरे देश को नाज होता है। भारतीय वायुसेना के साहस की कहानी एक बार फिर बयां करने के लिए तैयार हैं निर्देशक अभिषेक दुधैया। भुजः द प्राइड आफ इंडिया की रिलीज के बाद अभिषेक दो ऐसी फिल्मों पर काम करेंगे, जो देशभक्ति पर आधारित होंगी। इन दो फिल्मों में से एक बालाकोट हवाई हमले पर होगी, दूसरी परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन बाना सिंह की कहानी होगी। दैनिक जागरण से बातचीत में अभिषेक ने बताया कि मैं खुद एक वक्त पर सेना में जाना चाहता था, लेकिन वह नहीं हो सका। मेरे पास यही माध्यम है जिससे अपनी देशभक्ति की भावना को लोगों तक पहुंचा सकता हूं। दोनों ही फिल्मों की कहानियां मैं लिख चुका हूं। प्रत्येक फिल्म का बजट डेढ़ सौ करोड़ होगा। रक्षा मंत्रालय ने बालाकोट पर फिल्म बनाने की परमिशन भी दे दी है। कास्टिंग पर काम अभी बाकी है। स्क्रिप्ट को बस फाइनल टच देना है। जैसी सहूलियत मिनिट्री आफ डिफेंस की तरफ से आगे मिलेगी, वैसे ही दोनों फिल्मों पर काम शुरू होगा। दोनों ही फिल्में बनाने के राइट्स मैंने ले लिए हैं। बालाकोट फिल्म भारतीय वायुसेना द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के बालाकोट में किए हवाई हमले पर आधारित होगी। 14 फरवरी, 2019 को जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ काफिले पर आतंकी हमले के बाद, भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में हवाई हमला किया और जैश-ए-मुहम्मद के आतंकी शिविर को ध्वस्त किया था।

भारतीय वायुसेना के साहस को दिखाएगी अभिषेक निर्मित फिल्म • इंस्टाग्राम